छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा **प्रथम सत्र**

मंगलवार, दिनांक 12 फरवरी, 2019

(माघ 23, शक सम्वत् 1940)

[अंक 08]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 12 फरवरी, 2019

(माघ 23, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ0 चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, आपको बधाई। आज वित्तमंत्री और पंचायत पंचायत मंत्री के प्रश्न का पहला दिवस है और इनको विशेष रूप से बधाई क्योंकि दूसरे दिन इनका पहला प्रश्न है।

<u>बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण</u>

1. (*क्र. 437) श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने शौचालय का निर्माण किया गया है ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत कुल 65,791 शौचालय का निर्माण किया गया है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे आपके माध्यम से पहली बार पंचायत मंत्री बने बाबा साहब से पूछने का अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय मंत्री महोदय जी, आप कृपा करके बताने का कष्ट करेंगे कि बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वीकृति के आधार पर कितने शौचालय बनाये गये ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नई पारी की शुरूआत का आज अवसर मिला है और नये विधायक के दूसरे दिन के पहले प्रश्न की पहली पारी की पुनरावृत्ति में। माननीय विधायक जी ने जानना चाहा है कि बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने शौचालयों का निर्माण हुआ है

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आपको पहली बार अवसर मिला है। हम तो आपके लिए कहीं और अवसर देख रहे थे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस. सिंहदेव :- बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 65,791 शौचालयों का निर्माण हुआ है। बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बिलाईगढ़ की 112 और कसडोल की 65 विकासखंड के कुल 177 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें सभी ग्राम पंचायतें खुले में शौच मुक्त ओ.डी.एफ. घोषित किये जा चुके हैं। बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 65,791 शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से 42,522 एवं महात्मा गांधी मनरेगा नरेगा से 23,269 शौचालयों का निर्माण किया गया है। कुल निर्मित 65,791 के विरूद्ध कुल राशि 78.... मैं पूरी जानकारी दे दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मत दीजिए। उनको पूछने पर ही दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- जी-जी।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- मेरा पूछने का आशय बस इतना है कि आप कसडोल से 65 पंचायत बता रहे हैं। वर्तमान में 66 पंचायत हैं। चूंकि आंकड़े में भी भिन्नता है। जिस प्रकार से मैंने आंकड़ा विभाग से लिया है, बिलाईगढ़ विकासखण्ड में 42,612 और कसडोल विकासखण्ड से 26,997 कुल 69,584 है। आपके द्वारा बताये गये आंकड़े में 65,791 है। मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं। मेरा यह आशय है कि ये पूरे क्षेत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है, जहां आधे-अधूरे शौचालय बनाये गये हैं। पूरे जिला सहित विधान सभा ओ.डी.एफ. घोषित कर दिया गया है, जहां पर पूर्ववर्ती सरकार के समय में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ऐसे जो गरीब परिवार हैं, जिनके शौचालय आधी-अधूरे बनाये गये हैं, उस पंचायत से रिलेटेड सचिव, जनपत के सी.ई.ओ. और कलेक्टर के जहां पर भष्टाचार के भेंट चढ़ी है, वहां पर क्या आप जांच करावाकर कार्रवाई करवायेंगे तथा हितग्राहियों की शेष राशि आप कब तक वापस दिलायेंगे?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल निर्मित 65,791 शौचालयों के विरूद्ध में 78.94 करोड़ राशि का भुगतान किया जाना था। इसमें स्वच्छ भारत मिशन के 48.06 करोड़ और महात्मा गांधी नरेगा से 20.21 करोड़ की राशि, इस प्रकार 68.02 करोड़ राशि का भुगतान किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन में 2.41 करोड़, मनरेगा में 7.71 करोड़ का भुगतान लंबित है। 10.12 करोड़ का भुगतान लंबित है। 9.05 करोड़ की राशि बलौदाबाजार जिले में जल्द से जल्द इसका भुगतान भी हो जायेगा। माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है......

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय मंत्री महोदय जी, ये ऐसे दर्जनभर गांव हैं जहां मुझे लिखित शिकायत दिये हैं, जिसमें रायकोना, धोधरी, उड़काकन, सलोनीकला, बम्हनपुरी, साल्हेवना, कोठीखोल, रिकोतार, सोनपुर, नगेड़ी ये कसडोल क्षेत्र के और बिलाईगढ़ क्षेत्र के हैं। क्या इस पर आप कलेक्टर के माध्यम से जांच करवाकर कार्रवाई करवायेंगे?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस. सिंहदेव :-बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल 47 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें 46 शिकायतों का निराकरण हुआ है। एक शिकायत एस.डी.एम. के पास लंबित है। ज्यादातर शिकायतें प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने के संदर्भ में है। बलौदाबाजार जिले में 26 जनवरी को ओ.डी.एफ. घोषित किया गया था । यदि माननीय सदस्य के पास कोई भी ऐसी जानकारी है, जिसका वे निराकरण चाहते हैं, जांच चाहते हैं, तो अवश्य जांच करा देंगे। जांच के पश्चात यदि ऐसी कोई कमी पाई जाती है तो कार्रवाई भी होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपने उत्तर में जो एस0बी0एन0 में भुगतान की राशि लंबित होना बताया है। जो शौचालय हैं, उनके निर्माण कब पूरे हुए ? कितने दिन में उसका भुगतान किया जाना है ? अब तक भुगतान लंबित रहने के क्या कारण हैं ?

श्री अमरजीत भगत :- आप ही का तो सब गड़बडी किया हुआ है।

श्री दीपक बैज :- यह तो पूरा आप ही का किया हुआ है, मंत्री जी।

श्री अमरजीत भगत :- आप ही बोलते थे कि पूरा भुगतान हो गया है। अब आप ही प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो खड़े हो रहे हैं न, अभी मेरा भाषण है।

श्री अमरजीत भगत :- भाषण है तो क्या डरवाओगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जिसमें मैं बोलूंगा कि आप क्या प्रदर्शन कर रहे हो ? मैं बजट भाषण में मनरेगा के बारे में जरूर बोलूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी एक प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- हां, आप पूछेंगे। मेरे कहने पर पूछेंगे। मंत्री जी, आप चन्द्राकर जी का जवाब दे रहे हैं ?

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, साथियों ने तो बताया कि उनके पास संपूर्ण जानकारी रही है। (हंसी) शेष और जो भी जानकारी चाहेंगे, मैं और उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अमरजीत भगत :- अगर ये ठीक-ठाक काम किए होते तो उस पर थोड़े न गए होते।

श्री अजय चन्द्राकर :- अमरजीत जी, ऐसा है कि यदि मैं इधर आ गया, मैं 10 साल या 15 साल उधर रहा तो मेरे प्रश्न करने के अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते और पूरक प्रश्न करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, आपको जितनी जांच करानी है, जिससे करवानी है, जब करवानी है, मांग करिये और करवाईये। यहां चिल्लाने के बजाय, नंबर बढ़ाने के बजाय ताकत है तो ऐसा आईये। ...(व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- यहां जांच की बात तो ही हो रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अजय चन्द्राकर इन बातों से दबने वाला नहीं है। आप गलत आदमी से लग रहे हो। ...(व्यवधान)

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें विचलित होने वाली बात क्या है ? ...(व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- गड़बड़ी हुआ है, इसलिए आप उस पार चले गए हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- नंबर बढ़ाने की कोशिश मत करो। आप प्रक्रिया में आओ, शिकायत करो और जांच करवाओ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आदेश जारी हुआ, उसमें आपको इतनी बैचेनी क्यों है, बताओ ?

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- माननीय मंत्री महोदय जी, पूर्ववर्ती सरकार 8 साल शौचालय बनाकर ओ0डी0एफ0 घोषित कर दिए। उसकी भी तो जांच करवा दीजिये। उस समय पी0एच0ई0 मंत्री अग्रवाल जी रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- करायेगे-करायेंगे। चलिये-चलिये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सामान्य सी बात है कि प्रश्नकाल चल रहा है। माननीय सदस्य ने प्रश्न लगाया है। अपने यहां परम्परा है कि उसमें कोई भी सदस्य आपकी अनुमति से एकाध पूरक प्रश्न कर लेते हैं। कल तक यह प्रश्न पूछ रहे थे और यह जवाब दे रहे थे, परिस्थितियां बदल गई हैं। माननीय अजय चन्द्राकर जी ने प्रश्न किया तो चार माननीय सदस्य खड़े हो गए। खड़े होकर यह बोल रहे हैं कि कल तक आप थे। तो क्या अजय चन्द्राकर जी को जवाब देने के लिए वहां फिर बैठा दें ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सामान्य शिष्टाचार है कि जब माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे हैं तो माननीय मंत्री जी उसका जवाब देंगे, इतना तो इंतजार करना चाहिए। जब तक कल वे थे तो जवाब दिए, आज नहीं हैं तो माननीय राजा साहब जवाब दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोगों की भूमिका बदल चुकी है। इसलिए उसका अनुभव करिये। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक किस्सा है, मैं प्रश्न पूछने के पहले एक किस्सा बता दूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो नंबर बढ़ाने का तरीका है और कुछ नहीं है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं हैं, आपका कुछ नहीं होगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- पिक्चर में एक खलनायक हुआ करते थे-प्राण। लोग उसका देखकर डरते थे। उपकार पिक्चर से उन्होंने अपना कैरेक्टर बदला, थोड़ा टाईम लगा। इनको थोड़ा टाईम लगेगा। माननीय मंत्री जी, शौचालय की बात है।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैय्या, इस प्रश्न में प्राण कौन है ? (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- सबसे बड़े प्राण तो आप हो। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं इस बात के समर्थन में हूं कि सबसे बड़े प्राण वही है क्योंकि जब विधायक थे तो, एयरपोर्ट में भी अमित जोगी जी को भी लेने के लिए जाते देखा हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उनकी बहुत पूछ चल रही है।

श्री अमरजीत भगत :- उनको जानकारी बहुत अंदर तक रहता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपका कनेक्शन सामने वाले से थोड़ा कमजोर दिख रहा है। उधर केबल ज्यादा दिख रहा है। माननीय मंत्री जी, शौचालय निर्माण का प्रश्न आया है। इसलिए मैंने अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर पूछना चाहा। मुंगेली जिले में लोरमी विधान सभा क्षेत्र में अनेक फर्जी शौचालय बनाए गए हैं, जिसका भुगतान संबंधितों ने लिया है । उसकी जांच की मांग करके मैं थक गया हूं, इनके राज में तो जांच नहीं हुआ तो आप तो कृपा करके सम्पूर्ण लोरमी विधान सभा क्षेत्र के जितनी भी शिकायतें हैं, उनको प्राथमिकता से जांच कराकर दोषियों को दंडित करने या कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे क्या ? कलेक्टर और एस.डी.एम. के पास पूरी जानकारी है ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राण को जवाब देना है । मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि हालांकि ये प्रश्न से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, बिलाईगढ़ के संदर्भ में प्रश्न था, फिर भी यदि विभाग में कहीं भी, कभी भी, कोई भी ऐसी बात आती है, जिसमें कोई भी सदस्य या छत्तीसगढ़ के कोई भी नागरिक कभी भी जांच कराना चाहेंगे तो निश्चित रूप से जांच होगी और जांच में जो भी कमियां पायी जाएंगी, उसमें कार्यवाही भी होगी ।

<u>जिला कोण्डागांव अंतर्गत मल्टीपरपज इंडोर हॉल, जिला स्टेडियम तथा स्वीमिंग पुल निर्माण कार्य की लागत</u>

2. (*क्र. 111) श्री मोहन मरकाम : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव जिले में स्वीकृत मल्टीपरपज इंडोर हॉल, जिला स्टेडियम तथा स्वीमिंग पुल की कितनी लागत हैं ? (ख) क्या कार्य प्रारंभ हो गया है? यदि नहीं तो कब तक प्रारंभ किया जाएगा ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : (क) कोण्डागांव जिले में मल्टीपरपस इंडोर हॉल स्वीकृत नहीं है. स्वीकृत जिला स्टेडियम की लागत राशि रु. 599.90 लाख तथा स्वीमिंग पुल की लागत राशि रु. 198.67 लाख है. (ख) जी, नहीं. निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है.

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहा था, माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है, मेरा पूरक प्रश्न है । जिला स्टेडियम कोण्डागांव की स्वीमिंग पुल कब स्वीकृत हुई और कितनी लागत की स्वीकृत हुई ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेडियम की प्रशासनिक स्वीकृति अभी 2.2.2019 को मिली है और इसकी लागत 599.90 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति है ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आप वर्तमान की बता रहे हैं, मैंने पूछा है कि कब से, कौन से सन् में जिला स्टेडियम की स्वीकृति हुई थी और आप अभी का बता रहे हैं ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, इसकी स्वीकृति 2012 में मिली थी ।

श्री मोहन मरकाम :- कितने लाख की ?

श्री उमेश पटेल :- 490 लाख ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है कि कोण्डागांव में मल्टीपरपस इंडोर हॉल स्वीकृत नहीं है, जबकि मेरे प्रश्न क्रमांक 816, 21 नवम्बर, 2016 और 11 जुलाई, 2016 के प्रश्न में इसी विधान सभा में सरकार के द्वारा उत्तर दिया गया है । इंडोर हॉल निर्माण की स्वीकृति 16.10.2012 को 7 करोड़, 88 लाख की हुई है, आपका उत्तर आ रहा है कि स्वीकृत नहीं हुई है तो सही कौन सा है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2012 में इसकी स्वीकृति मिली थी । मेरा जो उत्तर है, वह आज के परिदृश्य में है । 2012 में इसकी स्वीकृति मिली थी, इसका दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 है, जिसमें 5.90 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई थी । ये हमको केन्द्र सरकार से मिला था, इसकी पहली किश्त 1.79 करोड़ रूपये प्राप्त हुई थी । उसमें कंडीशन ये था कि स्वीकृति का जो निर्माण कार्य है, वह 31 मार्च, 2014 तक पूर्ण होनी चाहिए, लेकिन किसी कारणों से ये पूर्ण नहीं हुई क्योंकि वन विभाग से इसमें जमीन नहीं मिली इस कारण से इसमें लॉस हुआ और इसका जो किश्त, पैसा है, वह भी केन्द्र सरकार को वापस जा चुका है ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2016 के उत्तर में आया है, जबकि माननीय मंत्री जी 2014 बोल रहे हैं । 2016 के उत्तर में भी दो बार इसी विधान सभा में उत्तर आया है कि ये स्वीकृति है, आप बोल कर हैं कि 2014 में ही ये वापस हो गया है तो फिर 2016 में उत्तर कैसे आ गया कि इतनी राशि ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दूसरी बात, चिह्नित वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु स्टेडियम के लिए कितनी राशि दी गई, क्या यह राशि अधोसंरचना मद से दिया गया या इसके लिए अलग से बजट में प्रावधान किया गया था ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि 31 मार्च, 2014 को इसको पूर्ण करने का कंडीशन था । 2017 में इसकी राशि वापस कर दी गई है तो 2016 तक पत्राचार चल रहा था, जिसमें ये वापस नहीं हुआ था । 2017 में वापस हुआ । कंडीशन ये था कि 31 मार्च, 2014 तक पूर्ण करना था, लेकिन वन विभाग से भूमि मिलने के कारण ये नहीं हुआ । आपका दूसरा प्रश्न क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- आपने तीन प्रश्न कर लिये ।

श्री मोहन मरकाम :- दो प्रश्न हुआ है । आपका संरक्षण चाहिये, माननीय अध्यक्ष महोदय । माननीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण कार्य 2012 से है, 7 साल हो गये हैं, कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है । सरकार के ऊपर खर्च बढ़ता जा रहा है । गंभीर प्रश्न है, इसलिए आपका मुझे संरक्षण चाहिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, चिन्हित वन भूमि को गैरवानिकी कार्य हेतु स्टेडियम निर्माण के लिए कितनी राशि दी गई, क्या यह राशि अधोसंरचना मद में था या उसके लिए अलग से बजट में प्रावधान किया गया था ?

अध्यक्ष महोदय :- आप ऐसा करें, मंत्री जी के कक्ष में चले जायें और मंत्री जी के कक्ष में जाकर उसे स्पष्ट कर दें ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं पांच साल से यही कर रहा हूँ ।
वर्ष 2012 से आज 7 साल हो गये । आज निर्माण कार्य नहीं हुये हैं, जिला मुख्यालय कोंडागांव हैं । माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जवाब आता है कि समयावधि बताना संभव नहीं है । एक उर्जावान युवा मंत्री से यह अपेक्षा नहीं कर सकते, ऐसा जवाब आये । माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो निराशा हुई है, आखिर पिछली सरकार भी 7 साल तक लटकाकर रखी । वर्तमान सरकार ऐसे ही जवाब दे तो किनसे उम्मीद करेंगे कि ऐसा होगा ? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूॅ कि इसकी समयवृद्धि होगा क्या ? आपने प्रारंभ में ही बताया कि प्रशासकीय स्वीकृति हुई तो कब तक काम चालू हो जायेगा ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मोहन मरकाम जी को मैं बताना चाहूंगा कि ये सरकार आपकी है, यह सरकार छत्तीसगढ़ जनता की है । जो काम आपके रूके हुये हैं, वह यथाशीघ्र पूर्ण होंगे । आपको पता होना चाहिये कि आपकी सरकार बन गई है । इसमें प्रशासनिक स्वीकृति हो गयी है । टेण्डर की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होगी । इसी कार्यकाल के अंदर दोनों चीजों का उदघाटन करके मैं देता हूॅ ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल जी कौशिक ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बिल्हा विधानसभा क्षेत्रातंर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य

3. (*क्र. 153) श्री धरमलाल कौशिक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 2015 से दिसंबर 2018 तक कितनी-कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किए गये हैं ? स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे ? (ख) क्या यह बात सही है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उक्त स्वीकृत कार्यों में से अप्रारंभ कार्यों को रोककर जारी की गई राशि वापस ली जा रही है ? यदि हां तो राशि वापस लिये जाने का क्या कारण है ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2015 से दिसंबर, 2018 तक राशि रुपए 38391.88 लाख के कार्य स्वीकृत किए गये हैं. कुल स्वीकृत 69,846 कार्यों में से 65,140 कार्य पूर्ण तथा 3,765 कार्य अपूर्ण हैं. तथा 941 कार्य अप्रारंभ है । अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है । योजनावार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 में दर्शित है । (ख) जी नहीं । पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों में से अप्रारंभ कार्यों को रोककर जारी की गई राशि वापिस नहीं ली जा रही है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा बिल्हा से संबंधित प्रश्न है । माननीय मंत्री जी ने भी उत्तर में संशोधित जवाब दिया है, जो कि मुझे प्राप्त हो गया है । सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने संशोधित उत्तर में यह कहा है कि अब जो निर्माण कार्य के जितने पैसे हमने दिये हैं, उसको हम वापस नहीं ले रहे हैं । सारे पैसे प्रदेश में जहां दिये हैं, वह कार्य वहां पर होंगे । इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- यह नहीं कहा है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- ये लिखा है ना । मैं पढ़ देता हूँ- अप्रारंभ कार्यों को रोककर जारी की गई राशि वापिस नहीं ली जा रही है । मैं यही समझ रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं, आप उसे बता देंगे । मैं तो उत्तर में यही समझ रहा हूँ ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य धरमलाल कौशिक जी ने जो जानना चाहा था, उसमें 2015 से 2018 के बीच में 38,391.88 लाख के कार्यों की स्वीकृति हुई थी । कुल स्वीकृत कार्यों में से 69,846 कार्यों में से 65,140 कार्य पूर्ण बताये गये हैं । 3765 कार्य अपूर्ण हैं । अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किये जाने के संबंध में समय भी मांगा है, समय भी पूछा है तो स्वाभाविक है कि कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती है । प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द सारे कार्य पूर्ण किये जा सके । योजनावार भी आपने जानकारी चाही है.....

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूँ । आपने जो जवाब दिया था, आपने संशोधित किया है । संशोधित जवाब में यह आया है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ । पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों में से अप्रारंभ कार्यों के रोककर जारी की गई राशि वापस नहीं ली जा रही है । मैं इसलिए आपको धन्यवाद दिया हूँ ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, 12-4-2017 को अपर मुख्य सचिव का एक पत्र गया था कि 10 मई 2017 तक अनिवार्य रूप से जो भी कार्य उन योजनाओं के जो बंद कर दिये गये हैं, वह संपूर्ण राशि मय ब्याज के तत्काल जमा कर दी जाये, यह 12-4-2017 की जानकारी है । यह स्पष्ट है कि कौन से पैसे वापस होने की बात है, कौन से पैसे वापस होने की बात नहीं है । जिन योजनाओं को बंद कर दिया गया था । 10 वें, 11 वें, 12 वें, 13 वें वित्त आयोग, बीआरजीएफ, आईएपी, मुख्यमंत्री सड़क ग्राम उत्कर्ष योजना, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण योजना, ग्राम विकास और भी योजनायें हैं, उसको बंद कर दिया गया था, इनकी राशियों को 12-4-2017 तत्कालीन सरकार की ओर से यह पत्र गया था । इसके परिपालन में उसी समय 26-5-2017 को सभी कार्यपालन अधिकारी महोदयों को पत्र चला गया था कि आप इन राशियों को वापस कर दें तो कौन सी राशि वापस होनी है, तो जो योजनाएं बंद हो गई हैं। शेष 22.12.2018 जो माननीय सदस्य महोदय आपका वर्तमान संदर्भ है कि इस परिपत्र के जारी होने से, एक और पत्र वित्त विभाग से आया है इस परिपत्र के जारी होने से दिनांक 22-12-2018 से राज्य बजट से वित्त पोषित सभी अप्रारंभ निर्माण कार्यों को वित्त विभाग की पुन: सहमति के उपरांत ही प्रारंभ किया जाए। पैसा वापस लेने की बात नहीं है। पुन: वापस किया जाए। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की बात अलग है। जवाब में भी यही है कि इसका परीक्षण किया जायेगा।

श्री सौरभ सिंह :- आप अपना धन्यवाद वापस ले लीजिए।

श्री अजीत जोगी :- विपक्ष के नेता जी, अपना धन्यवाद वापस लीजिए।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ये दो जवाब है। दोनों जवाब में आपका जो अंतर है वह संशोधित है। या तो इस संशोधन को आप वापस ले लीजिए और कहिए कि ये संशोधन गलत है ये जो मूल प्रश्न में जवाब आया है वह ठीक है। और यदि संशोधित उत्तर ठीक है तो यह तो मैंने आपको पढ़कर बता दिया। तो एक तो उत्तर में कन्फ्यूजन की स्थिति है और अभी भी क्लीयर नहीं हो रहा है कि जो राशि वापस नहीं ली जा रही है, कल भी वह विषय आया था और उस विषय में सारे सदस्यों ने बात की। उस विषय में आगे भी प्रश्न करेंगे। ये जो अपूर्ण कार्य है उस अपूर्ण कार्य में प्रधानमंत्री आवास योजना भी है जिसमें विभिन्न कालखंडों में राशि दी जाती है कि निर्माण के शुरूआत में, फिर लेंटर के समय आदि समय दी जाती है लेकिन उसमें काफी विलंब हो रहा है जिसके कारण बहुत सारे मामले लंबित हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि एक हितग्राहीमूलक योजना है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इस योजना के जो कार्य लंबित हैं उसमें इन्स्ट्रक्सन देकर उसे कब तक पूरे करा लिये जायेंगे क्योंकि उसके विभिन्न चरणों के कारण उसमें दिक्कत आ रही है और जो साल-दो साल से लंबित पड़ा है उसके कारण उसके हितग्राही बिना कारण के तकलीफ उठा रहे हैं तो जल्द से जल्द उनका मकान पूरा हो जाए तो इसको कब तक कर लिया जायेगा?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों बातें आई हैं। अपूर्ण कार्यों के संबंध में और जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं उनके संबंध में। तो जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं, मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि वह राशि वापस नहीं मंगाई गई है किन्तु वित्त विभाग की पुन: अनुमति के बाद ही वह काम लेने है या नहीं लेने हैं उस पर विचार हो सकता है, लेकिन राशि वापस नहीं बुलाई गई है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि राशि वापस नहीं बुलाई गई है बल्कि काम होंगे या नहीं वह वित्त विभाग के पुन: अनुमति के बाद ही वह काम प्रारंभ होंगे या पैसे किस कार्य में लगेंगे। जो अपूर्ण कार्य है उसकी राशि वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो काम अधूरे रहते हैं मान लीजिए कि आपने प्रधानमंत्री आवास के संबंध में पूछा तो केन्द्र सरकार से हमको कितनी राशि मिली है उसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, कितनी राशि नहीं मिली है, विलंब का कारण क्या होता है, ये सारी जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगा और कैसे वर्तमान शासन ने नये शासन में आने के बाद राशियों की प्राप्ति के लिए अपनी ओर से विशेष पहल करके पैसों की अदायगी करके केन्द्र सरकार से राशि भी ली है। उसकी भी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा तो देर का कारण मुख्य रूप से वही होता है और कोई राशि वापस करने वाली बात नहीं है यह क्लीयर होना चाहिए। राशि वापस करने वाली बात नहीं है लेकिन पुन: उस राशि के उपयोग के संबंध में विचार होगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को राशि आवंटित कर दी। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों में से अप्रारंभ कार्यों को रोककर जारी की गई राशि वापस नहीं ली जा रही है।

अध्यक्ष महोदय :- इसका जवाब आ गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब राशि वित्त विभाग ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आवंटित कर दी, तो अब वित्त विभाग के परमीशन की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? पंचायत विभाग क्या इस विषय में निर्णय करने में सक्षम नहीं है या पंचायत विभाग को निर्णय का अधिकार नहीं दिया गया है? आप ये स्पष्ट कर दें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत विभाग को निर्णय का अधिकार नहीं दिया गया है। ये आप स्पष्ट कर दें।

श्री टी.एस.सिंहदेव (पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णय के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अधिकार का प्रश्न ही नहीं है। काम कैसे मंजूर हुए, चुनाव के ठीक पहले आनन-फानन में हुए कि वे काम किन परिस्थितियों में मंजूर हुए। क्या वर्तमान सरकार को अधिकार है कि नहीं कि जो काम नहीं हुए हैं उनका पुनरीक्षण करें फिर सहमति दें? जैसे खर्च करने हैं, ये सरकार खर्च करेगी। क्या ये सरकार को.....।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, कैसे काम पास हुआ है, कैसे काम पास होता था अगर आपकी अनुमति हो तो बता दूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, काम उचित है, अनुचित है। काम होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। इसका निर्णय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग करेगा कि वित्त विभाग करेगा। ये आप स्पष्ट कर दें।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, कौन सा काम वित्त विभाग की अनुमति के बिना होता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग ने तो आपके विभाग को राशि जारी कर दिया है तो निर्णय तो आपको करना है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- वित्त विभाग ने सकुर्लर जारी किया है, जितने काम हैं वे हमारे से बिना पूछे चालू न करें। अब वित्त विभाग की क्या मंशा थी, हमको किसानों का कर्जा माफ करना है। हमको 2500 रूपये में धान खरीदी करना है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर से साबित हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, ये साबित हो गया।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर से चालू हो रहा है, अभी सुनिये तो, सुनिये तो।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आप ये हेराफेरी करने के लिए पूरे प्रदेश का काम रोक दिये, स्पष्ट हो गया कि पूरे प्रदेश का काम रोक दिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, उस काम का नाम बदलने से क्यों छटपटाहट हो रही है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, आपको क्यों तकलीफ हो रही है?

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जो काम स्वीकृति होने में दिया गया है, उसको वापस करना पड़ेगा, इसलिए छटपटाहट हो रही है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, अगर पैसे धान के लिए उपयोग करना होता तो, पैसे वापस आ जाते। क्या हमारे अनुभवी सदस्य लोग, इतना भी नहीं समझे? तुरंत उस पर कूद पड़े। अगर इनकी मंशा होती तो पैसे तो वापस ले लिये जाते, कई कारण होते हैं। वित्त विभाग निर्णय क्यों देते हैं, निर्देश क्यों देते हैं, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा है कि जब तक पुन: हमारी मंजूरी दोबारा नहीं ली जाती है, उन कामों को नहीं करना है। अध्यक्ष महोदय, केवल 941 कामों का ही तो

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

मामला है। 941 में से तो 900 काम मनरेगा के हैं, केवल 941 मामलों के लिए इतना बड़ा प्रश्न और इतनी बड़ी बात हो रही है। 1.42 प्रतिशत, कुल 1.42 प्रतिशत लगभग पौने 400 करोड़ रूपये के खर्चे में से केवल और 900 काम मनरेगा के हैं। क्यों इतनी चिंता हो रही है?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो आपके अधिकार की चिंता कर रहे हैं, जो आफत कार्य है उसे दूसरे को क्यों सौंप रहे हो।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- किसी विभाग का अधिकार वित्त विभाग के आगे नहीं होगा।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, क्या है माननीय राजा साहब पी.टी. ऊषा जो है, 100 वें सेकंड के हिस्से से स्वर्ण पदक से चूक गई थी। उसी तरह आपके साथ घटना घटी है। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि वित्त विभाग ने आपको जो परिपत्र जारी किया है। काम शुरू नहीं हुए हैं, अप्रारंभ हैं, और उसकी राशि लौटाई जाए या जो भी भाषा हो उसमें मैं नहीं जाता। जहां तक मेरी जानकारी है कि वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद ही विभाग ने प्रशासकीय स्वीकृति जारी करके नीचे डी.आर.डी.ए. संस्थाओं में भेजी। अब आप ये बताने का कष्ट करें कि विभिन्न योजनाओं में जो प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर की या डी.आर.डी.ए. स्तर पर जारी की गई। जिला पंचायत के स्तर पर या जनपद की जितनी क्षमता है उस स्तर पर, उसमें से कितने काम प्रारंभ हैं या अप्रारंभ हैं और वे कितनी राशि के हैं, उसको कब तक आप स्वीकृति देंगे या आप प्रशासकीय स्वीकृति को रद्द कर रहे हैं क्या ये बताईये?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो हमारी नई सदस्य श्रीमती अंबिका सिंहदेव जी आई हैं, आज उनका जन्मदिन भी हैं तो मैं आपकी अनुमति से जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि पहली बार काम मंजूर होने के बाद रूका है या बदला है, ऐसा पहली बार हो रहा है क्या?

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रह हूं और न आपके ऊपर मैं कभी लगाऊंगा। न मैं किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूं, मैं सिर्फ सूचना मांग रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, कितना ऐसा मामला है ....।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अनुभवी हो बैठ जाओ न यहां बैठ जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं चरण वगरा धो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- देवव्रत जी आप लोग समय खराब न करें। समय खराब न करें देवव्रत जी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय देवव्रत जी आप लोग समय खराब न करें।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चरण धोकर पीने वाला शब्द आपत्तिजनक है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- श्री देवव्रत सिंह।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चरण धोकर पीने वाला शब्द वापस लिया जाए। उसको विलोपित किया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- श्री देवव्रत सिंह।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, और भी विधायकों के प्रश्न हैं।

(माननीय सदस्य श्री सत्यनाराण शर्मा जी द्वारा सदन में घड़ी दिखायी जाने पर)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घोर आपत्तिजनक है, ये घोर असंसदीय आचरण है कि ....। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय शर्मा जी, माननीय चन्द्रकार जी आप लोग बैठ जाईये।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस शब्द को वापस लें।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय शर्मा जी, श्री देवव्रत सिंह जी को प्रश्न पूछने दीजिए। आधा घण्टा हो गया।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चरण धोकर पीने वाला शब्द वापस लें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आधा घ्ण्टा हो गया। माननीय शर्मा जी, आप लोग बैठिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी दादागिरी नहीं चलेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल चल रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात कहूंगा। मैं एक बार कहना चाह रहा हूँ ये मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आपने मुझे अनुमति दी थी, मैंने प्रश्न किया। मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। यदि उत्तर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन पूरक प्रश्न के दौरान घोर आपत्तिजनक बात ये हुई कि और प्रश्न हैं और लोगों के हैं आपको घड़ी दिखा रहे हैं, ये घोर आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा-आधा घण्टा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। मैंने देख लिया। श्री देवव्रत सिंह जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी को निर्देश थोड़ी न करेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। माननीय शर्मा जी, कृपया कर बैठ जाईये। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी सदाश्यता का...।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बतायेंगे, हम उतना पूछें क्या ? (व्यवधान)

वाणिज्यिक कर मंत्री(श्री कवासी लखमा):- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घोर आपत्तिजनक है। ये आदिवासी का अपमान किया है, इनको माफी मांगना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए। श्री देवव्रत सिंह।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी सदाश्यता का दुरूपयोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री देवव्रत सिंह।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर पर तैयार हूँ कि आप इन्हीं के प्रश्न लीजिए, हम लोग प्रश्न नहीं करते। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये वरिष्ठ विधायक हैं(व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय चन्द्राकर जी, आप धमकी मत दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। माननीय श्री देवव्रत सिंह जी को प्रश्न करने दीजिए।(व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चरण धोकर पीने वाली बात है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी घोर आपत्ति है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय वोरा जी, एक मिनट। देखिए, बात विवाद इसी स्तर पर कि माननीय सदस्य को माननीय आसंदी ने प्रश्न करने की अनुमति दी। अनुमति देने के बाद में माननीय मंत्री जी उत्तर दे ही रहे हैं। लेकिन यदि अन्य सदस्य उत्तर देंगे तो यदि मंत्री जी बोलें कि आप सामने आकर बैठ जाईये, आप उत्तर दीजिए और आप मंत्री बन जाईये तो वे क्या गलत बोलें? विवाद का कारण यही उत्पन्न होता है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय नेता जी, चरण धोकर पीने वाले शब्द की अनुमति किसने दी ?

श्री धरमलाल कौशिक :- ऐसा कुछ नहीं है और खासकर के मंत्रियों के जो व्यवहार है, वह ठीक नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चरण धोकर पीने वाले शब्द की अनुमति किसने दी ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निर्देश नहीं, मैं आसंदी से बात कर रहा हूँ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भी आसंदी से बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसंदी से आग्रह कर रहा हूँ कि ये प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का है और आपको लगता है कि प्रश्न नहीं करना है तो हम प्रश्न नहीं करेंगे, बैठ जाते हैं। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि हमारे प्रश्न हैं। आप यदि अनुमति देंगे तो हम लोग प्रश्न नहीं पूछते, हम बैठे हैं। हम बहिष्कार नहीं करते, हम बैठे हैं। हम प्रश्न नहीं पूछते। आप इनसे पूरक प्रश्न करवाईये। बिल्कुल हम आपको सहयोग करेंगे। हम लोग प्रश्न नहीं पूछते। उनके बहुत प्रश्न लगे हैं आप उनसे प्रश्न करवाईये।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा कि हम मुख्यमंत्री जी के पैर धोकर पीने वाले शब्द का हम विरोध करते हैं। अगर इन्होंने ऐसा शब्द सदन में बोला है तो इसको विलोपित करिये और ये माफी मांगे। ये क्यों नहीं हुआ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बिल्कुल बहिष्कार नहीं करेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप सदन में कैसे बोले कि मुख्यमंत्री के पैर धोकर पीयो, ये शब्द कैसे बोला गया?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अजय जी को अनुमति दी। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? भई, एक मिनट सुनिये। मेरी बात तो हो जाए। एक लाईन बोलूंगा फिर बोलना जरूरी है क्या ? आप प्रश्न भी कर रहे थे। कई बार इंट्रप्ट होता है। बहुत सारे सदस्यों को अपनी बात कहनी ही होती है और सब कुछ हम आसंदी की ओर देखकर ही कहते हैं। आप इधर प्रश्न भी कर रहे हैं आप बृहस्पत जी की तरफ बात भी कर रहे हैं, आप कवासी जी की तरफ जोर-जोर से, ऐसा नहीं है, अजय भाई आप बैठिये तो। संसदीय परंपराओं में और सदन के कार्य में प्रश्नकाल ही सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है और केवल एक प्रश्न जिसमें आदरणीय पंचायत मंत्री जी उत्तर दे रहे थे, कुल एक दशमलव कुछ प्रतिशत, लगातार सबको अवसर मिला, शिवरतन शर्मा जी को अवसर मिला, आपको अवसर मिला, माननीय नारायण चंदेल जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी को अवसर मिला। अध्यक्ष जी, एक प्रश्न में इतने अवसर के बाद भी इतनी उत्तेजना दिखा रहे हैं और कोई माननीय ने सदस्य अगर एक लाईन कह दिया तो आप पूरा प्रश्नकाल से बायकाट करेंगे, हम चले जायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम बायकाट नहीं कर रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के इस व्यवहार को सारा प्रदेश देख रहा है। आप प्रश्न करिये, उत्तेजित मत होईये। अभी तो कुछ दिन तक हमको सब आपके ही समय का जवाब देना पड़ेगा। आप इस बात को लेकर क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल चलाईये। आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप भाग लीजिए, आप भागने की क्यों बात करते हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम वो विपक्ष नहीं हैं जो प्रश्नकाल नहीं चलने देंगे। वह परिपाटी आपकी रही है। बहरहाल जो मुख्य विष्य था, आपने मुझे प्रश्न करने की अनुमति दी, मैंने प्रश्न किया, उत्तर आया, नहीं आया, मैंने आपत्ति नहीं ली। मुख्य विषय इस बात का है कि लगातार

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जब हम पूरक प्रश्न करते हैं तो पांच-सात लोग एक साथ खड़े होते हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यदि मेरा आचरण देख रहे हैं, प्रेस वालों से लेकर यदि पूरा प्रदेश डायरेक्ट रिले में देख रहा है तो आपके सदस्यों का ये भी आचरण दिख रहा है कि अध्यक्ष महोदय को घड़ी दिखाकर हमारे प्रश्न हैं ये कहकर निर्देश करने की कोशिश हुई। यह कहा जा रहा है कि हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है और हम लोगों के प्रश्न हैं। इसका आशय ये था बिना उत्तेजना के यदि आपके ही प्रश्न की मांग करनी हैं तो हम प्रश्न नहीं पूछते, हम बहिष्कार नहीं करेंगे। वह बार-बार कह रहे हैं कि हमारे प्रश्न हैं। यदि बिना उत्तर आये आग्रह कर रहे हैं तो हम नहीं पूछते हैं। हम कहीं नहीं जायेंगे, हम यहीं बैठेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्राकर जी की आपत्ति इस बात पर थी कि आपके निर्देश पर प्रश्नकाल बढ़िया ढंग से संचालित हो रहा था लेकिन माननीय सत्यनारायण शर्मा जी जो इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने आपको घड़ी दिखा करके ये कहा कि हमारा भी प्रश्न है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- घड़ी दिखाने में क्या आपत्ति है?

श्री अजय चन्द्राकर :- निर्देशित करना आपत्तिजनक है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, 36 मिनट हो गया है और हम लोग प्रश्न क्रमांक-03 पर पहुंचे हैं तो बाकी के सदस्यों के प्रश्न हैं उनका क्या होगा? इसलिए मैंने आपका ध्यान आकर्षित कराया कि इतना टाईम हो गया है, 36 मिनट हो गये हैं, 3 प्रश्न पर अटके हैं, सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाईये।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय, नारायण जी आपको वरिष्ठ मानते हैं न?

श्री नारायण चंदेल :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- वह वरिष्ठ होने के नाते मुझे सुझाव दे सकते हैं। देवव्रत जी।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, सुझाव नहीं, यह आसंदी की व्यवस्था है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, सुझाव और निर्देश में अंतर है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष जी, उनका जो भी जवाब है, मैं दे देता हूं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन आंसदी को चन्द्राकर जी का धमकाना ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, अनावश्यक विलंब हो रहा है, देवव्रत जी, अपना प्रश्न करिये।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, हम सुझाव नहीं देते, आपसे आग्रह करते हैं। हर सदस्य का अधिकार है, आपसे आग्रह कर सकता है। मैंने आपसे आग्रह किया था।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ग्राम ढोलपिहा में विभिन्न योजनाओं से खर्च की गयी राशि

4. (*क्र. 455) श्री देवव्रत सिंह :- क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत राजनांदगांव के छुईखदान विकास खण्ड के देनपराधार ग्रा.पं. के आश्रित ग्राम ढोलपिहा में वर्ष 2017-2018 एवं 2018-19 में किन-किन योजनाओं से विकास कार्य, आवास, कृषि, सिंचाई, पेयजल हेतु कुल कितनी राशि खर्च की गई ? (ख) कृपया मद वार जानकारी दें? कितना भुगतान किया गया ? (ग) ग्राम ढोलपिहा की जनसंख्या कितनी है?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) जिला पंचायत राजनांदगांव के छुईखदान विकासखण्ड में देनपराधार नामक न तो कोई ग्राम पंचायत है और ना ही ढोलपिहा नामक कोई आश्रित ग्राम है अतः जानकारी निरंक है. (ख) एवं (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह जो मेरा प्रश्न था, मूल रूप से एक गांव ढोलपिट्टा है जो कि बसाहट है। हमारे छत्तीसगढ़ की एक ऐसी विलुप्त जाति है जिसको हम लोग बैगा कहते हैं। इस गांव में 210 की जनंसख्या में लगभग 170 बैगा रहते हैं। बैगा प्रजाति को वहां सरक्षण मिले, शासन ने कुछ राशि भेजी, जिला पंचायत ने राशि स्वीकृत की। लगभग-लगभग 15 से 18 करोड़ रुपये की राशि 220 बैगा लोगों के संरक्षण हेतु भेजी गई। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं पूरे प्रकरण की जांच इसलिए कराना चाह रहा हूं वहां पर वन विभाग की भूमि में कलेक्टर द्वारा 40 बैगा लोगों को 2-2 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई। 2-2 एकड़ जमीन आवंटित करने के बाद वहां पर ट्यूबवेल की व्यवस्था कराने के लिए भी राशि भेज दी। आप इन बैगाओं को जमीन सरकार ने दी है, लेकिन वन-विभाग की जमीन पर वह कैसे खेती करने जाये ? उसके बाद वहां पर अभी बैगा लोगों के बीच में लगभग 12 से 15 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गयी है लेकिन बैगा लोगों तक न तो वह राशि पहुंची है, जो मकान बनाये गये, न तो उन मकानों की स्थिति वहां पर ठीक-ठाक है । जो कार्य कराये गये उसकी स्थिति भी ठीक-ठाक नहीं है । उसके अलावा इसमें एनजीओ के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से काम कराया गया । मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने जो जवाब भी भेजा है कि ढोलपिट्टा कोई गांव ही नहीं है, देवपुरा कोई पंचायत ही नहीं है तो मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करना चाहूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितना भी कार्य वहां संचालित हुआ है, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उस पूरे कार्य की एक जांच करायी जाये क्योंकि पिछली सरकार ने बैगा लोगों के संरक्षण के लिये 40

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करोड़ रूपये का एक मॉडल प्रोजेक्ट बनाया उस प्रोजेक्ट का क्या हाल है ? क्या बैगा लोगों को उसका लाभ मिला ? मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि क्या ढोलपिट्टा गांव में बैगा के संरक्षण के लिये जो भी राशि खर्च की गयी वह उचित हुई कि नहीं ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह होता है लिपिकीय त्रुटि में या लिखने में, कहीं पंचायत या गांव का नाम त्रुटिपूर्ण आ गया हो लेकिन माननीय सदस्य की ओर से जिस प्रकार से लिखकर आया था तो हम लोगों ने केवल उसको सुधारकर बताया कि पंचायत देनपराधार और उसका आश्रित नाम ढोलपिट्टा है, प्रश्न में नाम दूसरे आये थे लेकिन आशय समझकर हम लोगों ने और जिन बैगा जनजाति के संदर्भ में माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है । आपने लगभग 200 की जनसंख्या बतायी है, हम लोगों के पास 100 की ही जानकारी है । 100 के आसपास बैगा जनसंख्या में लगभग 29 परिवारों के लिये यह परियोजना बनी है और राशि में भी अंतर आ रहा है । वर्ष 2017-18 में 130 स्वीकृत कार्यों के लिये 181.048 लाख यानी 1 करोड़ 81 लाख की राशि स्वीकृत हुई थी । इसमें अलग-अलग कन्वर्जेंस में एलडब्ल्यूई से, जिला खनिज संस्थान से प्रधानमंत्री आवास योजना से, मनरेगा से, चौदहवें वित्त आयोग से राशियों का आवंटन हुआ था और वर्ष 2018-19 में 98.359 लाख की राशि पुन: एलडब्ल्यूई, जिला खनिज ये जो मद हैं इन मदों से राशि स्वीकृत हुई है और जैसा माननीय सदस्य ने भी कहा तो मैंने भी इसके संदर्भ में जब जानकारी लेना चाही तो मुझे भी लगा कि यह 100 की जनसंख्या के लिये यह राशि खर्च हो रही है किस प्रकार से यह राशि खर्च हुई होगी किंतु इसमें मुझे जो सुखद जानकारी प्राप्त हुई है तो मैं नहीं कह रहा हूं कि किस-किस सरकार ने कब कराया या नहीं कराया क्योंकि आपका सवाल आया है और मैं आपके साथ जाने के लिये तैयार हूं, उस गांव में जायेंगे क्योंकि मुझे यह जानकारी दी गयी कि एक आदर्श प्रोजेक्ट के रूप में यह परिणित हुआ है, करीब 141 एकड़ जमीन की लिंक फेंसिंग हुई है, 141 एकड़ की लिंक फेंसिंग छत्तीसगढ़ में, मेरी जानकारी में बहुत कम जगह हुई होगी । वर्ष 2017-18 में बोर खनन के लिये जो आपने कहा 29 के 29 बैगा परिवारों के लिये बोर करके पृथक से उनकी भूमि के लिये पानी की मात्रा वहां कम बतायी गयी है कि कम प्राप्त होती है तो प्रत्येक परिवार के लिये मुझे भी जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि कहीं भी मैंने यह नहीं सुना कि प्रत्येक परिवार के लिये, एक-एक घर के लिये बोरिंग करके पानी उपलब्ध करा दिया गया हो और 1.27 लाख प्रति परिवार के हिसाब से यहां पर बोर कराया गया और 1.25 से लेकर .25 लाख रूपये तक का भूमि समतलीकरण के लिये काम कराया गया और आज दो फसलीय यहां पर खेती हो रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि आप चाहेंगे उसकी जांच हो, मैं खुद जाना चाहूंगा ऐसे ग्राम और पारा को देखने के लिये और मैं जाऊंगा, आपके साथ चलेंगे और कहीं भी आपको लगता है कि इसमें अन्य कार्यों के लिये जो खर्चा हुआ है । भूमि संशोधन में 40.25, बोर में 36.83, चेनलिक फेंसिंग

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

में 49.84 और साल्हेवेरा मेन रोड से 27.3 लाख इसमें सड़क के लिये है, विकास कार्यों के लिये 29.53 इसकी डिटेल्स हैं । मैं उपलब्ध भी करा दूंगा । प्लांटेशन के लिये इतना है, अतिरिक्त निर्माण, मिट्टी-मुरूम का फिर से ढ़ोलपिट्टा में 42.53 तो जिस भी कार्य के लिये आप जानना चाहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री देवव्रत जी, आपने जितना पूछा है उससे ज्यादा उत्तर आ गया है । अब आगे बढ़ते हैं श्री सौरभ सिंह जी

अध्यक्ष महोदय :- देवव्रत जी, आपने जितना पूछा है उससे ज्यादा उत्तर आ गया है, अब आगे बढ़ने दीजिए । श्री सौरभ सिंह जी ।

श्री देवव्रत सिंह :- मैं मंत्री जी से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर मंत्री जी स्वयं न भी जा पाएं तो उसका भौतिक सत्यापन करवा लें । जो पैसा खर्च हुआ है उसका भौतिक सत्यापन करवा लें ।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने विधानसभा में कह दिया है कि आपके साथ जाएंगे।

श्री अजीत जोगी :- बस ।

<u>अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत सड़कों का संवर्धन एवं मरम्मत कार्य</u>

5. (*क्र. 325) श्री सौरभ सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तहत् अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन सड़कों का 05 साल पूरा होने के बाद पुनः संवर्धन का कार्य का ठेका हुआ है ? (ख) किस एजेंसी को कार्य दिया गया ? (ग) दिनांक 15.01.2019 की स्थिति में कितनी सड़कों का मरम्मत संवर्धन का कार्य लंबित है ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सड़क निर्माण 05 साल पूर्ण, होने के बाद पुनः संवर्धन (नवीनीकरण) कार्य हेतु ठेका हुआ है. सड़कवार विवरण †[1] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) सड़कवार नियुक्त एजेन्सी का नाम † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) दिनांक 15.01.2019 की स्थिति में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 14 सड़कों का मरम्मत संवर्धन (नवीनीकरण) का कार्य लंबित है.

[1] † परिशिष्ट दो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब में यह आया है कि 25 सड़कों में से 14 सड़कों का काम लंबित है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि काम क्यों लंबित है और कब तक पूर्ण होगा ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, इसमें सौरभ भाई का सहयोग लगेगा, राशि उपलब्ध करवा दीजिए तो काम जल्दी चालू हो जाएगा । वैसे जो काम प्रारंभ नहीं हुए हैं, आपने केवल उनके लिए पूछा है । अपनी ओर से भी इन 14 कामों के लिए, और जो छूट गया होगा उसको भी भेज देंगे । केन्द्र सरकार से इस राशि की मांग या शासन से इस राशि की मांग कर लेंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 और सड़कें ऐसी हैं, जिनका निर्माण हुए 7 साल से ज्यादा हो गया है । उन सड़कों की सूची मैं मंत्री जी को उपलब्ध करवा दूंगा । आपसे निवेदन है उन सड़कों का काम भी होगा क्या ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, राशि उपलब्ध होते ही निश्चित रूप से काम होगा । राशि के लिए पहल करनी होगी, काम होगा ।

श्री सौरभ सिंह :- एक सड़क है अकलतरा से अमोरा, अरसमेटा तक, 9 महीने से उसका काम चल रहा है और अभी तक काम पूर्ण नहीं हुआ है । ठेकेदार द्वारा काम नहीं किया जा रहा है । 9 महीने पहले उसका भूमि पूजन हुआ था और कार्य चालू हुआ था । उसी विधानसभा क्षेत्र की सड़क है और आपके विभाग, पीएमजीएसवाई से जुड़ी सड़क है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- कौन सा बोले भाई ?

श्री सौरभ सिंह :- अकलतरा-अमोरा-अरसमेटा सड़क । माननीय मंत्री जी यह नई सड़क है । इससे संबंधित नहीं है, नई सड़क है । आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, इस उत्तर में नहीं है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- ठीक है, आपने जो बताया उसमें त्वरित गति से कार्य हो, जिन्हें काम मिला है वे काम क्यों नहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से दिखवाता हूं।

<u>शराबबन्दी हेतु गठित अध्ययन दल की रिपोर्ट</u>

6. (*क्र. 29) श्री अजय चन्द्राकर : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि पूर्व में शासन ने शराब बन्दी के लिए अध्ययन दल गठित किया था ? यदि हां तो अध्ययन दल ने कहां-कहां का दौरा किया ? (ख) क्या समिति ने रिपोर्ट दे दी है ? यदि हॉ तो कब तथा उसके प्रमुख बिन्दु क्या-क्या है ? क्या शासन द्वारा पुनः इस विषय में कोई कमेटी गठित की है ? (ग) यदि हां तो उनमें कौन-कौन सदस्य हैं तथा किस विषय में कितने दिन में रिपोर्ट देगी ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) जी हां. अध्ययन दल द्वारा 05 राज्यों क्रमशः केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, तथा बिहार राज्य का दौरा किया गया है. (ख) जी हां. समिति द्वारा राज्य सरकार को दिनांक 10.12.2018 को अपनी रिपोर्ट दी गई. समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 52 से 56 पर उल्लिखित है, जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट में ++[2] संलग्न है. शासन द्वारा पुनः इस विषय में कोई समिति अभी तक गठित नहीं की गई है. (ग) प्रश्नांश च्च्खज्ज् के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है.

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि शराबबंदी के लिए जो अध्ययन दल गठित किया गया था । उसमें कौन-कौन शामिल थे ? उनके पद, नाम और योग्यता बताने का कष्ट करेंगे ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दल के सदस्यों का नाम नहीं पूछा था । इन्होंने पूछा था कि किस-किस राज्य में अध्ययन समिति गई थी ? केरल, तमिलनाडु ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी, वह उत्तर में लिखा है । उसे जानने में मेरी रूचि नहीं है ।

श्री कवासी लखमा :- दिल्ली और गुजरात ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह लिखा है ।

श्री कवासी लखमा :- बिहार ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह लिखा है ।

श्री कवासी लखमा :- इस प्रकार नाम मांगेंगे तो अलग से दे दूंगा (मेजो की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक है, ठीक है, बढ़िया, अच्छा । मैं आपके आत्मविश्वास की व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसा करता हूं, बहुत अच्छा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, फिर जाने दीजिए ।केशवप्रसाद चंद्रा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, छोटा सा प्रश्न है । अध्ययन दल ने जो रिपोर्ट दी है, जिसे आपने परिशिष्ट में दर्शाया है। उसकी अनुशंसाओं को आप स्वीकार करेंगे क्या ?

श्री कवासी लखमा :- माननीयअध्यक्ष महोदय, 10.12.2018 को इनकी रिपोर्ट हमारी सरकार को मिली है । हमने उसको खारिज किया है । हम पुन: गठन करके चालू करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में घोषणा की थी कि फिर से अध्ययन दल बनाएंगे । आप वह अध्ययन दल कब तक बनाएंगे ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है । हमारे घोषणा पत्र में है इसलिए हम लोग इसके लिए हाई पावर कमेटी का गठन करेंगे । नोटबंदी की

[2] परिशिष्ट तीन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तरह जल्दी नहीं करेंगे (मेजो की थपथपाहट) हम लोग इसके गठन में हर विभाग के, आपके क्षेत्र के लोग भी होंगे, सामाजिक होंगे, राजनीतिक होंगे, ग्राम पंचायत स्तर पर और दूसरे राज्यों में भी जाएंगे । हम लोग जल्दी चालू करने वाले हैं । अगले सत्र में मिलेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह सब जानता हूं, इसके बाद भी यह प्रश्न इसलिए लगाया था । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा, चूंकि आप मौजूद हैं इसलिए । आपने अभिभाषण में केवल एक लाईन कोड की थी कि दुकान बढ़ाने की संख्या दी है । आज वह रिपोर्ट सदन की प्रॉपर्टी बन गई, मैं आग्रह करता हूं कि मुख्यमंत्री जी उस रिपोर्ट को पूरा पढ़ें । आग्रह है मेरा और उसमें बहुत सारे अच्छे विषय है । उसे केवल राजनीतिक कारणों से उपयोग न करें, यदि आपके एजेंडे में शराबबंदी है तो, और लागू मत करें । उस रिपोर्ट की एक लाईन को कोड किया है, दुकान बढ़ाने की संख्या । जिसका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया है। मैंने इसलिए यह प्रश्न लगाया था । आपसे आग्रह है कि उस रिपोर्ट को पूरा पढ़ें।

अध्यक्ष महोदय :- वह सदन के पटल पर आ गया है, हर कोई पढ़ सकता है।

अध्यक्ष महोदय :- वह सदन के पटल पर आता है। हर कोई पढ़ सकता है। जोगी जी।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, इतने प्रचंड बहुमत से आयी सरकार ने चुनाव के पूर्व जो जनघोषणा पत्र जारी किया था, उसमें यह वादा किया था कि आदिवासी इलाकों को अलग छोड़कर अन्य स्थानों में पूर्ण शराबबंदी की जाएगी। जब यह बात घोषणा पत्र में शामिल की गई थी, तो इसका मतलब यह है कि पूर्ण अध्ययन करके, पूरी जवाबदारी से घोषणा पत्र में कोई बात बिना अध्ययन किये, बिना जवाबदारी के शामिल नहीं की जाती। जब इन्होंने उसे शामिल किया था तो जरूर अध्ययन हुआ होगा। विचार हुआ होगा। ऊंचे स्तर तक बातचीत हुई होगी और तब यह कहा गया होगा कि प्रदेश के हित में पूर्ण शराबबंदी मैदानी इलाकों में की जाएगी तो जब घोषणा पत्र में यह शामिल किया गया, अध्ययन किया गया, सब कुछ हो गया तो सरकार बनने के बाद फिर से अध्ययन करने की क्या जरूरत है ? आपने घोषणा पत्र में शामिल किया। इसका मतलब अध्ययन करके शामिल किया था। आंखें बंद करके तो शामिल नहीं किया था। मेरी दृष्टि से, मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से, शासन से कि छत्तीसगढ़ के लिए एक महती आवश्यकता है। हम बर्बाद हो रहे हैं। हमारा राज्य अगर बर्बाद हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण शराब है, मध्यपान है। 10 साल का बच्चा भी पी रहा है, बूढ़ा भी पी रहा है, औरतें भी पी रही हैं और भाजपा के 15 साल के शासनकाल में 15 गुना शराब की खपत बढ़ी है। तो मेरा मंत्री महोदय से यह प्रश्न है कि अगर अध्ययन करके इसे घोषणा पत्र में शामिल किया था तो अब अध्ययन मत करिए। इसको लागू कर दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी है। जहां अनुसूची 5 लागू है, उसे छोड़कर। इसमें कोई शक नहीं है और हम इस मामले में बहुत गंभीर हैं। हम शराबबंदी करेंगे लेकिन उस तरह नहीं जैसे नोटबंदी कर दिया गया था। एक झटके में करके लोगों को मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकते लेकिन यह भी हमें देखना होगा कि जिन राज्यों में लागू है, वहां क्या स्थिति है ? वे राज्य जहां शराबबंदी लागू किया गया था और फिर से शुरू कर दिया गया तो वहां विफलता के क्या कारण हैं ?

श्री अजीत जोगी :- तो घोषणा पत्र में शामिल था तो पहले आपने कहा होता।

श्री भूपेश बघेल :- सुनिए, जोगी जी, जब आप प्रश्न कर रहे थे तो हम धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। अब उत्तर भी थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए। घोषणा पत्र में कह दिया उसको तत्काल कर दो। घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें हैं। हमें जनादेश 5 साल के लिए मिला है। 50 दिन के लिए नहीं मिला है। (मेजों की थपथपाहट) इसे लागू करेंगे। विपक्ष तो ऐसा कहती है कि घोषणा पत्र में है तो कर दो। आपने 2100 रूपये के लिए कहा था, क्या आपने किया एक बार भी ? आपने जरसी गाय बांटने की बात की थी, क्या आपने दिया ? 15 लाख की बात के लिए 5 साल क्यों लिया ? क्या किसी के खाते में आया ?

श्री बृहस्पत सिंह :- किसानों के खेत से डीजल। बायोडीजल।

श्री भूपेश बघेल :- सरकार गंभीर है और गंभीरतापूर्वक एक-एक काम करती जा रही है। कभी कल्पना किये गये कि सरकार 2500 रूपये क्विंटल धान खरीदी करेगी। हमने कर दिखाया। (मेजों की थपथपाहट) यह काम भी करेंगे। हमारी इच्छाशक्ति बहुत दृढ़ है। हमें जनादेश मिला है। हम करेंगे लेकिन जो असफलता, विफलता हो रहा है जहां संचालित हो रहा है, उसका पूरा अध्ययन करेंगे और छत्तीसगढ़ का जो सामाजिक परिवेश है, इसे लेकर करेंगे । मेरा जो अनुभव है जो मैं महसूस करता हूं वह यह है कि सरकार एक झटके में दुकान बंद कर सकती है लेकिन यह सामाजिक बुराई है। जब तक समाज में हम जन-जागरण नहीं लायेंगे और उनका सहयोग नहीं लेंगे तब तक सफल नहीं हो सकता और इसलिए हमने दो प्रकार की कमेटी गठन करने का निर्णय लिया है। एक कमेटी जो उन राज्यों में जाकर अध्ययन करे। मैं सभी राजनीतिक दलों के साथियों को उस मीटिंग में आमंत्रित करूंगा और इसी सत्र के चलते हुए मीटिंग करूंगा और आप सब को आमंत्रित करूंगा और पूरे देश भर में इस प्रकार की स्थिति है, वहां जाकर अध्ययन करें और आकर बतायें कि वहां क्या परिस्थिति है। सफल है, असफल है, घर पहुंच सेवा हो रही है या नहीं हो रहा है, अन्य राज्यों से किस प्रकार आ रहा है, उसको किस प्रकार से रोका जाए, इसके बारे में आपसे सहमति लेंगे। दूसरी बात, सामाजिक संगठन के जितने मुखिया हैं, उनकी कमेटी बनायेंगे, जो पूरे प्रदेश के सामाजिक क्षेत्रों में अपने-अपने समाजों में इस प्रकार से वातावरण बनायें ताकि जब हम पूर्ण शराबबंदी लागू करें तो वह पूर्ण रूप से लागू हो। घर पहुंच सेवा न हो। हम यह व्यवस्था

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लागू करना चाहते हैं। इसके लिए भी बहुत जल्द कमेटी बनेगी। मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत होगा। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। केशव प्रसाद चन्द्रा।

<u>प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालय</u>

7. (*क्र. 127) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुल कितने शौचालय का निर्माण किया गया ? जिलेवार किस योजना या मद से निर्माण कराया गया ? प्रोत्साहन राशि कितना भुगतान किया गया ? कितना बाकी है ? (ख) जिला जांजगीर चाम्पा में खुले में शौच मुक्त करने हेतु किस-किस योजना से शौचालय का निर्माण कराया गया ? योजना या मद के साथ निर्मित शौचालय की संख्या, भुगतान की प्रोत्साहन राशि की जानकारी विकासखण्डवार बताने की कृपा करें. (ग) जिला जांजगीर चाम्पा को खुले में शौचमुक्त जिला कब घोषित किया गया एवं उसके अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड ओ.डी.एफ. विकासखण्ड कब-कब घोषित किये गये ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) छ.ग. प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुल 33,23,585 शौचालय का निर्माण किया गया. निर्मित शौचालय, भुगतान की गई प्रोत्साहन राशि एवं भुगतान हेतु शेष राशि की जिलेवार योजनावार/मदवार जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) जिला जांजगीर चाम्पा में खुले में शौच मुक्त करने हेतु योजना/मदवार निर्मित शौचालय संख्या, भुगतान की गई प्रोत्साहन राशि की जानकारी विकाखण्डवार ‡ संलग्न प्रपत्र "ब" पर है. (ग) जिला जांजगीर चाम्पा को खुले में शौचमुक्त जिला 26 जनवरी, 2018 को घोषित किया गया एवं उसके अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड ओ.डी.एफ. विकासखण्ड की घोषित दिनांक सहित जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र "स" पर है.

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय के प्रोत्साहन राशि के भुगतान के बारे में था। मैं पूरे प्रदेश के बारे में पूछा हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से जांजगीर-चाम्पा के बारे में जानना चाहता हूं क्योंकि पूर्व में ही मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न और सम्माननीय सदस्य माननीय धनेन्द्र साहू जी द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था, उसमें अलग जानकारी दिया गया था और आज के प्रश्न में अलग जानकारी दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मालखरौदा विकासखण्ड 15.08.2016 को ओ0डी0एफ0 घोषित हुआ है। जैजेपुर विकासखण्ड 26.01.2018 को ओ0डी0एफ0 घोषित हुआ है। बम्हनीडीह विकासखण्ड 15.09.2017 को ओ0डी0एफ0 घोषित हुआ है। मतलब ओ0डी0एफ0 घोषित हुए एक साल से ढाई साल हो गया है। लेकिन अभी भी सरकार के आकड़े पर जानकारी दी है कि 06 करोड़ 12 लाख रूपये जैजेपुर का प्रोत्साहन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

राशि शेष है। 05 करोड़ 30 लाख रूपये मालखरौदा का प्रोत्साहन राशि शेष है। 03 करोड़ 80 लाख रूपये बम्हनीडीह विकासखण्ड का प्रोत्साहन राशि शेष है। एक साल, ढाई साल तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह प्रोत्साहन राशि उनको आप कब तक देंगे ? क्या आपने ढाई साल के बाद बने हुए शौचालय का प्रोत्साहन राशि दिया ? प्राथमिकता क्रम में जो शौचालय पहले बने हैं, उसमें आपको पहले प्रोत्साहन राशि देना था। लेकिन बाद का भुगतान हुआ है, इनका क्यों भुगतान नहीं हुआ है ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान लंबित होने के कारणों में एक कारण हितग्राहियों द्वारा तीन महीने तक उसका लगातार उपयोग करना, इसका परीक्षण और उसके उपरांत भुगतान करना होता है। कुछ अन्य स्थानीय कारण हो सकते हैं। पैसों का अभाव मुख्य कारण होता है। केन्द्र सरकार से भी राशि उपलब्ध नहीं हुई थी। तत्कालीन राज्य सरकार भी अपने हिस्से की व्यवस्था नहीं कर पाया था। वर्तमान सरकार अपनी जिम्मेदारी को संभालते के साथ ही 93 करोड़ रूपये अपनी ओर से व्यवस्था करके अपना शेयर उपलब्ध कराकर के 229 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार से लेने में सफल हुई है। यह राशि आने के बाद जल्द से जल्द इसका भुगतान कराया जायेगा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यही प्रश्न था। मालखरौदा 15.08.2016 को ओ0डी0एफ0 घोषित हुआ। आप उसके बाद बने हुए शौचालयों के प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया। मालखरौदा के व्यक्ति ने सरकार का क्या अहित किया था कि आप उनको भुगतान नहीं किए और बाद में बनाए हुए शौचालयों का भुगतान कर दिए। माननीय मंत्री जी, क्या उस परिस्थिति में आपके पास पैसा नहीं था ?

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है कि तात्कालीन सरकार के पास नहीं रहा होगा या कुछ कारण रहे होंगे, जिस कारण से उन्होंने नहीं किया। मैंने बताया कि वर्तमान सरकार के द्वारा जिम्मेदारी संभालने के बाद क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अपना हिस्सा जमा करा करके उपलब्ध नहीं कराया गया था, तो केन्द्र सरकार से जो मैचिंग ग्रान्ट मिलता है, वह नहीं मिला था। राज्य सरकार ने जवाबदारी संभालने के बाद 93 करोड़ रूपया उपलब्ध कराया है, जतन करके उपलबध कराया और 229 करोड़ रूपये का मैचिंग ग्रान्ट केन्द्र सरकार से रिलीज करा लिया है। आपके पास वह राशि जल्द से जल्द उपलब्ध हो जायेगी। देर का कारण पड़ोस से पता चल जायेगा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि प्राथमिकता क्रम में जो पहले बना है, आप उसको भुगतान करेंगे। फिर वही गड़बड़ी आपकी भी सरकार में हुआ है।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रयास तो गड़बड़ियों के शून्य रहने का रहेगा और बिना भेदभाव के भुगतान होगा। अगर पूर्ण राशि उपलब्ध हो गई है तो पूर्ण राशि सब जगह चली

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जायेगी। केवल उपयोगिता वाली बात आ सकती है। अगर उपयोग हो रहा होगा तो निश्चित रूप से भुगतान कर दिया जायेगा और इसमें विलंब हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे **जन्मदिवस की शुभकामनाएं**

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्या श्रीमती अंबिका सिंहदेव जी का आज जन्मदिवस है, मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उन्हें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनके सुखमय उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

समय :

12:00 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2016 - 2017

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2016-2017 पटल पर रखता हूं।

(2) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-27/2017/32, दिनांक 06 अक्टूर, 2018

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-27/2017/32, दिनांक 06 अक्टूर, 2018 पटल पर रखता हूं।

पृच्छा

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है, शून्यकाल है । कल हमने स्थगन पर आपसे चर्चा कराने की मांग की थी । कल हमने जिस विषय को उठाया था और सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट किया था । कल सरकार के द्वारा जितने नामकरण पूर्व सरकार के द्वारा किये गए थे, पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से जो योजना चल रही थी, उसको बदलकर राजनैतिक द्वेषवश ये सरकार काम कर रही है । हमने पुन: स्थगन दिया है । पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना को माननीय राजीव गांधी जी के नाम से किया गया है । इसी तरीके से पंडित दीन दयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना को माननीय अम्बेडकर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जी के नाम से किया गया है, हमको कोई आपत्ति नहीं है । दीन दयाल एल.ई.डी. प्रकाश योजना को इंदिरा जी के नाम से किया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविकी केन्द्र योजना को राजीव जी के नाम से किया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेय जल योजना को इंदिरा प्रियदर्शिनी शुद्ध पेय जल योजना के नाम से किया गया है । ये परम्पराएं उचित नहीं है । हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं कि इस तरीके से मान्य परम्पराओं की अनदेखी मत करें । जो पहले सरकार ने महापुरूषों के नाम से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से....।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपने भाषण देने की अनुमति दी है ?....(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे आसंदी की अनुमति से बोल रहे हैं, आसंदी की अनुमति से बोलने के बाद भी आपत्ति ठीक नहीं है।....(व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से बोल रहा हूं । ....(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोग ऐसा चलाएंगे क्या ? ये उचित नहीं है । अब क्या आपसे पूछकर भी नहीं बोल सकते, ये परम्पराएं उचित नहीं है ।....(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी से अनुमति के बाद भी वे टोका-टाकी कर रहे हैं ....(व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, ये परम्परा उचित नहीं है....(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय सदस्य को भाषण की अनुमति दी है क्या ?

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से आप आसंदी को बोल रहे हैं, यह उचित नहीं है ....(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घोर आपत्तिजनक है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये सत्यनारायण शर्मा जी से पूछने की जरूरत नहीं है ।....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, मैंने उनका...। एक मिनट...।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, आप आसंदी से सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि इस तरीके से महापुरूषों का नाम को, योजनाओं को न बदलें । हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है, कृपया आपसे निवेदन है कि इसको ग्राहय करके इस पर चर्चा कराएं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा मानना है । महात्मा गांधी जी की तस्वीर हमने आपके पीछे लगाई है, सामने भी है । हम अपनी बात कहते हैं, उनके आदर्शों को

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्वीकार करते हैं । महापुरूष किसी भी विचारधारा से आयें, किसी भी सोच से आयें, उनका योगदान समाज के प्रति होता है और जिन कारणों से वे देश या समाज में पहचाने गए, उस वैचारिक आधार पर ये लोकतंत्र चलता है, बहुदलीय व्यवस्था हमने स्वीकार की है और ये समाज के महापुरूषों के नाम पर यदि कोई योजनाएं प्रारंभ की गईं तो उसको बदलना घोर अलोकतांत्रिक है और उस प्रक्रिया को तत्काल रोका जाना चाहिए । यदि सरकार कोई नई योजना शुरू करती है तो वे किसी के नाम से भी रखें...।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- चन्द्राकर जी, अलोकतांत्रिक क्या है, मैं बताता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बोल तो लेने दो । माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए ये अच्छी बात नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है, आपसे आग्रह है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की परम्पराएं विकसित नहीं की जाएं ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट रूकिये । नाम बदलना अलोकतांत्रिक हैं, बोल रहे हैं । आपने 2-1-2004 को इंदिरा विद्या भवन का नाम ज्ञानस्थली रखा । इंदिरा शहरी सरोवर धरोहर योजना का नाम आपने सरोवर धरोवर योजना रख दिया । राजीव खेल मैदान योजना को आपने उन्मुक्त खेल योजना बना दिया । नेहरू बाल उद्यान योजना को आपने पुष्प वाटिका उद्यान बना दिया । राजीव स्वावलंबन को आपने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बना दिया प्रियदर्शिनी बस स्टैण्ड को आपने प्रतीक्षा बस स्टैण्ड बना दिया । शुरूआात तो आपने किया है और अलोकतांत्रिक काम आप लोगों ने किया है और प्रजातंत्र की यहां पर दुहाई देते हो । (व्यवधान) (मेजों की थपथपाहट)

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- जिस हिसाब से आप .... (व्यवधान) कहते अलग हो, करते अलग हो । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :-चर्चा तो प्रारंभ हुई नहीं है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अलोकतांत्रिक काम आप लोगों ने पहले किया है, उसको हम लोग सुधार रहे हैं । शुरूआत आप लोगों ने किया है । दीनदयाल स्वावलम्बन योजना का नाम पहले राजीव गांधी स्वावलम्बन योजना था । इसको आपने बदला है । अलोकतांत्रिक काम आपने किया है, उसको हम सुधार रहे हैं और भी बहुत सारी योजनायें हैं, उसको छत्तीसगढ़ की विभूतियों के नाम से उसको भी करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य आ रहा है, वह संसदीय परम्परा के विपरीत है । आप स्थगन को स्वीकार कर लीजिए । चर्चा करा लीजिए । (व्यवधान) यह मंत्री जी का वक्तव्य था ..... (व्यवधान) ....उन कार्यों को रखेंगे । आप चर्चा करा लीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वीकृत कर दीजिए । मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उस बात के लिए तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय :-आपका पाईन्ट ऑफ आर्डर है क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- चन्द्राकर जी, शुरूआत तो आपने की है तो तकलीफ क्यों हो रहा है ? आपने महापुरूषों का, हमारे नेताओं का नाम हटाया....

श्री अजय चन्द्राकर :- कोई तकलीफ नहीं ।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रहा है ?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- पूरे प्रदेश में .....

अध्यक्ष महोदय :- आपने कोई स्थगन प्रस्ताव दिया है ।

श्री केशन प्रसाद चन्द्रा :- नहीं सर । ध्यानाकर्षण है ।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण में बाद में बात करेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, कल हमने एक स्थगन दिया था । आपने उसको अग्राहय कर दिया । हमारे स्थगन का विषय था कि सरकार राजनीतिक द्वेषवश पूरी कार्यवाही कर रही है और उसका एक प्रमाण आज सबके सामने है कि राज्य शासन की पांच योजनाओं का नाम बदल दिया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, नयी सरकार नयी योजना बनाये, आपने वैचारिक पृष्ठभूमि के महापुरूषों के नाम पर योजनाओं का नाम रखे, उसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । किसी महापुरूष के नाम पर कोई योजना संचालित हो रही है, उसके नाम को परिवर्तित करना अलोकतांत्रिक है । हमारा इस विषय पर स्थगन है । आप स्थगन ग्राहय करें और चर्चा करायें । हम अपना पक्ष इस पर रखेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय । स्थगन को ग्राहय करें, यह हमारा आपसे निवेदन है ।

श्री अमरजीत भगत :- शुरूआत तो आप ही लोगों ने किया था ।

अध्यक्ष महोदय :- स्थगन प्रस्ताव की सूचना का विषय स्थगन का विषय नहीं है । स्थगन प्रस्ताव के उल्लेखित तथ्यों के संबंध में चर्चा हेतु अन्य अवसर उपलब्ध हैं तथा आपके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को मैंने कक्ष में अग्राहय कर दिया है । ध्यानाकर्षण ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय.......

अध्यक्ष महोदय :-ध्यानाकर्षण, ध्यानाकर्षण । आपका पाईन्ट ऑफ आर्डर है क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाईन्ट आफ आर्डर है कि यह स्थगन का विषय इसलिए है, पूरी एक विचारधारा को कुचलने के लिए, उनके महापुरूषों को बदनाम करने के लिए, महापुरूषों का अपमान किया गया है । अपमान किया गया है, इसलिए इस पर

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

चर्चा होनी चाहिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, महापुरूषों का अपमान किया जाना, यदि यह परम्परा शुरू हो गयी तो देश में क्या होगा ? हम लोग यदि इसी प्रकार से अपमान करते रहेंगे तो महापुरूष भी देश में बंध जायेंगे । इस पर चर्चा करायी जानी चाहिये । हमको इस पर स्वीकार करना चाहिये ।

श्री अमरजीत भगत :- आपकी ही सरकार ने यह शुरूआात की थी ।

एक माननीय सदस्य :- चर्चा करा लें ।

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन जी, आपका ध्यानाकर्षण है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है । कल हमपंडित दीनदयाल जी का पुण्य तिथि मना रहे थे । रात को यह आदेश हो कि

सरकार के द्वारा राजनीतिक दूषित मानसिकता का प्रतीक है, जिस महामना का पुण्यतिथि मनायें, उस दिन उनके नाम से जो संचालित योजनायें हैं, उन नाम को रातों-रात परिवर्तित करे । शेम-शेम की आवाज परिवर्तित करने के बाद में किसी दूसरे महापुरूष के नाम से करें । हमको इस पर आपत्ति नहीं है कि वह नयी योजना बनाये और नयी योजना बनाकर पूरे परिवार के परिवर्तित कर किसी दूसरे महापुरूष के नाम से करे। हमको इस पर आपत्ति नहीं है कि वह नई योजना बनायें और नई योजना बनाकर पूरे परिवार के महापुरूषों का नाम उसमें अंकित रखें। लेकिन जो योजनाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर संचालित हैं और यदि उसका नाम वह परिवर्तित करें तो निश्चित रूप से ऐसे महापुरूष का अपमान है और ऐसे महापुरूष के अपमान पर यदि हम विधानसभा में इस विषय को नहीं उठायेंगे, आपका संरक्षण यदि उसमें नहीं मिलेगा तो इस विषय को हम बाहर कहां रखेंगे? इसलिए हमने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे गंभीर विषय के स्थपन प्रस्ताव पर यदि चर्चा नहीं होगी तो इस सदन के अंदर किस विषय पर चर्चा होगी? इसलिए हम मांग करते हैं कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाए और जो मंत्री अपना मंतव्य बता रहे थे, अपना वक्तव्य दे रहे थे वह इस स्थगन प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य दें और उस पर अपनी बात रखें तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस स्थगन प्रस्ताव पर आप चर्चा करायें। हमारे सथगन प्रस्ताव को आप स्वीकार करें और उस पर चर्चा कराई जाए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाईंट ऑफ आर्डर है। हमारी यू.पी.ए. सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत 920 करोड़ रूपये दिये थे मगर डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने उसे दीनदयाल उपाध्याय योजना बनाया। अभी भी दे रही है। आप ही की सरकार ने बनाया।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, क्या आपने स्थगन स्वीकर कर लिया है? अध्यक्ष महोदय, स्थगन स्वीकार करके चर्चा कराईये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाईंट ऑफ आर्डर है?

अध्यक्ष महोदय :- मरकाम जी, आप किस नियम के तहत पाईंट ऑफ आर्डर दे रहे हैं बताएं? आप नंबर बतायें? आपने किस धारा के तहत पाईंट ऑफ आर्डर दिया है?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न ये था कि लगातार जो कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- यह पाईंट ऑफ आर्डर किस नंबर पर है, बताएं?

डॉ. शिवकुमार डहरिया:- अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण पढ़वाया जाए, इसका कोई मतलब नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा पाईंट ऑफ आर्डर है?

अध्यक्ष महोदय :- कौन से नंबर से?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- कैसे रख रहे हैं बताईये ना?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ये शून्यकाल चल रहा है, शून्यकाल में जिन सदस्यों ने सूचनाएं दीं, अमूमन आपने उनको अवसर दिया। लेकिन जब मंत्री जी खड़े होकर बोले तो एक तो यह सही नहीं था और दूसरा सदस्य जिनकी इस विषय पर शून्यकाल की सूचनाएं नहीं हैं वह भी बोल रहे हैं। पहला तो यह तो परंपरा और नियमों के विपरीत है। दूसरी बात यह है कि यदि उनको बोलना है, माननीय मंत्री जी को कुछ बोलना है, इन सदस्यों को कुछ बोलना है तो प्रक्रिया के तहत आप स्थगन ग्राह्य कर लीजिए, फिर उनको अवसर मिलेगा। तो ये शून्यकाल में जो अवसर दिये गये हैं उसके विरूद्ध है। इसमें आपकी व्यवस्था आनी चाहिए। मैंने शून्यकाल पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि जिनकी सूचनाएं नहीं है वह बोल रहे हैं। ऐसी कभी परंपरा नहीं रही है।

अध्यक्ष महोदय :- अध्यक्ष की व्यवस्था पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। मैं ध्यानाकर्षण शुरू कर रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था हमें शिराधार्य है पर हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि एक आईडियोलॉजी बेस्ड महापुरूष के संबंध में हम चर्चा करना चाहते हैं, कल उनकी पुण्यतिथि थी, कल ही पांच योजनाओं का नाम बदल दिया गया, और विधानसभा चल रही है ऐसे समय पर इसे बदला गया, अगर विधानसभा में भी घोषणा की जाती तो समझ में आता है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है, कोई भी पालिसी डिसीजन विधानसभा के चलते समय बाहर नहीं लिया जा सकता, हम लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम चले, हमको वॉट्सअप के माध्यम से मालूम चले, ये उचित नहीं है। अगर इनको करना भी चाहिए था तो ये विधानसभा में आते, क्योंकि विधानसभा की अधिसूचना जारी हो चुकी है। विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और ऐसे समय पर हम पुन:

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आपसे चाहेंगे कि आप इस पर पुनर्विचार करें और आप इसको ग्राह्य करें। माननीय मंत्री जी जवाब भी देना चाहते हैं। जब वह जवाब देना चाहते हैं तो आप ग्राह्यता पर चर्चा करा लें और ग्राह्यता पर चर्चा कराकर मंत्री जी का जवाब पढ़ा दें। हम उसके लिए तैयार हैं। परंतु आप इस पर पुनर्विचार करें और उसे स्वीकार करें, इस बात का आपसे आग्रह है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, आसंदी को पूरा अधिकार है। माननीय सदस्यों ने एडजर्नमेंट मोशन दिया, आप ग्राह्य करें, नहीं करें, विधायी परंपरा है, संसदीय मर्यादाएं हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है लेकिन जिन मुद्दों को लेकर आदरणीय अजय जी बहुत उद्वेलित हो रहे हैं, माननीय बृजमोहन जी ने अपनी बात कही।

श्री बृजमोहन अग्रवाल:- इनका स्टाईल है।

श्री अमरजीत भगत :- वैसे भी संसदीय कार्यमंत्री रहे हैं और बैठकर बात कर रहे हैं।

समय :
12:15 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, क्या है, आपका और माननीय अजय चंद्राकर जी का स्टाईल बिल्कुल विरोधाभासी है। आप बड़े मीठे ढंग से कैसे लोगों को (हंसी) ....।

श्री कवासी लखमा (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री) :- सभापति जी, पंडित लोगों का काम क्या है? (हंसी)

सभापति महोदय :- देखिये शून्यकाल में इतनी लंबी चर्चा नहीं होती।

श्री रवीन्द्र चौबे (संसदीय कार्य मंत्री) :- सभापति जी, अब श्री अजय चंद्राकर जी को अभी चार ही दिन हुए हैं, उधर बैठते धीरे-धीरे सीख जायेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, हमारी पैदाईस ही इधर थी, हमारा नरमा इधर ही गड़ा है। (हंसी) इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, मूल स्थान पर वापस हो गये हैं।

श्री रवीन्द्र चौबे :- माननीय सभापति महोदय, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तब भी अर्बन डेव्लपमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत सारे योजनाओं का नामकरण किया था जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया। आदरणीय याद क्यों नहीं करते, उस दिन को ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री किसी विषय पर जवाब देना चाहते हैं .....।

सभापति महोदय :- देखिये, मैंने पहले ही निवेदन किया कि जीरो आवर्स पर और चर्चा नहीं हो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सकती। अब मैं नियम 139 ए के अधीन ध्यानाकर्षण की सूचना लूंगा। माननीय बृजमोहन अग्रवाल ध्यानाकर्षण की सूचना।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, शासन जवाब देने को तैयार है, तो चर्चा करवा लें। ससंदीय कार्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

सभापति महोदय :- जवाब की कोई अनुमति नहीं ली है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब देने को तैयार हैं।

श्री कवासी लखमा :- सभापति जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी उल्टा पुल्टा बोलते हैं न ......।

सभापति महोदय :- माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, सदन का समय बहुत कीमती है और सदन की कार्यवाही मुझे संचालित करनी है। इसलिए कृपा करके नियम 138 ए के अधीन ध्यानाकर्षण सूचना ले रहा हूं। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है पुलिस की लापरवाही से पूरे प्रदेश में कानून और व्यवस्था, लचर और अस्त-व्यस्त हो गई है। 30 जनवरी, 2019 को राजधानी रायपुर के चंगोराभांठा में लुटेरों ने जानलेवा हमला कर पिता-पुत्र से ज्वेलरी के बैग लूट लिये और इस घटना के ठीक 02 दिन बाद ही 02 फरवरी, 2019 की रात को टिकरापारा पुलिस चौकी के नाक के नीचे सिद्धार्थ चौक स्थित एक ज्वेलरी दुकान से लाखों का सामान चोर ले उड़े। यही नहीं जनवरी 2019 में ही दो अलग-अलग स्थानों पर बदमाशों द्वारा राजधानी में लूट और हत्या के प्रयास किये गये। राजधानी में डेड़ माह के भीतर बदमाशों, चोरों, लूटेरों और डकैतों ने जिस तरह से खुले आम आतंक मचाया है, उससे आम नागरिकों, बच्चों व्यापारियां एवं महिलाओं में असुरक्षा की भावना घर कर गई है। राज्य की राजधानी में जहां पुलिस महानिदेशक से लेकर मुख्यमंत्री तक रहते हैं, वहां, जब कानून और व्यवस्था बेहद खराब हो तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य के अन्य शहरों ओर गांवों में किस कदर आम नागरिकों का जीवन खतरे में है। पुलिस की रात्रिकालीन गस्त पूरे रायपुर शहर में सुस्त हो गई है। लड़कियों के स्कूल-दानी स्कूल, लक्ष्मीनारायण स्कूल, कालीबाड़ी चौक, चौबे कालोनी स्कूल, शांति नगर स्कूल, नूतन स्कूल, टिकरापारा सहित कॉलेजों के सामने भी डेढ़ माह से छेड़-छाड़ की शिकायतों पर कोई ध्यान पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। पुलिस की खुफिया तंत्र पूरी तरह से कमजोर हो गया है। इसके चलते पूरे प्रदेश की जनता में शासन-प्रशासन के खिलाफ भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- सभापति जी, क्यों मंत्री जी ये 15 साल पिछला बताये कि दो महीने पहले की बात कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, अभी दो महीने का।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कुलदीप जुनेजा :- मेरे को लगा कि पिछले 15 साल की बता रहे है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण जो माननीय सदस्यों ने उठाया, उस पर सरकार का जवाब इस प्रकार से है :-

यह कहना सही नहीं है कि पुलिस विभाग की लापरवाही से प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर और अस्त-व्यस्त हो गई है।

जबकि वस्तुस्थिति यह है कि प्रार्थी संजय सोनी उर्फ मोहित निवासी लाखेनगर सांई मंदिर चौक, पुरानी बस्ती रायपुर ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि दिनांक 01.02.2019 के लगभग रात्रि 8.30 बजे विजय चौक चंगोराभाठा स्थित अपने सांई नाथ ज्वेलरी दुकान को बंद कर सोने चांदी के ज्वेलरी को अपने साथ थैला में रखकर अपने पिता के साथ अलग-अलग दोपहिया वाहन से अपने निवास लाखेनगर जा रहे थे कि अचानक वसुंधरा नगर तिरंगा झंडा चबूतरा के पास में एक मोटर सायकल में सवार 03 अज्ञात व्यक्तियों ने अपना वाहन अड़ाकर हाथ-मुक्का से मारपीट एवं पिस्टल नुमा हथियार से पिता श्री जशराज सोनी के ऊपर फायर किया और संजय सोनी के सिर के पीछे पिस्टल नुमा हथियार के बट से चोट पहुंचाकर तीनों आरोपी सोने, चांदी के जेवर का थैला को लेकर भाग गये। प्रार्थी की थाना डी.डी. नगर में नम्बरी अपराध क्रमांक 33/19 धारा 307, 394, 397 भारतीय दण्ड विधान एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण के आरोपियों की पतासाजी हेतु विशेष टीम गठित कर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्रकरण विवेचनाधीन है।

दिनांक 02.02.2019 को प्रार्थी श्री संतोष अग्रवाल निवासी डुंगाजी कॉलोनी अनुपम गार्डन के पास, थाना सरस्वती नगर रायपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि सिद्धार्थ चौक स्थित छत्तीसगढ़ ज्वेलर्स की दुकान का चैनल गेट व शटर का ताला तोड़कर कोई अज्ञात चोर सोना, चांदी एवं डायमंड के जेवर एवं सोना, चांदी के सिक्के कुल कीमती 76 लाख रूपये का चोरी कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 72/19 धारा 457, 380 भारतीय दण्ड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना टीम द्वारा आरोपी (1) सागर नायक पिता शत्रुघन नायक, उम्र 21 वर्ष, निवासी बीएसयूपी कॉलोनी, टिकरापारा, रायपुर (2) लक्ष्मण छूरा पिता जटिया छूरा, उम्र 29 वर्ष, निवासी व थाना बघूमोडा, जिला बलांगीर(उड़ीसा), (3) सुनील सोना उर्फ बिलवा पिता बुड़ू सोना, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम देहली, थाना सिंदेकला, जिला बंलागीर (उड़ीसा), (4) मुच्ची पिता कमल मेहर, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम गोहेरापदर, जिला बलांगीर (उड़ीसा) एवं (5) अपचारी बालक की निशानदेही पर प्रकरण में चोरी गये सोने के जेवरात 01 किलो 367 ग्राम, चांदी के जेवरात 4 किलो 396 ग्राम विभिन्न किस्म के जेवरात एवं नगदी रकम 6,50,000 रूपये

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बरामद किया गया है। उक्त प्रकरण में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर शत प्रतिशत चोरी की गई संपत्ति बरामद कर ली गई है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल एवं 06 नग मोबाईल फोन को भी जप्त किया गया है।

जनवरी, 2019 में लूट के 06 प्रकरण और हत्या के प्रयास के 04 प्रकरण घटित हुए, जिसमें से लूट के सभी प्रकरणों में एवं हत्या के प्रयास के 03 प्रकरण में आरोपी गिरफ्तार किये गये हैं। रायपुर में पंजीबद्ध लूट के 06 प्रकरणों में से 06 प्रकरणों में सफलता हासिल किया गया है। रायपुर में डकैती की कोई घटना घटित नहीं हुई है।

यह कहना सही नहीं है कि लड़कियों के स्कूल दानीस्कूल, लक्ष्मी नारायण स्कूल, कालीबाड़ी चौक, चौबे कॉलोनी स्कूल, शांति नगर स्कूल, नेतन स्कूल, टिकरापारा सहित कॉलेजों के सामने डेढ़ माह से छेड़छाड़ की शिकायतों पर कोई ध्यान पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय पुलिस के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिये महिला हेल्प लाईन, रक्षा टीम संचालित है, जिसके द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के द्वारा शिकायत मिलने पर तत्काल कठोर कानूनी कार्यवाही की जाती है। जिसकी सराहना आम जनता के द्वारा की गई है। पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण के हर संभव प्रयास सुनिश्चित किये गये हैं।

यह कहना सही नहीं है कि राजधानी में डेढ़ माह के भीतर बदमाशों, चोरों, लूटेरों और डकैतों ने खुलेआम आतंक मचाया है, उससे आम नागरिकों, बच्चों, महिलाओं में असुरक्षा की भावना घर कर गई है, बल्कि चोरों, लूटेरों के विरूद्ध तत्परतापूर्वक समुचित कार्यवाही की जा रही है। थाना स्तर पर पेट्रोलिंग एवं गश्त किया जाता है। वास्तविकता यह है कि राज्य की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति संतोषजनक है। प्रदेश में धार्मिक, साम्प्रदायिक, समरसता और सौहार्द्र की स्थिति भी बनी हुई है जिससे शासन के प्रति आम जनता में विश्वास बना हुआ है। शासन प्रशासन के खिलाफ किसी प्रकार का आक्रोश एवं रोष व्याप्त नहीं हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में आपकी नई सरकार आने के बाद कितने हत्या के, कितने लूट के और कितने डकैती के प्रकरण दर्ज हुए हैं और उसमें से कितने में कार्यवाही हुई है? कृपया यह जानकारी दे दें।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण में जो दो-तीन बिन्दु स्पेसीफिक थे, मैं उसकी जानकारी दिया है, पूरे प्रदेश के विषय में..।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, यह कोई प्रश्नकाल नहीं है, आप इससे रिलेवेन्ट प्रश्न पूछिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप जरा पढ़ लें। मैंने लिखा है कि पूरे

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लचर और अस्त-व्यस्त हो गई है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं उत्तर दे रहा हूं।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ने अंत में रिप्लाई दे दिया कि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने शुरूआत में पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति लिखा है, इसलिए मैं पूरे प्रदेश के बारे में पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय :- पूरे प्रदेश में आप व्यापक प्रश्न नहीं कर सकते।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, कैसे नहीं कर सकते हैं? यह व्यापक थोड़ी है, सिर्फ एक- दो महीने का मामला है।

सभापति महोदय :- देखिये पूरे प्रदेश की जानकारी नहीं दी जा सकती है, आपने स्पेसीफिक दो घटनाओं का जिक्र किया है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति जी, मैं जानकारी दे रहा हूं। आप बैठिये तो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं पूरे प्रदेश की एक-एक घटना के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, पूरे प्रदेश की टोटल घटनाओं के बारे में प्रश्न कर रहा हूं। आप ही उनको संरक्षण पहले कर रहे हैं, आप हमको प्रश्न ही नहीं पूछने दे रहे हैं।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, जवाब दे रहे हैं, आप उत्तर सुनिये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं पूरे प्रदेश की जानकारी दे रहा हूं, आप बैठिये तो सही।

सभापति महोदय :- देखिये, माननीय बृजमोहन जी, जहां तक सवाल है, माननीय मंत्री जी के उत्तर में अंतिम पैरा में पूरा जवाब आ गया है, फिर भी आप चाहते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं आया है।

सभापति महोदय :- आप पढ़िये कि अंतिम पैरा क्या है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, अगर आप चाहते हैं तो हम अपना ध्यानाकर्षण विथ-ड्रा कर लेते हैं। अगर आप संरक्षण नहीं देंगे तो हम अपना ध्यानकर्षण विथ-ड्रा कर लेते हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- आप बैठिये, मैं उत्तर दे रहा हूं।

सभापति महोदय :- विथ-ड्रा क्यों? यह आपकी इच्छा पर है कि आप क्या करना चाहते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं विथ-ड्रा कर लेता हूं। .. (व्यवधान)..

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, प्रश्न पूछने का हमारा अधिकार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, फिर हम प्रश्न नहीं पूछेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, फिर आप उत्तेजना से बात कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- चलिये आप करिये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति जी, बृजमोहन जी ने प्रश्न किया, ध्यानाकर्षण आपके पास मे हैं, आप देख लीजिए। माननीय मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं।.. (व्यवधान).. यह उचित नहीं है।.. (व्यवधान)..

सभापति महोदय :- मैंने माननीय मंत्री को अनुमति दी है।.. (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- हाउस आसंदी के संरक्षण में चलेगा, सरकार के संरक्षण में हाउस नहीं चलायेंगे और आसंदी से इस प्रकार का होगा तो दिक्कत आयेगी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, सभापति और अध्यक्ष का इंटरफेरेन्स आखिरी में आता है, परन्तु शुरूआत में आपका हम लोगों को इस प्रकार का संरक्षण नहीं देना, ये मुझे लगता है कि ऐसे अगर आपका संरक्षण नहीं मिलेगा तो उचित नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अगर आप चाहते हैं कि हम प्रश्न नहीं पूछें तो हम प्रश्न नहीं पूछेंगे।

सभापति महोदय :- आप गलत कह रहे हैं मैं आपके आरोपों को खारिज करता हूं। माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय बृजमोहन जी, प्रश्न ही नहीं पूछना चाहिए, रहने दीजिए। ठीक है, हम लोग प्रश्न नहीं पूछते।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आपके निर्णय को स्वीकार करते हैं, हम कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। आपका निर्णय शिरोधार्य है।

सभापति महोदय :- आप जवाब नहीं सुनना चाहते, इसमें क्या है ? माननीय मंत्री जी, आप जवाब दीजिए, वह प्रश्न पूछें या न पूछें।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमारा प्रश्न विथ-ड्रा है, कोई उत्तर नहीं चाहते।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैंने प्रश्न का उत्तर तो दे ही दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- प्रश्न का उत्तर तो मैंने दे ही दिया है । प्रश्न का उत्तर तो मैंने पहले ही दिया है । आप जो सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे रहा हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- हम लोगों ने सप्लीमेंट्री वापिस ले लिया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में पिछले 1 महीने में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रही । कहीं भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है । दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को थाना लोरमी में सामाजिक विवाद की स्थिति पैदा हुई थी जिसे समय रहते हल कर लिया गया । दिनांक 08 एवं 09 जनवरी को ट्रेड यूनियन का देशव्यापी धरना-प्रदर्शन संपन्न हुआ । किसी भी प्रकार की बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं हुई । आपराधिक मामले में जिला रायपुर, कोरिया एवं जिला गरियाबंद को अच्छी सफलता मिली है । जहां जिला रायपुर में स्क्रेप व्यापारी मोहम्मद सिराज की हत्याकाण्ड का खुलासा किया गया वहीं जिला कोरिया में डकैती के आरोपियों को, अपराधियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता पायी। करीब 5 लाख रूपये का माल-मसरूका इन डकैतों से बरामद किया गया । दिनांक 18.01.2019 को रिसाली बस्ती भिलाई निवासी श्री हरिप्रसाद देवांगन के अपहरण एवं हत्या के मामले में खुलासा किया गया है । कृष्णा ज्वेलर्स पाटन में चोरी की गयी, माल-मसरूका सहित अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली । थाना टिकरापारा क्षेत्रांर्गत सिद्धार्थ चौक स्थित छत्तीसगढ़ ज्वेलर्स दुकान में दिनांक 01.02.2019 की दरमियानी रात अज्ञात चोरों के द्वारा लाखों की चोरी के मामले में सफलता मिली है। मामले में 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर 01 किलो 367 ग्राम सोना, 4396 चांदी विभिन्न किस्म के जेवरात एवं नगदी रकम, 6 लाख 50 हजार रूपये बरामद किया गया है । गिरफ्तार आरोपियों में 3 आरोपी जिला बलांगीर उड़ीसा के मूल निवासी हैं। दिनांक 06.02.2019 को 3.00 बजे गरियाबंद फॉरेस्ट नाका के पास पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम मशीन को चोरी कर ले जाने के उद्देश्य से कट्टा से फॉयर किया गया । फॉयर करने वाले आरोपी आजाद एवं उनके साथ अन्य चार आरोपियों को जो कि राजस्थान के मूल निवासी हैं । घटना पश्चात् तत्काल गिरफ्तार कर उनके कब्जेसे एक नग गैसकटर, एक नग देशी कट्टा, 03 नगर जिंदा कारतूस, 01 नग खाली कारतूस एवं 01 पिकअप वाहन बरामद किया गया ।

प्रदेश में हत्या के अपराध में शीर्ष में माह जनवरी 2018 में जहां 80 अपराध घटित हुए थे वहीं माह जनवरी 2019 में मात्र 44 अपराध घटित हुए हैं इस तरह हत्या के अपराध में 45 प्रतिशत की कमी आयी है । इसी प्रकार हत्या के प्रयास शीर्ष में जनवरी, 2018 में जहां 58 अपराध घटित हुए वहीं माह जनवरी, 2019 में मात्र 40 अपराध घटित हुए । इस तरह हत्या के प्रयास के अपराध में 31 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है । महिलाओं से अपराध जैसे बालात्कार में जनवरी, 2018 में जहां 160 अपराध घटित हुए थे वहीं माह जनवरी, 2019 में मात्र 112 अपराध घटित हुए हैं इस तरह बालात्कार के अपराध में 30 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है नक्सल मोर्चा पर भी विगत् माह सफलताभरा रहा । नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी के सदस्य नकावेंकटराव ऊर्फ मूर्ति को राजनांदगांव पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार नक्सली के कब्जे से 8 नग नक्सली साहित्य, 01 नग मोबाईल, 02 नग मेनपेगसेट एवं 23

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नगर डेटोनेटर जब्त किया गया है । जिला राजनांदगांव में ही जिला पुलिस बल एवं एसटीएफ की संयुक्त कार्यवाही में भावे के जंगलों में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुआ जिसमें सौलर प्लेट, प्रिंटर, नक्सल साहित्य, नक्सल वर्दी एवं भारी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री जब्त की गयी है । पूरे प्रदेश में 4 माओवादियों द्वारा आमंत्रण किया गया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यह हो क्या रहा है ? गृह विभाग की मांग पर तो चर्चा हो नहीं रही है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- पूरे प्रदेश की चर्चा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप आंकड़े बताईये न ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- आंकड़े तो दे रहा हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप तो एक-एक घटना का जिक्र कर रहे हैं ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- पूरे प्रदेश का आंकड़ा दे रहा हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप आंकड़े बता दीजिये, कितना बलात्कार, कितना चोरी, कितना डकैती, कितना लूट, कितनी हत्या यह बताईये न भई ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सब बता रहा हूं, पूरे प्रदेश का बता रहा हूं । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आप तो किस्सा-कहानी पढ़ने लगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- घटना का उल्लेख तो करेंगे न ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- तो आप पूरी घटना को क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- श्री बृहस्पत जी, आप तो बैठिए । हम मंत्री जी से बात कर रहे हैं न, आप हैं क्या मंत्री जी?

श्री ताम्रध्वज साहू :- आखिरी आ गया है, आप बैठिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप उसको समाप्त करिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- जो आप लोग कहें वह सब सच है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- पूरे प्रदेश में 4 माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है । दिनांक 07.02.19 को जिला बीजापुर में बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए 10 नक्सलियों को मार गिराया गया व बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किये गये । एनडीपीएस, जाली नोट अनियमितता, वित्तीय कंपनियों पर दर्ज प्रकरणों की विवेचना में गुणवत्ता सुधार हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा एनडीपीएस की मार्गदर्शिका अनियमित वित्तीय कंपनियों एवं जाली नोट की मार्गदर्शिका तैयार कर पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से राज्य के समस्त थानों को पालन हेतु प्रेषित किया गया है । जिससे विवेचना के स्तर पर काफी सुधार आ रहा है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- मंत्री जी बस, हो गया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- बहुत बढ़िया, हम लोग आराम से बैठे हैं ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, बस ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- आपने पूछा है तो उसका उत्तर भी सुनें ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री अजीत जोगी :- पूरा सदन संतुष्ट है आपके जवाब से ।

सभापति महोदय :- आपने ध्यानाकर्षण के जवाब में बोल दिया है कि अंतिम अंश पढ़ता हूं । इसमें लिखा है कि वास्तविकता यह है कि राज्य की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति संतोषजनक है, इसमें सारी बातें आ गईं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्रदेश के आंकड़े पूछे। मैं पूरे प्रदेश का आंकड़ा दे रहा हूं सभापति जी । मेरे पास पूरी तैयारी है लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है ।

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत सिंह जी अपना ध्यानाकर्षण पढ़ें या और कोई सदस्य, शिवरतन जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था के विरोध में हमने तय किया है कि मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा ।

सभापति महोदय :- मत पूछिए, चलिए जाने दीजिए । आपकी इच्छा है, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप प्रश्न पूछें या न पूछें । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति जी को धमकाना नहीं है बृजमोहन भाई ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- सभापति महोदय, हम माननीय आसंदी से कम से कम यह अपेक्षा और आग्रह तो करेंगे कि यदि कोई माननीय सदस्य बोल दे कि मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा तो वहीं पर उसे समाप्त कर दें ।

सभापति महोदय :- मैंने शिवरतन जी से पूछा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने तो सीधे धर्मजीत जी का नाम पुकारा ।

सभापति महोदय :- मैंने पूछा है शिवरतन जी से ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं पूछ रहा हूं भाई ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सरकार से तो अपेक्षा नहीं करेंगे । सदन के अंदर आसंदी से व्यवस्था करते हों । निश्चित रूप से जहां पर सत्ता और प्रतिपक्ष है ।

सभापति महोदय :- मैंने शिवरतन जी से पूछा है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप आसंदी पर विराजमान हों, तो मैं बात करूं । जहां पर पक्ष की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

संख्या स्वाभाविक रूप से ज्यादा है । प्रतिपक्ष में वही बैठेगा, जिनकी संख्या कम है और प्रतिपक्ष की उम्मीद आसंदी से ही है । यदि सत्ता पक्ष के द्वारा आसंदी पर आप जैसे सभापति के विराजमान होने के बाद भी प्रतिपक्षकी आवाज को दबाया जाए और कहा जाए कि आपकी इच्छा । मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि पूरा संरक्षण मिलना चाहिए और यदि बृजमोहन जी ने किसी कारण से कहा कि वे प्रश्न नहीं करेंगे तो आपको कम से कम आग्रह तो करना चाहिए। कल भी आपने विलोपित कर दिया । आपने कहा कि दर्ज नहीं होगा । हम अपनी बात यहां रखें और हमारी बात दर्ज न हो और आप आसंदी पर बैठे रहें, यह कैसे संभव होगा? हम यह अपेक्षा तो आपसे करेंगे, इसलिए मैं पुनः आसंदी से आग्रह करता हूं, बृजमोहन जी कोई नए सदस्य नहीं हैं, लगातार जीतने वाले सदस्य हैं । यहां के सीनियर सदस्य हैं । इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि यदि उनके मन में किसी भी प्रकार से आसंदी की बात से कोई बात आई है तो आसंदी को निश्चित रूप से उस पर बात करनी चाहिए, यह अपेक्षा तो हम आपसे करेंगे ।

सभापति महोदय :- माननीय कौशिक जी, स्पेसीफिक ध्यानाकर्षण में स्पेसीफिक सवाल था । माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह भी कहा कि आंतरिक सुरक्षा ठीक है। उसके बाद पूरे प्रदेश का व्यापक प्रश्न पूछना, क्या उचित है ।(श्री शिवरतन शर्मा सदस्य द्वारा कुछ कहने की कोशिश करने पर) । शिवरतन जी मैंने आपको अनुमति नहीं दी है, आप बैठिये । उसके बाद इन्होंने कहा कि हम कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहते । तो मैंने शिवरतन जी का नाम पुकारा, शिवरतन जी खड़े नहीं हुए।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने धर्मजीत जी का नाम पुकारा, बाद में सचिव जी ने कहा तो आपने मेरा नाम पुकारा । सभापति जी, हम भी कोई नए सदस्य नहीं है, पिछले पांच साल विधानसभा में आपके साथ हम भी सदस्य रहे हैं । लेकिन पहली बार यह स्थिति निर्मित हुई कि मंत्री जी के बजाय आसंदी से जवाब आ रहा है कि माननीय मंत्री जी ने पूरा जवाब दे दिया । यह उचित नहीं है । हमारा ध्यानाकर्षण आसंदी के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ है । तो हम प्रश्न मंत्री से करेंगे, हमारा प्रश्न आसंदी से नहीं है । आसंदी की जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष को संरक्षण देना और अगर विपक्ष को प्रश्न करने से आसंदी रोके तो कैसे चलेगा सभापति जी ? कल भी एक घटना घटित हुई । हम विषय रख रहे थे तो आपने कहा कि कोई भी बात दर्ज नहीं होगी । संसदीय लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता ।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी हो गया । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । मैं फिर से कह रहा हूं । मंत्री जी ने जवाब दिया । जवाब में स्पष्ट लिखा हुआ है । माननीय बृजमोहन जी प्रश्न किया पूरे प्रदेश का । सदन का वक्त भी कीमती है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अरे, सदन काहे के लिए है ? क्या कीमती है, आप अजीब बात कर रह हैं आसंदी पर बैठकर ।आप वहां बैठकर अजीब बात कर रहे हैं । (व्यवधान) हमारा ध्यानाकर्षण कीमती नहीं है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सदन क्यों है। आप वहां बैठकर अजीब बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धनेन्द्र साहू :- आसंदी से आप इस तरह से पेश आ रहे हो। (व्यवधान)

सभापति महोदय :-बृजमोहन जी....(व्यवधान) आपका कर्तव्य है इसीलिए तो मैंने आपका नाम पुकारा। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप उनका भी नाम तो पुकारिए...(व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, हम सभापति की व्यवस्था के विरोध में बहिर्गमन करते हैं।

समय :
12:40 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

श्री बृहस्पत सिंह :- इनको सबको डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत हो गई है। सभापति महोदय, डॉ. बुलाइए।

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:-

20-21 जनवरी, 2019 की दर्दनाक अग्निकांड की घटना ने सिम्स अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। अस्पताल प्रबंधन अपने कारनामे को छुपाने बिली कन्ट्रोल पेनल यूनिट में शार्ट सर्किट की नई कहानी गढ़ रहा है। प्रबंधनकी इस लापरवाही से लगभग 40 नवजात शिशु सहित परिजन भी सकते में आ गये। शार्ट सर्किट की चिंगारी इतनी तेज थी कि पूरा अस्पताल परिसर धुऑ से घुप अंधेरा हो गया, मरीज परिजन बदहवास चीख पुकार लगाते रह गए, वहीं आईसीयू में धुऑ भरने से नवजात शिशु की मृत्यु हो गई और दर्जनों बच्चे कोमा में चले गये। आनन-फानन में नवजात शिशुओं को जिला अस्पताल एवं शिशु भवन में शिफ्ट किया गया, मगर आज भी घोर धुऑ से प्रभावित बच्चे एक एक करके दम तोड़ रहे हैं। दिनांक 29-30 जनवरी तक 5 बच्चों को मौत हो गयी और दर्जन भर बच्चे आज भी अचेत अवस्था में हैं। वही सिम्स में प्रसूति सहित नवजात शिशुओं का इलाज ठप्प है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

शासन/प्रशासन प्रभावितों को दिलासा देने में लगा है कि प्रभावित बच्चों के ईलाज का खर्चा शासन वहन करेगी। अस्पताल प्रबंधन में ना तो इलेक्ट्रिशियन है ना किसी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। मेंटनेंस के नाम पर हर महीने लाखों का वारा-न्यारा हो रहा है, आज भी सिम्स में उलझे तार बयां कर रहे हैं कि कोई भी गंभीर घटना घट सकती है। बिजली कन्ट्रोल पेनल यूनिट में आग का मुख्य कारण यहां पर एकत्रित कचरा और जनरेटर चालू करने के लिए रखे ड्रम (डीजल/पेट्रोल) हैं। यहां यूनिट बोर्ड की सुरक्षा तथा उचित रखरखाव की व्यवस्था नहीं है। उपलब्ध 42 अग्निशमन यंत्र में से आधे एक्सपायर पीरियड के हैं, जिसके चलते भीषण अग्नि को रोक पाने में हर प्रयास नाकाम सित्र हुआ। प्रभावित परिजनों सहित समूचे प्रदेश की आम जनता में इस घटना से शासन/प्रशासन के खिलाफ रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- यह कहना सही नहीं है कि दिनांक 20-21 जनवरी, 2019 की दर्दनाक अग्निकांड की घटना में कोई कहानी गढ़ी गई है, अपितु कलेक्टर, बिलासपुर के द्वारा प्रेषित जॉच प्रतिवेदन के अनुसार विद्युत पैनेल में लूज कनेक्शन के कारण आग लगने की घटना हुई है। यह कहना भी सही नहीं है कि 40 नवजात शिशु सहित परिजन सकते में आ गए, वास्तविकता यह है कि एन.आई.सी.यू. में केवल 20 मरीज भर्ती थे, जिसमें से 10 मरीज गम्भीर अवस्था में तथा 2 बच्चे अति गम्भीर स्थिति में लाइफ सपोर्ट पर भर्ती थे।

समय :
12.44 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

यह कहना भी सही नहीं है कि आई.सी.यू. में धुआं भरने से नवजात शिशु की मृत्यु हो गई और दर्जनों बच्चे कोमा में चले गए तथा घोर धुआं से प्रभावित बच्चे एक-एक कर दम तोड़ रहे हैं। वास्तविकता यह है कि गम्भीर अवस्था के मरीजों को अस्पताल प्रबंधन के द्वारा पूरी सावधानी से विशिष्ट जीवन रक्षक उपकरणों के साथ तत्काल निजी अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया एवं शेष शिशुओं को अन्य वार्डों में स्थानांतरित किया गया। अति गम्भीर स्थिति में भर्ती दो शिशुओं की मृत्यु इलाज के दौरान हुई है एवं उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनके फेफड़े स्वस्थ पाए गए थे तथा उसमें धुआं एवं कार्बन पार्टिकल्स नहीं पाए गए हैं। 22 से 28 जनवरी के बीच शेष पॉच शिशओं की मृत्यु भी पूर्व से गम्भीर बीमारी से होने के कारण हुई है।

यह कहना सही है नहीं है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा लापरवाही बरती गई है। उक्त अग्निकांड की जांच प्रतिवेदन के अनुसार घटना स्थल के पैनेल का अंतिम रख-रखाव दिनांक 31/12/2018 को किया गया था। कर्मचारियों के द्वारा अस्पताल में उपलब्ध अग्निशामक यंत्रों के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माध्यम से आग पर काबू पाया गया एवं धुएं के नजदीक स्थित तथा एन0आई0सी0यू0 में भर्ती शिशुओं को शहर के दूसरे सक्षम अस्पतालों में तत्काल स्थानान्तरित किया गया है। अत: यह कहना सत्य नहीं है कि प्रबंधन के द्वारा लापरवाही बरती गई एवं अग्निशमन यंत्र लाइफ एक्सपायर्ड हैं, जिसके चलते अग्निकाण्ड को रोका नहीं जा सका।

यह कहना कदापि सही नहीं है कि छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर से लोगों का विश्वास उठा चुका है तथा प्रबंधन विफल है, अपितु अस्पताल के द्वारा मात्र दो घंटे में ही सुरक्षात्मक उपाय कर स्थिति को काबू में लाया गया। उक्त अग्निकाण्ड एक आकस्मिक दुर्घटना है, जिसे आपात परिस्थिति में पूरी सूझ-बूझ के साथ एवं सावधानी से काबू किया गया है।

अत: यह कहना कदापि सही नहीं है कि उक्त घटना से प्रभावित मरीजों तथा पूरे प्रदेश की आम जनता में शासन/प्रशासन के खिलाफ रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। बल्कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उक्त घटना के दौरान की गई त्वरित कार्रवाई को सराहा जा रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को फ्री करवा दीजिये।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- नहीं, मैं सुन रहा हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह विधायक जी बैठी हैं। वह कैसे जवाब देंगे।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- मैं सुन रहा हूँ। प्लीज।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप कैसे जवाब देंगे ? उससे हमारा कान्स्ट्रेशन भी नहीं रहेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- ऐसा लगता है कि आप ...।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- क्षमा, क्षमा करेंगे। मैं सुन रहा था।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, क्षमा हम लोग मांग रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर दिए। एम0एल0ए0 साहब का काम जरूरी था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह जवाब पूरी तरह से 5 मासूम बच्चों की हत्या की जिनकी जिम्मेदारी है, उनको बचाने का प्रयास है। सही मायने में सिम्स नर्क है। आपका भी बयान है, आपने बिलासपुर के प्रेस कान्फ्रेंस में यह कहा था कि सिम्स की व्यवस्था के बारे में बहुत ही ज्यादा शिकायतें हैं। मंत्री जी, आप जांच करने के लिए भी गए थे। इस घटना के 3 दिन पहले गए थे। आपके अंदाजे से लग रहा था कि आप बहुत अच्छी तरह से जांच करने गए थे। पर चूंकि अभी आपकी सरकार बनी है, आपके पीछे आपके कार्यकर्ताओं की फौज चल रही थी और उसमें लगभग 02 हजार लोग आपके पीछे घुसना चाह रहे थे। परन्तु आप बहुत विद्यान मंत्री हैं। आप गेट से ही वापिस आ गए क्योंकि लोगों को इन्फैक्शन होगा। काश, आप उस दिन जांच कर लिए होते, वह सोनोग्राफी मशीन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जिसका आप उद्‌घाटन करने वाले थे, तो यह घटना नहीं होती और ये 5 बच्चें नहीं मरते। माननीय मंत्री जी, मैं तो पहले यही पूछ लेना चाहता हूँ कि क्या आपको मालूम है कि सिम्स में एक और अग्निकाण्ड हो चुका है ? सिम्स में इसके पहले एक और अग्निकाण्ड हो चुका है। वहां 500 फर्जी भर्तियों के लिए सारे डाक्टर्स, डीन, डेप्यूटी मेडिकल सुपरीटेन्डेंट, इन्होंने पांच सौ फर्जी भर्ती की थी। इनके शासनकाल में उसमें एस0आई0टी0 की जांच गठित की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री महोदय, इन डाक्टरों ने पूरे दस्तावेजों को कमरे में रखकर के आग लगा दिया। वहां एक दस्तावेज नहीं है। यह भी कोई न कोई अग्निकाण्ड करके अस्पताल से कुछ सबूत मिटाने के लिए यह षड़यंत्र हुआ है। क्योंकि सारे डाक्टर्स, डाक्टरी छोड़कर बाकी सब काम करते हैं। सबके ऊपर भ्रष्टाचार का क्विंटलों वजन रखा हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सिम्स के उस घटना की अग्निकाण्ड की जांच की रिपोर्ट आपके पास आ गई है क्या ? इस घटना की जांच किसने किया और उसका क्या प्रतिवेदन है ? यह बता दीजिये ?

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व घटना की रिपोर्ट भी जरूर आई होगी। क्योंकि आज के ध्यानाकर्षण के सन्दर्भ में वह नहीं था। तो मैंने उसको तत्काल नहीं देखा है। मैं उसको देख भी लूंगा और आप, माननीय सदस्य को उसकी प्रति भी उपलब्ध करा दूंगा। वर्तमान घटना की जांच रिपोर्ट आई है। कलेक्टर द्वारा भी जांच टीम गठित की गई थी। उन्होंने प्रतिवेदन दिया है कि है कि ये शार्ट सर्किट से केबल में आग लगने के कारण ये घटना हुई है और उस रिपोर्ट में ये भी बात आई है कि 31.12 को पीडब्ल्यूडी के ईएण्डएम विभाग के द्वारा उसका मेंटनेंस भी किया गया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, वह रिपोर्ट मुझे नहीं चाहिए । आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, करके बहुत उम्मीद है इसलिए मैंने वह प्रश्न पूछा कि वहां गोरखधंधे का अड्डा बना हुआ है-सिम्स । जब छत्तीसगढ़ बना, अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बने तो छत्तीसगढ़ का दूसरा मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में हम लोगों ने शुरू किया और उस जिला अस्पताल में शुरू होकर वहां के गरीबों की सेवा करने का वह केन्द्र बना, बाद में वहां पर कॉकस सब आ गए, वहां लूटेरे आकर बैठ गए और सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार होता है । कोई आदमी जिन्दा जायेगा तो सिम्स में मरकर ही बाहर आयेगा। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, दो-तीन प्रश्नों का जवाब पूछ लूं, फिर मैं आपसे एक, दो आग्रह भी करूंगा । वहां पर बिजली कंट्रोल यूनिट के पास जनरेटर चालू करने के लिए कितने डीजल और पेट्रोल रखे गए थे ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कंट्रोल पैनल के पास कितना डीजल रखा गया था, ये जांच रिपोर्ट में तो नहीं आया है, लेकिन जांच रिपोर्ट में ये जरूर आया है कि वहां कुछ सामग्री थी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां डीजल पेट्रोल रखा था और बच्चों के वार्ड के पास में ही रखा था ।

श्री शैलेष पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रूकिए न पाण्डेय जी, अभी तो मेरा नम्बर है । बाद में पूछिएगा, अभी आप नहीं पूछ सकते । मेरा प्रश्न पहले खतम हो जाए, फिर आप पूछिएगा ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं...

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नई परम्परा हो जाएगी । इसलिए मुझे पूछ लेने दीजिए । अस्पताल के सेट-अप में कितने इलेक्ट्रिशियन का पद वहां पर स्वीकृत है और कितने इलेक्ट्रिशियन वहां पर काम कर रहे हैं ?

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां और आवश्यकता है, जो चीज आप कह रहे हैं । जिस दिन शार्ट सर्किट हुआ, अग्निशमन विभाग या अन्य शासन के तंत्र के पहुंचने के पहले ही सिम्स के कर्मचारियों ने जान को भी जोखिम में डालकर धुंआ जो उठा था, उसमें तीन कर्मचारी गंभीर रूप से धुंए से प्रभावित भी हुए थे, लेकिन उन लोगों ने वहां उपलब्ध उपकरणों के आधार पर ही पूरा कंट्रोल कर लिया था ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये सब पूछा ही नहीं हूं सर । मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके सिम्स में इलेक्ट्रिशियन के कितने पर स्वीकृत हैं और उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- अब इसमें विस्तृत चर्चा अगर आप और जानना चाहते हैं तो बैठकर कर लीजिएगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट और लगेगा, एक बार हो जाने दीजिए ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां जांच रिपोर्ट में जो बात आई है, जो व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, उसको भी बनाया जायेगा । आपका कहना सही है कि वहां इलेक्ट्रिशियन का पद नहीं है, वहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम कर रहे हैं । वह डबल लॉक में ताला जो है, वह डबल लॉक में है, एक सिम्स के पास में है और एक पीडब्ल्यूडी के पास है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिम्स में एक भी मशीन काम नहीं कर रही है और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं । अगर सरकारी अधिकारियों ने आपको रिपोर्ट दी है तो वह गलत है । वहां पर एम.आर.आई. मशीन नहीं है, वहां पर सोनोग्राफी मशीन नहीं है, वहां पर लिथोट्रेप्सी मशीन नहीं है, वहां और भी जो-जो मशीनें हैं, वह सब बंद हैं । बाहर में स्लिप भेजकर बाहर में सबसे कमीशन फिक्स है, वहां भेजकर जांच कराते हैं । अगर मेरी बात आपको गलत लग रही हो तो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

यहीं से कार में बैठिए, पोर्च में चलकर बैठते हैं और बिलासपुर चलकर जांच कर लेते हैं । अगर मैं गलत बोल रहा होऊंगा तो इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए । ऐसा थोड़ी होगा कि हमारे बच्चे मरते रहें और अधिकारी अपनी लीपापोती करके भ्रष्ट लोगों को बचाते रहेंगे । माननीय मंत्री जी, बिलासपुर में सिम्स के लिए जगह मिल गई है, उसमें सिम्स का भवन कब बनवाएंगे, ये बता दीजिए । नया बिल्डिंग बनवाईए । आपने तो बजट में डाल दिया है कि वहां मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनेगा, कहां बनेगा ? सिम्स अस्पताल के लिए 10 साल पहले 38 एकड़ जमीन रिजर्व है, आप एक बिल्डिंग के लिए पैसा मंजूर नहीं कर रहे हैं । आप तो कर दीजिए, नया बिल्डिंग बनाइए । बनारस में कचौड़ी गली है-सिम्स अस्पताल । तो आप बताइए कि बिल्डिंग बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- इसमें माननीय सदस्य महोदय ने अपनी इस्तीफे की पेशकश की । मैं तो जल्दी भागने वाला नहीं हूँ, मेरा तो इस्तीफा नहीं होगा और मैं आग्रह करूंगा कि आप भी इस्तीफे की बात मत करें । कमियां किसी भी तंत्र में न हो, यह तो हो ही नहीं सकता । चाहे आपका घर हो, कोई भी व्यवस्था हो, कमियां न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता । जिन कमियों की तरफ आप इंगित कर रहे हैं, मुझे कोई संकोच नहीं है, आपके साथ भी चलेंगे । यूनिवर्सल हेल्थ की जांच भी कर लेंगे, पड़ताल भी कर लेंगे । जो करने के लिए संभव होगा, हम लोग इसमें अवश्य पहल करेंगे । इस्तीफे तक तो बात जाने की बात ही नहीं है । हम लोग उसमें मिलकर पहल करेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट सर । बिल्कुल ठीक । मैं इस्तीफा देने की बात इसलिए कह रहा हूँ, आपको लोग समझाते होंगे, वही अधिकारी पहले इधर समझाते थे कि सब ठीक है ।

श्री अमरजीत भगत :- क्या धर्मजीत भईया, अभी नया-नया है, इस्तीफा की बात कर रहे हैं । चार दिन तो हुआ है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मेरा मतलब है, आप अधिकारियों की बात को आंख मूंदकर मत सुनिये । आप जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को समझिये । यहां पर सिम्स की व्यवस्था और दुर्व्यवस्था की बात इसलिए हो रही है, गरीबों का एकमात्र अस्पताल है । सिम्स का भवन बनना चाहिये । आपको कह रहा हूँ कि आप चलिये और जनप्रतिनिधियों की बैठक लीजिए, बजाय आपके कार्यकर्ताओं के फौज के और निरीक्षण करिये । निरीक्षण के बाद बैठक लीजिए । उसकी व्यवस्था सुधार दीजिए ।

जिनको आपने ट्रांसफर किया है, उन लोगों को वापस मत लाईये । कुछ लोग मांग किये थे । आपके ट्रांसफर के बाद आपकी पार्टी के लोग एक दूसरे मंत्री से मांग किये थे कि इनको वापस ले आओ । क्यों वापस लाओ ? वहां आप डॉक्टरों की भर्ती करेंगे, तत्काल नियुक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह बता दीजिए और मीटिंग लेंगे कि नहीं और हम लोगों के संग निरीक्षण करेंगे कि नहीं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- निश्चित रूप से करेंगे । आपके साथ भी करेंगे, जनप्रतिनिधियों की बात भी सुनेंगे । अधिकारियों की बात भी सुनेंगे । उनको काम करने का मौका भी देंगे । उनको जिम्मेदारियां भी देंगे । कहीं भी जिम्मेदारियों के निर्वहन में कमी पाई जायेगी तो अपने आपको सुधार करने के लिए भी कहेंगे । यही हम लोगों की जनप्रतिनिधियों के रूप में जवाबदारी है । सिम्स के लिए आपने कहा तो कोनी में कैंपस के लिए प्लान बन रहा है । आपने भी कहा कि कुछ परिवर्तन अभी हुये । स्वाभाविक है कि बहुत सारी बातें, आपने भी जिन बातों को कहा, कहीं न कहीं कोई कारण रहा होगा । परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई, हम लोगों ने भी उसको भांपा और महसूस किया और परिवर्तन की क्रिया और प्रकिया से और भी बेहतर स्थिति बन सके । अपने आप में ट्रांसफर हो गया तो सब ठीक हो गया, नहीं हो सकता । अभी तो यह पहला कदम है, हो सकता है कि ....

श्री धर्मजीत सिंह :- सिम्स का बोल दीजिए कि नया भवन बनवायेंगे ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- नया भवन, राशि जैसे ही उपलब्ध होती है, बिल्डिंग प्लॉन बन रहा है और कुछ अतिक्रमण था, अतिक्रमण भी हटाया गया । नर्सिंग कॉलेज की भी बात हो रही है । काम हो गया है । सोनोग्राफी की भी अभी तीन मशीने है । एस.ई.सी.एल. केलिए जिस उपकरण के लिए आपने एम.आर.आई. के लिए कहा था, वह भी बहुत जल्द एम.आर.आई. के मशीन के लिए राशि और उपकरण उपलबध हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय:- नेता प्रतिपक्ष ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर घटना है । पांच बच्चे की वहां पर मौत हुई है । आपात स्थिति में अपने यहां व्यवस्था है, जहां पर ऐसी परिस्थितियां आती है, सरकार के द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती है । मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जिस परिवार में यह घटना घटित हुई है, बाकी परिवार के लोग जो हताहत हुये हैं, बादमें जो अस्पताल से डिस्चार्ज हुये हैं, ऐसे परिवार को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति मेंरी जानकारी के अनुसार नहीं दी गई है । क्या माननीय मंत्री जी क्षतिपूर्ति की राशि की घोषणा करेंगे और क्षतिपूर्ति की राशि देंगे ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें यदि कोई लापरवाही की बात सामने आती है तो क्षतिपूर्ति या सहायता राशि की बात पर चर्चा हो सकती थी । जांच में यह बात सामने आई नहीं है कि ......

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- दुर्घटना तो है । लापरवाही हो या मत हो । मृत्यु तो हुई है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- छोटे-छोटे बच्चों को ले जाना ही लापरवाही हो गयी । चाहे कारण कुछ भी हो । छोटे-छोटे बच्चों को बिना कोई लाईफ सपोर्ट के ले गये और वे मर गये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस भी कारण से आग लगे, आग लगने केकारण से, दम घुटने के कारण से मृत्यु हुई है । इस बात को आपने ही कहा है कि तीन कर्मचारियों को बचाव में घुंये के कारण उनको परेशानी हुई है । घुंयें से लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हुई है, आपात स्थिति ही मानेंगे, लापरवाही के कारण यह हुई है तो इसे हम आपात स्थिति ही मानेंगे और यह लापरवाही के कारण हुई है तो इसमें उस परिवार को सहायता राशि मिलनी चाहिए यह मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं और उनके इलाज का खर्च मिलना चाहिए। दूसरी बात मेरी जानकारी में है कि वहां पर अगिनशमन यंत्र खरीदे गये हैं लेकिन उसे स्टाल नहीं किया गया है, यदि उसे स्टॉल कर दिये होते तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती। इसे भी आप जानकारी में ले लीजिए। मशीन खरीदने के बाद स्टाल नहीं किया जाना क्या ये लापरवाही नहीं है? ये घोर लापरवाही है और इसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी है तो मैं माननीय मंत्री जी से दोनों प्रश्न का जवाब चाहता हूं?

श्री टी.एस.सिंहदेव - माननीय अध्यक्ष महोदय, शार्ट सर्किट, अग्निशमन लगने का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अग्निशमन की व्यवस्था हो वह एक अलग बात है, शार्ट सर्किट होकर हो यह एक अलग बात है। आपने अग्निशमन नहीं लगाया इसलिए शार्ट सर्किट हो गया ये तो कोई कनेक्शन ही नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप मुझे यही बता दीजिए कि अग्निशमन यंत्र क्यों लगाते हैं? कोई शार्ट सर्किट से आग लगे, किसी घटना से आग लगे तो फिर अग्निशमन यंत्र लगाने की आवश्यकता क्यों, उस मशीन को क्यों खरीदा गया?

श्री टी.एस.सिंहदेव - माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वहां यंत्र था तभी तो मैंने बताया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- शार्ट सर्किट से लगने वाली आग को बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र होता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- किसी दिन पूरे अस्पताल के मरीज जलकर मर जायेंगे। गोरखपुर टाईप पचासों बच्चे जलकर मर जायेंगे।

श्री टी.एस.सिंहदेव - माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने जवाब में भी कहा, शायद या तो मैं अच्छे से नहीं बोल पाया या आप सुन नहीं पाये कि वहां पर फायर को वहां के लोगों ने कंट्रोल कर लिया था। अगर यंत्र नहीं होते तो कंट्रोल किस चीज से करते, उन्होंने कंट्रोल कर लिया था।

श्री शैलेष पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन ये घटना हुई थी मैं और हमारे तखतपुर के विधायक घटना के आधे घंटे के अंदर वहां पहुंच गये थे। तब उस वक्त माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय विधायक जी उस दिन तक वहां दिखे नहीं। सारे बच्चों को हम लोगों ने अस्पतालों में जा-जाकरके शिफ्ट किया और उनकी जान बचाई। अगर आपने उस दिन जाकर बच्चे देखे होते जो कि वहां

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के अस्पतालों में भर्ती थे उनमें से 12 बच्चे पहले से ही ऐसे थे जो कि अन्य स्थानों में जन्म लिये थे और कुछ परेशानियों के तहत यहां आये थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये नेतागिरी करने गये थे और यहां आकर सब सर्टिफिकेट दे रहे हो, आप बिलासपुर के एम.एल.ए. हो, बिलासपुर में इतनी शर्मनाम घटना हुई है और आप इसको सर्टीफाई कर रहे हो, उसको जस्टीफाई कर रहे हो? आप देखने गये तो कोई कृपा किये क्या? आपकी सरकार की लापरवाही के कारण ये मौतें हुई हैं। आप चले गये तो क्या हो गया?

श्री शैलेष पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए।

श्री धरमलाल कौशिक :- ये घटना कोई हमारे कारण हुई है क्या? इस घटना के दोषी हम हैं क्या? आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, आप उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, हम बिलासपुर में हैं या नहीं है और आप यह कह रहे हैं। ये घोर आपत्तिजनक बात है। घटना के दिन हम बिलासपुर में हैं या नहीं है, ये वहां के लोकल विधायक हैं और लोकल विधायक के बाद यह तो नहीं होना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष वहां थे या नहीं थे। यह घोर आपत्तिजनक है, इसे विलोपित किया जाए।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप इस घटना को जस्टीफाईड कर रहे हैं। आप बिलासपुर के एम.एल.ए. हो, बिलासपुर की जनता निपटेगी आपसे। आठ बच्चों की मौत हुई है, ये सरकार हत्या की जिम्मेदार है और आप इस तरीके से सरकार के बचाव में बिना किसी अधिकार के खड़े हैं? आपको क्या मालूम है, कभी कोई प्रश्न लगाये? कभी विधानसभा में एक शब्द बोले कि बच्चे मर गये? फिर क्या लापरवाही हुई है, आप सर्टीफिकेट दे रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, ये गलत बात है। ये सर्टीफिकेट नहीं दे सकते। 5 बच्चों की जान लापरवाही से चली गई, सरकार की लापरवाही से 5 बच्चे मर गये, आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जवाब आ नहीं रहा है इसके विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, यहां कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और जवाब नहीं आने के कारण हम इसका बहिर्गमन करते हैं।

समय :
1.04 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

(भारतीय जनता पार्टी एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे.) पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों एवं श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के नेतृत्व में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे.) के सदस्यों द्वारा शासन का जवाब नहीं आने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

समय :

1.04 बजे

नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा उन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा:-

1. श्री सौरभ सिंह
2. श्री सत्यनारायण शर्मा
3. श्री धर्मजीत सिंह
4. श्री अरूण वोरा
5. श्री अजीत जोगी

समय :

1.05 बजे

अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-66, वैशाली नगर के सदस्य श्री विद्यारतन भसीन

अध्यक्ष महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-66, वैशाली नगर के सदस्य श्री विद्यारतन भसीन की ओर से दिनांक 10 फरवरी, 2019 को आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने 8 फरवरी, 2019 से लेकर 15 फरवरी, 2019 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थिति की सूचना दी है। उनके आवेदन में उल्लेख है कि मैं चिकित्सकीय कारणों से प्रवास पर हूं। अत: दिनांक 8 फरवरी से 15 फरवरी तक सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकूंगा। उनके आवदेन के परिप्रेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 66 वैशाली नगर के सदस्य विद्यारतन भसीन को 8 फरवरी 2019 से 15 फरवरी 2019 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाए। मैं समझता हूं सदन इससे सहमत होगा। आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं सभा सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य को अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लाबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है, कृपया सुविधानुसार भोजन करें।

अब आय व्यय पर जो चर्चा चल रही थी। मिस्टर मोहन मरकाम जी।

श्री रश्मि आशिष सिंह :- मैं सिम्स से संबंधित बात कन्टीनीव कर सकती हूं क्या ? आज्ञा चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं कर सकते।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मौजूद हैं, बार बार ये कहा गया कि....।

समय :
1:06 बजे

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी इस बात पर आपत्ति है कि जब आय व्यय महत्वपूर्ण बजट सरकार का साल भर का महत्वपूर्ण मामला होत है और उस समय पर पूरी अधिकारी दीर्घा खाली है। वित्त सचिव नहीं हैं, वित्त मंत्री नहीं हैं। ये तो विधानसभा की अवमानना है। आपको निर्देशित करना चाहिए कि कोई अगर वित्त विभाग के बजट पर चर्चा हो रही है, इससे मुख्य काम विधानसभा का और कुछ नहीं है। पूरा वित्त विभाग जबकि ......।

श्री कवासी लखमा (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, इन लोग 15 साल में 15 रह गए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जबकि पूरे वित्त विभाग के अधिकारी और हमारे प्रमुख वक्ता पहले वक्ता भी बोलने वाले हैं और ऐसे समय पर कोई उपस्थित नहीं रहे। वित्तमंत्री उपस्थित नहीं हैं, उनको भी उपस्थित रहना चाहिए। ये आपत्तिजनक है, आप इस चर्चा को स्थगित कर दीजिए, आप इसको स्थगित कर दें।

अध्यक्ष महोदय :- आ रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग के नहीं, सारे विभाग के अधिकारी रहना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी विभाग का समावेश है। सिंचाई का बोलना चाहते हैं, पी. डब्ल्यू डी. का बोलना

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चाहते हैं, वन का बोलना चाहते हैं, पी.एच.ई. का बोलना चाहते हैं, सुनेगा कौन ? सबको बुलवा लीजिए, दो घंटे रोक दीजिएगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो घंटे स्थगित करवा दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगित कर दीजिए सभा को। स्थगित करके आप उसके बारे में बाद में उस पर चर्चा करवा लें। आप स्थगित कर दें जब सब लोग आ जाएं, माननीय वित्त मंत्री जी आ जाएं, सब अधिकारी आज जाएं ....।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये आप वरिष्ठतम सदस्य है,...।

श्री रवीन्द्र चौबे (संसदीय कार्य मंत्री) :- अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर लूं। माननीय अध्यक्ष जी पूरी सरकार बैठी हुई है। आय व्यय में आपको चर्चा करना है, परंपरा है ये सच्चाई है, आप जो कह रहे हैं कि अधिकारी दीर्घा में भी अधिकारी होने चाहिए लेकिन एक मिनट का ये जो ट्रांजिट पीरेड, आप लोगों ने जो गृह विभाग का ध्यानाकर्षण लगाया।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, आपकी बात का मैं समर्थन कर रहा हूं। कल आपके पहले वक्ता माननीय मोहन मरकाम जी जब बोल रहे थे, आज की बात तो छोड़ दीजिए। कल सिर्फ पुलिस वाले लोग थे। कोई अधिकारी किसी विभाग का नहीं था, आपका पहला वक्तव्य ये बात छोड़ दीजिए। एक घंटे उनका भाषण चला, एक घंटे।

श्री रवीन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, अधिकारियों की उपस्थिति पर चर्चा नहीं होती। ये सामान्य परंपरा रहती हैं लेकिन यहां पूरी मंत्रिमंडल आपको सुनने के लिए बैठा हुआ हूं। हम बैठे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, अच्छा प्रशासन है।

श्री रवीन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, अच्छा आप शुरू करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्यमंत्री जी मैं आपके अनुभव को....।

श्री रवीन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मैंने कहा मैंने माना पंरपरा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, मुझे मालूम है आप क्या व्यवस्था देने वाले हैं, वो भी मुझे मालूम है, परंतु माननीय सचिव महोदय के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि यहां की उच्च परंपराएं रही है। हमें मालूम है कि माननीय राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला जी ने, माननीय प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी ने, माननीय धरम लाल कौशिक जी ने जब ऐसी परिस्थितयां निर्मित हुई है मंत्री नहीं रहे, अधिकारी नहीं रहे तो उन्होंने सभा को स्थगित किया है और शासन को ताकित किया है। ये सदन इस प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है। इसका सम्मान होना चाहिए, अगर ये अधिकारी वर्ग सम्मान नहीं करेंगे, इससे पूरे विभागों को बजट मिलने वाला है। इस पर चर्चा प्रारंभ हो रही है। अगर चर्चा के प्रारंभ में ही इस सदन का अपमान हो तो ये उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की उच्च परंपराओं को बनाये रखने

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

के लिए, इस सदन के सम्मान के मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप शासन को निर्देशित करें कि संबंधित लोग आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। ये उच्च परम्पराएं रहीं हैं और इन परम्पराओं का पालन किया जाना चाहिए। क्योंकि सदन केवल नियम-कायदे, कानून से नहीं चलता है, ये परंपराओं से चलता है और परंपराओं का पालन अगर नहीं होगा तो हमारे सदन की अवमानना है और उसी दिशा में आपको अध्यक्ष जी लेना चाहिए। इस सदन का सम्मान बढ़ाना, ये आपके साथ-साथ हम सबका भी दायित्व है और इसलिए हम आपसे इस बात का आग्रह करना चाहते हैं आप इस सदन के सम्मान, क्योंकि अभी विधान सभा को प्रारंभ हुए आज दूसरा दिन है। अगर दूसरे दिन ही ये स्थिति रहेगी तो आने वाले 5 सालों में क्या हालत होगी ? हम इसकी कल्पना कर सकते हैं और मैं तो चाहूंगा कि जरा सचिवालय के बारे में चर्चा नहीं होती है, जरा सचिवालय को भी इस मामले में जो परम्पराएं हैं, उससे भी अवगत माननीय अध्यक्ष जी को करवाया जाना चाहिए, जिससे कि उन परम्पराओं का पालन हो सके।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं लोग सीखायें हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा ध्यानाकर्षण समाप्त हुआ। बहिर्गमन हुआ, शून्यकाल की सूचना आई, ट्रांजिट पिरयड, थोड़ा सा हमने कहा न, अधिकारी भी आये, मंत्रिमण्डल पूरा बैठा हुआ है और जिन परम्पराओं का बृजमोहन जी जिक्र कर रहे हैं, पं. राजेन्द्र प्रसाद जी शुक्ल का। तब की परिस्थितियों से आज को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अभी कोई बहुत ऐसी परिस्थितियों का निर्माण नहीं हुआ है । इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। आपने दीर्घा की चर्चा की। फाईनेंस के ए.सी.एस. भी बैठे हुए हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि इसको पटाक्षेप करके आगे बढ़ना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ....।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है। आप लोग 15 सालों में जो आदत बिगाड़े थे, सुधारने में समय तो लगेगा भई। चलिये आपका स्वागत है। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- होगा-होगा। आपका धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- एक बार जैसे कर्ज माफी की घोषणा किये वैसी एक बार डण्डा चला दीजिए, सब सुधर जाएंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोगों ने आदत बिगाड़ी है यह स्वीकार तो करना होगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री तो लेट कर रहे थे, वे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी कहां गायब हो गये ? उनको भी जल्दी बुलाईये। आप दोनों भूत को बुलाईये। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, सम्माननीय भूपेश बघेल जी को बधाई देना चाहता हूँ। बधाई का पहला कारण है कि पहला बजट उनका है। पर जो बजट के विषय है मैं उसको पढ़-पढ़ के खोज रहा हूँ कि मैं बधाई कैसे दूं। मैं वास्तव में ईमानदारी से बधाई देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी सरकार की और मुख्यमंत्री की, ये सदन की विश्वसनीयता होती है। आप दो तिहाई से ज्यादा बहुमत लेकर आये हैं। तीन चौथाई, पूरा शत प्रतिशत, आंकडें से कह लीजिए। आप उतना बहुमत लेकर आएं हैं। लेकिन जो बात कह रहे हैं प्रदेश को जिस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके वित्तीय बातें आपने मुख्य बजट में कहीं हैं, उसमें मैं किस भाव से कैसे प्रशंसा करूं ? यदि सबसे महत्वपूर्ण बात आपका बजट लगभग 91 हजार करोड़ रूपये का बजट है। 91 हजार करोड़ के बजट के पत्र में आपका भाषण है उसमें लगा है। ज्यादा लम्बा नहीं दूंगा, क्योंकि आज व्यवस्थाएं बहुत आ रही हैं। सदन का समय कीमती है। सदन का समय कीमती है उत्तर भी आ रहा है। क्या आप चर्चा से भागना चाहते हैं ? हमने अध्यक्ष महोदय को वायदा किया है आप पूछ लीजिए। हम प्रश्नकाल चलायेंगे, पूरा रचान्तमक सहयोग देंगे। पर मुझे ये आप लोगों की रीति-नीति से ये लगता है कि आप सहयोग नहीं लेना चाहते। आप चर्चा से भाग रहे हैं। आपने 15 दिनों में ऐसा कोई काम नहीं किया है, आप गिलटी में मत आईये कि आपको चर्चा से भागना पड़े। आप जिन लोगों को खड़ा करते हैं, बाधित करने की कोशिश करते हैं क्या बोलना चाहते हैं क्या दिखाना चाहते हैं ? क्या करना चाहते हैं मुझे इन तीन-चार दिनों में समझ में नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चन्द्रकार जी, आप मुझे देखकर भाषण दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल इस बात में बात हो रही थी कि कल बजट है। आसंदी से एक व्यवस्था आई कि बजट है, विनियोग है, डिमाण्ड मांग है, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। जब मैं उसमें चर्चा करने की कोशिश करता हूँ तो भी ये कहते हैं कि साहब बजट में आईये। तो मैं उसी में बात करता हूँ। कुल व्यय का जो अनुमान है 90 हजार, 909 करोड़ का अनुमान है, उसमें राजस्व व्यय 78 हजार, 594 करोड़ है और पूंजीगत व्यय 12 हजार, 109 करोड़ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सरकार में राजस्व व्यय बढ़ रहा है, पूंजीगत व्यय घट रहा है, आप प्रदेश, देश को क्या बताना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2018-19 के बजट भाषण में आप देखेंगे तो घाटे को नियंत्रित करने की कोशिश की गई है कि घाटे को नियंत्रित करेंगे। आपने 2018-19

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

का राजकोषीय घाटा बताया है। वही अधिकारी, वही शासन, वही लोग हैं, पर जो अंतिम परिणाम आया राजकोषीय घाटा 6.2 प्रतिशत से ज्यादा हो गया जो कि 3 प्रतिशत में रहना चाहिए। किसमें? राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट अधिनियम में रहना चाहिए। जबकि इस वर्ष घाटा का जो अनुमान है, पिछले वर्ष 18 हजार करोड़ का राजकोषीय घाटा था, इस साल राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा का अनुमान है, आपने कहा है कि 2.9 प्रतिशत के आसपास रखने की कोशिश करेंगे। पिछले साल जब हमने कर्ज नहीं लिया, जब इस तरह की चीजें नहीं हुई तो राजकोषीय घाटा जो नियम से ऊपर गया, जब अगले साल हम बहस करेंगे तब देखेंगे कि ये 10 प्रतिशत से ऊपर जायेगा और आज की तारीख में सरकार की ये स्थिति बन रही है। पेपरों में छपा एक महीने के अंदर सरकार तीसरी बार कर्ज की लाईन में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप देखेंगे तो सरकार की ये छवि उभर रही है कि आप कर्ज पटाने के लिए कर्ज ले रहे हैं। सरकार की देयतायें कितनी हैं? बजट में ही जो लिखा है 53,350 करोड़ रुपया राज्य सरकार की देयतायें हैं और लोकलेखा में 14,202 करोड़ रुपया है, यदि उसको जोड़ें तो 67,552 करोड़ रुपया कुल ऋण है। ब्याज दर कितनी है? लगभग 7.98 प्रतिशत है। आप निकाल लीजिए। मेरे पास तो कोई अधिकार ही नहीं हैं आप निकलवा लीजिए। बजट का इस्तेमाल रोजाना की जरूरतों पर जब पूंजीगत व्यय नहीं है, पिछले सालों से आप लगातार देख लीजिए कि पेंशन, वेतन, स्थापना इसी में बढ़ोत्तरी हुई है, रोजमर्रा के कार्यों के लिए बजट का असली प्रतिशत व्यय हो रहा है। सरकार की कुल देयतायें हैं वह बजट के 21 प्रतिशत से ऊपर की ओर लगभग बढ़ रही हैं। हम देयताओं के लिए बजट बना रहे हैं, देयताओं के लिए ही कर्ज ले रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सब्सिडी दी है, कल बहुत बार मेज थपथपाये। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जेस्टर पोसचर देख रहा था, मैं सबसे ज्यादा मेज थपथापने वाले मुख्यमंत्री देखा, अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि अच्छे वक्ता का थपथपा रहे थे या अच्छे बजट की कर रहे थे, मैं इसको समझ नहीं पाया। पर मैं इस बात को मानता हूं वह उत्साह से छलक रहे थे, अच्छा है, पहला बजट है, उनका उत्साह है, यह स्वाभाविक है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपके आक्रोशित भाषण पर हम लोग मेज थपथपा रहे थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये बातें समझ में नहीं आयेंगी।

श्री अमरजीत भगत :- जहां समझ में नहीं आये, एक बार पूछ लिया करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं, सब समाचार-पत्रों में छपा कि इसमें इतना प्रतिशत, इतना प्रतिशत, इतना प्रतिशत किसान के लिए है। हम लोगों ने पढ़ा, एक से एक बढ़कर प्रतिक्रियायें आईं। अब मैं पहला बजट है इसलिए अपनी शैली से विपरीत शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- लेकिन आपके इस्तीफे को पेपर में खूब छपा है, वह कब होगा?

श्री सौरभ सिंह :- वह इस्तीफा तब देंगे, जब आप शराबबंदी करोगे। आप शराबबंदी कब करोगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं अपनी शैली के विपरीत भाषण दे रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- आप उनकी ओर नहीं हैं, वह जगह में आप बैठते थे तो वैसे ही करते थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय टी.एस.सिंहदेव साहब, गांव, गरूआ, घुरूआ, बारी, नहीं मालूम हमारी चिन्हारी, उसमें बात करूंगा। पंचायत ग्रामीण विकास का बजट पिछले बार कुल व्यय 9222 करोड़ रुपये अनुमानित था, इस बार वह 8996 करोड़ रुपया अनुमानित है, उसमें 2.45 प्रतिशत की कमी है माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोककल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा । स्वास्थ्य, शिक्षा जो सबसे प्रमुख....

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अजय चंद्राकर जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- साहब सुन लीजिये न, आप बड़े प्रभावशाली माने जाते हैं। आपका प्रभाव में बजट में देख रहा हूं ।

श्री अमितेश शुक्ल :- श्री अजय साहब, उसमें 15-20 परसेंट जो वह एक्सेस होता था वह नहीं है न इसलिये वह कम हो गया है । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा ।

श्री अमितेश शुक्ल :- मैं बता रहा हूं कि वह चीजें खत्म हो गयी हैं । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- आप जल्दी इधर आओ न । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं में से प्रमुख तत्व, पिछले साल 3470 करोड़ रूपये, इस बार 3385 करोड़ मायनस 2.44 स्वास्थ्य के बजट में कटौती । जल संसाधन विभाग । मैं अभी ऋण माफी पर बोलूंगा । ऋण माफी से किसान वॉयब्रेंट फ्रोर्स में तब्दील नहीं होता, छत्तीसगढ़ के किसान कोई यदि वॉयब्रेंट फ्रोर्स बनाना होगा तो उसके उपाय दूसरे हैं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सोचने का, अक्ल का ठेका शायद कुछ वामपंथी सलाहकारों के पास है जिनके पास मैं नहीं सोचता कि कोई योग्यता है । आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके निकट के हो सकते हैं, आपके कोई हो सकते हैं लेकिन ऐसे विशेषज्ञ नहीं हैं, उसमें जल संसाधन विभाग, कहां हैं वह भी प्रभावशाली मंत्री हैं ? ऐसा माना जाता है, आप हैं कि नहीं हैं, आप जानें ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- आप जिन शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं उसमें मुझे आपत्ति है ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं वापिस ले लेता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- मैं सलाहकार किसे रखूं, न रखूं यह आपसे पूछकर नहीं रखूंगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं मानता हूं कि यह आपका विशेषाधिकार है । मानता हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- हां, इस बात को याद रखियेगा । उसके पास विशेषज्ञता है, नहीं है उसको हम तय करेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- सलाहकार रखना आपका विशेषाधिकार है ।

श्री भूपेश बघेल :- आपने 15 साल क्या किया है उसे पूरे प्रदेश ने देखा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- सलाहकार रखना आपका विशेषाधिकार है यह मैंने मान लिया ।

श्री भूपेश बघेल :- हां, फिर आप उस पर चर्चा कर रहे हैं ? (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- मान लिया न, मैंने मान लिया ।

श्री भूपेश बघेल :- दूसरी बात, कहां हैं जल संसाधन मंत्री ? यह कौन सा तरीका है ? इस तरीके से मत करिये । जल संसाधन मंत्री दूसरे काम से गये हैं । कहां हैं जल संसाधन मंत्री ? यह आपका कौन सा तरीका है ? आप अपने तौर-तरीके का ध्यान रखिये ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे लोग खोज रहे हैं कि ओडीएफ करा दिये पैसा नहीं दिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना आवेश में आने की जरूरत नहीं है । उन्होंने कोई नाम नहीं लिया । उन्होंने ईशारों में कहा ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय बृजमोहन जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कहां हैं जल संसाधन मंत्री ? क्या यह कोई तरीका है ? ढंग से बात करिये । जितना सम्मानित आप हैं उतने ही सम्मानित मंत्रीगण भी हैं । आप उस प्रकार से मत करिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको इतना आवेश में आने की जरूरत नहीं है उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है ।

श्री भूपेश बघेल :- उस प्रकार से करेंगे तो आवेश आना ही है, लेकिन इस तरीके की बात न करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है । आपको इतने आवेश में आने की जरूरत नहीं है । मुझे लगता है कि सामान्य परम्पराओं में हम लोग इस प्रकार की बात कह देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- श्री बृजमोहन जी, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए । आप उनकी भाव-भंगिमाएं नहीं देख रहे थे । आपका चेहरा इधर है, मैं तो देख रहा हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जल संसाधन मंत्री जी जहां भी होंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- आप ऐसे ही बोलिये अच्छा लगता है ।(हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जहां भी होंगे सुखी होंगे । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसा है साहब मैं आपके प्रसन्न रहने लायक ही बात बोलता हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी भी भाव-भंगिमा बड़ी आक्रामक थी । आपका चेहरा भी और भाव-भंगिमा सौम्यता के साथ रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री भूपेश बघेल :- धन्यवाद ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी आप भी आक्रामक मुद्रा में थे ।

श्री अजय चंद्राकर :- जल संसाधन में 11.75 प्रतिशत के बजट की कटौती । किसानों की प्राथमिकता, किसान कल्याण आपने एक पैराग्राफ दिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नौजवान मंत्री पहली बार बने हैं माननीय उमेश पटेल जी । युवा, इतने 10 लाख युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, मैं उसमें बात करूंगा । बेरोजगारी भत्ता की बात तो छोड़ दीजिए । उसके बजट में, पिछली बार 139 करोड़ था इस बार 110 करोड़ रूपये है और 20.75 प्रतिशत की कटौती है । एक रोजगार कल्याण तकनीकी विभाग उन्हीं के साथ ही है । 708 करोड़ रूपया अब 691 करोड़ रूपया मायनस 2.38 परसेंट बाकी विभागों का ही है । प्रमुख विभाग, स्कूल शिक्षा में भी यही स्थिति है । माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में ऋण माफी, ऋण माफी पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने कहा सारे ऋण माफ । आज भी सुबह बात हो रही थी, जब आप उस विषय में बात करते हैं तो शायद उत्तेजना आती है । सदन के नेता की उत्तेजना क्यों है, यह मैं नहीं जानता ।

श्री अमरजीत भगत :- उसमें सुधार कर लीजिए, वह कृषि ऋण है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, 6230 करोड़ रूपए अल्पकालिक ऋण का है । फिर आपने 4 हजार करोड़ रूपए व्यवसायिक बैंकों के लिए भी बजट में रखा। पहली बात है अध्यक्षमहोदय, इसे थोड़ा समझने की जरूरत है । 62 सौ करोड़ रूपए में सोसायटियां जो ऋण देती हैं । अधिकतम ऋण सीमा 5 लाख है । 60/40 का रेश्यो, 60 परसेंट राशि और 40 परसेंट सामग्री । यदि सामग्री वहां नहीं है तो वह रेश्यो कम हो जाएगा । दूसरी बात, कर्ज माफी की गई 61 करोड़ रूपए । अध्यक्ष महोदय, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा । दूसरी बार बजट में आया 4 हजार करोड़ रूपया व्यवसायिक बैंकों के लिए है । जब हम सोसायटी में खरीफ का ऋण पटाते हैं तो वे रबी का देते हैं । सिंचित का देते हैं, व्यवसायिक बैंक के 4 हजार करोड़ की मांग की घोषणा हुई । व्यवसायिक बैंक अनलिमिटेड ऋण देते हैं,30 नवम्बर तक की घोषणा शायद, मेरे ख्याल से इसीलिए की गई, यह अनुमान है कि वे अनलिमिटेड ऋण लेते हैं । यदि सिंचित जमीन है तो खरीफ और रबी दोनों के लिए दे देते हैं । अब व्यवसायिक बैंको के 4 हजार करोड़ के लिए जो अपने ऋण माफी की, आपने खरीफ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया । अध्यक्ष महोदय, अब

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मेरा यह आरोप बनता है कि कांग्रेस या और कुछ, व्यवसायिक बैंकों के जो बड़े बकायादार हैं उसके लिए 30 नवम्बर की अवधि घोषित करके 30 नवम्बर तक की तरीख जोड़ी गई क्योंकि वे खरीफ और रबी के लिए अनलिमिटेड देते हैं और 4 हजार करोड़ रूपए को, मैं अगली बार पूछूंगा कि कितने कृषकों की कितनी राशि दी गई। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप व्यवसायिक बैंकों को जो 4 हजार करोड़ रूपये ..।

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- कोई भी आरोप लगाने के पहले ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नाम नहीं लिया हूं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- आपने कहा कि मेरा आरोप है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह आरोप नहीं है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- उन्होंने कहा कि आरोप है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बोलने की परम्परा है, बजट पर चर्चा में बोल सकते हैं । बजट पर चर्चा हो रही है, इस प्रकार की बातों को कहा जा सकता है कि आप लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, यह आरोप लगाने का हमारा अधिकार है । जब आप जवाब देंगे तो आप जवाब दीजिएगा । एक आरोप वह होता है जो किसी व्यक्ति को, कि फलाने व्यक्ति ने, उसका नाम लेकर, जैसे मोहम्मद अकबर ने 4 हजार करोड़ की गड़बड़ की है । तब हमको प्रमाण देना पड़ेगा । अगर हम शासन के मामले में बोलते हैं तो हमें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- आपने कहा है कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, इसका क्या मतलब ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- शासन के बारे में बोल सकते हैं, यह हमारा अधिकार है।

श्री मोहम्मद अकबर :- किन लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने की कोई बात ही नहीं है ऐसी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- शासन के बारे में बोल सकते है । शासन की खामियों के बारे में बोलने का अधिकार है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- जिस तरह से पंचायत का 610 करोड़ रूपया आपने टावर खड़ा करने के लिए दिया था, उसतरह से हम लोगों नेनहीं दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मंत्री जी को वह आरोप लगता है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप चलने दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, 4 हजार करोड़ रूपए रखे गए हैं, वे खरीफ के लिए हैं, किसके लिए हैं, क्योंकि व्यवसायिक बैंक अनलिमिटेड देते हैं । दूसरी बात, मैं बधाई देना चाहता था

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पहला बजट है इसलिए । मुख्यमंत्री जी गांव के आदमी मैं जानता हूं और मैं बधाई देना चाहता था । लेकिन मैं बधाई तब देता जब मध्यमकालीन ऋण, एक माननीय मंत्री जी का मैंने बयान पढ़ा कि ट्रैक्टर किसान नहीं लेते । मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम ट्रैक्टर से किसान पानी की जोताई करते हैं ? क्या वे समुद्र में ट्रैक्टर चलाते हैं । तो मध्यमकालीन ऋण के लिए नाबार्ड ने जो शर्तें तय की हैं वे किसान लेते हैं और जो नरवा, घुरवा, बाड़ी में मैंने जो चर्चा लगाई है, यदि आपने चर्चा स्वीकार की तो ये विषय आएंगे कि वो जो चीजें हो रही हैं । किसान उसमें ज्यादा परेशान है । इसलिए मैं चाहता हूं कि जब आप 47 परसेंट से ऊपर बजट छूट के लिए दे रहे हैं, जब आपने यह परम्परा डाल दी कि पूंजीगत व्यय से सरकार काम नहीं करना चाहती, छूट देना चाहती है और किसानों को यदि आप पूरी छूट देना चाहते हैं तो हम आपके समर्थन में है । फिर से आप कहीं से विशेष सत्र बुला लीजिए । इस बजट को पारित करने के बाद दो दिन और कर लीजिए । मुख्यमंत्री जी हम आपके साथ हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय एक लाइन। आप खाली दूसरे से उम्मीद करते हैं। आप बोले थे कि अगर कर्जा माफ होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसका क्या हुआ?

श्री अजय चन्द्राकर :- शायद, आप मेरा भाषण पिछली बार डिमांड मांग में नहीं सुने थे।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं, आप बोले थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें भी बोल देंगे। आप चिंता मत करिए।

श्री मोहन मरकाम :- आपको 2003 की याद नहीं है। भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह 87 का है।

श्री मोहन मरकाम :- 15 साल हुए और 15 साल में आपको किसानों की चिंता नहीं हुई। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों की हितैषी है। 10 हजार करोड़ रूपये माफ किये हैं। मुझे लगता है इसमें आपको दर्द तो नहीं होना चाहिए। आप भी एक किसान पुत्र हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक है ठीक। बढ़िया। बिजली बिल हाफ। 111.4 में कोई शब्द नहीं है बिजली बिल हाफ के आगे पीछे कोई शब्द नहीं है। बजट पुस्तिका में 400 करोड़ रूपया आपने रखे हैं। यदि हर तरह के टेरिफ को शामिल कर दें। बी.पी.एल. घरेलू, स्ट्रीट लाइट को, एन.डी.एल.एस. को 11 के.व्ही. 3311 के.व्ही, 220, 132 और भी जो टेरिफ हैं आपने टेरिफ का उल्लेख किया है। आपने जो जनघोषणा पत्र बनाया है उसमें बिजली बिल हाफ कहा है, जिसे कि मैंने पढ़ा है। आपने जो 400 यूनिट दिया है, मैं उसमें आपत्ति नहीं कर रहा हूं। विश्वसनीयता का सवाल है। राजनीति में विश्वसनीयता की। यदि आप मेरे ऊपर जैसे आलोचना याद कर रहे हैं तो साहब ठीक है। जनता ने जनादेश को स्वीकार किया। हमने गलती की और हम इधर आ गये। मुझे इस मंच में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

शायद, आपने बेहतर तरीके से बात की हो, आपकी जनघोषणा पत्र की विश्वसनीयता बनी हो। मैं भाषण के माध्यम से सिर्फ यही कह रहा हूं कि आप विश्वसनीयता में, उस बात में इस पवित्र सदन में खरे उतरे। दूसरी बात यदि आप पूरे टेरिफ की बात करते हैं तो 900 करोड़ रूपये प्रति महीने है। यदि आप 12 महीने का लेते हैं तो 10,400 करोड़ रूपये होते हैं। बिजली बिल हाफ करने के लिए आपको लगभग 5,400 करोड़ रूपये चाहिए। यदि आप 400 यूनिट की बात कर रहे हैं। यदि आप घरेलू और बी.पी.एल. की बात करते हैं तो लगभग शायद 50 लाख कनेक्शन है पता करवा लीजिएगा। आप 400 यूनिट में सिर्फ 20 लाख लोगों को फायदा दे रहे हैं। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आप जो कर रहे हैं, आप जो कहना चाहते हैं वही मैं बोल रहा हूं कि आप जो लिखे हैं उसी पर बोल रहा हूं। मैं अपने मन से कोई बात नहीं जोड़ रहा हूं। आपके विभाग में स्वास्थ्य है। चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर एवं जगदलपुर में मल्टी सुपर स्पेशयलिटी की स्थापना के लिए बजट में 22 करोड़ रूपये है। साहब, एक कॉलम और है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा हेतु स्टाफ नर्सों के 242 पदों की भर्ती है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि 22 करोड़ रूपये में आप सुपर स्पेशयलिटी बनाने जा रहे हैं। एक मशीन लग रही है आप माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करिएगा। डी.के. अस्पताल में गामा मशीन और पेटी स्केन मशीन का इन्टालेशन शुरू हो गया है। वह जब लग जाएगा तो छत्तीसगढ़ देश में कैंसर के मामले में दूसरे स्थान का संस्थान बन जायेगा। एक मशीन 22 करोड़ रूपये का इन्टालेशन संस्थान में है। आप अस्पताल को कौन सा सुपर स्पेशयलिटी दे रहे हैं, कैसी सुपर स्पेशयलिटी। अब 242 पद। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घंटे चिकित्सा सेवा की क्यों बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि मैं इधर उधर का बोल रहा हूं। मैं तो कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूं। मैं तो बधाई देना चाहता हूं लेकिन आप मेरी बधाई नहीं ले रहे हैं। अब मैं सिर्फ बाकी संस्थाओं को नहीं गिनाना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में 792 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। आपको बजट में लिखना चाहिए था कि आप कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घंटा चिकित्सा सेवा देना चाहते हैं ? किस क्षेत्र में देना चाहते हैं ? क्या देना चाहते हैं ? आप क्यों वाहवाही लूट रहे हैं ? हमने तो कहा ही नहीं है। आपने बनाया। आप मुझे खड़े होकर बतायें। आप डिमांड मांग में बता दीजिएगा कि 242 पदों के 792 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उसमें 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी दी जा सकती है ? अब आप कहेंगे मुझे बधाई दीजिए। मैं ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब शराबबंदी में जो लाईन है, जो टाईप्ड प्रेस से   लेकर ...।

श्री अमरजीत भगत :- अभी तो हमारा यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम पूरी तरह से आया नहीं है। जब आयेगा न, तो आप देखते रह जाओगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बजट में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के बारे में एक लाईन कही गई है और मुझे उस भाष पर आपत्ति है। बजट इस वर्ष है कि अगले वर्ष का है ? अगले वर्ष यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाने वाले हैं, तो भाई आपको 5 साल का मेन्डेट है, आप बार-बार इस बात को बोलते हैं कि 5 साल का हमारे पास जनादेश है, तो 5 साल के जनादेश के लिए अगली बार लिख लेते कितना बजट, क्या यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है, किसके लिए है, क्या है ? साहब, अभी तो उसमें भ्रम की स्थिति है। इसमें कैसे राजनीति हो रही है। यदि हम एक लाईन बोलते हैं तो इधर से, उधर से बत्ती आ जाती है, ठीक है साहब, हम गलत बोल रहे हैं, मान लेते हैं। लेकिन आप बोलते हैं कि आयुष्मान भारत बंद होगा, लेकिन आयुष्मान भारत में ईलाज हो रहा है। आप बोलते हैं कि प्रायवेट अस्पताल को बंद करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में आपने बंद किया या नहीं किया है, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में बिना यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लागू किए भ्रम की स्थिति में आप रोगियों के साथ मजाक, जरूरतमंदों के साथ मजाक कर रहे हैं। अब मैं उसके लिए कौन सी भाषा बोलू, मुझे सीखना है, मैं संसदीय भाषा ही बोलूंगा अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शराबबंदी में आ रहा हूँ। जन घोषणा-पत्र, माननीय नायक जी जा रहे हैं, जन घोषणा-पत्र में शराब बंदी "एक शब्द"। आज का जो बजट है, वह राजस्व आधारित बजट है। आधे से ज्यादा राजस्व खर्चे में बजट जा रहा है। नैतिक रूप से यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं दारू बंदी कर सकूं। ये टालने की बातें हैं कि मैं सलाह लूंगा, दो स्तरीय कमेटी बनेगी, तीन स्तरीय कमेटी बनेगी, चार स्तरीय कमेटी बनेगी। आप दम दिखाईये। आपने 207 करोड़ रूपया माफ किया, कर्जा लेकर माफ किया। आप तो उधार चुकाने के लिए कर्जा ले रहे हैं। 63 करोड़ की जगह और सौ करोड़ हो जायेगा, हमारा क्या जाता है। आप कर्जा लीजिये, माफ कीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब दुकानों की संख्या कम होगी, लेकिन राजस्व बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कहानी है। एक भेड़ से कहा गया कि हम अगले से साल ऊन फोकट में देंगे। मैं फोकट में मिल रहा है, समझकर के भेड़ों की सभा सभी ने ताली बजा दी। घर आये तो बुजुर्ग ने पूछा कि ऊन कहां से आयेगा ? उनको डांटा। अरे, ऊन तो हमको ही छिलने से आयेगा। तो ये इधर से कान पकड़ो, उधर से कान पकड़ो, इधर से बांटे, उधर से बांटे, कटना छत्तीसगढ़ की जनता को ही है। ओ हा छत्तीसगढ़ी हाना ला बहुत अच्छी तरह से समझथे। कोहड़ा ककरो ऊपर गिरय, तलवार कोहड़ा ऊपर गिरय, कोहड़ा तलवार ऊपर गिरय, लेकिन कटना कोहड़ा ही ला हे। मरना जनता ही ला हे। जनता भेड़ की तरह मुड़ाही। माननीय भूपेश बघेल जी भेड़ जैसे नहीं मुड़ाय, ये सदस्य मन भेड़ जैसे नहीं मुड़ाय, मुड़ाही छत्तीसगढ़ जनता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी विश्वसनीयता की बात कर रहा था। आपको जो मेन्डेट मिला है, आपने कुछ किया है, आपकी विश्वसनीयता बढ़ी है, तो उसका परिपालन होना चाहिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण के क्रमांक-54 में 1,384 पर उच्च शिक्षा के आये। सरकार श्रेय लेती है। माननीय भूपेश बघेल जी भी श्रेय ले रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं बड़े-बड़े पोस्टर और भाषण में देखता हूँ कि ये 50 दिनों की उपलब्धियों में शामिल करते हैं , तो वह पूरी फाईल पटल में रख दें। पी0एस0सी0 को कब, कौन से सन् मेंबिजनेस भेजी गई ? परीक्षा योजना कौन से तारीख को भेजी गई ? कौन-कौन से पद में किस तरह के लिटिगेशन हुए और चुनाव के पूर्व वह लिटिगेशन कैसे क्लीयर हुए और भरने की अनुमति मिली। श्रेय लें, लेकिन यह बात ईमानदारी से स्वीकार करनी चाहिए कि पिछली सरकार ने उसको भरने के लिए ईमानदारी से कोशिश की थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण के कण्डिका-92 में है कि ए0डी0बी0 फेस-3 परियोजना के तहत 3500 करोड़ की लागत से 35 सड़क बनने वाली है। यह लिखा है, फ्लैग लगा है, मैं खोल दे रहा हूँ, चाहे तो आप देख सकते हैं। मैं फिर वही बात जानना चाहूंगा, मैं श्रेय देता हूँ, मैं रोज श्रेय दूंगा । हमेशा हर बात के लिए मैं आपको श्रेय दूंगा । जो चीजें परिपक्व हो गई हैं, मेच्योर हो गए हैं, जिसके टेण्डर लग गए हैं, वर्क आर्डर होने है, उस प्रोसेस में है, एडीबी के हैं, उसकी प्रक्रिया है, मनीला जाती है । क्या 50 दिन में वह स्वीकृत हो गए हैं, जो काम चल रहा है, उसको बजट में छपवाना चाहिए । ये कौन सी परम्परा है कि अगले साल यूनिवर्सल हेल्थ केयर आयेगा, उसको इस साल बोलेंगे । जो काम अगले साल के बजट में छप चुका है, उसको इस साल के बजट में छापेंगे, वह भी मेन बजट में छापेंगे । सरकार आती है, उसमें श्रेय मिलेगा, इसमें मुझे कोई असहमति नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय भैया, सीधा खड़ा होकर शांति से भाषण नहीं दे सकते, ऐसे-ऐसे बहुत हिलते हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, अभी तो कम हिलते हैं, पहले ज्यादा होता था । (हंसी) मैं तो बाजू में बैठता ही नहीं था । नारायण चंदेल मोटा-तगड़ा है तो चल जाता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नरवा, घुरवा, गरवा, बारी, 96 नम्बर में उल्लेख है ।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें तो आप विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, इसमें समय क्यों खराब कर रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी चीज बोल रहा हूं, ये बजट के अंदर है, उसको बोल रहा हूं । उद्यमिता विकास के माध्यम से, उस योजना से दो लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा । प्रदेश में जितनी वीटीपी हैं, पालीटेक्निक संस्थाएं हैं, आईटीआई हैं, उसमें गोबर सेतनें और छेना थापने का कोर्स नहीं है । दुर्भाग्यजनक स्थिति जब मोदी जी इस बात को करते थे, स्वरोजगार के लिए एक उदाहरण दे दिया तो इन लोगों ने पहाड़ उठा लिया कि पकौड़ा बनाना कोई रोजगार है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्या तो क्या गोबर सेतने और छेपा थोपही अब खातु पलाही, ते रोजगार ए गा । इस काम को छत्तीसगढ़ के लोग रोज करते हैं । उद्यमिता विकास से दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा । आप 50 लाख लिख दो, उसमें क्या जाता है । तो गोबर सेंकना हमर नीयती हरे । वह दस्तावेज में आ गे, छेना थोपना हमर नीयती हरे अउ वो दिशा में हम लउट गेन, ये बजट से प्रमाणित होगे कि हम छेना थोपबो, गोबर सेतबो । वाह से छत्तीसगढिया के स्वाभिमान वाला बजट, अउ वाह से कौशल विकास, अउ वाह रे छत्तीसगढ़ के उद्यमिता विकास। अब मेरी असहमति है । आप उद्यमिता विकास की बात करते हैं । आप बहुत विद्वान हैं । मेरी बात पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपत्त ले ली । माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा परिवार, खुद, सार्वजनिक जीवन, पढ़े-लिखे सब हैं, मैं जानता हूं और उससे बढ़कर जो मानसिक मजबूती है, वहां ट्रेनिंग लेने चाचा जी के पास, डा. साहब के पास मैं भी जाता हूं, अभी चुनाव के पहले । चुनाव होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी पद ग्रहण करने के बाद कुरूद आये थे कि जो आत्मविश्वास उनसे बातचीत से मैं मरने से नहीं डरता, जब बोलते हैं तो मैं भी यही बात बोल रहा हूं कि मैं भी मरने से नहीं डरता । जो मरने से जीत जाता है या उस स्प्रिचुअलटी को स्वीकार कर लेता है, जहां से ये सीखे हैं, मैं भी उस बात को वहीं से सीखा हूं तो ये जो बातें हैं कि धमकी, चमकी, गलत, सही यदि आपके पास वह बात लागू होती है, आप डरते नहीं हैं तो कोई नहीं डरता और मैं तो बिल्कुल नहीं डरता ।

श्री अमितेश शुक्ल :- अध्यक्ष महोदय, नरवा-घुरवा में ये क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री दीपक बैज :- वे अभी नरवा, घुरवा से भटक गए हैं ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- किसानों को केवल चुल्हा से खाना बनाने की बात कर रहे हैं, गैस की बात नहीं कर रहे हैं ।

श्री अमितेश शुक्ल :- मैं अजय चन्द्राकर की बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि ये नरवा, घुरवा से इसका क्या संबंध है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमितेश जी, नरवा, घुरवा समझना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आप शिक्षा लेने जाओ, वे आपको ज्यादा अच्छे ढंग से समझा देंगे ।

श्री अमितेश शुक्ल :- मैंने शिक्षा ली हुई है, तभी तो खड़े होकर बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- और कितना समय लेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस दो, चार मिनट । आप कहें तो मैं तुरंत समाप्त कर दूंगा । मेरी ओर से पहली बार है, पहला बजट है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, हमारा पहला वक्ता है ।

अध्यक्ष महोदय:- मैं समझ गया, पर आपके तो 9 वक्ता हैं और 9 लोगों का समय ले जाएंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और उनको पूरा समय मिलना चाहिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे अनुशासन का पालन करूंगा, जो आपका निर्देश होगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनको पर्याप्त समय मिलना चाहिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब उद्यमिता विकास में हम गोबर सेतेंगे, छेना थोपेंगे, खातु पलाएंगे । वीटीपी हमको सिखायेगी । जो सरकार सब्सिडी की सरकार है, उसका उद्यमिता से क्या संबंध है । छत्तीसगढ़ की जो इंटरपेन्योरशिप है, छत्तीसगढ़ की जो स्वाभाविक उद्यमिता है, जो स्वाभाविक क्षमता है, ये सब चीजों को खतम करने की साजिश है और आप माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रघुरामन जी देश के ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री हैं, जो माननीय आपके नेता जी, जिसके लिए अपने सेन्ट्रल मेनीफेस्टो के लिए मदद ले रहे हैं, उन्होंने कहा है कि किसानों का ऋण माफी उपाय नहीं है, उपाय है कृषि में निवेश । जो फार्म 24 खेत से किचन तक फसल पहुंचे, सुरक्षित पहुंचे, दाम मिले, उसके स्टेप क्या-क्या हो सकते हैं, उसका परिणाम पहली बार यह आया है कि सिंचाई का बजट कम हुआ है, किसी दूसरे पर्यायमूलक, पर्यायवाची योजनाओं की घोषणा नहीं हुई है । यदि सब्सीडी होती है, मैं एक जिम्मेदार राजनीतिक दल का पदाधिकारी हूँ, चुनाव जीतने को जो उपकरण बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ को मध्ययुगीन दौर में ले जा रहे हैं । ठीक है, आप लोक लुभावन कारणों से आ सकते हैं, संघर्षों से आ सकते हैं, विचारधारा से आ सकते हैं, असहमति से आ सकते हैं, असफलता से आ सकते हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- भाषण देने के बाद बैठना । भागना मत । भाषण देने के बाद निकल मत जाना, बैठना ।

श्री अजय चन्द्राकर :-यह छत्तीसगढ़ की उद्यमिता को खत्म करने का षडयंत्र है । माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था 99 नंबर पेज में है । हमारी सरकार न केवल नीति बनाना जानती है, बल्कि उसको पालन करने में भी सक्षम है । साहब, जो मुख्य बजट भाषण आया है, आप पूरे बजट पढ़ लो । जो तीन मंत्री का बजट है,

एक संस्थान खुले हैं, सरगुजा में । एक मर्रा में । खैर वह मुख्यमंत्री जी विशेषाधिकार है भई । एक संस्थान साजा में खुला है । वह अनिला जी भेंडिया है, वह खोली है। मुझे हाऊस में नहीं बोलना चाहिये । मैं बजट पलट-पलट के थक गया, यह सरकार और यह सदन अध्यक्ष महोदय का ध्यान रखती होगी । हम लोग तो अध्यक्ष जी के पास खुद ही जायेंगे । जब यह विरोधाभाषी बजट, यह छूट का बजट और राजस्व व्यय का बजट बढ़ रहा है, हम यदि जनआकांक्षाओं पर यदि उतर नहीं सकते, हमारे पास एक रास्ता बचता है, हम आपके पास याचिका लगायें । जनता के पास जाकर हम भीख नहीं मांग सकते, मुंह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नहीं मोड़ सकते, आपके पास माननीय अध्यक्ष महोदय, याचिका लगायेंगे । आप क्रियान्वयन करना जानते हैं, साहब । ठीक है ।

क्रियान्वयन में क्या है, पुलिस को काम करने दीजिए, डिटेक्ट मत कीजिए कि आपको यह परिणाम देना है, यह लिखना है, यह करना है। जो अधिकारी बैठे हैं, वह हमारे साथ 15 साल किये हैं । मैं तो इसमें एक लाईन बोलता हूँ । हम लोग तो आते-जाते रहते हैं, इधर से उधर चिढ़ाते रहते हैं ।

पुरूष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान ।

भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण ।

आप कभी इधर हैं, कभी उधर हैं, आप अपने दायित्वों पर रहिये । आप संवैधानिक संस्था है । टूल मत बनिये । उपकरण मत बनिये और आज मुझे दुख है कि एक अधिकारी सी.जे. साहब के पास जाकर सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाता है कि साहब मेरी जान-माल की रक्षा कर दीजिए । सही हो, गलत हो, राजनीतिक हो, उसमें मैं नहीं जाना चाहता । नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाली संस्था है, परिणाममूलक संस्था है । आप चीफ सेक्रेटरी का बंगला खाली करवा देते हैं, आप कलेक्टर को धमकाते हैं । आप नोटिस देते हैं । बात करते हैं कि अधिकारी नहीं है, कितने लोगों को एक महीने से ऊपर हो गया, आई.ए.एस. अधिकारियों को बिना विभाग के रखें हैं । आप कहते हैं कि नीति बना रहे हैं, यह कहिये कि मैं अपनी पसंद का मैं जो कहूं लिखे, करे, ऐसा प्रशासन चाहता हूँ तो फिर इस प्रदेश का भगवान मालिक है ।

अध्यक्ष महोदय :- समाप्त करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट अध्यक्ष महोदय, आप मुद्रा बदल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एस.आई.टी. बनाते हैं, मैंने डिमाण्ड मांग में कहा था, एक एस.आई.टी. बननी चाहिये, एस.आई.टी. किस-किस बात पर बनाई जाये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रमाण दूंगा । एक नेता का बयान आया कि कांग्रेस की टिकट मंत्री जी ने 20 करोड़ में खरीदी । मैं उसका क्लिपिंग दूंगा । एक प्रभारी मंत्री, यहां के वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय पार्टी के प्रभारी हैं, उसके लिए गलत और इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल हुआ है, मैं इस बात को सही तरीके से बोल सकता हूँ कि माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर, वह प्रदेश अध्यक्ष हैं, उंगली नहीं उठा सकते, पर यह आरोप लगा है तो मैं चैलेंज करता हूँ कि इसकी एस.आई.टी. बनाकर जांच करवायें, जब सब में एस.आई.टी. हो रही है ।

समय :
1:50 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, सबमें यदि एस.आई.टी. बन रही है तो वाकई में कांग्रेस की टिकट 20 करोड़ में क्या मैंने खरीदी इसकी भी एस.आई.टी. जांच हो जाए। जब अंतागढ़ 5

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

साल बाद निकल सकता है, जब और कोई चीजें 10 साल बाद निकल सकती हैं अभी हमारी उपलब्धियों में यही चीजें हैं कि हम खोद खोदकर निकालें।

श्री शिवरतन शर्मा :- अंतागढ़ का हीरो और इस टेप कांड का हीरो एक ही व्यक्ति है। जिसने आपको स्टिंग किया है, उसका हीरो भी वही है। मुख्यमंत्री जी, एस.आई.टी. गठित करने की घोषणा कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। घोषणा पत्र का एक जो महत्वपूर्ण विषय है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। जितने लोगों को आप बेरोजगारी भत्ता देंगे, जितने पैसे की घोषणा हुई है और बजट सत्र में जितने लोगों की घोषणा हुई है उसके लिए तीन हजार करोड़ रूपये चाहिए और तीन हजार करोड़ रूपये के लिए तो तीन पैसे आपने नहीं दिये बल्कि उस विभाग का बजट कम कर दिया। माननीय मंत्री जी चले गये। लगभग 19500 के करीब गांव हैं उनकी योजना बनाने के लिए, योजना तो जीपीडीपी चल रही है, गांव वाले बनाते हैं और कोई योजना आपको बनानी है तो वह शासन का विशेषाधिकार है, उसके लिए 97 लाख रूपये दिये गये हैं, यानी एक गांव को 425 रूपये दिये गये हैं। 425 रूपये में एक गांव की योजना बनेगी। बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है। अब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक बात आज हुई कि पूरे बजट में एक जवाहर सेतु योजना और एक कोई सुराजी योजना । योजना पहले से चल रही है, पुल बन रहे हैं उसका आपने नामकरण दे दिया। ये पहला बजट है जिसमें छूट के सिवाय कोई नई स्कीम की घोषणा नहीं हुई और यदि पी.डब्ल्यू.डी. और निमा्रण कार्यों में नये मद आये हैं, उस डिमांड मांग में मैं बोलूंगा कि वह नये काम किसको दिये गये हैं, दो माननीय मंत्रिगणों के क्षेत्र में दो संस्थाएं, दो-तीन स्कूल और ये प्रदेश का दृष्टिकोण जो बजट में झलकना चाहिए उसका अभाव। जब आप योजना नहीं बना रहे हैं तो नामकरण कैसे करेंगे? आगामी चुनाव है, जनता को जाकर बताना है कि हमने इतनी योजनाएं बनाईं। साहब, आप नाम बदलने के बजाए नई योजनाएं बनाईये ना। योजना बनाईये तो आप दामाद के नाम से रख सकते हैं, भांचा-भांची के नाम से रख सकते हैं, पत्नि के नाम से रख सकते हैं और भी जो लोग हैं उनके नाम से रख सकते हैं। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आप नाम बदलकर गलत परंपरा की शुरूआत करें लेकिन यह भी स्वीकार।

श्री अमरजीत भगत :- यही बात जो आप बोल रहे हैं, अपने देश के नेताओं को भी समझा देते कि जिस प्रकार से नाम बदलने का काम वह कर रहे हैं। आप दूसरों से केवल उम्मीद करते हो और करने की बारी आती है तो ठीक उल्टा करते हो। आप वहीं सही किया करो ना।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी, जी, जी, जी, जी। (हंसी) माननीय सभापति महोदय, ये वर्ष 2019-2020 महात्मा गांधी का 150वीं जयंती वर्ष है। तश्वीर लगी है, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इम्पावर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कमेटी बनी है, चीफ सेक्रेटरी जी की अध्यक्षता में इम्पावर कमेटी बनी है, माननीय मोदी जी जब बजट अभिभाषण में संपूर्ण स्वच्छता पर बोल रहे थे तो इन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए, मैं मांग करता हूं कि उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वह एक कार्यक्रम नहीं था, वह एक सामाजिक आंदोलन है कि अस्वच्छता के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। यह सबकी जिम्मेदारी है। मैं शामिल होउंगा तो मैं जाउंगा। सवाल इस बात का है कि गांधी की भाषा बदल गई, गांधी की परिभाषा बदल गई। गांधी का योगदान बदल गया, गांधी के अर्थ बदल गये और जनमशती समारोह के लिए शून्य बजट, 150 वीं जयंती के लिए शून्य बजट । और यदि कोई दूसरा गांधी, रिमिक्स वाला गांधी भी आयेगा, अब नाम लूंगा तो हुल्लड़ हो जायेगा आज नहीं लेता लेकिन रिमिक्स गांधी भी रहेंगे तो उसके लिए भी बजट दे दिये जायेंगे। सरदार पटेल जी की बाद में बात करेंगे लेकिन एक रूपये महात्मा गांधी जी की 150 वीं जयंती के लिए नहीं है। आपकी व्यवस्था सही है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अपना पहला बजट पेश किया, किन कारणों से आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक अर्हता आपकी हो सकती है, राजनीतिक जरूरतें हो सकती है और मुझे आपका पहला बजट सिर्फ राजनीतिक लगा। आशा करता हूं जो आपको जनादेश मिला है, बड़े नेता के गुण होने चाहिए, जो इनबिल्ट आपके अंदर है जो मन में कुछ करने की इच्छा है, सकीर्णताओं से परे हक है। बड़े नेता पदों से बड़ा नहीं होता। इतिहास में जो बड़े नेता लोग रहे हैं, महात्मा गांधी जी किसी पद पर नहीं थे, जो विचारक लोग थे वे किसी पद पर नहीं थे जो बड़े नेता हुए, मुख्यमंत्रियों में भी भारत रत्न मिले। एम.जी रामचंद्रण साहब जी को मिला, विधानचंद्र राय जी को मिला, गोपीचंद्र बरदोली जी को भारत रत्न मिला वो इसलिए नहीं मिला कि भाजपा को परेशान करेंगे या विरोधी दल को परेशान करेंगे, इसलिए नहीं मिला कि मूल्यों के खिलाफ जाएंगें, इसलिए नहीं मिला कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करेंगे, इसलिए मिला कि उन्होंने सबको ले के चलने का तरीका अख्तियार किया। वो इसलिए बया कहलाये कि समावेशी विकास के बारे में सोचा। वे इसलिए बड़े कहलाये कि उनके पास दिशा, दशा और दृष्टिकोण था। उनके पास एक विचार था कि मैं अपने जन्मभूमि और अपने कार्यक्षेत्र को कहां तक ले जाना चाहता हूं। ये दुर्भाग्य है कि इन चीजों का मेरे पास अभाव है लेकिन उसके बावजूद मैं आपके पहले बजट के लिए आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिए धनयवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति जी, अमरजीत जी पूरा बताइयेगा कि गोबर थोपने से कितने लोगों को नौकरी मिली।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- सभापति जी, इसका भी उत्तर दीजिए कि पकौड़े से कैसे बन रहे थे रोजगार है न ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 2019-20 के लिए 95,899 करोड़ का जो बजट पेश किया गया है, मैं उनके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी बात की शुरूआत यहां से करना चाहता हूं, श्री अजय चंद्राकर जी भाग गये।

चट्टानों से होकर जब मैंने गुजरा, तो रह गई छाप मेरे पांव की।

सोचों कितना बोझ उठाकर उन राहों से गुजरा ।

श्री केशव चंदाकर :- सभापति जी, आपके लिए तो बराबर है, इधर बैठे या उधर बैठे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अमरजीत जी, अब आपको पांच साल पत्थर ही उठाना है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी ये हरे छत्तीसगढ़ के चिन्हारी, येला बचाना हे संगवारी। ये एक संदेश, एक विचार, छत्तीसगढ़ियों को दिया है मैं उसकी भूरी भूरी प्रसंशा करता हूं (मेजों कि थपथपाहट) कि आपके इस भाव में छत्तीसगढ़ का सपना छुपा हुआ है, छत्तीसगढ़ की पहचान छुपी हुई है और जहां ग्रामीण परिवेश पूरी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, जहां कृषि पर आधारित है उनके लिए इस प्रकार की सोच रखना, इस प्रकार की बजट बनाना और पूरे छत्तीसगढ़ में नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी को जो कांसेप्ट है, कल हम लोग भोजन करने बम्हकुमारी आश्रम गये थे पूरे, छत्तीसगढ के माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे, माननीय अध्यक्ष जी गये थे। वहां भी उद्घोषक इन बातों को लाइनप कर रहे थे, जो गुजरात से आएं हैं वे बता रहे थे और कुछ नहीं जानते हैं तो आई.ए.एस. लोग पूछ रहे थे कि What is नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी तो एक आदमी बोले This is a beasd line in Chhattisgarh Development ये छत्तीसगढ़ विकास की आधारशिला है। जमीनी हकीकत है, हम दूसरे के पीछे भागते भागते कहां से कहां निकल गये थे। हमारे गांव का नाला, जलस्त्रोत, लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज हम गांव में गाय पालते थे, उसको छोड़कर के हम डेयरी के पीछे आ गये थे। प्लास्टिक में बंद दूध पीना शुरू कर दिये थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की उस सोच को सलाम करता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ की वास्तविक फीजा, छत्तीसगढ़ की वास्तविक नक्शे को प्रदर्शित करने की कोशिश की है। लोगों को सही लाईन में चलने के लिए एक मागदर्शन दिया है, उनकी मैं भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूँ और विपक्ष के साथियों को इन शब्दों के साथ कि

मंजिल दूर है, सफर मुश्किल है,
यदि साथ चल सकते हो तो चलो।।
वरना समय है परिवर्तन का
संभल सकते हो तो संभलो।

आप कहां थे और कहां पहुंच गये? आप लोगों की यही सोच, आप लोगों को इस पार से उस पार पहुंचा दिया। जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भाषण देते थे तो क्या बोलते थे? कि अगली बार जब

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सरकार आएगी तो विपक्ष (कांग्रेस के लिए ईशारा करके बोलते थे) सिमट कर रह जाएगी। श्रीमान, आपने ऐसा कौन सा कर्म किया कि वह आप ही के पल्ले पड़ गई ? क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ की जनता के दु:ख को नहीं समझा। छत्तीसगढ़ की जनता के दर्द को नहीं समझा। छत्तीसगढ़ की जनता को क्या चाहिए था, उनके मर्म को आप नहीं पकड़ पाये। कहने के लिए तो आपके मुख्यमंत्री जी डॉक्टर थे, लेकिन लोगों को बुखार था और सिरदर्द की दवा लिखना, देना शुरू कर दिये थे। ये इसका रियेक्शन है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना बजट पेश किया, उसमें महात्मा गांधी जी के उन शब्दों को उल्लेखित किया है इसमें कहा है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वास्तविक भारत गांव में बसता है यदि गांव नहीं बचे तो देश भी नहीं बचेगा। यह बात भी सार्थक प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ की 75 प्रतिशत आबादी गॉवों में निवास करती है और आज भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वह कृषि पर आधारित है। कृषि और किसान के विकास से ही हमारे गॉवों में समृद्धि आएगी। इसी अवधारणा को लेकर इस सरकार ने पहला बजट पेश किया है। किसानों और कृषि के क्षेत्र में विकास के कार्यों को केन्द्रित करते हुए, बजट पेश किया गया है। मानसून जब धोखा दे जाए और अनिश्चिता की स्थिति हो जाए। वर्षा आधारित कृषि में हमारे देश में किसानों का भविष्य निर्धारित करती रही। अधिकांश खेती किसानी का काम अल्पकालीन ऋण लेकर लोग करते हैं। परंतु समय पर वर्षा, पानी नहीं मिलने से फसलों को नुकसान तो झलते हैं साथ ही कर्ज चुकाने का बोझ उन पर आता है।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट पूरी तरह से यहां के किसान कृषि पर आधारित है। सिंचाई कर मात्र 207 करोड़ रूपये किया गया है। इसमें 15 लाख किसानों को फायदा हुआ है और धान खरीदी के लिए जो 2500 रूपये प्रति क्विटल दाम तय किया गया है, उसमें 17 लाख किसानों को फायदा हुआ है । खरीफ फसल खरीदी में वर्ष 2017 में 10 हजार, 597 करोड़, जबकि वर्ष 2018 में 19 हजार, 733 करोड़ का भुगतान किया गया है। इनकी जो भी योजनाएं बनती थीं कमाओ, खाओ योजनाएं रहती थीं। उसमें लिंकेज बहुत रहती थी, उसमें अपव्यय बहुत रहता था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है,उसमें फिजूलखर्ची को बंद कर दिया है और आवश्यक कदम उठाये हैं। सोयाबीन उत्पादन पर कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए 10 करोड़, गन्ना उत्पादन प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़, समर्थन मूलय पर दलहन एवं तिलहन खरीदी करने के लिए 7 करोड़ 12 लाख, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 316 करोड़, एकीकृत बागवानी विकास के लिए 205 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 359 करोड़, टार्गेटेड राइस फैलो एरिया के लिए 95 करोड़, कृषक समग्र विकास योजना के लिए 77 करोड़, , राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 120 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं पर किसानों के लिए एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के लिए 200 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 74 करोड़, माईक्रो माईनर सिंचाई योजना के लिए 25 करोड़, 5 एच.पी. तक के कृषि पम्पों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लिए 2 हजार 164 करोड़, नये कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 100 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 2000 करोड नहीं, 200 करोड़ है, 73 हजार करोड़ नहीं, 720 करोड़ हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, सौर ऊर्जा के सहयोग से सिंचाई हेतु 20 हजार नये सोलर पंपों की स्थापना हेतु 467 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नई सिंचाई पंप परियोजनाओं के लिए 300 करोड़, महानदी-परियोजना के लिए 216 करोड़, अरपा-भैंसाझार परियोजना के लिए 127 करोड़, लघु-सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु 524 करोड़ एवं कमाण्ड-क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति हेतु 116 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। यह पूरी तरह से किसान और कृषि कार्य के लिए बजट पेश किया गया है। यहां के किसान अगर समृद्ध होंगे तो छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा बदलेगी। जिस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था, वहीं पिछली सरकार ने केवल धूल, धूआं और प्रदूषण का राज्य बना दिया था। यहां के तालाब, यहां के जल स्त्रोत को बेचा गया था। यहां की अर्थव्यवस्था को अस्त्-व्यस्त कर दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, वास्तव में जिसकी जरूरत थी, यहां के लोगों को उस संकट से निकालने की जरूरत थी, अगर आज किसानों का कर्जा माफ किया गया है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और बहुत-बहुत बधाई देता हूं। जिस राज्य की पहचान धान के कटोरे के रूप में हो, वहां के किसान आत्महत्या करें। यहां के किसान आत्महत्या करें तो पिछली सरकार किसी को आपसी विवाद के कारण आत्महत्या, किसी को चोरी के आरोप के कारण, किसी के ऊपर अन्य तरह का कोई भी आरोप लगाकर के किसानों को एक तरह से कलंकित करने की कोशिश की गई है । माननीय सभापति महोदय, इनकी इतनी बुरी स्थिति नहीं होती । किसानों के मामले को इन्होंने समझा ही नहीं । किसान तो जब इनसे पानी मांगते थे तो पिछली सरकार उनके ऊपर लाठी बरसाती थी, जब गंगरैल में किसान पानी मांग रहे थे तो माननीय सामने बैठे हैं उनके ऊपर लाठी बरसायी गयी । उनके साथ मारपीट की गयी, उनको जेल की सलाखों में अंदर डाला गया । क्या छत्तीसगढ़ में ऐसे ही संस्कृति आगे बढ़ेगी ? जहां के किसानों के साथ मारपीट की जायेगी, जेल की सलाखों के भीतर डाला जायेगा, पानी मांगेंगे तो लाठी दिया जायेगा तो पिछली सरकार की स्थिति तो ऐसी होनी ही थी । इसके लिये कोई और जिम्मेदार नहीं है, स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे हैं ।

श्री दीपक बैज :- श्री अमरजीत भैया, लेकिन बहुत ज्यादा ही हो गया न।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, डेयरी उद्यमिता विकास योजना के लिये 15 करोड़ 12 लाख, मुर्गी पालन हेतु 21 करोड़, बकरी पालन हेतु 4 करोड़ 35 लाख, शुगर पालन हेतु 4 करोड़ 49 लाख, 20 नवीन पशु औषधालय खोलने की स्वीकृति । महासमुंद, जगदलपुर एवं सूरजपुर में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रीजनल फर्स्ट एण्ड ट्रेनिंग सेंटर फॉर एनीमल्स हेल्थ की स्थापना हेतु 2 करोड़ का नवीन मद प्रावधान हेतु रखा गया है ।

मानननीय सभापति महोदय, माननीय अजय जी अभी बोल रहे थे कि यहां की संस्कृति, यहां की जो ट्रेडिशनल संस्कृति है उसके बारे में क्या कहा कि यहां के लोगों को गोबर थोपवायेंगे । यहां के लोगों को गोबर थोपवाने जैसी बात कह करके उन्होंने यहां के निवासियों का, यहां के मूल निवासियों का उपहास किया है । हमारी सरकार गोबर गैस बनायेगी और उन गोबर गैस से हमारी बहनें खाना बनाने का भी काम करेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा । इनको क्या मालूम है कि गोबर से क्या-क्या बनता है । जैसा जिसका मुखिया होता है वैसे उसके दल के लोग होते हैं । इनके मुखिया ने जब चुनाव में घोषणा किए थे कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे । जब नौकरी मांगने लगे तो उनकी तरफ से क्या कहे कि पकौड़ा बेचो, चाय बेचो । इतनी हल्की बात करने वाले दल के लोग क्या बात करेंगे ? सभापति महोदय, जिस प्रकार से उस पार के लोग हमारे विरोधी दल के साथी एसआईटी पर उपहास उड़ाते हैं । संवैधानिक संस्था है, हमारी जांच एजेंसी है और एसआईटी गठन मात्र से आप इतना फडफड़ाने क्यों लगे ? यह उन लोगों के लिये है जिन लोगों ने गलत काम किया है और गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । किसी को भी स्वेच्छाचारिता की ईजाजत इस प्रदेश में नहीं होनी चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय, इनके मुखिया बड़े-बड़े संवैधानिक संस्थापक जिस प्रकार से कुठाराघात किया । रिजर्व बैंक के जो चैयरमेन होते हैं उनको ऐसे हटाया जैसे हम ऑफिस के किसी बाबू को हटा रहे हैं । यह बात करते हैं नीति और सिद्धांत की । एसआईटी का मुखिया, हम उसी अधिकारी को बनाये हैं जो इनके बहुत चहेते थे, प्रिय थे । इतना उनके नाम से डरने क्यों लगे हैं ? कहीं जाने-अनजाने में बहुत सारे गलत काम तो नहीं किये हैं ? इसी बात का अंदेशा है लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार किसी के साथ बदले की भावना से काम नहीं करेगी । इनको सोचना चाहिए कि किस प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे ? आधी रात को उनकी जमीन नपवाये थे । आधी रात को । उस समय एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच-पांच बार जमीन को नपवाये । उस समय इनकी नीति और सिद्धांत कहां था ? इनको इस प्रकार की बात करना शोभा नहीं देती । ये नीति और सिद्धांत की बात करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हम गोबर गैस प्लांट एवं कम्पोस्ट खाद बनायेंगे । प्रत्येक गांव से 10 युवाओं को प्रशिक्षण देंगे जिससे लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सकेगा । मनरेगा योजना, भूमिहीन मजदूर एवं लघु सीमांत किसानों को रोजगार हेतु 1542 करोड़ का प्रावधान किया है । माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिये 306 करोड़ जिसे महिला

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

स्वयंसहायता समूह को उपलब्ध कराया जायेगा । ग्राम के विकास उसकी अवधारणा, उसके विकास के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये 1565 करोड़ रूपया, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 238 करोड़ का प्रावधान, स्वच्छ भारत अभियान के लिए, ग्राम में कचरा निकासी, प्रबंधन हेतु 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है । सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं ग्रामीण विकास योजना के लिए 1723 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । मिनी माता अमृत जल योजना के लिए, ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है । सभापति महोदय, यहां पर खाद्य एवं पोषण के लिए प्रावधान कियागया है । महिला बाल विकास विभाग में, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीब परिवारों के प्रति राशन कार्ड में 35 किलो चावल हेतु 4 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

श्री दीपक बैज :- अमरजीत भैया, महिला बाल विकास विभाग में माननीय मंत्री जी अंडा खिला रही हैं। पूरे देश में चर्चा हो रही है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय महिला बाल विकास विभाग मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई । जिन्होंने पोषण के लिए अंडा खिलाने का निर्णय लिया है । इससे निश्चित रूपसे गुणात्मक सुधार होगा । सभापति महोदय, आज भी जब हम लोग गांव में दौरे पर जाते हैं । अधिकांश आवेदन राशन कार्ड के लिए आता है । कई आवेदन ऐसे रहते हैं जिसमें वृद्ध माता-पिता लाठी टेकते हुए आते हैं और कहते हैं कि बाबू बेटे ने हमको छोड़ दिया है, बहुरिया ने हमको छोड़ दिया है । हमारा सहारा कुछ नहीं है और किसी कारणवश उनका राशन कार्ड नहीं बन पाता है, कई लोगों को चावल नहीं मिल पाता है । माननीय मुख्यमत्री भूपेश बघेल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने सभी राशनकार्ड धारियों को एक नजर से देखा और सबको 35 किलो चावल देने का निर्णय लिया । इसके लिए 4 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, एकीकृत बाल विकास योजना में पूरक पोषण आहार हेतु एवं बच्चों की कुपोषण दूर में कमी लाने हेतु 1340 करोड़ का प्रावधान किया गया है । किशोरी बालिकाओं के पोषण के लिए 37 करोड़, महतारी जतन योजना के लिए, गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए 24 करोड़, ईसीई योजना आंगनबाड़ी को नर्सरी के रूप में विकसित करने के लिए 15 करोड़ का प्रावधान, कन्यादान योजना के लिए 19 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है । सभापति महोदय, पिछली सरकार कितना-कितना देती थी, मात्र15 हजार रूपए, जिसमें लोगों की शादी ब्याह ठीक ढंग से नहीं हो पाती थी । लेकिन उन कमियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा और प्रत्येक जोड़े के लिए 25 हजार देने का निर्णय लिया, हम उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 15989 करोड़ का प्रावधान किया है । अनुसूचित जाति योजना के लिए 5485 करोड़ का प्रावधान किया गया है । पिछली सरकार आदिवासियों के, अनुसूचित जाति के अधिकारों का हनन कर रही थी । यही सदन है, बाकायदा जमीन के कानून में संशोधन करके, आदिवासियों की जमीनों को छीनने की कोशिश की गई थी । सभापति महोदय, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं । आदिवासियों के पास अगर जमीन बची है तो उन नियमों और कानूनों के चलते बची है। अन्यथा उनके पास एक इंच जमीन नहीं बचती, उद्योगपति उनकी जमीन हड़प लेते । उस पर पिछली सरकार की नजर थी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, जमीन के कानून में संशोधन लाने के लिए और संशोधन के माध्यम से उनकी जमीन को हड़पने के लिए पूरी कोशिश की थी। हम लोगों ने बहुत विरोध किया। हमने समझाने की कोशिश की। लेकिन पिछली सरकार नहीं समझी और जिसका नतीजा है कि आज उस तरफ सीमित सीटों में ही सिमटकर रह गई है।

सभापति महोदय :- माननीय अमरजीत जी समाप्त करें।

श्री अमरजीत भगत :- बस दो मिनट। वन भूमि अधिकार पत्र जो पिछली सरकार ने केन्द्रीय अधिनियम 2006 के तहत अक्टुबर 2005 तक के कब्जाधारियों को पट्टा देने का निर्णय लिया था उसमें पिछली सरकार ने केवल खानापूर्ति की। लोगों को वन अधिकार पत्र नहीं दिया। लोगों को निस्तार हेतु अधिकार नहीं दिया। बड़े पैमाने पर आवेदन निरस्त किये गये। मैं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। सरकार बनने के बाद उन्होंने इसके लिए बैठक बुलाई। पूरे प्रदेश के कलेक्टरों को बुलाया। सेक्रेट्रियों को बुलाया और इसमें स्पष्ट निर्देश दिया कि इसमें हमको पुनर्परीक्षण चाहिए और जिनका भी आवेदन निरस्त किया गया है उन सभी लोगों का परीक्षण करके उनको वन अधिकार पत्र दिया जाना चाहिए। तेंदूपत्ता संग्राहकों के साथ इस सरकार ने बहुत बड़ा न्याय किया है। पिछली सरकार ने 15 साल में नहीं बढ़ाया था। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, हमारे आदिवासी वर्ग के लोग जो जंगल पहाड़ में रहते हैं तेंदूपत्ता तोड़ते हैं उनके लिए 2500 के स्थान पर बढ़ाकर 4000 रूपये प्रति मानक किया गया। सरकार ने वनोपज का संग्रहण कुल्लू, गोंद, नांगरगोथा, शहद, बहेड़ा, बेल, गुदा, कालेमेघ, फूलझाड़ू आदि का सरकारी दर पर खरीदी करने का निर्णय किया है। माननीय मुख्यमत्री जी को और बधाई देता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ एक बहुत बड़ा न्याय किया है। जो उन्होंने घोषणा की थी कि सरकार में आने के बाद हम लोगों का बिजली बिल आधा करेंगे, हाफ करेंगे। उसके लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और अच्छा बनाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 242 स्टाफ नर्स के पद स्वीकृत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किये गये हैं। 100 बिस्तरीय जिला अस्पताल सरगुजा हेतु 135 पदों का सृजन किया गया है। 7 करोड़ 26 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है और इस प्रदेश में जिस दिन यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम लागू हो जाएगा, यहां कि जो सारी स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं, वह दूर होंगी।

श्री सौरभ सिंह :- अमरजीत जी, लागू कब होगा, यह भी जरा बता देते। यूनिवर्सल हेल्थ केयर कब लागू हो जायेगा। अभी तो किसी का इलाज ही नहीं हो रहा है। पता ही नहीं है कहां पर जाना है। स्मार्ट कार्ड बंद।

श्री दीपक बैज :- माननीय सौरभ सिंह जी, वह हेल्थ केयर भी मालूम है कहां से आयेगा। थाइलैण्ड से आयेगा।

सभापति महोदय :- माननीय अमरजीत जी, जल्दी समाप्त करें।

श्री अमरजीत भगत :-जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के विकास के संदर्भ में जो सपना देखा है उससे जरूर यहां पर खुशहाली और समृद्धि आयेगी। यहां के किसान समृद्ध होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ कन्सेप्ट सफल होगा। आपने मुझे बोलने के लिए जो अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द ।

सभापति महोदय :- आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में अभी 35 सदस्यों के नाम हैं, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि संक्षिप्त में अपनी बात कहें। श्री नारायण चंदेल जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- अमरजीत जी, आपके आधे घण्टे का भाषण बेकार गया। क्योंकि जो लोग सुनकर आपकी सी0आर0 लिखते, सुनने वाला कोई नहीं था।

श्री शिवकुमार डहरिया :- वह सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हर चीज उनकी नजर में है।चिंता मत करो।

श्री शिवरतन शर्मा :- अगर हर चीज उनकी नजर में है, तो फिर आपके लिए बड़ी चिंता का विषय है।

श्री शिवकुमार डहरिया :- मैं सुरक्षित हूँ, मेरी चिंता मत करो। अपनी चिंता पहले करो।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चाम्पा) :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आम बजट प्रस्तुत किया है। यह करीब 91 हजार करोड़ का यह बजट है। प्रथम दृष्टा यह बजट असंतुलित है। असंतुलित इसलिए है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस प्रकार से विकास की झलक, विकास का खाखा दिखना चाहिए, वह इस बजट में कहीं पर दिखाई नहीं देता है। हम एक तरफ जशपुर से लेकर बस्तर तक, रायगढ़ से लेकर डोंगरगढ़ तक, हम कहीं पर देखते हैं तो कोई उल्लेखनीय कार्य का उल्लेख इस बजट में परिलक्षित नहीं हो रहा है। हम यह कहते हैं कि इस बजट को राजनीतिक दृष्टि से हटकर बनाना चाहिए। बजट पूरी जनता के लिए होनी चाहिए। बजट में समग्र विकास दिखना चाहिए, संतुलित विकास की झलक दिखनी चाहिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय सभापति महोदय, हम बजट को देखे, किसानों की कर्ज माफी की बात हमारे सब पूर्व वक्ताओं ने कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जितने किसानों का कर्ज माफ किया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। बाकी मुख्यमंत्री जी, प्रदेश सरकार की जो थीम है, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, शब्द बहुत अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों, किसानों, नौजवानों के दिल को छूने वाले शब्द हैं। लेकिन इनके विकास के लिए कितनापैसा दिया गया है? उस मद में कितनी राशि दी गई है ? एक करोड़ से भी कम राशि इसके विकास के लिए है। हम इस बजट को देखते हैं तो यह सिर्फ आकड़ों का मायाजाल है। सिर्फ इधर से उधर करके आकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। कोई ठोस कार्ययोजना इस बजट में सरकार की दिखाई नहीं देती है कि यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास को बढ़ाने वाला बजट है या पीछे ले जाने वाला बजट है।

माननीय सभापति महोदय, हमारा जो बजट है, वह कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारी सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। लेकिन छत्तीसगढ़ में किसानों की क्या गति है ? सिंचाई का रकबा कैसे बढ़े, छोटी-छोटी नालियां कैसे बने, सुदूर क्षेत्रों तक कैसे सिंचाई के संसाधन बढ़े, सुदूर क्षेत्र में जो रहने वाले किसान हैं, जो सुदूर गांवों में रहते हैं, आदिवासी वनवासी अंचलों में रहते हैं, वहां पर कैसे सिंचाई के साधन पहुंचे, इसके लिए कोई कार्ययोजना, कोई मद इस बजट में नहीं है। सरकार ने समग्र रूप से इस बजट को नहीं बनाया है। ऐसा लगता है कि बहुत हडबड़ी में बनाया है। माननीय सभापति महोदय, समाज के अंतिम छोर पर रहने वाला कौन व्यक्ति है- दुकालू, सुकालू, बैसाखू, समारू, पहारू, दहारू है। उसके लिए क्या कार्ययोजना है ? माननीय सभापति महोदय, वही व्यक्ति अंत्योदय पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति अंत्योदय है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर चलने वाली जितनी योजनाएं हैं, वह इस सरकार ने कल जिस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 11 फरवरी को पुण्य तिथि थी, कल ही उन सारी योजनाओं का नाम बदलकर अपनी सोच को प्रदर्शित कर दिया है इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी सहित इस सरकार को आग्रह करना चाहते हैं कि बड़े मन से काम करे । इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खरा नहीं होता। इसलिए बड़े मन से काम करने की आवश्यकता है । जनादेश आपको मिला है, जनता के जनादेश का सम्मान करते और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी सरकार को बड़े मन से काम करने की आवश्यकता है ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी घूम-घूमकर किसानों की बात करते हैं । इस बजट में किसान पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है । सरकार ने कहा था कि किसान आयोग का गठन करेंगे । आप के जन घोषणा पत्र में है, लेकिन किसान आयोग गठन करने का किसी प्रकार का कोई मद

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

और बजट में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है । किसान बीमा का जिक्र किया गया था, उसका इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है । सिंचाई कर को माफ करने की बात कही गई थी, परन्तु सिंचाई शुल्क पूर्णत: समाप्त करने का इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है । सामुदायिक कृषि योजना रोड़ में प्रस्तुत नहीं किया गया है । कृषि यंत्रों की खरीदी पर सब्सिडी और किराये से उपलब्धता का बजट में कहीं कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं है । किसान सेवा केन्द्र का जिक्र नहीं किया गया है, जहां आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की बात कही गई थी । इस बजट में उसका कोई उल्लेख नहीं है । कृषि अनुसंधान विस्तार बजट तीन गुना करने की बात कही गई थी, जिसका इस बजट भाषण में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है । शुरूआती 6 महीने में मंडी विकास बोर्ड के गठन की बात कही गई थी, जिसका इस बजट में कोई प्रावधान कहीं पर नहीं है । अब ये सारी चीजें किसानों से जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ की जो बुनियादी समस्या है-सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल। हम सड़कों का निर्माण कैसे करेंगे-विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में, पहुंचविहीन क्षेत्रों में । सड़क के लिए नाममात्र का बजट प्रावधान किया गया है, क्या उतनी ही राशि में हम छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्रों में बजट से सड़कों का निर्माण कर सकते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रामीण परिवेश के हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सोच कि गांव के विकास से ही इस देश का विकास होगा, किसान के विकास से ही इस देश का विकास होगा, ये सरदार बल्लभभाई पटेल जी ने कहा था, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जय, जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था । किसी प्रकार का इस बजट में इनके उत्थान के लिए, इनकी प्रगति के लिए किसी प्रकार की कोई राशि का उल्लेख नहीं है और इसलिए ये बजट मैंने कहा कि सामान्य रूप से आंकड़ों का मायाजाल है । सरकार के संतुलित विकास की झलक इस बजट में दिखाई नहीं देती । हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, इस सरकार से निवेदन करेंगे कि हर जिले में किसानों के लिए किसान सदन बनें, किसानों का विश्राम गृह बनें । माननीय चौबे जी उस दिन जांजगीर गए थे, मैंने उनसे कृषि मेले में निवेदन किया था । बड़े लोग सर्किट हाऊस में रूक जायेंगे, बड़े विश्राम गृह में रूक जायेंगे, लेकिन जो सुदूर गांव से आने वाला किसान है, जब जिला मुख्यालय आता है, प्रमुख स्थानों पर आता है, उसके लिए कोई छांव की व्यवस्था नहीं है । वह पचहत्ती पहनकर, बंडी पहनकर, आने वाला किसान, जो हमारा भूमि पुत्र है, अन्नदाता है, वह कहां पर रहेगा ? कहां पर रूके ? वह कलेक्ट्रेट के काम से आता है, वह कृषि के काम से आता है, उसके लिए हर जिले में किसान सदन बनाने के लिए बजट में प्रस्ताव रखना चाहिये । माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बजट में इस बात की घोषणा करें । माननीय सभापति महोदय, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, जब अपने-अपने क्षेत्र में प्रवास पर जाते हैं, दौरे में जाते हैं, 60 साल, 70 साल, 75 साल] 80 साल के वृद्ध मिलते हैं] बुजुर्ग मिलते हैं, जो पीड़ित हैं और आज समाज के अंदर बुजुर्गों की क्या हालत है ? इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से, आग्रह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करता हूँ, हर जिले में सुसज्जित वृद्धाश्रम का निर्माण करना चाहिये । इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बजट भाषण में करे । नये स्कूल, नये अस्पताल, आज भी हम सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चले जायें, जैसे कई गांव हैं, जहां की स्कूल जर्जर है, जीर्ण-शीर्ण हैं, दीवालों में दरार है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो कन्या स्कूल है, वहां पर टायलेट की व्यवस्था नहीं है, यह बुनियादी चीजें हैं । बाउंड्रीवाल नहीं है, स्कूल परिसर सुरक्षित नहीं है । इस बजट में हर स्कूल में बाऊंड्रीवाल बनाने के लिए, टायलेट बनाने के लिए, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए, कोई प्रावधान नहीं है । आप अस्पताल चले जाईये । चाहे वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, जिला चिकित्सालय हो । आज के ध्यानाकर्षण में बिलासपुर के सिम्स में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, उसका जिक्र हुआ । ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जिला चिकित्सालय में, ब्लॉक लेवल में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो । उसके लिए इस सरकार ने इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है । हर चिकित्सालयों में डॉक्टरों की कमी है । हर चिकित्सालय में मशीन तो है, लेकिन उसको आपरेट करने वाला व्यक्ति नहीं है । वह धूल खाते-खाते कई सालों से खराब हो रही है । यह बुनियादी चीजें हैं । इन बुनियादी चीजों की तरफ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने बजट उत्तर में इन चीजों का जिक्र करेंगे । माननीय सभापति जी, शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे मिडिल स्कूल से हाई स्कूल खोलें, हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी खोले, आज भी सुदूर क्षेत्रों में आप चले जाईये, उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । नये महाविद्यालय भवन कैसे बने, मुख्यमंत्री जी ने प्राध्यापकों की नियुक्ति का जरूर आदेश जारी किया है । कन्या महाविद्यालय कैसे खुले, हमारी बेटियों को कैसे उच्च शिक्षा मिले, इन सारी चीजों का हमारे बजट में नाममात्र प्रावधान किया है। नये सड़कों का निर्माण कैसे हो, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ बन गया, आज भी अनेक काम सुदूर क्षेत्रों में ऐसे हैं कि आज भी आवागमन के लिए सड़कों का अभाव है । ग्रामीण क्षेत्रों में उन नवीन सड़कों के निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है, सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है । हम सुदूर क्षेत्रों में चले जायें, छोटे-छोटे नाले है, उनमें पुल-पुलिया का अभाव है, उसका निर्माण नहीं हुआ है । इससे आवागमन में संकट पैदा होता है । लोग पांच किलोमीटर, सात किलोमीटर, दस किलोमीटर घूमकर जाते हैं, उनको अस्पताल जाना है, हाट बाजार जाना है, उसके लिए कोई व्यवस्था ......

श्री अमरजीत भगत :- माननीय चंदेल जी, हम लोग जिस कालोनी में रहते हैं ना, वह सड़क जो है, 15 साल में नही बन पाया है । इस सरकार से मांग कर लो, बन जायेगा ।

श्री नारायण चंदेल :- मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। मैं उसके लिए भी माननीय मंत्री जी से और इस सरकार से निवेदन करूंगा कि कि 36 मॉल के पीछे जो विधायक कालोनी है वहां मात्र 100-150 मीटर की सड़क है और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की सड़क से भी जर्जर और जीर्ण-शीर्ण है। एकाध दिन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय मुख्यमंत्री जी को चाय पिलाने ले जायेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सदन में मोहम्मद अकबर जी बैठे हैं, आप उस सड़क का ध्यान दे दीजिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, इस पूरे प्रदेश में रेल्वे ओव्हरब्रिज का अभाव है। हम जब कहीं जाते हैं तो रेल्वे के फाटक में आधे-आधे घंटे तक वाहनों की एक-एक, डेढ़-डेढ़ किलोमीटर लंबी कतारें लगती हैं। इस सरकार को बजट बनाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना था कि जितने हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राज्यमार्ग हैं वहां पर जितने रेल्वे फाटक हैं वहां पर रेल्वे से बात करके रेल्वे ओव्हरब्रिज का निम्ा्रण हो, उसमें राज्य शासन का जो मद होता है उसे स्वीकृत करें, लेकिन इस बजट में उसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है और कोई मद नहीं है। मैंने इसलिए कहा, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जयसिंह अग्रवाल जी वहां आते-जाते रहते हैं। वे चांपा से ही कोरबा जाते हैं। चांपा में जो हसदेव नदी है वहां पर हमने नये पुल के निर्माण के लिए आग्रह किया है। वह पुल जर्जर और जीर्ण-शीर्ण हो गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब वह अपना उत्तर देंगे तो उसमें उसका उल्लेख करेंगे कि चांपा के हसदेव नदी में नये पुल का निर्माण हो। वह राष्ट्रीय राजमार्ग 49 से जुड़ा हुआ है। कल हम लोगों ने इस बात को उठाया था कि खनिज विकास मद में जो काम चल रहे थे, जो काम स्वीकृत हैं, जिसका वर्क आर्डर हो गया है, जिसके टेंडर और वर्क ऑर्डर हो गये उन कामों को भी सरकार ने आदेश जारी करके रोक दिया है। वह काम किसी के घर पर नहीं हो रहे थे, वह काम सार्वजनिक जनता के लिए काम हो रहे थे। कहीं पर सड़क का निर्माण हो रहा है, कहीं पर पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है लेकिन खनिज विकास मद के उन कामों को भी जिसे कि जिला स्तर पर सब लोग बैठकर तय किये थे उन कामों को भी रोकने का जो कार्यादेश जारी हुआ है, यह उचित नहीं है। वह काम पुन: शुरू हो जाएं क्योंकि वह विकास के काम हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार से निवेदन है कि खनिज विकास मद के जिलों में जो काम चल रहे हैं उन्हें पुन: प्रारंभ करने की घोषणा अपने भाषण में करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, वास्तव में इस प्रदेश के पानी और जवानी को रोकना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। उसका दुरूपयोग मत हो और उसे हम कैसे काम में लगायें, पानी को सही दिशा दें कि पानी को हम किसान के खेत तक कैसे पहुंचायें, हम पानी का एक-एक बूंद कैसे सदुपयोग करें, हम कैसे जो छोटे-छोटे तालाब हैं, डबरी है उसका संवर्धन करें, उसकी कार्ययोजना के लिए इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है। प्रदेश में जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको हम कैसे रोजगार उपलब्ध करायें, चाहे हम कौशल विकास के माध्यम से करायें या हम कैसे रोजगार श्रृजन करें, वास्तव में इस सरकार की कोई ठोस नीति इस बजट के परिपत्र में नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, हर जिला मुख्यालय में उसके कलेक्टरेट में कंपोजिट बिल्डिंग होनी चाहिए, जिसमें सारे ऑफिस एक जगह लगने चाहिए। हम जिस जिले से आते हैं, हमारे जांजगीर-चांपा जिले में जो जिला मुख्यालय जांजगीर है वहां जो कलेक्टर ऑफिस है वहां कंपोजिट बिल्डिंग नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जांजगीर में कम्पोजिट बिल्डिंग की स्वीकृति प्रदान हो, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में इस बात का उल्लेख करें । सभापति महोदय, हम लगातार देख रहे हैं कि सड़क दुर्घटना, चाहे वे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे गांव की छोटी सड़के हो, चाहे राज्यमार्ग हो लगातार सड़क दुर्घटना में वृद्धि हो रही है....।

सभापति महोदय :- माननीय नारायण चंदेल जी, अपना भाषण जल्द खत्म करें।

श्री नारायण चंदेल :- सभापति जी, मैं सकेला थो।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति जी, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर प्रमुख शहर में बायपास का निर्माण होना चाहिए लिंक रोड का। उसके निर्माण के लिए इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है। ये सरकार की दूर दृष्टि को परिलक्षित करता है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, आपकी सरकार ने माननीय रमन सिंह जी ने मेरे खुद के गांव में 2016-17 में बजट मे भी शामिल हुए उसके बाद आज तक प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हुई, आप ये बोल रहे हो कि ढपोसला है। पिछला भी थोड़ा अध्ययन करके आप बात करिये।

श्री नारायण चंदेल :- अब ले टार न यार पिछलू बात ला। (हंसी) अभी नया सरकार बनगे, कहां कयिहा के बात ला बईहा ले गे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, वीही मा पड़े रहू त कोई काम नई कर सकव। बढ़िया सर्वोत्तम काम करव। कोन रोके हे, हां अपन बुता ल करव।

श्री संतराम नेताम :- सभापति जी, अपन बुता ह तो नई हो पात हे अभी पिछला बार भी अध्ययन कर के आय करव।

श्री नारायण चंदेल :- सभापति जी, अब तो कराव। यही सारी बातें इस बजट में समाहित होना चाहिए। वास्तव में जो प्रदेश का बजट प्रस्तुत हुआ है आम बजट, वो बजट संतुलित होना चाहिए और दिखना चाहिए कि ये पूरे प्रदेश का बजट है। समाज के जो अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति हैं, उसके विकास की छलक इस बजट में प्रस्तुत होना चाहिए, दिखना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपको धनयवाद देता हूं ।

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापति महोदय, नई सरकार की नई बजट का मुख्य उद्देश्य, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना के साथ नई सरकार का प्रथम बजट पेश हुआ है। ये कुल बजट 91 हजार 542 करोड़ का है। सभापति महोदय, मैं सुन रहा था, विपक्ष के साथियों का भाषण और उनकी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बात, छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको 15 साल शासन करने का अवसर दिया। आज उसके बाद भी बोल रहे हैं, इस बजट में सड़कें नहीं हैं, पुल नहीं है, स्कूल नहीं है, बाउंडरी नहीं है, शौचालय नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने 15 साल रहने के बावजूद ये बता रहे है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। बड़ी मुश्किल से 50 दिन हुए हैं काम करते हुए और 50 दिन में छत्तीसगढ़ का काम, छत्तीसगढ़ की जनता ने, पूरे देश की जनता ने देख चुकी है छत्तीसगढ़ का काम, अन्य सरकार देश का उदाहरण दे रहे हैं। अगर काम करना है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार की तरह करिये, अगर सीखना है तो छत्तीसगढ़ की सरकार से सीखिये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार को सबसे बड़ा धान का कटोरा कहे जाने वाले, छत्तीसगढ़ का बजट, सबसे पहला और सबसे बड़ा बजट कृषि बजट के रूप में 21 हजार 597 करोड़ का बजट आया है। वो बजट किसके लिए है, वो बजट गरीब किसानों के लिए, मध्यम वर्गीय किसानों के लिए, गांव के अंतिम छोर में बसने वाले किसानों के लिए है, क्या सरकार ने कभी उन किसानों की चिंता की ? यही कहते रहे कि हमें सरकार में आने दो, 300 रूपये बोनस देंगें, हमें सरकार में आने दो 2100 रूपये धान खरीदी देंगे। कितने साल दिये, 2100 रूपये समर्थन मूल्य, 300 रूपये बोनस इसी का नतीजा है कि 15 में आ के लटक गये हो। गनीमत है कि इधर वाले नहीं होते तो 5 में आ जाते।

माननीय सभापति महोदय, आज ये पहली कांग्रेस की सरकार है, माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार, उन किसानों को हिम्मत दिखाते हैं जहां ज्यादा वर्षा होती है तो किसान नुकसान में रहता है, जहां वर्षा नहीं होती तो किसान नुकसान में रहता है आज उन किसानों को लाभ मिला है। 10 हजार करोड़ का कर्ज माफ हुआ है। इतनी बड़ी हिम्मत मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है, इतना बड़ा साहस अगर कोई सरकार दिखा सकती है तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार दिखा सकती है। बाकी इधर तो सिर्फ सपना दिखा सकते हैं उसके सिवाए कुछ नहीं है और इससे कितने किसानों का फायदा हुआ ? लगभग 20 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा और तो और हमने किसानों का कर्ज माफ किया। माननीय अजय चन्द्राकर जी बड़े-बड़े दावे किये थे किसान का कर्ज माफ हो जाए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। हम आपका इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं एक इस्तीफा दे देंगे तो आप लोग 14 हो जाएंगे, आप और कम हो जाएंगे इसलिए आपका इस्तीफा रहने दीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर किसी सरकार ने साहस किया है तो कांग्रेस की सरकार ने इतनी बड़ी राशि में कर्ज माफ करने का साहस किया है, वह भी तीन घण्टे में निर्णय लिया। एक के अंदर पैसा उनके खाते में जाना चालू हो गया। ये कांग्रेस सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति है और उसके बाद हमारी सरकार ने वायदा किया था कि कर्ज माफ करेंगे और किसानों का समर्थन मूल्य 2500 रूपये भी देंगे। 2500 रूपये समर्थन मूल्य, वह भी एक साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए देने के घोषणाएं की हैं। हमने तो इनकी सरकार को देखा है पिछले 15 सालों से, 10 साल सदन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के बाहर से देखा हे, 5 साल सदन के अंदर से देखा है। चुनाव से पहले एक साल बचा रहेगा, तो ये समर्थन मूल्य और बोनस देने की कोशिश करते हैं। बाकी 4 सालों में किसानों के लिए क्या होता है ?

श्री भीमा मण्डावी :- माननीय बैज जी, सरकार इधर नहीं है। सरकार उधर है। आप उधर दिखाईये।

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापति महोदय, मैं पिछला वाला याद दिला रहा हूँ।

श्री भीमा मण्डावी :-आप वह पिछला छोड़िए।

श्री दीपक बैज :- माननीय भीमा मण्डावी जी, आप भी पिछली सरकार के समय रहे हैं।

श्री भीमा मण्डावी :- मुझे लगता है कि आप पिछले टाईप का भाषण दे रहे हैं। इस बार चेंज करिये नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे।

श्री दीपक बैज :- माननीय मण्डावी जी, आपको सुनना पड़ेगा। आप जो कर्म किये हैं उसको अभी सुनेंगे। आप 15 साल झूठ बोलकर सरकार बहुत चलाये। हमारी सरकार आने के बाद कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं है। 5 साल किसानों को लाभ देने के लिए हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी की सरकार ने, हमने किसानों को 2500 रूपये समर्थन मूल्य देने की घोषणा की। मैं इनकी सरकार को देखा हूँ 270 रूपये में 30 रूपये बढ़ा दिये, 300 रूपये हो गया। मना लिये बोनस त्यौहार। फिर उसके बाद समर्थन मूल्य का त्यौहार, बिजली त्यौहार, ये लोग जितना पैसा दिये नहीं, उससे ज्यादा त्यौहार में खर्च कर लिये। ये कांग्रेस की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार है। आज 10 हजार करोड़ कर्ज माफ करने के बाद 2500 रूपये समर्थन मूल्य देने के बाद न हमने कर्जा त्यौहार मनाया, न समर्थन मूल्य देने का त्यौहार मनाया। अगर यही जगह, यही साथी होते तो कर्जा त्यौहार भी मना लेते, समर्थन मूल्य का भी त्यौहार मना लेते। उसकी जगह पता नहीं कितने करोड़ों रूपये और छत्तीसगढ़ की जनता को कर्ज में डूबा देते। ये संवेदनशील, कांग्रेस की सरकार है। पिछली सरकार में 69 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी हुई थी और इस समय हमारी सरकार वर्तमान में 85 लाख टन मीट्रिक टन की धान खरीदी हुई है वह भी कोई 5, 10 क्विंटल की सीमा नहीं रखा। जो किसान जितना आना चाहे, धान बेचना चाहे वह धान बेच सकता है और तो और उसके बाद सबसे बड़ा निर्णय ये बोलते थे कि मैं खाऊंगा, न खाने दूंगा। प्रत्येक राशनकार्ड पर 35 किलो चावल देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया, उसके लिए 4 हजार करोड़ का बजट किया है। केन्द्र में जब हमारी सरकार थी तो बहुत बड़े-बड़े दावे करती थी कि हम गांवों में जाकर चावल दे रहे हैं हम चना दे रहे हैं चावल, चना, दारू वाले बाबा, सब बाबा हो गये, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 किलो चावल से 35 किलो चावल किया।

श्री शिवरतन शर्मा :- दीपक जी, अब दारू वाले बाबा बदल गये हैं। दारू वाले बाबा वही बैठते हैं, जहां पहले बैठते थे। पहले से कोचिये बढ़ गये हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री दीपक बैज :- दारू वाले बाबा अभी भी उधरी हैं, लेकिन अभी वह भूतपूर्व हो गये हैं।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- वर्तमान वाले इधर आ गये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा, यह बताईये, हमारी दारू पालिसी के खिलाफ बहुत बोलते थे, उसी पालिसी को क्यों एडाप्ट कर रखे हो ?

श्री दीपक बैज :- अभी दारूबंदी के दो कदम की ओर बढ़ रहे हैं।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- भाई साहब बढ़ते-बढ़ते 5 साल हो जायेंगे।

श्री दीपक बैज :- आप तो 15 साल बीता दिये, अभी तो हमारी सरकार को सिर्फ 50 दिन ही हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, चावल वाले बाबा, दारू वाले बाबा, चना वाले बाबा, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35 किलो चावल की घोषणा करने के बाद कोई बाबा नहीं हैं, वह आज भी किसान के बेटा हैं। इधर छोटा सा काम करते हैं, बाबा बन जाते हैं।

श्री सौरभ सिंह :- अब एडवांस वाले बाबा हो गये हैं।

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापति महोदय, यह कांग्रेस सरकार की दृढ़ इच्छा है। कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार आयेगी तो बिजली बिल आधा करेंगे, बिजली बिल का फायदा किसानों, हितग्राहियों को देंगे। अगर यही इनकी सरकार होती तो चुनाव से 6 महीने या एक साल पहले फायदा मिलता। हमारी सरकार ने सिर्फ 50 दिन में काम करके दिखाया है। 400 यूनिट तक विद्युत-व्यय भार पर आधी छूट का लाभ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को देने के लिए बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे बड़ा निर्णय कोई हो सकता है। छत्तीसगढ़ की सरकार देश की पहली सरकार होगी जहां इतना बड़ा निर्णय हुआ है। पिछले 5 सालों से हम लोग गिड़गिड़ा कर थक गये, मांग कर, चिटठी लिख कर थक गये, कितने कागज खत्म हो गये, कितने लेटर चले गये, कम से कम विधायक निधि बढ़ा दो लेकिन विधायक निधि नहीं बढ़ाया। आज हमारी सरकार ने किसानों का कर्जा भी माफ किया, किसानों को 2500 रुपये समर्थन मूल्य भी दिया और आपके लिए 2 करोड़ रुपये भी दिया है। (मेजों की थपथपाहट) किसी सरकार में इतना बड़ा निर्णय हो सकता है। हम लोग जब विधायक निधि बढ़ाने की मांग करते थे तो कहते थे कि पहले किसानों का काम करेंगे, किसानों की खेती-किसानी में सूखा हो गया है, पानी ज्यादा गिर गया है। हमारी सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया है, शिवरतन भैया आपको धन्यवाद देना चाहिए। जब आपका भाषण का समय आयेगा, आप धन्यवाद दीजिए। यह हमारी सरकार के निर्णय हैं। 5 नये फूड पार्क प्रांरभ करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- किस-किसमें धन्यवाद देना है, उसकी एक सूची बनाकर मेरे को दे देना। हम पटल पर रखवा देंगे।

श्री दीपक बैज :- आप उसी के लिए धन्यवाद दे दीजियेगा। माननीय सभापति महोदय, 5 नये

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

फूड पार्क बनाने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आश्रम एवं छात्रावासों में रहने वाले प्री-मेट्रिक स्तर के अनुसूचित जाति-जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिष्यवृत्ति की राशि 900 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये, पोस्ट मेट्रिक छात्रों की भोजन सहायता की राशि 500 रुपये से 700 रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। लगभग 70 हजार मध्यान्ह भोजन रसोईयां पिछले 15 साल से मांग-मांग कर थक गये, हमारी से कम से कम 1200 रुपये से ज्यादा मानदेय तो बढ़ा दीजिए, तीन-चार महीना हड़ताल में बैठे, लेकिन इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी थी। आज हमारी सरकार ने हिम्मत दिखाते हुए उनके मानदेय को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का निर्णय लिया है, शिवरतन भैया, जब आप बोलेंगे तो उसके लिए भी धन्यवाद दे दीजिए।

मानमीय सभापति महोदय, सिंचाई कर भी माफ कर दिया। छत्तीसगढ़ के किसानों को गंगरेल, नहर, डेम से पानी लेने के लिए लाठी खाना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने सिंचाई कर नहीं दिया, इसलिए इनकी सरकार ने कभी उनको पानी देने का काम नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद सिंचाई कर का 207 करोड़ रुपये उनका भी माफ किया है ।

श्री सौरभ सिंह :- रबी फसल में आप पानी दे रहो हो, उसकी धान खरीदी की व्यवस्था भी करवा देना।

श्री दीपक बैज :- उसके बाद 1700 रुपये समर्थन मूल्य में मक्का खरीदी का निर्णय हुआ है। हमारी सरकार ने निर्णय किया है बस्तर में 105 करोड़ का सबसे बड़ा मक्का प्लाण्ट बनेगा, वह भी हमारे कोण्डागांव के माननीय विधायक मोहन मरकाम जी के यहां बनेगा।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों की बात हो रही थी। हमने बहुत करीब से देखा है कि बस्तर की सड़कों की क्या हालत है। दिन को सड़क बनती है और रात को सड़क उखड़ जाती है, ये हालत इनकी सरकार की रही। कौन ठेकेदार थे ? इनके मंत्रियों के करीबी, रिश्तेदार, चहेते ठेकेदार थे और बस्तर में सड़क बनाने के लिए रायपुर से भेजते थे। सड़क बनती थी, सिर्फ मिट्टी और डब्ल्यू.बी.एम. का काम होता था। जब बी.टी. का काम होता था, इनके लोग छोड़कर भाग जाते थे। क्यों ? क्योंकि पैसा मिट्टी, डब्लयू.बी.एम., बी.टी. में नहीं हैं। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद 1565 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रधानमंत्री सड़क के लिये हुआ है और वह भी बनकर रहेगा । (मेजों की थपथपाहट) उसी तरह से मुख्यमंत्री सड़क के लिये 238 करोड़ का प्रावधान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपये किया गया है । मुख्यमंत्री कन्या विवाह सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने चालू किया था । इन्होंने 15 साल चलाया । 15 हजार रूपये में क्या हालत रही ? इधर शादी हो रही है, कोई मापदण्ड नहीं । उधर बाप बैठा है और एक बेटा को लेकर शादी कर रहा है । पता नहीं वह कौन सी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

शादी है मुझे नहीं मालूम ? श्री भीमा मण्डावी जी, आप हंस रहे हैं। आप उससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं ।

श्री भीमा मण्डावी :- मैं इसलिये हंस रहा हूं कि उसमें आप भी तो शामिल नहीं थे ?

श्री दीपक बैज :- हमें लग रहा है कि वैसे ही आपको भी कराना पड़ेगा । माननीय सभापति महोदय, इनके शासनकाल में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह में एक छोटा सा ड्रम, एक डब्बा लेकर दे देते थे और दोनों दुल्हा-दुल्हन लेकर जाते थे और उसके बाद 1 हजार रूपये का चेक देते थे वह भी नहीं मिलता था । श्री शिवरतन भैया, अब हमारी सरकार ने 25 हजार रूपये की व्यवस्था की है जब उसकी बात आयेगी तो आप उसके लिये भी धन्यवाद दे देना । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, जगदलपुर एवं बिलासपुर के लिये मल्टी स्पेश्यलिटी अस्पताल । जगदलपुर की क्या हालत है ? हमारे बस्तर में छोटा सा एक हेड इंजूरी हो जाता है तो केवल जगदलपुर को रिफर सेंटर के नाम से जाना जाता है । आज हमारी सरकार ने हिम्मत करके मल्टी स्पेश्यलिटी सुपर अस्पताल के लिये 22 करोड़ का काम हुआ है, निश्चित रूप से बस्तर के लोगों का काम होगा और बस्तर के लोगों का ईलाज होगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप जरा यह बता दीजिये कि यह 22 करोड़ रूपये कितने हॉस्पिटल के लिये है ?

श्री दीपक बैज :- 22 करोड़ रूपये मल्टी स्पेश्यलिटी अस्पताल और दो अस्पतालों के लिये, जगदलपुर और बिलासपुर के लिये...।

श्री शिवरतन शर्मा :- हो जायेगा ?

श्री मोहन मरकाम :- साहब अभी तो शुरूआत है ।

श्री दीपक बैज :- श्री शिवरतन भैया, अभी शुरूआत है । आप देखते जाईये । उसके बाद लौहण्डीगुड़ा में टाटा स्टील प्लांट, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, महत्वपूर्ण बिंदु है । लौहण्डीगुड़ा स्टील प्लांट मेरा क्षेत्र है । मैं उसी गांव से आता हूं, उसी क्षेत्र से आता हूं । 10 गांव प्रभावित हैं । 1707 किसान प्रभावित हैं, किसानों की 1764 हैक्टेयर जमीन गयी । वर्ष 2006 से इनकी सरकार ने आदिवासियों की जमीन को छीनने की कोशिश की । हम मांग करते रहे कि आप आदिवासियों की जमीन मत छीनिए । हम मांग करते रहे कि आप टाटा स्टील प्लांट दूसरी जगह लगाईये क्योंकि यह घनी बस्ती है । आदिवासी बस्ती है, यहां की खेती अच्छी है, जमीन अच्छी है लेकिन इस सरकार ने कभी नहीं सुना । बंदूक की नोंक पर इन्होंने उस जमीन को हड़पने का काम किया और जब टाटा वापिस हुई तो जमीन वापसी के लिये लगातार हमने इसी सदन में इस सरकार के सामने गिड़गिड़ाते रहे, किसानों की जमीन वापिस कर दो क्योंकि उनको खाद-बीज नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है और न ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है लेकिन अगर इस सरकार को किसानों की चिंता होती तो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निश्चित रूप से उन किसानों की जमीन वापिस करते । लास्ट में मौखिक रूप से बोल रहे हैं मुआवजा वापिस कर दो और आप जमीन ले लो, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, मैं माननीय राहूल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बस्तर की सभा में कहा, बस्तर की जनता और उन किसानों को कहा कि हमारी सरकार आयेगी तो हम नि:शर्त किसानों की जमीन वापिस करेंगे । आज देश का पहला राज्य है, देश का पहला ऐसा उद्योग है जिसे स्वयं सरकार ने अपनी इच्छा से वापिस किया है । आज मुख्यमंत्री जी पूरे देश के लिये उदाहरण बन गये हैं। आज पूरा देश सीख रहा है कि छत्तीसगढ़ में जमीन कैसे वापिस हुआ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे किसानों की जमीन वापिस करने के लिये, श्री शिवरतन भैया आप उस किसान से जाकर पूछ लीजिये कि आपकी जमीन वापिस हुई, आपको कैसा लग रहा है ? किसान आपको बतायेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- वह जमीन तो उनके कब्जे में थी ही । किसानों के कब्जे में जमीन थी ।

श्री दीपक बैज :- किसके कब्जे में थी, कोई कब्जे में नहीं थी । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- इस सदन में कई बार चर्चा हुई है । उस जमीन में किसानों का कब्जा था ।

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापति महोदय, वे किसान तरशते थे, धान बेचने के लिये तरशते थे । जाति-निवास के लिये तरशते थे । वे किसान सरकारी योजनाओं के लाभ के लिये तरशते थे । उन किसानों का नया पट्टा आपने फिर दोबारा बनाकर दिया और वह कांग्रेस की सरकार ने दिया है इसके लिये भी श्री शिवरतन शर्मा जी आप धन्यवाद दे दीजिये । माननीय सभापति महोदय, सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना । सुपेबेड़ा में जब किडनी रोग से पूरे लोग मर रहे थे, वहां का जन-जीवन अस्त-व्यस्त था । आपकी सरकार, आपके स्वास्थ्य मंत्री थे । कभी जाने की हिम्मत नहीं किये, लोकसभा में बात उठी, दिल्ली की सरकार में बात उठी, दिल्ली में भी इनकी सरकार थी लेकिन उन लोगों के लिये क्या हुआ ? 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की । लेकिन हमारे मंत्री माननीय टी.एस.बाबा ने जाकर देखा और उसी का नतीजा है आज 2 करोड़ रूपए पानी के लिए दिया गया है और वहां अस्पताल खोलने की घोषणा की, ताकि सुपेबेड़ा के लोगों को फिर से किडनी के रोगों से पीड़ित न होना पड़े ।

सभापति महोदय, इन्होंने तेंदूपत्ते का रेट 2500 रूपया किया तो उसके लिए तेंदूपत्ता बोनस त्यौहार मना लिया । अरे, धन्यवाद दीजिए 4000 रूपया करने के बाद भी हमने त्यौहार नहीं मनाया । मुझे अच्छे से याद है जब बीजापुर में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है तो वे गांव की एक महिला को चप्पल पहनाते हैं, जबरन का नौटंकी करने के लिए । गांव की महिला को चप्पल पहनाया और कहा कि देखिये हमने गांव की महिला को चप्पल पहनाया, यह बहुत खुश है । दूसरे दिन प्रधानमंत्री

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दिल्ली पहुंचते हैं तो वह महिला पेंशन मांगती है । वह कहती है मुझे चप्पल नहीं, पेंशन चाहिए। 2500 से बढ़ाकर 4000 करने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया, शिवरतन जी जब बोलेंगे तो उसके लिए भी धन्यवाद दे देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं तो बोल रहा हूं कि किस-किस बात के लिए धन्यवाद देता है उसकी सूची दे दो ।

श्री दीपक बैज :- मैंने आपको बता दिया है कि किस किस बात के लिए धन्यवाद देना है । मैंने पिछले पांच साल इस सदन में रहकर देखा है । इनका बजट आता था तो कहते थे गांव का बजट गांव में, इमली के पेड़ के नीचे का बजट है । उस बजट का क्या हुआ । पूर्व मुख्यमंत्री सदन में नहीं हैं, इनके मुख्यमंत्री विधायकों से वन टू वन चर्चा करते थे ।

सभापति महोदय :- अब समाप्त करें ।

श्री दीपक बैज :- दो मिनट लगेगा । इनके मुख्यमंत्री जी चर्चा करते थे, क्या चाहिए आपको बताइए । हम लिस्ट लेकर जाते थे तो उसमें से एक काम भी नहीं होता था। हमने वह बजट भी देखा है । इन्होंने हाफ पैंट पहनकर डंडा घुमाने का काम किया । आपका विकास हुआ फुलपैंड पहनकर डंडा घुमाया फिर भी बोलते हैं बदलापुर की राजनीति । सभापति महोदय, यह बजट किसानों का बजट है । यह बजट छत्तीसगढ़ के ढाई करोड जनता का बजट है । मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना को ध्यान में रखकर बजट रखा । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाए गए बजट पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । यह बजट छत्तीसगढ़ प्रदेश को पीछे ले जाने वाला बजट है । इस बजट में माननीय अजय चन्द्राकर जी जिस बात को बोल रहे थे मैं उन बातों को आगे ले जाउंगा । इस बात में कहीं भी ग्रोथ की बात नहीं है । इकोनॉमिक्स का मुख्य सिद्धान्त यह है कि बजट को ग्रोथ इन्डयूज करना चाहिए। यह बजट कहीं पर भी ग्रोथ इन्डयूज नहीं कर रहा है । सभापति महोदय, जो बजट है पिछले 2018-19 में 6.08 प्रतिशत ग्रोथ की ये बात कर रहे हैं । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब यह बजट समाप्त होगा तो 5.5 प्रतिशत से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी । बजट में ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे जीडीपी में ग्रोथ आए । सभापति महोदय, अगर जीडीपी की ग्रोथ नहीं आएगी तो यह दावे के साथ कहता हूं और यह प्रजातंत्र का सिद्धान्त है कि अगर जीडीपी की ग्रोथ नहीं आएगी तो सरकार बाहर होगी । यह पूरे भारत में, भारत के सभी राज्यों में और विश्व के प्रजातंत्र में यह देखा गया है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल यहां राज किया तो एक बार 12.63 प्रतिशत की ग्रोथ रेट था, तब सरकार बार-बार, बार-बार आ रही थी । उस ग्रोथ रेट के आधार पर पूरे प्रदेश में एक

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

खुशहाली थी । सभापति महोदय, धीरे-धीरे ग्रोथ रेट डाउन हुआ । पिछली सरकार में भी ग्रोथ रेट डाउन हुआ । तरह तरह की बातें होंगी जनघोषणा पत्र आया, यह आया, वह आया । उसका बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक सिद्धान्त था कि पिछली सरकार में, पिछले तीन सालों में ग्रोथ रेट धीरे धीरे स्लो होने लगी ।

श्री दीपक बैज :- सौरभ भैया, पिछले 15सालों में ग्रोथ रेट....।

श्री सौरभ सिंह :- दीपक जी, मुझे बोलने दीजिए बहुत टेक्नीकल मामला है । मुझे बोलने दीजिए। मेरा निवेदन हे, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, इसको सुनिये ।

श्री मोहन मरकाम :- सौरभ जी, हम लोग भी थोड़ा बहुत वित्त के जानकार हैं, ग्रोथ रेट कहां गया, यह हमको पता है साहब ।

श्री सौरभ सिंह :- मैं आपको आंकड़ों के साथ बता दूंगा, आप बैठिये ।

श्री मोहन मरकाम :- आंकड़े हमारे पास भी हैं । 10 सालों का आंकड़ा मैं भी लेकर चलता हूं, ऐसी बात नहीं है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- कांग्रेस पार्टी को भी अर्थशास्त्र आता है।

श्री सौरभ सिंह :- आंकड़ों के साथ बता दूंगा किस साल कितनी ग्रोथ हुई थी 2010 में 12.63 प्रतिशत ग्रोथ रेट हुई थी, वह छत्तीसगढ़ की पीक ग्रोथ रेट थी। छत्तीसगढ़ उससे ज्यादा आज तक ग्रोथ रेट अचीव नहीं किया है। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। मैं आपको आग्रह कर रहा हूं। अगर ग्रोथ रेट धीरे-धीरे कम होती गई तो सरकार बाहर चली जायेगी। यह पूरे प्रजातंत्र का इतिहास है और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब सरकार बनी तब 8 हजार करोड़ रूपये का बजट था। 2013 में 72 हजार करोड़ रूपये का बजट हुआ। उसी ग्रोथ रेट की मैं चर्चा कर रहा हूं। पैसा सरकार के पास आ रहा था। ग्रोथ रेट थी तो ग्रोथ रेट के कारण बजट का साइज बढ़ रहा था तो खुशहाली थी और सरकार फिर से वापस आ रही थी । मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले 5 सालों में 2013 से 2018 के बीच में बजट की ग्रोथ रेट 82000 करोड़ का बजट, 83000 करोड़ का बजट, 84000 करोड़ का और और अब 90000 करोड़ में पहुंच गया। हम वहीं पर थे और यह 90000 करोड़ रूपये का जो बजट आया है उसमें जो हमारी राजस्व की आमदनी है 79000 करोड़ ही है। बाकी लोन से आयेगा। तो हमने कहां ग्रोथ किया? हम तो कर्जा ही ले रहे हैं न और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। बिहार में जाइए आज की क्राइसल की रेटिंग में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट बिहार में है और बिहार की ग्रोथ रेट के कारण नीतिश कुमार जी बार-बार चुनाव जीतकर आ रहे हैं। आप उड़ीसा जाइए और देखिए कि कैसे वे ग्रोथ रेट मेंटेन कर रहे हैं? ये सरकार से संबंधित अधिकारी बैठे हैं और मंत्री बैठे हैं। एक बार जाकर देख लें कि उड़ीसा में कैसे ग्रोथ रेट मेंटेन हो रही है? उस ग्रोथ रेट के आधार पर सरकार बार-बार लौटकर आ रही है। हमारे

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ की ग्रोथ रेट धीरे-धीरे नीचे गिरती जा रही है और आज हम 10 से भी नीचे चले गये हैं और एक समय था जब हम पहले तीन या चार राज्यों में होते थे। उसके बाद हमारी पर कैपिटा इनकम मार खायी है । आज जो बात चल रही है। 17 परशेंट हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है जो जी.डी.पी. है 17 परशेंट है एग्रीकल्चर और 47 परशेंट इंडस्ट्री है और 35 परशेंट सर्विस है, कुल 82 परशेंट। इस बजट में मैक्सिमम एलोकेशन अगर किसी के लिए है तो एग्रीकल्चर के लिए है। किसान के लिए है। मैं इसका विरोध नहीं करना चाहिता। किसान के लॉट के लिए अच्छी बात है।

श्री मोहन मरकाम :- हमारे साथ उत्तराखण्ड राज्य बना था छत्तीसगढ़ के साथ । वहां का जी.डी.पी. 11.09 परशेंट है। सिक्किम का 13 परशेंट है। हमारे साथ बना था। हमको मात्र ढाई साल मिला था। 15 साल आपकी सरकार थी तो जी.डी.पी. का क्या हश्र है। आप लोगों को पूरा पता है।

श्री सौरभ सिंह :- सिक्किम की जो मैंने बात कही थी। सिक्किम की ग्रोथ रेट भी इनको बताना चाहूंगा। सिक्किम में आज एक सरकार 32 साल से इसी ग्रोथ रेट के भरोसे राज कर रही है । जो ये उत्तराखण्ड की बात कर रहे हैं, मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूं कि सिक्किम में एक ही सरकार है, जो 13 साल से राज कर रही है यदि ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। 82 परशेंट जो हमारे राज्य का जी.डी.पी. है, जो हमारे राज्य का सेक्टर है वह सर्विसेस और इंडस्ट्री से आता है और सर्विसेस और इंडस्ट्री का सेक्टर है, उसके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है, तो आप ग्रोथ रेट कहां से लाएंगे ? कैसे आगे बढ़ेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय सभापति महोदय, आप भी जानते हैं कि 15 साल में जी.डी.पी. कम होने का और पिछले 3-4 साल से कम हो रहा था, उसका कारण क्या है ? लोगों की परचेसिंग पावर कम हुई है। आप यह बात मान रहे हैं। अभी हम लोगों ने बोनस दिया, 2500 रूपये किया तो 80 प्रतिशत लोगों को फायदा हुआ। उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। अगर उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो इकॉनामिक फ्लो बढ़ेगा कि नहीं। आप यह बता दीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- आप परचेसिंग पावर बढ़ा रहे हैं। आप ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं। आपका जी.डी.पी. का आंकड़ा कहां जाएगा, आप बजट के बाद देख लीजिएगा।

श्री उमेश पटेल :- सर्विस सेक्टर आपका बढ़ेगा। क्योंकि आप जैसे ही परचेसिंग पावर बढ़ाएंगे, सर्विस सेक्टर आगे बढ़ेगा और सर्विस सेक्टर जैसे ही बढ़ेगा, हमारे जो इकॉनामिक फार्म हैं, उसमें सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा पार्ट है और अगर सर्विस सेक्टर बढ़ेगा तो आपकी इकॉनामी भी बढ़ेगी। आपका जी.डी.पी. भी बढ़ेगा।

श्री सौरभ सिंह :- आप एक साल बाद इस पर चर्चा करेंगे। अभी 5 साल है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम मरकाम :- आप भी रहेंगे और हम भी रहेंगे।

श्री सौरभ सिंह :- एक साल बाद इस पर चर्चा करेंगे । आप मेरा बजट भाषण देख लीजिएगा और आप अपना बजट भाषण देख लीजिएगा।

श्री उमेश पटेल :- मैं आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

श्री सौरभ सिंह :- बिल्कुल।

श्री मोहन मरकाम :- सौरभ साहब, हम आपके साथ पक्का चर्चा करेंगे।

श्री सौरभ सिंह :-एक साल बाद बैठें या 5 साल के लिए। 5 साल के लिए आप हो और 5 साल के लिए हम यहां पर बैठे हैं। चर्चा करेंगे 5 साल बाद क्या होगा करके?

सभापति महोदय :- अपनी बात जारी रखें माननीय सौरभ सिंह जी।

श्री बृहस्पत सिंह :- सौरभ सिंह जी आपको बता दूं पिछले बार हम लोग जब आये थे तो लोगों ने कहा 57 लोग नहीं थे उसमें से हम लोग आये थे। इस बार पता चला कि हम लोग आये तो 90 लोग में से सिर्फ 30 लोग पुराने बचे हैं 60 लोग जो नहीं थे, वे आये हैं। इसलिए कौन रहेगा कौन नहीं बाद की बात है, अभी चर्चा करेंगे।

श्री सौरभ सिंह :- बृहस्पत सिंह जी, मैं तो 5 साल अंत की बात कर रहा हूं। आप मेरी बात को नहीं समझे। सदन जब लास्ट बजट में जायेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। चुनाव में कौन जीतकर या हारकर आयेगा, यह ऊपर वाला तय करेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला तय करेगा।

श्री सौरभ सिंह :-ऊपर वाला, नीचे वाला तय करेगा जो बात है उसको सुन लीजिए। आपके ऊपर से बात जा रही है।

श्री मोहन मरकाम :- साहब सुन रहे हैं, सुन रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 साल सिर्फ हमारा राजस्व घनत्व का बजट आया। रेवेन्यू माइनस बजट था । जब सन् 2000 से 2003 तक आपकी सरकार थी, तब भी रेवेन्यु मायनस बजट था। चलिये हम मान सकते हैं कि नया राज्य बना था, उसमें बहुत सारी विसंगतियां थी। इस बार जो रेवेन्यु मायनस बजट आया है, वह छत्तीसगढ़ के 18 साल के सरकार में सबसे बड़ा रेवेन्यु मायनस बजट है। तो आज हम कहां पर जा रहे हैं, इस को देखने की जरूरत है। अगर आपके पास राजस्व नहीं आयेगा, तो खर्चे की पूर्ति करने के लिए आपको कर्जा लेना पड़ेगा और कर्जे की कहानी अजय चन्द्राकर जी सुना रहे थे कि कितना कर्जा कितने प्रतिशत में कैसे-कैसे लिया जा रहा है। रोज पेपरों में आ रहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप, चन्द्राकर जी और कहानी नहीं सुन पाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सौरभ सिंह :- आज जो कर्जा लिया जा रहा है, आज हम जो कर्ज ले रहे हैं, उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए हमारा इन्टरेस्ट बर्डन बढ़ते जा रहा है। 45 सौ करोड़ रूपये का इन्टरेस्ट बर्डन है। हम इस साल कहीं भी पुराने लोन को चुकाने के लिए व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इन्टरेस्ट सर्विसिंग कर रह हैं। मेरी आशंका है कि हम धीरे-धीरे कहीं डेब्ट ट्रेप की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। कर्जा को चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा और इन्स्टरेस्ट को चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। डेब्ट की ओर यह सरकार तो नहीं बढ़ रही है, यह प्रदेश तो नहीं बढ़ रहा है ?

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, हम लोग 2004 में थे तो लगभग चार सौ करोड़ रूपये सरकार के खजाने में था। जब 15 साल रमन सिंह की सरकार थी, 45 हजार करोड़ रूपये छत्तीसगढ के ऊपर कर्ज है।

सभापति महोदय :- मरकाम जी, बैठिये। कृपया सहयोग करें।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, हम आर0बी0आई0 से कर्जा ले रहे हैं। करीब-करीब 12 हजार करोड़ रूपये के कर्ज पर आ गए हैं। आगे कैसे चलेगा ? आर0बी0आई0 का जो क्रेडिट सिस्टम है, उसमें हमने 12 हजार करोड़ रूपये का कर्ज ले लिया है। 60 दिन में 5 हजार करोड़ रूपये और ले लिया है। करीब-करीब 10 हजार करोड़ रूपये ले चुके हैं। जैसा कर्ज बढ़ रहा है, हमारी क्रेडिट रेटिंग नीचे जाते जा रही है। रेट आफ इन्टरेस्ट बढ़ता जा रहा है। अभी हम 8.5 प्रतिशत पर आ गए हैं, 8. समथिंग पर लिया जा रहा है। आप इसके पहले का कर्जदेख लीजिये, वह 7. समथिंग पर है। जब बजट का कान्टम इतना है, कर्ज का इतना कान्टम है तो एक-एक पाईंट परसेंट रेट पर फर्क होगा। अभी 15 दिन पहले आर0बी0आई0 ने .25 प्रतिशत रेपो रेट कम किया है। लेकिन हमको कर्ज जिस रेट पर मिल रहा है, वह ऊपर बढ़कर मिल रहा है। क्योंकि हमारी रेटिंग गिर रही है। जब हमारी रेटिंग गिरेगी तो हमको ज्यादा ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा। इससे फिर सरकार के ऊपर इन्स्टरेस्ट बर्डन बढ़ना चालू हो जायेगा। माननीय सभापति महोदय, यदि आज हम कर्ज ले रहे हैं तो इन्स्टरेस्ट देना पड़ेगा। उसके साथ-साथ इस्टेबिलिसमेंट एक्सपेन्डीचर की बात कर रहे थे। वित्त सचिव के संबोधन पत्र में यह है कि वर्ष 2017-18 में 5,26,751 कर्मचारी थे, जो 2019-20 में बढ़कर 5,58,568 कर्मचारी हो जायेंगे।

सभापति महोदय :- श्री सौरभ सिंह जी, 10 मिनट हो गए हैं। समया का ख्याल रखिये।

श्री सौरभ सिंह :- 31,777 लोग अतिरिक्त आयेंगे और उसमें 18,076 करोड़ रूपये इस्टेबिलिसमेंट एक्सपेन्डीचर सिर्फ सैलरी का पैसा देना पड़ेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

3:18 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ0 चरण दास महंत) पीठासीन हुए)**

मान्नीय अध्यक्ष महोदय, अगर सैलरी का पैसा देना पड़ेगा तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि सैलरी का क्या हो रहा है, सरकार कैसे चल रही है, सरकार के सिस्टम कैसे चल रहे हैं, लोअर लेवल पर क्या करप्शन है, किस तरह से पब्लिक परेशान है, मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा। परन्तु आज इस तरह से सैलरी बंटेंगी, यदि आज हम सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी के बाद उसमें पेंशन का भी कम्पोनेन्ट भविष्य में आयेगा। जब पेंशन का कम्पोनेन्ट भविष्य में आयेगा2018-19 में 4,604 करोड़ रूपये पेंशन का कम्पोनेन्ट है, वह 2029-30 तक 20,785 करोड़ रूपये हो जायेगा। हम हमारे छत्तीसगढ़ को क्या भविष्य देंग ? हम सिर्फ 20 हजार करोड़ रूपये का पेंशन देंगे। हम इस आधार पर चल रहे हैं। सैलरी और पेंशन मिलाकर इस बजट का 33.54 प्रतिशत राजस्व खर्च सिर्फ सेलरी और पेंशन में जा रहा है। यह किस धरा से कार्य चल रहा है।

मान्नीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रोथ की चर्चा कर रहा था। ग्रोथ को इन्डयूज करने वाले सिस्टम हैं, जो सिंचाई विभाग है, हमारे ग्रामोदय मंत्री जी बैठे हैं, जहां से इम्प्लायीमेंट जनरेशन हो सकता है, उस पर कोई ज्यादा विशेष बात नहीं कही गई है। अनइम्पलायीमेंट जनरेशन के लिए क्या किया जायेगा ? अनइम्पलायीमेंट जनरेशन के जो सेक्टर्स हैं, इम्पलायीमेंट एक्सपेन्डीचर एग्रीकल्चर में हो सकता है। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए जो एलोकशन है, वह एलोकशन सिर्फ बोनस पर है, एलोकशन केपिटल एक्सपेन्डीचर के ऊपर नहीं है। सिर्फ ऋणी एक्सपेन्डीचर के ऊपर है। जब सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा, सिंचाई के लिए एलोकेशन बढ़ेगा, तब एग्रीकल्चर की ग्रोथ आयेगी । अंत में एक बात बोलना चाहूंगा कि सरकार जब तक अपना राजस्व बढ़ाने की तरफ प्रयास नहीं करेगी, तब तक सारी बातें खोखली हैं । अंत में हमको राजस्व बढ़ाने की बात करनी पड़ेगी चाहे माईनिंग हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एक्साईज हो, चाहे फारेस्ट हो, चाहे स्टाम्प ड्यूटी हो, चाहे डायवर्सन टैक्स हो, सारी चीजें और राजस्व तब बढ़ेगा, जब ग्रोथ आयेगी । अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो राजस्व बढ़ेगा और ग्रोथ इंड्यूस करने के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है । दूसरी चीज, अंत में बोलूंगा कि जो ग्रोथ होगी, आज बहुत बड़ी लिस्ट हम पढ़ रहे हैं कि राज्य में 22 पीएसयू हैं, 26 पीएसयू है, उन पीएसयू में हमने पैसा लगाया है और पीएसयू में कितना रिटर्न आ रहा है, उस रिटर्न का क्या हिसाब-किताब है ? छत्तीसगढ़ स्टेट ब्रेवरेज कारपोरेशन शराब में नुकसान, शराब के सिस्टम में नुकसान । इस चीज पर हम चल रहे हैं, जब तक हम रेवेन्यू जनरेशन की बात नहीं करेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो भविष्य है, जो ग्रोथ का भविष्य है, वह मुझे बहुत अंधकारमय दिख रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- श्री केशव प्रसाद चन्द्रा । 10 मिनट में अपने क्षेत्र और जिले से संबंधित ज्यादा बात रखें ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट में पूरे प्रदेश की बात रख देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- मत करिए न, बाद में कर लीजिएगा ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, मैं बजट की थोड़ी व्यावहारिक बात रखूंगा । 10 मिनट पर्याप्त समय है और आपकी कृपा रहेगी तो 5 मिनट बढ़ा देंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसानों की चिन्ता की, कर्ज माफ किया और उन्होंने अपनी चुनाव घोषणा-पत्र में 25 सौ रूपये क्विंटल धान का मूल्य देने का वादा किया था, उसको पूरा किया । उसके लिए निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के किसान की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये बजट आंकड़ों का मायाजाल है, यह केवल एक कागज का पुलिंदा है । अगर वास्वतिक पर हम जाएंगे तो आज बजट पर जो प्रावधान रखे गए हैं, वह न तो साल भर में पूरा होने वाला है, न पांच साल में पूरा होने वाला है । इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिछली बार मैं चुनाव जीतकर आया, पहली बजट पर मेरी मांग पर सड़क स्वीकृत की गई । क्षेत्र में गए, खूब माला पहने, खूब गाजा बाजा हुआ, खूब स्वागत हुआ । पांच साल निकल गए, पांच साल के बाद फिर जब हम वहां वोट मांगने गए तो पांच साल तक वह सड़क नहीं बनी थी । कारण, जमीन का मुआवजा अभी भी लंबित है इसलिए ये तमाम बजट केवल आंकड़ों का मायाजाल है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक का कर्ज माफ कर दिया, अभी आपने बजट पर 4 हजार करोड़ का प्रावधान व्यावसायिक बैंक के लिए रखा हैं । पिछले समय भी हमने मांग की थी कि तमाम प्राईवेट सेक्टर के बैंक, जो सरकार की अनुमति से संचालित हैं, । वहां भी किसान, चलिए आप शार्ट टर्म के लोन की बात कर रहे हैं तो उसमें भी किसानों ने लोन लिया है, उनके लिए भी आप प्रावधान लाईए और ऐसे किसान जिनके पास जमीन नहीं है, अधिया से, ठेका से खेती करते हैं, जो आज भी सेठ-साहूकार के चंगुल में फंसे हैं । उनके लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा राहत की जरूरत उन किसानों को है, बड़े किसानों की अपेक्षा छोटे किसानों को ज्यादा राहत की आवश्यकता है, लेकिन उनके लिए सरकार ने कहीं प्रावधान नहीं किया । न वे धान बेच पाएंगे क्योंकि उनका जो है, पंजीयन नहीं हुआ है, उनके पास जमीन नहीं है और आज आप 25 सौ रूपये क्विंटल समर्थन मूल्य पर तो दे रहे हैं, लेकिन कितने धान पर आप 25 सौ रूपये दे रहे हैं । केवल 14 क्विंटल 80 किलो पर और 14 क्विंटल 80 किलो के बाद अगर किसान अपने धान को बेचने के लिए ले

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जा रहा है तो उसके लिए मंडी विभाग खड़ा है, खाद्य विभाग खड़ा है, तहसील विभाग खड़ा है, वे धान की जप्ती कर रहे हैं । सरकार बता दे कि किसान के उत्पादन को बेचने के लिए टैक्स कहां लगता है, लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि हर चौक-चौराहे पर खड़ा होकर किसान के धान की जप्ती बनाई जा रही है, उसको थाने पर खड़ा करवाकर उनके धान को जप्ती की जा रही है ।माननीय अध्यक्ष महोदय, औसत उत्पादन हम और आप जिस जिले में है, प्रति एकड़ 30 से 35 क्विंटल अभी पहुंच गया है । 14 क्विंटल 80 किलो आप खरीद रहे हैं, बाकी को आप कहां बेचेंगे ? आज उसी धान को सेठ साहूकार लोग 1200-1300 रूपये में खरीद रहे हैं । हम तो उसी स्थिति पर आ गये । 14 क्विंटल को हमने 2500 रूपये में बेचा, बाकी धान को हम 1200-1300 रूपये क्विंटल पर बेच रहे हैं । आप किसानों की आय को दोगुना करने की बात कर रहे हैं । यह केवल आंकड़ों का मायाजाल है । माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रति व्यक्ति आय 96,887 रूपये बताया गया है । ग्रामीण अंचल का ऐसा कौन सा व्यक्ति है, जिसकी आय 96,887 रूपये है ? हो सकता है, उद्योगपति का होगा ? हो सकता है बड़े किसान का होगा ? हो सकता है, शराब माफिया का होगा ? लेकिन आज आम किसान वहीं पर है । माननीय अध्यक्ष महोदय, 35 किलो चावल प्रति कार्ड देने का प्रावधान इस बजट में किया गया है, लेकिन इसमें उन कार्डों का उल्लेख नहीं है, जिसमें बिना बताये, बिना कारण के राशन कार्डों को काट दिया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज भी दावा कर रहा हूँ कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में, प्रत्येक महीना, पांच से दस-दस राशन कार्ड कट रहा है । हितग्राही दुकानदार के पास जा रहा है, क्यों कट रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है । हितग्राही कलेक्टर के पास आवेदन लेकर जा रहा है, उसका कहीं कोई निराकरण नहीं है । आप एक तरफ दे तो रहे हैं, दूसरी तरफ आप छीन भी रहे हैं, ऐसे में लोग कैसे उम्मीद करेंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली बिल को 400 यूनिट तक हाफ किया गया है, लेकिन हमारा जो लाईन लॉस हो रहा है, 30 प्रतिशत से ऊपर हमारा लाईन लॉस हो रहा है । बिजली की चोरी हो रही है, अगर लाईन लॉस और चोरी को हम रोकें, आप तमाम यूनिट को जो है, आधे दाम पर देंगे, तब भी सरकार जो है, फायदे पर रहेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ट्रेनिंग पर दिल्ली गया था । वहां पर सरकार ने अपना बिजली बिल आधा किया है । वहां जो प्रेजेन्टेशन दिये, हाफ करने के बाद भी सरकार को फायदा है । जबकि पूरे दर से ले रहे थे तो भी सरकार घाटे पर चल रहा था । फायदा होने का कारण वही है । उन्होंने लाईन लॉस को रोका और बिजली की चोरी को रोका । एक तरफ हम बिजली बिल हाफ कर देंगे, दूसरी तरफ हमारा लाईन का विस्तार बढ़ गया, सब स्टेशन बढ़ गया, हर गांव में ट्रांसफार्मर बढ़ गया, कन्ज्यूमर बढ़ गया, लेकिन जब कर्मचारी की बात करें, तो जहां 20 कर्मचारी थे, वहां 5-6 कर्मचारी बचे हैं । मैन्टेनेंस कैसे होगा, सुविधा कैसे मिलेगा, किसी गांव में अगर लाईट बंद है तो एक-एक सप्ताह तक बंद है, ऐसे हाफ करने का कोई औचित्य नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, रसोईयों के ऊपर सरकार ने

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सहानुभूति दर्शाया है । लेकिन कैसी सहानुभूति, पंडाल मत लगाओ, माईक मत लगाओ, आपको भी हमने कुछ दिया, 1200 रूपयें के जगह में 1500 रूपये कर दिये हैं । 1500 रूपये महीने में एक रसोईया दिन भर में कैसे काम करेगा, कैसे वह अपने परिवार को चलायेगा, कैसे वह ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम करेगा ? वह कैसे वहां चावल की चोरी नहीं करेगा ? कैसे वहां दाल की चोरी नहीं करेगा ? कैसे वह ईमानदारी और निष्ठापूर्वक हमारे बच्चों को खाना खिलायेगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि विकास के लिए 21,597 करोड़ का सबसे बड़ा बजट है । बहुत बड़ा बजट है । पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कृषि के लिए बड़ा बजट रखा था, क्योंकि यह कृषि प्रदान प्रदेश है । लेकिन चूक कहां पर हो रहा है, योजना अच्छी है, आप किसानों को सब्सीडी दे रहे हैं, लेकिन उन सब्सीडी का क्या मतलब, 75 प्रतिशत सब्सीडी पर हम स्प्रिंकलर ले रहे हैं, वह खाली बाजार में जाकर, मार्केट में 25 प्रतिशत राशि लेकर जा रहे हैं तो उससे बेहतर कंपनी का स्प्रिंकलर हमको मिल रहा है । 75 प्रतिशत की राशि कौन खा रहा है, यह राशि कहां जा रही है, जब तक इस व्यवस्था पर सरकार अंकुश नहीं लगायेगी, जब तक प्रत्यक्ष रूप से किसानों को लाभ नहीं मिलेगा, बजट बढ़ाने का और सब्सीडी दंने का कोई औचित्य नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद, बीज और दवाई की गुणवत्ता पर बोलना चाहूंगा। चाहे कृषि विभाग हो या बागवानी विभाग हो जो भी दवाई, बीज और खाद दे रहे हैं वह अनुपयोगी है। इसलिए अनुपयोगी है क्योंकि वह यहीं से खरीदी होकर जा रहा है। प्रदेश में खरीदी हो रही है और सभी जिला में ले जाकर उसे किसानों को बांट रहे हैं जबकि बागवानी विभाग में प्रावधान है कि आपको किसान को प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ राशि देना है। किन्तु वह राशि न देकर दवाई, खाद और बीज देते हैं। किसान के लिए भी है कि जितने प्रदर्शन हैं उसमें आपको राशि देना है लेकिन आप राशि नहीं देंगे, इसलिए राशि नहीं देंगे क्योंकि आप राशि देंगे तो बाकी का बीच का जो हिस्सा है 75 प्रतिशत, जिसका यहां खेल चल रहा है वह 75 प्रतिशत राशि उनको देना पड़ेगा। आवश्यकता है तो सही प्रबंधन और निष्ठा और भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन की आवश्यकता है। जिस दिन भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बन जायेगा, अधिकारी-कर्मचारी लोग ये समझ जायेंगे कि इसी तनख्वाह से हमको काम करना है, बाहर का हमको एक पैसा नहीं मिलना है। अगर बाहर का एक पैसा लेंगे तो हमको जेल जाना पड़ेगा, उस दिन किसान का समग्र विकास होगा और किसान को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा जिला 85 प्रतिशत सिंचित है लेकिन यह कागज और रिकार्ड पर है। वास्तव में नहीं है और नहीं होने का कारण नहर की सही मरम्मत नहीं होना, पानी का अपव्यय होना है। आप मुख्य कैनाल को देख लीजिए। मेन कैनाल से जितनी क्षमता से पानी जाना चाहिए उतनी क्षमता से पानी नहीं जा रहा है। तो आप जो एरीगेटेड एरिया तय किये हैं, जो कमांड एरिया आप तय किये हैं, जब मुख्य कैनाल पर ही आप पूरी क्षमता से पानी नहीं देंगे तो आपका टार्गेट

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एरिया कैसे पूरा होगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत से गांव- देवगांव, बरपाली, बासीन, डोमा, अचरितपाली, अमलीडीह, अमेराडीह, भूतहा, भड़ोरा, बरभांठा, पिरदा, मिरौनी, नरियरा, मरघट्टी, भातमाहू, लालमाटी, भनेतरा, पिसौद, बरेकेलखुर्द, खरझिट्टी, बोईरडीह, रींवाडीह, अमलीडीह, हरदीडीह, करऊआडीह, मुरलीडीह, खम्भारडीह, सलनी, मलनी, भोथिया में जब से नहर बना है तब से एक बूंद पानी नहीं गया है लेकिन सिंचाई विभाग का नोटिश हर साल किसान के पास जाता है। हर साल सिंचाई विभाग इन गांवों को सिंचित क्षेत्र घोषित करते हैं। हर साल बोलते हैं कि हम पानी दे रहे हैं लेकिन इन गांवों में जहां नहर नहीं बनी है वहां पानी जा पाना कैसे संभव है? ये सरकार जब इधर बैठती थी तो प्रधानमंत्री फसल बीमा की आलोचना करते थे कि हम बीमे की किस्त तो देते हैं लेकिन उसका लाभ किसानों को नहीं मिलता। लेकिन इस बार भी सरकार ने 316 करोड़ रूपये प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए प्रावधान रखा है। यह हमारी समझ से बाहर है।

अध्यक्ष महोदय, गांव की छोटी-मोटी आवश्यकता से गांव के लोगों का विकास होगा। कहीं सी.सी. रोड है, कहीं नाली की व्यवस्था है, कहीं मुक्तिधाम का निर्माण है, कहीं निर्मला घाट का निमा्रण है और ये तमाम काम मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना से होते थे किन्तु उसमें मात्र 200 करोड़ रूपये रखा गया है? आप लोग तो पिछले समय असंतुलन की बात कर रहे थे कि मंत्री जी जहां चाहते थे वहां बांट देते थे। अब आपके मंत्री जी चाहेंगे तब भी अपको नहीं बांट पायेंगे। तो कम से कम ऐसी जगहों पर जहां आम लोगों की आवश्यकता पूरी होती है वहां तो कम से कम बजट को बढ़ाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार कुपोषण की संख्या बढ़ रही है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित हैं चाहे रेडी टू ईट की बात करें या गर्भवती महिला को गर्म भोजन की बात करें, चाहे मुर्रा-लाडू की बात करें। ये तमाम योजनाएं हैं किन्तु इन तमाम योजनाओं का संचालन सही ढ़ंग से नहीं होने के कारण उनको गुणवत्तायुक्त पोषक आहार नहीं मिल पा रहा है। आज आप व्यावहारिक तौर पर जाकर देख लेंगे, जो रेडी टू ईट लेते हैं उसे खाली जाकर जानवर को खिलाते हैं और कोई बच्चा उसे खाता नहीं है क्योंकि उसमें गुणवत्ता नहीं है। और यदि सैंपल के लिए भेजते हैं और गुणवत्ता खराब आ भी जाती है तो उस समूह के ऊपर कोई काईवाई नहीं होती। कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि वह समूह उसका संचालन करने के लिए प्रतिमाह एक मोटी राशि उन अधिकारियों को देते हैं। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपका आदेश होगा शिरोधार्य है। ये छत्तीसगढ़ राज्य जब हम लोगों का बना, तो छत्तीसगढ़ राज्य को मात्र 5 हजार करोड़ का बजट होता था, जहां से हमारी छत्तीसगढ़ की शुरूआत होती है और छत्तीसगढ़ में 3 साल हमारी सरकार रहने के, जब कांग्रेस के लोग छोड़ के जाने लगे, सरकार के खजाने में हम लोगों ने 600 करोड़ छोड़ के गया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

था। सरकार चलाईये, भाजपा के लोंगों को ये जिम्मा मिला था। जब 15 साल इन लोगों ने सरकार चलाया, जब हम लोग वापस आये, 15 साल बाद, 45 हजार कर्जे के साथ इन लोगों ने हमको सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी है जो बड़ी चिंता का विषय है। आज छत्तीसगढ़ में कोई भी जन्म लेता है तो, 15, 17 साढ़े सत्रह हजार रूपये कर्जे के साथ जन्म लेता है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बृहस्पत जी, बहुत खड़े होते हो, थोड़ा सुन भी लो। आज जब इधर थे न तो अपने मन से पढ़ लिख के बोलते थे, वो 45 हजार जो कर्जा है न वो लिख के आया है, वही लोग कर्जा लिये थे, थोड़ा सुनो टाईम कम है श्री दीपक बैज जी बोले हैं उनके समर्थन में बोल के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ये बोल दो।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, थोडा़ सा सुनने का हिम्मत जुटाइये। बहुत बोले हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए। इनसे समय कटौती किया जाए। ये 45 हजार कर्जे के साथ हम लोग को जिम्मेदारी दिये है। इसके बाद भी आज जो 90 हजार करोड़ का बजट आया है और इस बजट में उन लोगों का सबसे पहले खयाल रखी है छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो अन्नदाता हैं। जो लगातार पांच साल बैठकर ये कहते थे, इनके मंत्री इधर से जवाब देते थे, इतने किसानों ने आत्महत्या किया, दारू पी के मर गये, किसी ने कुछ कहा, ये आप लगातार मजाक उड़ाते थे उन किसानों को सम्मान देने का काम किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ की माननीय श्री भूपेश बघेल की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये किसानों के कर्जा माफी होने से पता नहीं क्यों हमारे साथियों के पेट में दर्द जोने लगा है। किसने मना किया था कि मत माफ करो, आपको तो छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल सरकार चलाने को दिया था। आपको किसने मना किया। अध्यक्ष महोदय, उसके पहले मुझे याद है, एक बाद इन लोगों ने कर्जा माफी का काम किया था।

श्री केशव चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, तो ये आप हर साल करेंगे क्या कर्जा माफी।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सुन तो लीजिए, कर्जा माफ तो इन्होंने कर दिया और आदेश कर दिया कि बैंक के खाते से कांट दिया, बजट में प्रावधान तक नहीं किया। मुझे याद है, सहकारी बैंकों के सिस्टम ये है कि गवर्नमेंट सिर्फ गारंटी देती है। नाबार्ड रिजर्व बैंक से हम लोग कर्जा लेते हैं और उसको किसानों के ऊपर फायनेंस करते हैं, उसको बढ़ा के जो ब्याज की रकम होती थी उससे संस्था चलती थी, वो भी बैंक डिफाल्टर हो गई। नतीजा ये हुआ कि हमने छत्तीसगढ़ में दो सहकारी बैंक संचालित किया, एक लांग टर्न का एक साट टर्न का। जो किसानों को 2 तरह का कर्जा देती थी। वे सारे बैंक बंद हो गये, इनको 15 साल के अंदर बैंको को मर्ज करना पड़ा। ये हाल इन्होंने किये हैं और बड़े लंबे लंबे भाषण दिये जा रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी विडंबना है, इन्होंने धान का 2100 रूपये का बड़ा लंबा लंबा भाषण दिया, जनता ने इन भरोसा भी कर ली, और इन्होंने ऐसा पाला झाड़ा कि चिल्लाते रह गये

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ की जनता, किसान और हम सारे लोग लेकिन एक न सुनी, और जब यहां आएं तो विपक्षी सरकार ने तय कर दिया किसानों के धान की कीमत तो बड़ा पेट में दर्द होने लगा।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, किसके पेट में कैसा दर्द हो रहा है। कौन डायगनोसिस किया दर्द को, मेरे पेट में तो नहीं हो रहा है दर्द।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, जिनके पेट में दर्द होता होगा वे बार बार खड़े हो के सफाई देने लगे।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरे पेट में तो दर्द नहीं हो रहा है, जबर्दस्ती क्यों बोल रहे हो। आप बताओ नाम ले के किसके पेट में दर्द हो रहा है। मेरे पेट में नहीं हो रहा है दर्द।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, जो विरोधी होंगे उनके पेट में हो रहा होगा दर्द।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, देखो पहले आप बाला करते थे तो आपकी स्पीड मेल की रहती थी, लेकिन आज पैसेंजर पर आ गए हैं और अगले सत्र तक बैलगाड़ी की स्पीड में आ जाओगे, यह तय है । हम लोगों ने आपके स्वाभाविक स्वरूप को देखा है और उसके बाद मंत्री नहीं बन पाओगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह प्रभार हमने आपको 5 साल सौंपा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग डिस्टर्ब मत करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन हम लोगों के पेट में दर्द हो ही नहीं रहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारे किसान पानी मांगने जाते थे। डण्डा चलता था और किसानों को पानी न देकर, उद्योगों को पानी दिया जाता था और उस समय जब हम लोग विरोध करते थे तो पता नहीं, इनको बड़ी तकलीफ होती थी मैं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने किसानों को पानी देने का भी तय किया है और 2500 क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव में जब बिजली का बिल जाता है तो गांव के लोग डर जाते थे कि फिर से इतना बिजली का बिल आ गया। मेरे क्षेत्र के कुछ ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने बिजली, पहले नाम सुनते थे कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से बिजली लग रही है, बाद में पता चला कि उसमें बोर्ड लगना चालू हो गया, दीनदयाल विद्युतीकरण योजना, क्या कुछ ऐसा नाम इन लोगों ने रखा। ये नाम बदलने का भी काम कर रहे हैं और वहीं ये हाल था कि तार तो खींचा नहीं था खम्भे गड़े थे, मीटर घर भर लग गये। बिजली बिल आना चालू हो गया। जब हम लोगों ने सदन में मामला लाया, माननीय उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी थे। वे जवाब देने लगे तो कहने लगे कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तार मैंने नहीं खींचा, उसके बाद भी 2 सालों तक बिल आता था। ऐसे बिजली को चालू करके उनके घर में कनेक्शन देकर और बिजली बिल को हाफ करने का काम हमारी सरकार ने किया है तो उससे पता नहीं हमारे विपक्ष के साथियों को क्या तकलीफ हो रही है? मैं तो कहता हूँ कि आप इसका समर्थन करना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कांग्रेसी हैं क्या ? आप कांग्रेसी हैं या नहीं हैं ? आप घोषणा पत्र पढ़े हैं ? आप ये बताईये?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इनको एक बीमारी हो गई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कांग्रेसी हैं या नहीं हैं ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी बीमारी का...

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय बृहस्पत सिंह जी, आपको बधाई हो, आपके भाषण को सुनकर, अजय चन्द्राकर जी सो रहे थे वह अचानक से खड़े हो गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कांग्रेसी हैं या नहीं हैं ? ये बताईये ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेसी हूँ या नहीं, इसका प्रमाण पत्र आपको देने की जरूरत नहीं है। ये जनता ने आपको दे दिया है।

श्री दीपक बैज :- ये बताना जरूरी है क्या ?हमें सर्टीफिकेट देना पड़ेगा क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप घोषणा पत्र पढ़िये, बिजली बिल हाफ कहां है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 400 यूनिट तक का, आपमें तो उतनी भी हिम्मत नहीं हुई साहब।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप घोषणापत्र पढ़ लीजिए, वह तो नहीं हुआ, इसलिए हम आये हैं, आप उसको छोड़िए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समय कम है। जल्दी करिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षमा करियेगा। मेरे समय से कटौती न की जाए। क्योंकि इन्होंने छेड़कर समय बर्बाद किया है। अनुसूचित जन जाति के गरीब बच्चे गांवों में सरगुजा, बस्तर में रहते थे और अजजा विभाग के सारे स्कूल संचालित थे और उन 3 हजार स्कूलों के गरीब बच्चें, जो उन स्कूलों में पढ़ते थे। उन स्कूलों को इन लोगों ने बंद कर दिया और हमारे गरीब बच्चे पढ़ाई से वंचित रह गये। ऐसा इन्होंने काम किया है जिसकी सजा, इनको 15 सालों में 15 सीटों पर जनता ने पहुंचा दिया और मैं आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि जो दुर्भावनावश उन स्कूलों को बंद कर दिया गया। उन स्कूलों को भी खोलने के लिए आग्रह चाहूंगा कि सरकार को ऐसा सुझाव दिया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जाये, आपसे प्रार्थना है और मैंने 4-5 महीने चुनाव के पहले देखा कि पूरे रायपुर के सभी जिला मुख्यालयों में नारे लगते जा रहा था तो मैंने देखा, वे लोग ये नारा लगा रहे थे कैसी ये बेशर्मी है, शिक्षक ठेका कर्मी है ऐसा लोग नारेबाजी कर रहे थे। मैंने कहा कि भईया क्या हो गया? मैंने तत्कालीन माननीय पंचायत मंत्री आदरणीय चन्द्राकर जी को बताया कि साहब मैंने ऐसी नारेबाजी देखी, लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं आया। मैंने कहा कि अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो मैंने पंचायत मंत्री जी से कहा कि जनता उत्तर दे देगी, मुझे ऐसा लगता है और उस जनता ने उत्तर दे भी दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय,इसलिए इनके शासनकाल का बता दूं मैं थोड़ा सा समय लूंगा। आउट सोर्सिंग के माध्यम से शिक्षाकर्मी, शिक्षकों की भर्ती की गई और 25 हजार रूपये प्रति शिक्षक के मान से ठेकेदारों को दिया जाता था और ठेकेदार हमारे ही छत्तीसगढ़ के लड़कें जो शिक्षा मितान बनकर पढ़ाते थे, उनको कितना देते थे मात्र 15 से 16 हजार रूपये देते थे। मतलब 9 से 10 हजार रूपया महीना, कंपनी और तत्कालीन सरकार मिलकर उन शिक्षकों की कमाई का कमीशन खा जाते थे इसलिए ये बातें कहने में बड़ा बार-बार खड़े होने का काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय,जहां तक धान की बात है अभी कुछ साथियों ने कहा, मैं खुद किसान हूँ जब हाईब्रिड और आधार बीज, प्रमाणित बीज आने के पहले, जब हम लोग गांव का धान लगाते थे तो 6 से 10 क्विंटल होता था जब ये हमारा प्रमाणित बीज आया, आधार बीज आया तो आई आर 64-36 आये तो तब 12 से 15 क्विंटल हम लोग कमाने लगे, 15 से 20 क्विंटल और जब हाई ब्रीड का जमाना आया तो आज भी हम लोग पैदा करते हैं तो बहुत खराब हुआ तब भी 15 नहीं तो 28 क्विंटल तक पैदावार होती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी भी पैदा करते हैं?

श्री बृहस्पत सिंह :- जी साहब, धान पैदा करते हैं, आपके जैसे बाकी कुछ और नहीं हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, वह तो अभी भी पैदा कर रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय चन्द्राकर जी, आपको क्या संदेह है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बधाई हो, अभी भी पैदा कर रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो फैसला किया है, इनको टोकने का काम है, हमारा समय उधर काउंट कर लिया जाये। जब मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब से कांग्रेस पार्टी ने किसानों को 5 एच.पी. तक के मोटर पंप पर छूट दे रखी थी। यह सरकार आते ही सारा बंद कर दिया। किसानों के साथ इतना हीं नहीं बंद किया, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, आपके गांव में बिजली है, आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। सौर ऊर्जा से कनेक्शन लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योकि आप जो 1 लाख 25 हजार रुपये की छूट देते थे उसको भी इस सरकार ने बंद

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कर दिया था। क्योंकि अगर आप सौर ऊर्जा से सब्सिडी लेंगे तो 5 लाख तक मिलेगी, लेकिन इन्होंने सवा लाख की छूट को बंद कर दिया। और तो और अगर किसान अपने ही खेत में ट्यूबवेल करना चाहे तो बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं कर सकेगा, ऐसा आदेश भी जारी हो गया। इस तरह से लागू किया हुआ था। अभी सरकार ने राहत दी है, आपसे अनुरोध है कि इस पर पूरा शिथिल करवाया जाये ताकि स्वतंत्र रूप से अपने खेत में स्वयं के खर्चे से भी बोर कर सकें और पंप कनेक्शन में किसानों को सवा लाख रुपये का अनुदान मिलता था उसको पुन: चालू कराया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत छोटा निवेदन है दवाई लगातार कमीशनखोरी की भेंट चढ़ती रही, आज भी सरकारी अस्पताल में जाईये, अब कुछ सुधार हो रहा है, सिर्फ रिफर करने शिवाय कुछ नहीं रह जाता है, उस पर और सुधार करने की जरूरत है। पिछली दफा हम लोगों ने देखा था बाजार में जो दवाईयां 20 पैसे, 30 पैसे में मिलती थीं और हमने आर.टी.आई. में जो जानकारी निकाली है उसमें देखा कि उसकी सरकारी खरीदी 10 रुपये प्रति गोली के हिसाब से हुई है। तभी मैंने कहा कि सरकारी अस्पताल में ईलाज कराने के लिए जाते हैं तो लोग क्यों ठीक नही होते हैं। ये बड़ा अजीब सा मामला है।

श्री अमरजीत भगत :- अचय चन्द्राकर जी सरकार में नहीं हैं, उसकी तरफ देखकर मत बोला करें, अध्यक्ष जी की तरफ देखें।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी अस्पतालों का यह बिल है, इनके समय में जितना हमारा बजट है, उसका बहुत ज्यादा पैसा निजी अस्पतालों को दिया गया है। मेरा आग्रह है कि सरकारी अस्पताल में ही व्यवस्था कराई जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत नहीं कहते हुए एक ही निवेदन करूंगा कि ये जो बार-बार सदन में छेड़ते हैं, इस पर कुछ करिये, यह मेरा आग्रह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- बृहस्पत सिंह जी, विपक्ष में बोलते थे तो मजा आता था या अभी पक्ष में बोल रहे हैं तो मजा आ रहा है?

श्री बृहस्पत सिंह :- पक्ष या विपक्ष में रहें पता नहीं क्यों यह इतना ज्यादा छेड़ते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, चतुर्थ विधानसभा की अभी एक किताब बंटी है, सदस्य जिनके 12 बच्चे हैं, वह एक मात्र हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या यहां जनगणना का हिसाब हो रहा है?

डॉ.(श्रीमती) रेणु अजीत जोगी (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। सबसे पहले जो बात हुई है हमारे प्रदेश के किसान भाईयों के लिए धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है, उसका तो मैं स्वागत करती ही हूं। पर ये भी कहना चाहूंगी कि इस बजट में प्रावधान करना चाहिए कि जो इतना धान

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

का उत्पादन हो रहा है, विगत 18 वर्षों से धान खरीदी केन्द्रों में धान खुले में पड़ा रहता है। समय-असमय वर्षा होती है, उसकी सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान इस बजट में नहीं रखा गया है। मैं सदन का ध्यान आपकी तरफ से आपकी ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि कुछ ऐसा प्रावधान करें कि इसमें गोदाम बनाने की व्यवस्था जोड़ें ताकि भविष्य में जो काफी धान नष्ट हो जाता है, वह न हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के बारे में जरूर बोलना चाहूंगी क्योंकि मेरे पूरे क्षेत्र में अरपा नही बहती है। और प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई योजना अरपा-भैंसाझार वहां निर्माणाधीन है। शुरू में उसका बजट लगभग 6 अरब था परंतु अब बढ़कर वह 11 अरब 40 लाख पिछले बजट में हो गया था और इस बार 127 करोड़ रूपया और उसके लिये दिया गया है । इसकी शुरूआत सन् 2013 में हुई थी पर लगता है मुझे 5 साल तक अभी भी लगेगा कम से कम क्योंकि नहरें उसमें जो बननी थी करीब 125 किलोमीटर वह मुश्किल से 20 किलोमीटर बनी हैं तो मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगी कि इसमें गति लायें क्योंकि जब पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी तो मात्र एक-दो साल में ही हंसदेव बांगो का पानी खरसिया के अंतिम छोर तक पहुंच गया था तो ऐसी व्यवस्था करें कि इसको भी टाईम लिमिट के अंदर पूरा करें क्योंकि इसमें करीब 65 हजार एकड़ में सिंचाई प्रस्तावित है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग में काफी चर्चा हो चुकी है । नया सिम्स भवन क्योंकि वह मेरा गृह जिला है और हम लोग पेशेंट रिफर करते हैं तो स्थान के अभाव में, चिकित्सा के उचित अभाव में उनका जैसा ईलाज होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है । नया भवन बने तो बहुत ही अच्छा होगा और उसके लिये प्रावधान भी है लगभग 38 एकड़ का अकोनी में जगह भी आवंटित है और इसके अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा के बारे में भी यह कहना चाहूंगी कि पूर्व में त्रिवर्षीय जो पाठ्यक्रम डॉक्टरों के लिये स्वीकृत हुआ था । चूंकि यह पूरी प्रक्रिया विधानसभा के द्वारा ही पारित हुई थी और उनका संचालन त्रिवर्षीय चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने का इसी सदन के माध्यम से हुआ था तो उसे पुन: प्रारंभ किया जाये, सुदूर अंचलों में भी 80 प्रतिशत डॉक्टर वही काम कर रहे हैं । मेरे क्षेत्र के अलावा मैं समझती हूं सभी क्षेत्रों में यही स्थिति होगी तो वह इस सरकार के लिये एक अच्छा कदम होगा, अच्छी सोच होगी ।

श्री अमरजीत भगत :- भाभी जी, यह जो इंवर्सल हेल्थ स्कीम आयेगी न तो यह जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान हो जायेगा ।

श्रीमती रेणु अजीत जोगी :- देखिये कब आयेगा ? कब होगा ? थाईलेण्ड में आप लोग क्या करके आये हैं मालूम नहीं ? परंतु जो हो चुका है । आजमाये चुके को आजमाना चाहिए और विगत् सरकार ने किन्हीं कारणोंवश 96 एएनएम के जो कॉलेज थे जिसमें 16 शासकीय थे, लगभग 80 प्राईवेट थे उनको अचानक एक आदेश पारित करके संभवत: हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं उन्होंने बंद कर दिया था

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तो इस सदन के माध्यम से मैं, चूंकि अभी स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं हैं तो उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो मितानिन हैं यदि वे प्रशिक्षित हो जायेंगी । चूंकि एएनएम का कोर्स गांव की लड़कियां ही ज्यादा करती हैं, दो वर्ष का रहता है ।

श्री अमरजीत भगत :- भाभी जी, आप अभी भी श्री चंद्राकर जी को स्वास्थ्य मंत्री जी समझती हैं । (हंसी)

श्रीमती रेणु अजीत जोगी :- नहीं, मैंने तत्कालीन कहा । वर्तमान के तो नहीं हैं परंतु आप संदेश दे दीजियेगा वह आपके ही जिले के हैं तो उसको प्रारंभ कर दिया जाये तो हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि होगी ऐसा मैं मानती हूं । मैं अपने ही क्षेत्र की बात कर लूं क्योंकि समय का अभाव है । यदि इन सब मांगों को छोड़ दें । माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि एक ही बात मुझे कहनी पड़े कि सौ सुनार की और एक लोहार की तो मैं आपके माध्यम से एक ही अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारा गौरेला, पेण्ड्रा और मरवाही जो आपका भी पूर्व में क्षेत्र रहा है उसे जिले का दर्जा दिया जाये तो अपने आप काफी समस्याएं हल हो जायेंगी क्येांकि हम लोग 175 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पर स्थित हैं और छोटी-छोटी बातों के लिये बिलासपुर जाना पड़ता है तो यह सबसे प्रमुख मांग है । इसके अलावा पर्यटन की मेरे क्षेत्र में अपार संभावना है । अमरकंटक, रतनपुर, अचानकमार टाइगर रिजर्व का दोनों छोर मेरे क्षेत्र में है । इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं समझती हूं चूंकि रेल्वे स्टेशन भी लगा हुआ है । हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी इस पर विचार करेंगे । धार्मिक नगरी रतनपुर है । अनेकानेक श्रद्धालु वहां आते हैं । मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि जितना कार्य या जितनी राशि रतनपुर के विकास लिए अन्य क्षेत्रों के लिए आवंटित की जाती है । वह राशि नहीं मिलती है । वहां माघी पूर्णिमा का आदिवासी मेला लगता है, जिसे स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला जी ने प्रारंभ किया था । 4-5 दिनों के बाद माघी पूर्णिमा आने वाला है। वह 7 दिवसीय मेला है, उसके लिए पहले मात्र 5 लाख की राशि दी जाती थी, फिर धीरे-धीरे वह बढ़कर 10 लाख हुई। निवेदन है उसे कम से कम 20 लाखकिया जाए । यहां तक कि रतनपुर की अधोसंरचना के लिए भी पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा कुछ विशेष योगदान नहीं मिला है । वहां एक मुक्तिधाम भी नहीं है । अभी भी खुले मैदान में अंतिम संस्कार किया जाता है ।

श्री अमरजीत भगत :- भाभी जी, विधानक निधि बढ़ी है उसके लिए तो धन्यवाद दे दीजिए ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- हां, उसके लिए तो पक्ष-विपक्ष सभी लोग धन्यवाद देता है (मेजो की थपथपाहट) । लेकिन उससे मुक्तिधाम का निर्माण नहीं कराना चाहूंगी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसे से मुक्तिधाम बनवाना है क्या ? भाभीजी मुक्तिधाम की बात कर रही हैं, तुम कहां वहां विधायक निधि ले आए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री कुलदीप जुनेजा :- मेरे यहां देवेन्द्र नगर का मुक्तिधाम पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा बना है, दिखवा लेना ।

श्री अमरजीत भगत :- हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे, विधायक निधि बढ़वाने के लिए और बिना मांगे मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा दिया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अरे कई विधायक मुक्तिधाम के उद्घाटन के लिए भी जाते हैं भाई ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- नहीं, अभी तक हम लोग उदघाटन नहीं किये हैं ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- अमरजीत भगत जी, मैं तो अभी भी संघर्ष ही कर रही हूं, पहले भी विपक्ष में थी, अभी भी विपक्ष में ही हूं । अब आप लोगों की कृपा दृष्टि रहे ।

श्री धर्मजीतसिंह :- अब क्या करेंगी भाभी । 2 तारीख तक तो हां, हां बोले, नहीं दिये तो हम लोग क्या करें (हंसी) ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- आप लोगों के आशीर्वाद से कम से कम सदन तक तो आ गई हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- भाभीजी, आप तो घोषित रूप से विपक्ष में, अमरजीत जी तो अघोषित रूप से विपक्ष में हैं । अंतर इतना ही है, हैं वे भी विपक्ष में ही ।

श्री अमरजीत भगत :- आप कहां हैं यह तो बताइए, कोप भवन में आप भी हैं?

श्री शिवरतन शर्मा :- जहां हूं, सामने हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- लेकिन अमरजीतजी आपको ऐसा नहीं करना था । भाभीजी के संग, 2 तारीख तक, इतना बड़ा धोखा, ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- धोखा देने वालों की यही गति होती है ।

अध्यक्ष महोदय:- चलिए, हिसाब किताब बाद में कर लेना ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- अभी जो छत्तीसगढ़ के विकास का मूल मंत्र, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी जो है उस दिशा में यह कहना चाहूंगी कि हमारे क्षेत्र में अपारसंभावना है । कई नदियों का उद्गम स्थल है । सोन नदी, तिपान नदी, जोहिला नदी, नर्मदा नदी तो मध्यप्रदेश में चली गई। परंतु मैं उसको भी अपना ही मानती हूं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि उसके भी उद्गम स्थानों को संरक्षण मिले । इसी निवेदन के साथ मेरी अंतिम और पुरानी मांग महिला थाने की है। हम लोग सुदूर अंचल में स्थित हैं । भवन की भी जरूरत नहीं है, वहां गौरेला में पुराना थाना भवन है । वहां यदि महिला थाना खुल जाए तो उस पूरे क्षेत्र की महिलाओं की समस्या दूर हो सकती है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद्।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 जनवरी को जब पहला अनुपूरक बजट पेश हुआ उस कहा गया कि हमारा आने वाला बजट 1 लाख 5 हजार करोड़ का होगा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

और हम भी 1 लाख करोड़ बजट वाले प्रदेशों के क्लब में शामिल हो जाएंगे । लेकिन 8 तारीख को जब बजट आया तो वह लगभग 93 हजार करोड़ का बजट और उसमें भी जो राजस्व व्यय है और जो पूंजीगत व्यय है, उसको देखने के बाद निश्चित रूप से जो पिछले 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है और जिस गति से हो रहा है इस बजट को देखने के बाद लगता है कि हम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसमें निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत पीछे जा रहे हैं। किसी भी राज्य का विकास देखने के लिए जी.एस.डी.पी. को उसका आधार माना जाता है और मानवीय संवेदनाओं का जो सूचकांक है किसी राज्य के लिए चाहे वह मातृत्व शिशु मृत्यु दर हो, कुपोषण हो चाहे फिर वह शिशु मृत्यु दर हो और यह सब लगभग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए मसले हैं और स्वास्थ्य विभाग का जो बजट है, बार-बार कहा जा रहा है कि हम अनलिमिटेड हेल्थ केयर लाएंगे लेकिन इनका अनलिमिटेड हेल्थ केयर आते-आते इस राज्य में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और हो रही हैं, जिसके कारण हमारे गांव के गरीब लोग इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दें और जो योजनाएं अभी जारी हैं, वे चलती रहें। ज्यादा बजट को छोड़कर आपका आदेश भी है कि जिले के बारे में या विधान सभा के बारे में बोलें। मैं दो-तीन विषयों पर और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रोजगार यूनिटी योजना जो मनरेगा के नाम से चलती है, पिछले कुछ वर्षों से उसका जो एफ.पी.ओ. होता है चाहे लेबर भुगतान का हो, मजदूरी भुगतान का या मटेरियल भुगतान का, उसका एफ.पी.ओ. रायपुर से होता है, जिसके कारण बहुत विलंब होता है। अभी भी जो बार-बार विषय आता है कि मजदूरों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे यदि बहुत बड़ी वजह है तो रायपुर से उसका एफ.पी.ओ. होना है तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह अधिकार जिला पंचायत को दिया जाए। निश्चित रूप से यदि जिला पंचायत में एफ.पी.ओ. होना शुरू हो जायेगा तो जो अनावश्यक कई-कई महीने तक भुगतान विलंब होता है, वह सुचारू रूप से जल्दी होगा। इसी प्रकार जो पेंशन मिल रहे हैं चाहे वह राज्य आधारित पेंशन योजना हो, चाहे केन्द्र से प्राप्त होने वाली पेंशन योजना की राशि हो, उसका भी जो एफ.पी.ओ. होता है वह उप-संचालक जिला कार्यालय से होता है, जिसके कारण महीनों तक पेंशन पाने वाले ऐसे जो बहुत वृद्ध हैं जो चल-फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों को कई-कई महीने तक पेंशन नहीं मिल पाता। इसलिए इसका एफ.पी.ओ. जनपद स्तर पर होना चाहिए तो निश्चित रूप से यह समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है। एक विषय मेरे विधान सभा बेलतरा में एक ऐसा क्षेत्र हैं, जहां के लगभग 3 हजार मतदाता हैं, वे लोकसभा के वोटर हैं, वे विधान सभा के मतदाता हैं लेकिन उनका कहीं भी ग्राम पंचायत में, नगर-पंचायत में और वार्ड में नाम नहीं है और इसके कारण वहां जो भी राशि चाहे विधायक मद का हो, सांसद मद का हो या राज्य के अन्य योजनाओं की हो राशि है जो मूलभूत सुविधा के लिए जाना चाहिए, वह नहीं जा पाता। इसलिए वह क्षेत्र

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अभी वन ग्राम है। बिलासपुर शहर के बीचों-बीच है। कोई बहुत सुदूर जगह नहीं है। एक तरफ बिल्हा विधान सभा है, एक तरफ बिलासपुर और बीच में बेलतरा विधान सभा में है। इसलिए यहां के लिए माननीय जो संबंधित मंत्री हैं, आपके माध्यम से उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उस जगह को दिखवाकर और उसका जो भी निराकरण हो, करें और बेलतरा विधान सभा के चाहे वह बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी मांग मैंने किया था, वह नहीं जुड़ पायी है। कई महत्वपूर्ण सड़क हैं, कई सिंचाई की परियोजनाएं हैं, कई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी में उन्न्यन है, हाई स्कूल का उन्नयन है, भवन की मांग है, इन्हें भी आपके माध्यम से जोड़ने का निवेदन करता हूं। आज आपने बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री लालजीत सिंह राठिया।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारा ले के हमन सरकार ला बनाय हन। येमा हमर छत्तीसगढ़ के जनता, किसान मन हा, इहां के युवा मन हा अउ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी मन हा इही नारा ला आगे बढ़ाय बर हमन बहुत ज्यादा जनोदश दे हे। एखर बर हमन छत्तीसगढ़ के जनता ला बहुत धन्यवाद करत हावन, उखर आभार व्यक्त करत हवन। आज हमर छत्तीसगढ़ मा हमर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व मा हमन आय हावन। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, ये चार चिन्हारी ला ले के हमन आय हावन। आज हमन ला जीवन का जीये बर अनाज के जरूरत पड़थे। किसान मन मेहनत करथे। अनाज ला पैदा करथे, खून-पसीना का गवाथे। आज पूरा विश्व ला भरन-पोषण करे बर अनाज के जरूरत होथे, सबो ला जरूरत होथे। आज किसान मन के हित बर हमर सरकार हा, ओमन खेती-बाड़ी करथे, कर्ज लेथे, तेला हमन माफ करे हन। हमर सरकार हा 2500 रूपया किसान मन ला धान के समर्थन मूल्य देय हे। ये भा0ज0पा0 के सरकार ठगत-ठगत आत रहिस हे, 2100 रूपया देबो, 300 रूपया बोनस देबो। लेकिन ठगत रहिस हे। ओखरे सेतिर ये मन ला, भा0ज0पा0 वाले मन ला जनता हा ठगे हे अउ हमन ला जनादेश देय हे। एखर बर जनता मन ला धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमर छत्तीसगढ़ मा सुख-शांति हे, हमर कांग्रेस के सरकार हा किसान मन के दिल ला छूये हे। पिछले बार एखर मन के सरकार रहिस हे तो एक फरमान जारी करे रहिन। अगर किसान गर्मी में धान की खेती करेगा तो हम उन लोगों को जेल भेज देंगे। उनके बिजली की लाईन को काट देंगे। पानी पर डंडा चलाय रहिस हे। किसान मन बांध के पानी मांगे गइन तो ये मन डंडा चलाय रहिन। आज हमन ओही नरवा ला सरंक्षित करे बर नरवा ला चिन्हारी देय हन कि हमन येला बांध बनाबो, पानी ला रोकबो, खेत मा पहुंचाबो, सिंचाई करबो, ऐसे कहके हमन नरवा ला, नदी नाला ला सरंक्षित करे के संकल्प हे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहिली जो सरकार रहिस तेन हा घर-घर बायोगैस लगात रहिस। जेमा हमर किसान परिवार हा अपन खाना-पीना बनाय के इंधन के व्यवस्था करत रहिन। आज हमर सरकार हा नया फिर से लागू करना चाहत हे। मोदी जी गैस बांटे रहिस हे। बड़े-बड़े पोस्टर टांगे रहिस हे। हमन चार सौ रूपया मा देवत रहेन, ये हा दो सौ रूपया मा तो देवत रहिन लेकिन हमन ला हजार रूपया पड़त रहिस हे, किसान मन ला ठगत रहिस हे। आज ओ मन ला चूल्हा नइ मिलत हे। लेकिन हमर सरकार हा किसान के घर मा गोबर के माध्यम से फ्री मा बायोगैस लगाबो। ओमा घर ले बाहर जाय के जरूरत नइ पड़य। लकड़ी जोरे बर जंगल नइ जाय बर पड़य। ओला घरे मा ही गैस मिल जाही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमर बाड़ी के विकास हे, आज हर गांव मा कुंआ हे, तालाब हे, नदी हे, नाला हे, किसान हा पंप लगा के अपन डेली के नकद आय मा वृद्धि करे बर बाड़ी के योजना है। खेती-बड़ी हे, घर मा महतारी हे, जे हा खाना-पीना बनाथे तहाले बाड़ी के बुता में लग जाथे । साग भाजी ला कामा डारौ, मसाला-मिर्चा जो भी हे । ओला करथे, तेकर बाद में ओला दो पइसा अर्जित होथे । बेचके ओला साग-भाजी, मसाला-मिर्चा, तेल खरीदथे । गांव के देहाती आदमी आन, ओकर पीड़ा ह मोला सदन में याद अईस तो ओला आपो मन ला घलो बताना चाहथौं । आज हमर ऊर्जा माने किसान मन ला फ्री में पांच एचपी पम्प के छूट देके कतेक-कतेक राशि हे, करोड़ो में हे, एमे ओ मन ला छूट देबर हमन प्रावधान करे हन कि किसान मन ला कतना-कतना बिजली बिल एमन भेज देत रिहीन हे, किसान मन परेशान रिहीन हे कि बिजली बिल ला पटाई कि खेती-बाड़ी करी, ओमन ला चिन्ता रिहिसे । किसान मन ला फ्री में बिजली कनेक्शन दे के हमर योजना सरकार मन के हे, ये बढ़िया योजना हे ।

अध्यक्ष महोदय, एक ठी बात ये रिहीसे कि हमन कइसे विकास करबो। छत्तीसगढ़ में विकास के कल्पना कहीं पर नहीं हे, कहाथें । हमर सरकार ह सड़क ला जोड़ेबर गांव ले सड़क ला जोड़ेबर अब सड़क ला रेल लाईन ले जोड़ेबर जो हे, बहुत अकन के प्लानिंग करे हे, हमर सरकार ह योजना बनाए हे । हमर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी मोला बताए हे कि हम सरकारी नौकरी पर भी सहायक प्राध्यापक के 13 सौ से ज्यादा पद का विज्ञापन जारी कर दिए हैं । पिछली सरकार में कई सालों से ये पद नहीं भरा गया था । वईसने प्रकार के आज शिक्षा कर्मियों के भर्ती के पद हैं, जो हमारे प्रदेश के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है । आज शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पिछली सरकार ने तो कई साल ले प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाईस्कूलों को जो इन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन आज हम लोग शिक्षा को बढ़ाने के लिए गांव में युवाओं को रोजगार देने के लिए 15 हजार से ऊपर पद हमारी सरकार ने वैकेन्सी निकाली है, भर्ती करने का जो निर्णय लिया है, ये पहला कदम है। कहां ये लोग दो करोड़ नौकरी देने की बात केन्द्र की मोदी सरकार बोलती थी, लेकिन आज दो लाख लोगों को रोजगार नहीं दे पाये । खाली पकौड़ा बेचने की बात करते हैं, होटल चलाने की बात करते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने शासकीय नौकरी,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

शासकीय रोजगार देने का हमने संकल्प लिया है और हमारी सरकार जल, जंगल और जमीन में वनवासी भाई है, उनको पट्टा देने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है और उसी के अनुसार प्रत्येक आदिवासी भाई जो भूमिहीन है, उनको हम लोग जमीन देंगे, ऐसा संकल्प हमारी सरकार ने लिया है । अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद ।

श्रीमती छन्नी चन्दू साहू (खुज्जी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य फसल हावे-धान, जेमे हमर छत्तीसगढ़ में किसान मन निवास करथें और खून-पसीना एक करके, धरती माता के सेवा करके अन्न ला उगाथें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार जब 15 साल ले रिहिसे तो किसान मन के चिन्ता नहीं करत रिहीसे । आज हमर मुख्यमंत्री सम्माननीय किसान माटी पुत्र ला बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहहूं कि हमर सरकार अइस और हमर किसान मन के प्रति चिन्ता करिस । किसान के दुख वही हा चिनथे, जो खेती-बाड़ी करे रहिथे । जो खेत मा हल चलाए रहिथे, खेत में धान के बीजा सीचे रहिथे अउ अपन कंधा में लादके धान के भारा ला बियारा में लाए रहिथे । बियारा में लाके कलारी ला चलाए रिहथे ! मैं छत्तीसगढ़ के पूरा किसान के तरफ से हमर मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद देना चाहूं । अध्यक्ष महोदय, मैं इही सदन के माध्यम से बताना चाहूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार रहिसे, किसान हा अपर अधिकार के लड़ाई लड़े बर सड़क में उतरिस । वही भारतीय जनता पार्टी के सरकार मन बोलेरहिस कि हमर सरकार म 2100 रूपया समर्थन मूल्य और 300 रूपया बोनस देबो । उही बात ला हमर किसान मन भारतीय जनता पार्टी मन ला सुरता देवइस, किसान मन सड़क म उतरिस, इही भारतीय जनता पार्टी के नेता मन किसान न सुते दसना ले उठाके जेल म भेजिस हावे । माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी मन लाठी अऊ गोली के बात करत रहिसे, दादागिरी करे के आरोप लगावत रहिसे । मैं हा ए सदन के माध्यम से बताना चाहूं कि तीन साल के जिला पंचायत के राजनीति में देखे ला मिलिस कि भारतीय जनता पार्टी वाले मन हमन ला कुचरे बर हर प्रकार के धारा लगाय गिस । हमर सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हा किसान मन के कर्जा ला माफ करके वोला ऊपर उठाये के कोशिश करे हावय । जब किसान सूखा से प्रताड़ित रहिसे, त इही भारतीय जनता पार्टी हा हमन ला नोटिस ऊपर नोटिस भेजे रिहिस, तेला भुलागे । ओखर ले प्रताड़ित होके हमर किसान भाई मन फांसी अरो लिन । अध्यक्ष महोदय, मे हा सदन के मध्यम से आप मनला बताना चाहूं कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हा एक नारा दे हावय- नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी । अऊ एला बचाना हेसंगवारी । नरवा ला वही जानथे जेन खेती-किसानी करथे । जेन नरवा ला हम स्टॉप डेम के माध्यम से बांध बो, पानी हा रूकहि तो जलस्तर ह बाढ़हि । जेन किसान हा बोर खनन करथे, जलस्तर जब तक नहीं बढ़ही तब तक वोमन पानी नई पाय । हमर मुख्यमंत्री जी के बहुत बढ़िया सोच हे । जौन किसान हा खेती करथे, नाला ला बांध बो तो वोहा हमला पानी दिही ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती इन्दू बंजारे ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :-अध्यक्ष महोदय, दू मिनट । मैं बताना चाहूं कि किसान मन बिजली बिल मा कतेक प्रताड़ित हे । ये सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद देना चाहूं कि 400 यूनिट के छूट दे हावय । एखर लिये पूरा मंत्री ला अऊ मुख्यमंत्री ला बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूं । आप मन मोला बोले के मौका देव, एखर लिये बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिन्द ।

अध्यक्ष महोदय :- तीन मिनट ।

श्रीमती इन्दू बंजारे (पामगढ़) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम सत्र में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसके बारे मेंतो कुछ नहीं बोलूंगी । उन शब्दों के बारे में बोलना चाहूंगी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया है और न ही बजट में उसका उल्लेख किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बजट में कहना चाहूंगी कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल 252 महाविद्यालय हैं, इसमें प्राध्यापक के 595 स्वीकृत पद हैं । इसके बावजूद भी पद रिक्त पड़े हुये हैं । मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि उन पदों को भरे और ठीक इसी तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में 49 विभाग है, उन सभी विभागों में हमारे अधिकारी, कर्मचारी के रिक्त पद हैं । उनको भी भरने की इस सदन में मांग करती हूॅं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप और हम सभी सदस्य संविधान का शपथ लेकर आरक्षण के बेस पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक जो अधिकारी, कर्मचारी के पद रिक्त है, उसमें आरक्षण बेस पर कहीं भी कार्य नहीं किया जाता तो इस सदन में आप लोगों से कहना चाहूंगी कि हम संविधान के आरक्षण बेस पर एस.सी., एस.टी. के समस्त भाईयों को, बहनों को.....

श्री अमरजीत भगत :- इंदू जी, जो आप कालेज में प्राध्यापकों के रिक्त पद के बारे में बोल रही हैं उसे भरने के लिए सरकार की तरफ से पहल हो गई है। उसके लिए सरकार को धन्यवाद दीजिए। अच्छा बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनका मेडेन स्पीच हो रहा है, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- उन्हीं को सपोर्ट कर रहा हूं, आपको खाली दूसरा दिखता है। आप अच्छा बोल रही हैं।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय भगत जी, मैं आपको बोलना चाहती हूं कि मैं जो बोल रही हूं वह आपके बजट में उल्लेख नहीं है इसलिए मैं उसे बोल रही हूं। आपके बजट में सहायक प्राध्यापक का उल्लेख है लेकिन प्राध्यापक का उल्लेख नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूं। मेरे जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में टावर लाईन वालों ने हमारे किसान भाईयों की 50 प्रतिशत निजी जमीन अधिग्रहित कर ली है लेकिन उनको मुआवजा के रूप में केवल 8-10 लाख रूपये दे रहे हैं। और जो बंजर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जमीन पड़ी रहती है उसे भी शासन ने लीज पर दे दिया है जिससे हमारे छोटे-छोटे किसान जो भूमिहीन हैं उन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए थोड़ा बहुत इकट्ठा किया था उसे भी शासन ने लीज पर दे दिया है जिसके कारण वह जमीन भी उनसे छिन गई है। मैं आपके माध्यम से इस सदन में निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे प्रत्येक किसान भाई को एक-एक डिसमिल का एक-एक लाख रूपये मुआवजा प्राप्त हो। ताकि वह अपनी दिनचर्या को बहुत ही सुविधा और आसानी से जीवन व्यतीत कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जांजगीर-चांपा में 9 विकासखंडों में चिकित्सालय विभाग में डॉक्टर और कंपाउंडर के पद रिक्त हैं। मैं आपके माध्यम से इस सदन में निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे जांजगीर-चांपा के 9 विकासखंडों में समस्त प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्रों में जो पद रिक्त हैं उसे भरने की मैं मांग करती हूं। मेरे पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भलवाही, मेऊ, कोसा, खोरसी, रसौटा, भुड़गांव, लोहर्सी, धरदेई, मेहंदी, भदरा, डोगाकोहरौद, जेवरा इन सभी गांवों में हायर सेकेण्डरी स्कूल की मैं इस सदन के माध्यम से मांग करती हूं। मेरे जांजगीर क्षेत्र में ऐसे बहुत से रोड हैं जिनकी स्थिति बहुत जर्जर है जहां हमारे भाई-बहनों को आये दिन एक्सीडेंट के कारण बहुत क्षति हो रही है तो मैं इस सदन के माध्यम से मेरे क्षेत्र के लिए - मुरली से जोगीडीपा के मध्य पुल निर्माण का कार्य, जेवरा से डिघोरा पुल निर्माण, चुरतेला से खरखोद में पुल निमा्रण, कोसा से डोंगाघाट एनीकट निर्माण, बिलारी के कंजीनाला में एनीकट निर्माण, बुंदेला के नाला में एनीकट निर्माण, मुड़पार के नाला में एनीकट, चोरभठ्ठी से पकरिया तक पक्की सड़क और भलवाही से लगरा तक पक्की सड़क की मांग करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री रेखचंद जैन (जगदलपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों की तरह कृषि प्रधान राज्य है और इस राज्य में किसानों के लिए पिछली सरकारों ने जो घोषणा की थी कि वह कृषि में जितनी मेहनत करके और अपनी जितनी लागत लगाते हैं उतना भी उनको समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा था। इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ में लगभग 309 किसानों ने आत्महत्या की और कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज बनकर पूरे सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने अपने बजट में सबसे पहले किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की और इससे किसानों को बहुत राहत मिली है। उन्होंने 2500 रूपये समर्थन मूल्य देने का जो काम किया यह भी बहुत सराहनीय है। इससे किसान बहुत खुश हैं।

हमारे बस्तर में जो स्वास्थ्य सुविधा का मामला है, वहां जनता बहुत ज्यादा परेशान थी। वहां पर सुपर सपेशियालिटी हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर की जो घोषणा की गई है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत ही बधाई देता हूं कि उन्होंने बस्तर को लेकर ये घोषणा की। उन्होंने गरीबों के लिए 35 किलो चावल की जो योजना लाई है इससे भी गरीबों को काफी फायदा मिलेगा। इसके लिए भी मैं उन्हें बधाई

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

देता हूं। इसी प्रकार 400 यूनिट तक बिजली का बिल हॉफ करने का जो निर्णय है वह भी सराहनीय है। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री डमरूधर पुजारी :- अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस भाषण में जो भी बजट छत्तीसगढ़ के विकास के नाम से लाया गया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हमारे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था, उस समय का नकल किया है। नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, येला चलाना हे संगवारी। जब 2003 में छत्तीसगढ़ बना तब कांग्रेस पार्टी ने उस समय एक जोगी डबरी बोलेते थे, उसमें आज तक पानी नहीं है। वो डबरी गांव गांव में खोद दिये हैं और किसानों की जमीन इतनी बर्बाद हुई है कि पहले उसका जोगी डबरी नहीं खोदना था। जोगी डबरी खोद दिये उसमें किसानों का जमीन बर्बाद हुआ है। दूसरी बात मेरे क्षेत्र में एक बजट आया है। सूपेबेड़ा में पानी की समस्या का है। क्योंकि मे क्षेत्र में जो बड़े हास्पिटल देवभोग में खोलवा देते, स्वास्थय मंत्री जी तो अच्छा होता। अभी स्वास्थय मंत्री जी मेरे क्षेत्र में गये थे, उसमें पानी है, उसमें डॉक्टर नहीं रहेंगे, आदमियों का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ये हमारी समस्या है और जो बड़े बड़े वक्ता लोग इस लोकतंत्र में हमारे जो चुन के आये हैं, हमारे सदस्य लोग बोल चुके हैं, मगर जब हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद, जब हम पास हो जाते हैं और पास हो जाने के बाद हमको अच्छा बोलते है, अच्छे डिग्री पाने से और जो फेल होते हैं, उसको गधा बोलते हैं। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल से थी और 15 साल में जनता का विकास, छत्तीसगढ़ का विकास, हमारे कांग्रेस पार्टी ने नकल करके इस बजट को लाया है। क्योंकि 35 किलो आलरेटी 1 रूपये किलो हमारे चावल वाले बाबा दे रहे थे, उसको भी नहीं करना था। आज हमारे युवा साथी ने बड़े बड़े घोषणा पत्र में बात किया, वादा किया ये कांग्रेस की सरकार, ...।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, जब वो चावल वाले बाबा थे तब तो ठीक था जब दारू वाले बाबा आये तो गड़बड़ा गये सब।

श्री डमरूधर पुजारी :- अध्यक्ष जी, श्री अमरजीत भगत जी, हमारी सरकार का आप नकल किये हो। पहले आपकी सरकार 2003 में थी तो आपकी सरकार का विचार था, हमारी सरकार ये नियम नहीं बनाती। आप हमारी सरकार की नकल किये हैं। ये नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, के नाम से आज पानी तक नहीं रूकता। अध्यक्ष जी, ये मेरे क्षेत्र की बात है, ये किसानों का कर्जा माफ और बिजली हाफ। ये कर्जा माफ तो किये मगर राष्ट्रीयकृत बैंक से कैसे कर्जा माफ नहीं किये। इसको भी करना था। उस समय तो बड़े बड़े बात किये कि किसानों का कर्जा तो सबको माफ कर देना था। मैंने एक प्रश्न भी लगाया था, बिजली की। बिजली ऐसी जलती है, जैसे बीड़ी से कम जलती है। एक प्रश्न आया है, उसका भी उद्धार कर देते हमारे मुख्यमंत्री जी। टेंडर लगा के 132 के.बी लगा देते, वो भी अच्छा हो जाता।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विकास को नकल करके कांग्रेस की सरकार कर रही है। लोकतंत्र में तो आना जाना रहता है, मगर अभी का बजट देखें तो हमारी छत्तीसगढ़ में विकास की गति नहीं है, क्योकि ये नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अभी अनुदान की मांग आयेगी उसमें अच्छे से तैयारी करके आइये।

श्री डमरूधर पुजारी :- अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री शैलेष पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से एक कृषि प्रधान बजट इस प्रदेश को दिया उससे हमारे प्रदेश की छवि जो पूरे भारतवर्ष में थी कि छत्तीसगढ़ धान का एक कटोरा कहलाता था, वो एक छवि सार्थक होती है। पिछले 15 वर्षों से जिस प्रकार से किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, जिसे प्रकार से किसान शोषित हो रहे थे, ये एक छवि छत्तीसगढ़ धान का एक कटोरा कहलाता था। वह एक छवी सार्थक होती है। पिछले 15 वर्षों से जिस प्रकार से किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, जिस प्रकार से किसान शोषित हो रहे थे। ये एक खुशी की लहर रही कि जो एक छवी हमारे छत्तीसगढ़ की थी उसको सार्थक हमारी नई सरकार हमारे भूपेश बघेल जी की मुख्यमंत्री जी के उसमें हुआ है ये एक बहुत अच्छा मैसेज किसानों में गया है और इसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था है, हमारे किसान भाईयों को उसका बहुत ही लाभ मिला है और एक खुशी की लहर है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त मंत्रिमण्डल का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का प्रदेश में खुशहाली लाने के लिए बजट दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री जी का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 25 हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल, 25 पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल बनाया है। ये एक बहुत जरूरी था हमारे प्रदेश में जिस प्रकार स्कूल एजुकेशन में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेश्यों है, उसको लेकर स्कूलों की अभी भी आवश्यकताएं हैं। हालांकि पिछली सरकार ने लगभग 3 हजार स्कूल बंद किये हैं ये एक विरोध की बात थी क्योंकि वहां पर काफी जनता ने विरोध किया कि स्कूलों को बंद किया गया और शराब की दुकानें खोली गईं तो हमारी सरकार ने जिस प्रकार से स्कूलों को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया और नई 40 प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला 25 और 100 हाईस्कूल ये जो उन्होंने खोलने का यहां पर बजट दिया है इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। स्कूल शिक्षा मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी जिन्होंने आज लगभग 475 कॉलेजेस गवर्नमेंट और प्राईवेट कॉलेजेस हैं जिनको मिलाकर छत्तीसगढ़ में लगभग लाखों बच्चे उच्च शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारी जरूरत प्रदेश में जो है मैं अगर बिलासपुर की भी अगर बात करता हूँ तो जितने भी शासकीय कॉलेजों में जाता हूँ तो उसमें कॉमर्स और आर्टस् में ज्यादा बच्चे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आज हमको नये कोर्सेस की जरूरत थी। ऐसे कोर्सेज जो कि रोजगार दे सकें, एक नये कोर्सेज जो कि प्राईवेट कॉलेजेस में रहते हैं। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जो नये कॉलेजेस में नये पाठ्यक्रम दिये हैं उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि हायर एजुकेशन में आज युवाओं को रोजगार देने के लिए उन्होंने नये पाठ्यक्रम खोलने की घोषणा की है। इसके साथ-साथ उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए लगभग 1384 पदों में भर्ती करने का आश्वासन दिया है आज उन्होंने यहां पर बताया कि उनका नोटिस भी निकाल दिया है तो ये ज्यादा खुशी की बात है इससे शिक्षकों की कमी पूरी होगी और शिक्षा में गुणवत्ता भी आएगी। साथ ही साथ केवल डिग्री देना ही शासन का एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसके साथ-साथ उनके अंदर कौशल का उन्नयन भी होना चाहिए तो हमारी सरकार ने रोजगार, कौशल विकास और आई.टी.आई. के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होने बढ़ावा दिया है, इसके लिए बजट दिया है, पर्याप्त बजट दिया है इससे हमारे प्रदेश में जो युवा है जो एक संगठित क्षेत्र में बच्चे पढ़ते हैं जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में और एक असंगठित क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों, दोनों ही तरफ के बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ये मैं उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिलासपुर के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 11 करोड़ रूपये दिये हैं। जो एक चिकित्सा महाविद्यालय सिम्स में बहुत जरूरत थी। सिम्स में सुधार करने की बहुत जरूरत है मैं इस बात से सहमत हूँ कि वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हमें और बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वहां पूरे जिले और संभाग से बच्चे लोग आते हैं मरीज आते हैं तो सिम्स को जितना भी हम आगे बढ़ा सकते हैं जितना बजट हम दे सकते हैं उतना अच्छा होगा। साथ ही साथ वहां पर जो बर्न यूनिट के लिए तीन करोड़ 46 लाख दिये हैं, इसके लिए भी मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि इस प्रकार की सुविधा वहां पर नहीं थी। कैंसर एक ऐसी बीमारी हो गई है इसको लेकर उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल के लिए 10 करोड़ का प्रावधान दिया है उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि बिलासपुर संभाग मुख्यालय है और संभाग मुख्यालय में स्वास्थ्य की सेवाएं जो हैं वह बहुत अच्छी होनी चाहिए और इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मैं गृहमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, मैं जेल के दौरे में गया हुआ था, मैं वहां बिलासपुर में जाकर देखा कि 1500 कैपेसिटी की जेल है, लेकिन उसमें लगभग साढ़े 3 हजार कैदी रहते हैं। मैंने उनकी स्थिति और परिस्थिति जाकर देखी और फिर मैंने उनसे कहा कि आपके पास इससे बड़ी क्षमता की जेल होनी चाहिए, फिर वहां से प्रस्ताव लेकर मैंने माननीय मंत्री जी को दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट का प्रावधान किया। ये बहुत खुशी की बात है तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कैदी भाईयों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने कैदियों को लेकर एक मानवीय दृष्टिकोण रखा, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 400 यूनिट बिजली तक उन्होंने बिजली बिल हाफ करने का निर्णय किया है इससे बिलासपुर के लोगों में बहुत खुशी की लहर है और मैं बिलासपुर की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इससे एक हमारा जो प्रदेश है जिसमें हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है और उसका लाभ हमारे प्रदेश की जनता को मिलता है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है इससे पहले भी सरकार थी,लेकिन उन्होंने ये कदम नहीं उठाया। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत -बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलोदाबाजार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो सदन में बजट पेश किया गया है जिसमें किसान के हित में चाहे वह कर्जमाफी, समर्थन मूल्य हो, विधायक निधि बढ़ाने का फैसला हो, निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है, लेकिन मैं बजट में थोड़ा सा संशोधन की मांग करता हूं। और आपके माध्यम से शासन का थोड़ा सा ध्यान बलोदाबाजार विधानसभा की ओर ले जाना चाहता हूं। बलोदाबाजार विधानसभा छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में एक ऐसी विधानसभा है, जहां सबसे ज्यादा सीमेन्ट संयंत्र हैं। 7 सीमेन्ट संयंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमेन्ट संयंत्र यहां स्थापित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कितने अच्छे तरीके से 2 हजार करोड़ रुपये की बलोदाबाजार विधानसभा से टैक्स की चोरी हो रही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- जैसे वह बताना भी चाह रहे हैं कि चोरी हो रही है तो सरकार कहां है?

अध्यक्ष महोदय :- सरकार बैठी है न। सरकार के तीन-चार प्रतिनिधि लोग बैठे हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- उद्योग मंत्री हमारे बाजू में बैठे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उद्योग मंत्री जी तो यहां बैठे हैं, वहीं से 2 हजार करोड़ वाली सारी बातों को सुन रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- तब तो वह बिल्कुल समझ जायेंगे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बलोदाबाजार विधानसभा से करीब 40 हजार टन क्लिंकर, क्लिंकर मतलब एक सीमेन्ट का ठोस रूप होता है, क्लिंकर को पीसने से सीमेन्ट बन जाती है जिसमें राज्य सरकार की जी.एस.टी क्लिंकर में भी 28 प्रतिशत है और सीमेन्ट में भी 28 प्रतिशत है। लेकिन सीमेन्ट का रेट 260 रुपये बोरी, 5400 रुपये टन है और वहीं पर क्लिंकर का रेट सिर्फ 1800 रुपये से 2000 के बीच में है। जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं इनको क्लिंकर बेचना ही नहीं है, ये लोग मनमाने तरीके से अपना रेट रखे हुए हैं। सी.एम.ए. (सीमेन्ट मेन्युफेक्चरिंग एसोशियेशन) में शासन का

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

न तो कोई आदमी है। यह लोग खुद प्रोडक्ट कर रहे हैं और खुद निर्धारण कर रहे हैं। इसलिए 28 प्रतिशत के हिसाब से पर डे 40 हजार टन छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा अन्य राज्यों में जा रहा है जिससे 4 से 5 करोड़ रुपये का प्रतिदिन राजस्व नुकसान हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आापसे निवेदन करूंगा कि इसके पूर्व की सरकार की हो सकता है कि मिलीभगत हो, मैं खुला आरोप नहीं लगाऊंगा, जो भी गलत हो रहा था, उस पर तत्काल रोक लगातार जो राजस्व का नुकसान हो रहा है उसको बचाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन्हीं सीमेन्ट प्लाण्टों के द्वारा अधिकारियों से मिलकर किसान, आदिवासी की जमीन है, बिना प्रकिया, नियम के और शासकीय जमीन को बिना शासकीय प्रक्रिया के हथिया लिया जा रहा है। इस प्रकार की जो वहां गतिविधियां चल रही हैं उसे आपके माध्यम से शासन से मांग कर रहा हूं कि इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बलोदाबाजार में डी.एम.एफ. फंड की जो राशि है, चूंकि बलोदाबाजार क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, उस डी.एम.एफ. फंड राशि का उपयोग बलोदाबाजार प्रभावित क्षेत्र में किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। श्री कुंवर सिंह निषाद।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात का और निवेदन करना चाहता हूं। वर्तमान में बलोदाबाजार जिले में जिस हिसाब से राजस्व जिला रहा है, वर्तमान बजट में बलोदाबाजार जिला उपेक्षित रहा है। मैं कुछ संशोधन की मांग करता हूं, शासन उसमें संशोधन करके बजट में सुधार करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री कुंवरसिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 तारीख को जो बजट में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया उसके संबंध में, उसके पक्ष में अपनी बातें रखना चाहता हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह स्वागतयोग्य है । जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है । जन घोषणा पत्र में किसानों की ऋण माफी एवं धान का समर्थन मूल्य 25 सौ रूपये क्विंटल देने का जो वायदा किया है उसे सरकार ने पूरा किया है ।

समय :
4.41 बजे **(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, किसानों एवं जनमानस में इसके लिये बहुत ही ज्यादा हर्ष व्याप्त है । ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों के कृषि ऋण के साथ-साथ हमारी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों द्वारा बांटे गये अल्पकालिक ऋण, कृषि ऋण को भी माफ करने का फैसला लिया है

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जिसके लिये बजट में 5 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है इससे किसानों एवं जनता में भी खुशी की लहर है । गरीब परिवार को मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत् प्रति परिवार को 35 किलो चावल देने का जो प्रावधान रखा गया है, जो वायदा किया गया है वह भी स्वागत योग्य है । घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल हाफ करने की दृष्टि से 400 यूनिट तक विद्युत व्यय भार पर आधी छूट का लाभ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को देने का निर्णय लिया गया है वह भी स्वागत योग्य है ।

मानननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग में आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के अमलों को रेस्पांस भत्ता देने के लिये 45 करोड़ 84 लाख का जो प्रावधान किया गया है उससे भी पुलिस विभाग के कर्मचारियों में भी बहुत ही ज्यादा खुशी की लहर इस बार देखने को मिली है और प्रदेश में खाद्य पदार्थ, फल-फूल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिये फूड पार्क बनाने का और जो प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है वह बहुत ही लाभकारी रहेगा । छात्रावास में रहने वाले प्रीमैट्रिक एवं पोस्टमैट्रिक विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति की राशि बढ़ाने एवं स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में खाना बनाने वाले रसोईयों के मानदेय में वृद्धि की गयी है उसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं । जहां धार्मिक आस्था का केंद्र है उस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने गिरौदपुरी, दामाखेड़ा एवं भण्डारपुरी के समन्वित विकास के लिये भी 5-5 करोड़ का भी जो प्रावधान रखा है उसके लिये मैं सम्मानित मुख्यमंत्री जी को इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा साथ ही 207 करोड़ का बकाया सिंचाई कर भी सरकार ने माफ किया है उसके लिये भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर धन्यवाद देना चाहता हूं । बालोद जिला में महिला महाविद्यालय खोलने, बौद्धिक मंदता के कारण मानसिक रूप से नि:शक्त लोगों के आजीवन आश्रम एवं सुधारात्मक सुविधा हेतु बालोद जिला में घरोंदा केंद्र की स्थापना एवं नि:शक्तजनों के लिये केंद्र की स्थापना के लिये बजट में जो प्रावधान किया गया है उसके लिये मैं बालोद जिला की ओर से और गुण्डरदेही विधानसभा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का सादर आभार करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं तथा राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिये बजट में जो अतिरिक्त प्रावधान किया है वह भी स्वागत योग्य है । साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच कि नरवा, गरूआ, घुरवा, बारी एवं गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना अब साकार होते दिख रही है इसके लिये मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं कि 15 वर्षों के बाद लगता है कि अब छत्तीसगढ़ में सुराज आया है ।

माननीय सभापति महोदय, अब लगता है कि 15 वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ में सुराज आया है इसके लिये मैं दो लाईन आपको सादर समर्पित करना चाहता हूं कि-

लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ।
नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है
नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है
चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है ।
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है ।
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ।
संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम

चूंकि शायद अभी माननीय अजय चंद्राकर जी नहीं हैं ।

संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम
कुछ किये बिना ही किसी की जय-जयकार नहीं होती ।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । धन्यवाद ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय सभापति महोदय, हम यही सोचते थे कि यह कांग्रेस सरकार का पहला बजट है और इस बजट में महामहिम की बातें, घोषणा पत्र की बातें, कुछ नई नीतियों, नई योजनाओं पर अमल किया जाएगा । लेकिन यह जो बजट आया है, यह छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छलावा है । जो-जो बातें इस बजट के पूर्व की गई थीं । उनका इसमें कोई उल्लेख नहीं है । यहां के बेरोजगारों को ऐसा सपना दिखाया गया, यहां के युवाओं को ऐसा सपना दिखाया गया कि हम उनको वेतन देंगे, भत्ता देंगे । लेकिन इस बजट में उसका कोई उल्लेख नहीं है । वे बेरोजगार लड़के आज छला हुआ महसूस कर रहे हैं । चुनाव के पहले आपने शिक्षाकर्मियों की बहुत बातें कीं । शिक्षाकर्मियों को बहुत आश्वासन दिया । उन्हें उम्मीदें थीं । लेकिन इस बजट से उन्हें भी ठेस पहुंची है । आपने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो अनलिमिटेड मेडिकल केयर का जो कॉन्सेप्ट लाया है, उसका जमीनी स्तर पर क्या परिणाम आ रहा है, कब लेकर आएंगे, क्या प्रावधान किया गया है, कुछ पता नहीं । जो स्मार्ट कार्ड पहले से चल रहा है, लेकिन उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज परेशान हो रहे हैं । ये कैसी नीतियां हैं, कैसी योजनाएं हैं । कोई सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है तो आमजनों को उसका लाभ मिल रहा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है, लेकिन आपने नया कॉप्सेप्ट लाकर बजट में प्रावधान किया । लेकिन अभी धरातल पर कुछ नहीं है, यह केवल सोच है, कल्पना है ।

शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपने कितने स्कूलों का हायर सेकेंडरी में उननयन किया ? जिसका असर छत्तीसगढ़ के शिक्षा के क्षेत्र में पड़ने वाला है । आप उसकी संख्या बताइएगा कि पूरे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कितने हायर एज्युकेशन के लिए बजट का प्रावधान किया गया ? उनको छोड़ा गया है । आपने कॉलेजों में हायर एज्युकेशन में कौन सी नई फकल्टी की कल्पना की । जिस तरह से आज पूरा देश एक नई क्रांति की ओर जा रहा है, आपने कैसा बजट बनाया कि उसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा । अब उन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैसे मौके मिलेंगे, उनके लिए क्या योजनाएं बनाईं ?

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ नक्सल समस्या से पीड़ित है । उस क्षेत्र के लिए आपकी कल्पना, केवल राजनीतिक तौर पर सोचकर योजना बन रही है, उसकी चर्चाएं हो रही हैं । लेकिन जमीनी हकीकत में इस बजट में कुछ देखने को नहीं मिल रहा । इस तरह से यह बजट एक छलावा है । हम कर्जा माफ करेंगे, आपने बहुत सारे किसानों का कर्जा माफ किया, उसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं । लेकिन जिन किसानों ने अन्य बैंकों से कर्ज लिया है, उनके प्रति आपकी कोई विचारधारा नहीं है । जिन मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आपने आश्वासन दिया था । अगर उन्होंने कर्जा लिया है तो हम उसे माफ करेंगे । उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, वे भी ठगा सा महसूस कर रहे हैं ।

सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र लीलागर नदी, अरपा नदी से घिरा हुआ है । आप गरवा, घुरवा की बातें कर रहे हैं । मेरे मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र के कौन से नरवा, घुरवा को आपने अपने बजट में लिया है । उस लीलागर नदी में जो ग्राम उनी में कहां पर एनीक्ट के लिए उसको बजटेड किया है? ताकि किसान समृद्ध हो सकें । बहुत सारे अवसर हैं, वह स्वीकृत भी हुआ था । सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में देवरीखुर्द है, गतौरा है, लोहर्सी है । लगभग 23 हजार जनसंख्या वाला ग्राम पंचायत है । जिसके मतदाता लगभग 12 हजार हैं । उसको नगर पंचायत करने के लिए हमने बहुत सारी प्रक्रियाएं की हुई हैं । उसके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है । नगर निगम क्षेत्र का किस एरिया में कितना होगा, ग्रामीण दुविधा में पड़े हुए हैं । कोई स्पष्ट नहीं हैं। मेरे क्षेत्र में करीब-करीब डेढ़ हजार एकड़ जमीन ग्राम चिल्हाटी में, गोढ़ाडी में, भुरगुंडा में, पतइडी में किसानों के जमीन को उद्योग-धन्धे के लिए अधिग्रहित किया गया है। क्या उन ग्रामीणों और किसानों की भी जमीन वापिस करेंगे?

सभापति महोदय :- बांधी जी समाप्त करें। अभी नेता प्रतिपक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी भाषण होना है। कई सदस्यों को भी बोलना है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति जी, एक सेकण्ड बस और। मेरा आग्रह है कि उन किसानों की जमीनें जो इसमें 10-10 साल से अधिग्रहण किया गया है और वह भूमि अधिग्रहण भी बिना किसी योजना के किया गया है तो उस अधिग्रहण के अनुरूप उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। क्या उन्हें भी वापस किया जाएगा? मेरा आग्रह है कि उनके ऊपर भी आग्रह किया जाए। किसानों पर भी विचार किया जाए। धन्यवाद साहब।

सभापति महोदय :- श्री शिशुपाल शोरी जी।

श्री शिशुपाल शोरी (कांकेर) :- सभापति महोदय, यह जो बजट है वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि ग्राम सुराज जब तक नहीं होगा तब तक उस देश का विकास नहीं होगा। अभी बहुत सारी बातें आईं। मैंने सुना, बजट कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल यह है कि हम समाज को किस ओर ले जाना चाहते हैं। आज हमारे प्रदेश में अगर 70 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं तो यह जो नरवा,गरवा, घुरवा, बारी का जो कन्सेप्ट है, इस पर ध्यान दिया जायेगा और देना चाहिए, जो हमारी सरकार ने हमारे बजट में भी कहा है और हमारा एक नारा भी है जो हम इसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। अभी बहुत सारे देशों में विकास का जो पैमाना है, यह केवल भौतिक विकास से नहीं लिया जा रहा है। अभी हैप्पीनेस इंडेक्स की भी बात आ रही है कि वहां के लोग किस तरह का जीवन जीते हैं और कैसा अपने आपको महसूस करते हैं? कितना खुशी महसूस करते हैं? अगर गांव को हम खुशहाल नहीं बनाएंगे। उधर ध्यान नहीं देंगे तो चाहे हम कोई भी संरचना बनाएं। हम कितनी भी बातें करें पर अगर हम जनता को, गांव में रहने वाले लोगों को खुशियां नहीं दे सकें। अगर उनके दुखों को दूर नहीं कर सके तो सब काम मेरे ख्याल से बेमानी है। अब इसमें बहुत ज्यादा बजट की भी आवश्यकता नहीं है। जो बजट है जो सामान्य तौर पर पंचायतों को जाते हैं, छोटे-छोटे चेकडेम हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मिट्टी के जो अदर डेम बनाकर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस तरह के उपायों से हम वहां पर जल स्तर ऊपर कर सकते हैं और जल स्तर जब ऊपर होगा तो पीने के पानी के साथ ही साथ सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी और यही एक सोच है और इसमें बहुत सारी बातें है, जिसके लिए कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनकी पूरी जो नीति है, पूरा जो बजट है, वह इसी दिशा में जा रहा है। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहर की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें। श्रीमती संगीता सिन्हा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- (xx)[3]

सभापति महोदय :- श्री प्रकाश शक्राजीत नायक।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :-(xx)

सभापति महोदय :- डॉ. विनय जयसवाल।

डॉ0 विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2019-20 का बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और उसके पक्ष में मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, अभी पिछले शनिवार और रविवार का दिन था, जो हम नये विधायकगण है, जो नव निर्वाचित विधायक हैं, उनके लिए प्रबोधन का कार्यक्रम हुआ था। उसमें राजगोपाल, जो गांधीवादी थे, उनके विचार को सुनने का मौका मिला। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम किसी भी राज्य का, किसी भी देश का इन्डेक्स देखते हैं कि उसमें शिशु मृत्यु दर कितना है, मातृ मृत्यु दर कितना है, ये विकास के इन्डेक्स होते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर वह प्रदेश का निवासी है, प्रदेश का जो सिटीजन है, उसके खुशी के इन्डेक्स को देखना चाहिए। पिछले 15 सालों से छत्तीसगढ़ का अन्नदाता है, हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, उसका अन्नदाता मैं कहां जाऊ, कहां जाऊ, की स्थिति थी। अपने दर्द का जाकर कहां सुनाऊ। लेकिन बात यह होती थी कि अगर अन्नदाता अपनी कुछ बात रखता था, पूर्व में हमारे कई लोगों ने विचार रखा, आपने भी बोला कि अगर वे बात करते थे कि हमको पानी चाहिए तो उनका क्या मिलता था, लाठी, जेल और गोली मिलती थी। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र भूपेश बघेल जी ने धान का समर्थन मूल्य 2500 रूपया किया है। छत्तीसगढ, पूरे देश में पहला राज्य है, जहां धान का समर्थन मूल्य 2500 रूपया मिल रहा है। जिससे आज किसान खुश है। जब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में घूम रहा था, लोग आभार व्यक्त कर रहे थे, सारे किसान लोग आकर एक ही बात बोलते थे कि ये धान का समर्थन मूल्य जो 2500 रूपया हुआ है, यह उनके लिए कल्पना वाली बात थी। उन लोग कभी कल्पना नहीं किए थे कि 2500 रूपया उनके धान का समर्थन मूल्य होगा, जो माननीय भूपेश बघेल जी ने किया। इसके साथ ही साथ कर्ज माफी की बात है। बहुत सारी बातें है, समय कम मिला है। विधायक निधि, यह केवल एक दिलेर मुख्यमंत्री कर सकते हैं, बिना विधायकों के मांग किए विधायक निधि को सीधा 01 करोड़ से 02 करोड़ कर दिया है। इससे विधायकों के बहुत सारे काम जो हैं, वे सम्पन्न होंगे। अगर वन भूमि अधिकार पट्टे की बात करें, पिछली सरकार में वन भूमि अधिकार पट्टा के लिए, छोटी-छोटी बातों के

[3] (xx) अनुपस्थित

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कारण जो आदिवासी और किसान थे, उनको भगा दिया जाता था। लेकिन उसको माडीफाइ करके माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वन अधिकार पट्टा देंगे, यह बहुत ही अच्छी बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक-दो मिनट अपने क्षेत्र के बारे में बोलूंगा। चूंकि मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, उसमें कृषि का रकबा कम है। चूंकि मैं कोयालाचंल से आता है और वहां की बहुत सारी बातें हैं। वहां के श्रमिकों, वहां के लोगों, वहां के व्यापारियों को कठिनाई होती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन मे मांग रखना चाहूंगा कि वहां जो लगातार बंद होती कोयला खदानें हैं, उन कोयला खदानों को कहीं न कहीं इसलिए बंद कर दिया जा रहा है ताकि कहीं न कहीं बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली बात है। कोयला रहते हुए कोयला खदानों को बंद किया जा रहा है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि जो बंद होते हुए कोयला खदानें हैं, उनको खोलने का प्रावधान करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिंहावा) :- माननीय सभापति महोदय, 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला है और उस जनादेश का सम्मान करे हुए हमारे माटी पुत्र, किसान पुत्र मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए, छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही संतुलित है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। गांधी जी ने जो सपना देखा था, वह देश को ऊचाईयों तक ले जाना चाहते थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भारत को 21वीं शदी में महाशक्ति बनाने का जो सपना देखा था। हम जब तक इन सबका विकास नहीं करेंगे, चाहे एस0टी0 हो, एस0सी0 हो, चाहे आ0बी0सी0 हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि हो, जब तक इसका विकास नहीं करेंगे, भारत महाशक्ति नहीं बन सकता है। इस चीज को हमारे मुख्यमंत्री जी भंलीभांति समझ गए थे और बजट में इन सबको स्थान दिया है। मैं सिंहावा विधान सभा क्षेत्र को बिलांग करती हूँ। मैं चुनाव जीतने के बाद मैं जब आभार व्यक्त करने के कार्यक्रम में गई।

समय :
05:00 बजे

तो जिन लोगों ने अपनी समस्याएं मांग पत्र के रूप में रखीं, उस मांग पत्र में स्कूली शिक्षा, हॉस्पिटल, सड़क, जितनी भी समस्याएं हैं, उसे बजट में शामिल किया गया है । 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया, विकास का त्यौहार मनाया और दुनिया भर के त्यौहार मनाए, ऐसा लगने लगा था कि ये लोग कितना विकास करेंगे, लेकिन जब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र को देखती हूं तो चारों ओर ही गड्डे ही गड्डे दिखाई देते हैं । सड़क का तो कहीं नामो-निशान नहीं है और एक

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हमारा रिसगांव क्षेत्र है, वह नक्सली समस्या से जुझ रहा है, वहां आवागमन तक की सुविधा नहीं दी गई है, ऐसी स्थिति में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1565 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 238 करोड़ और समग्र विकास में 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि इस योजना से न केवल हमारे सिहावा क्षेत्र के बल्कि छत्तीसगढ़ के सड़कों की यही हालत है, उसमें सुधार होगा और कृषि के अलावा कृषक की आमदनी के जो साधन है, पशु-पालन के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री जी ने लगभग 45 करोड़ रूपये का बजट का प्रावधान किया है, उसमें डेयरी और मुर्गी फार्म के लिए योजनाएं हैं । यदि इनका लाभ किसानों को मिलता है तो निश्चित तौर से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा । इसके साथ-साथ गांव के लिए सुराजी योजना नरवा, घुरवा, गरवा, बारी लागू की गई है, ये छत्तीसगढ़ की चार चिह्नारी है । इसकी मैं बहुत-बहुत प्रशंसा करती हूं क्योंकि ये चारों योजनाएं लागू होंगी तो छत्तीसगढ़ के विकास की दशा और दिशा बदल जायेगी और गांव का जो स्वरूप है, वह बिल्कुल नये रूप में दिखाई देगी । अजय भैया अभी भी पुराने युग की बात कह रहे थे कि गोबर का छेना थोपेंगे, चूल्हा जलाएंगे तो आज हम आधुनिक युग की ओर बढ़ रहे हैं, क्यों गांव के लोगों के लिए गैस प्लांट नहीं बनाया जा सकता ? उज्ज्वला योजना के माध्यम से जितना भी रेट बढ़ाए थे, हमारे किसान भाई त्रस्त थे, उससे उनको राहत मिलेगी और रासायनिक खाद के प्रयोग से तरह-तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, उन बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा तो निश्चित तौर से ग्राम सुराज की जो चार चिह्नारी है और कौशल विकास उन्नयन की बात कहूं तो यदि गोबर गैस प्लांट लगेगा और 10 लोगों को कौशल उन्नयन योजना के तहत प्रशिक्षित किया जायेगा तो निश्चित तौर से दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा । मैं इतना ही कहना चाहती हूं क्योंकि भैया ने किसानों के हित के लिए सोचा, सभी वर्ग के लिए सोचा, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं और इस बजट की भूरी-भूरी प्रशंसा करती हूं । धन्यवाद ।

श्रीमती ममता चन्द्राकर (पण्डरिया) :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2019 का बजट छत्तीसगढ़ के किसान पुत्र माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, जो ग्रामीण और किसान में हित में उनकी छवि में एक नया रंग भरता है । गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ इस ध्येय वाक्य को आत्मसात कर छत्तीसगढ़ सर्वांगीण विकास को मूर्त रूप देने, समृद्ध किसान, समृद्ध गांव एवं समृद्ध छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा । बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के भाव को अपने आप में समाहित करता ये बजट किसान, गांव, गरीबों के लिए कल्याणकारी बजट है । शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, पेयजल जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को बजट में विशेष ध्यान दिया गया है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी । चूंकि मैं अपने विधान सभा के बारे में कहना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र के अलावा लगभग 100 गांव

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वनांचल है । वनांचल में बैगा आदिवासियों की बाहुल्यता है । उस क्षेत्र में पेयजल, शिक्षा की थोड़ी कमी है । मैं इस सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जाये और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह निश्चित ही सराहनीय है । हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को समृद्ध, खुशहाल बनाने में आगे आएगी । इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आसंदी का निर्देश है, अधिक से अधिक बात अपने जिले से संबंधित रखी जाये ।

उससे पहले आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ । अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा विकास प्राधिकरण और बस्तर विकास प्राधिकरण स्थापित हैं । मैं शासन से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी, मैदानी क्षेत्र के लिए भी विकास प्राधिकरण का प्रावधान रखकर मेरे विधान सभा के आसपास के सभी गांवों को लाभान्वित किया जाये ।

समय
5.05 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुये)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि सकरी और गनियारी में उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय की स्थापना हेतु निवेदन करती हूँ । इसी तरह पिछली सरकार ने तखतपुर में एस.डी.एम. कार्यालय की घोषणा की हुई थी, लेकिन अभी भी तखतपुर विधान सभा कोटा एस.डी.एम. से संचालित होता है । मैं तखतपुर के लिए भी एस.डी.एम. कार्यालय के लिए निवेदन करना चाहूंगी । तखतपुर में एक बड़ा अस्पताल, जिसमें 100 बिस्तर हो, साथ ही वहां चिकित्सकों के लिए भी व्यवस्थाहेतु आग्रह करना चाहूंगी । तखतपुर में अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापनाका भीमेराआग्रह है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है । तखतपुर में गन्ने की उत्पादकता है, इसलिए धन्यवाद करते हुये कहना चाहूंगी, तखतपुर में एक शक्कर कारखाना और वहां बीही की भी अधिकता से उपज होती है । वहां पर बीही के एक फुड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु मांग करना चाहूंगी । संस्कृति मंत्रालय में जिस तरह से राजिम उत्सव के लिए जिस प्रकार से बजट का प्रावधान है, तखतपुर के बेलपान में माघी पुन्नी मेला होता है, वहां आसपास के सभी क्षेत्रों से लोग आते हैं । उसके लिए भी संस्कृति मंत्रालय से निवेदन करना चाहूंगी कि उसे भी व्यापक स्वरूप दिया जाये । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बाद बिलासपुर और इसके आसपास के जिले के बारे में बात करना चाहूंगी । कई जिलों के मरीज सिम्स पर आश्रित हैं । सिम्स के ऊपार बात किये बिना मेरी बात अधूरी रह जायेगी । मैं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निवेदन करना चाहूंगी कि सिम्स में जितनी भी अव्यवस्थायें हैं, 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का दौर धीरे-धीरे ही हटेगा । उसमें सुधार शुरू हो गया है और भविष्य में भी सुधार दिखाई देगा । वहां पर 7 डॉक्टरों को अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है । उसके स्थान पर नये डॉक्टरों की जल्द से जल्द व्यवस्था कीजाये, इसका भी आग्रह स्वास्थ्य मंत्री जी से है । जो नवजात बच्चों की मृत्यु हुई है, पहले जिस शिशु की मृत्यु हुई है, वह भाटापारा से था । भाटापाराका उक्त शिशु 15 दिसम्बर से वहां भरती था । अंडर वेट होने के साथ ही अन्य समस्यायें थी । यह निवेदन मैं इसलिए कर पा रही हूँ कि घटना के 15-20 मिनट के अंदर ही मैं यहां पहुंच चुकी थी । मुझे खेद है किघटना की सूचना मुझे मीडिया के द्वारा प्राप्त हुई कि सिम्स में आगजनी हो गयी है । घटना कितनी बड़ी है, इसका अनुमान नहीं लगा पा रही थी, मैं वहां तत्काल पहुंच गयी थी । ईश्वर का बहुत धन्यवाद है कि घटना छोटी थी । पहली बार सिम्स के प्रशासन ने सूझबूझ का निर्णय लेते हुये उन बच्चों को धुयें से नुकसान न हो, इसलिए समुचित व्यवस्था करके और मेरे साथी विधायक शैलेष पाण्डे के सामने अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित किया । हम तीन चार दिनों तक बच्चों और उनके माता-पिताओं के संपर्क में रहे । उन बच्चों के लिए सिम्स में भी जो रिपोर्ट थी, उसके आधार पर वहां आगे इलाज होता रहा । सिम्स अपने अपने क्षेत्र की जनता के भले के लिए बहुत बडा केन्द्र है जिस पर हम आश्रित रहते हैं। अपने क्षेत्र के कम से कम 15-20 लोगों के लिए रोज हम सिम्स में निवेदन करते हैं कि इनके लिए बेहतर व्यवस्था की जाए और इनके लिए जो संभव हो वह मदद की जाए। मैं इसके अलावा चर्चा करना चाहूंगी कि बजट में अरपा भैंसाझार के लिए 127 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। लेकिन मैं आग्रह करती हूं कि इससे पूर्व अरपा भैंसाझार में जो कार्य हुए हैं उनमें हुए भ्रष्टाचार की भी जांच का मैं निवेदन करना चाहूंगी। महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा (बेमेतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस पर चर्चा हेतु खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं जिन्होंने बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय की भावना से ओतप्रोत होकर वर्तमान बजट वर्ष 2019-2020 को यहां पर प्रस्तुत किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने के लिए भी इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या सर्वाधिक है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और बहुत खुशी की बात है कि कुल राशि के लगभग 21 प्रतिशत की राशि का प्रावधान इस बजट में

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। जहां पुराने कर्ज माफी के लिए 6230 करोड़ रूपये अल्पकालीन कृषि ऋण की माफी के लिए प्रावधान रखा गया है उसी प्रकार व्यावसायिक बैंकों के लिए जो अल्पकालिक ऋण था लगभग चार हजार करोड़ रूपये का इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान रखा है। 2500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का जो वायदा किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने किया था उसको भी पूरा करने के लिए इस बजट में प्रावधान और वर्ष 2019-20 में भी समर्थन मूल्य में धान खरीदी हेतु लगभग 5 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल हॉफ करने को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत देयकों में 400 यूनिट तक का विद्युत भार पर आधी छूट का लाभ 01 मार्च, 2019 से दिया जायेगा, इसके लिए भी 400 करोड़ रूपये का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में रखा है। 05 नये फुड पार्क प्रारंभ करने हेतु जिसका लाभ हमारे उन किसानों को मिलेगा जो फल, फूल और सब्जी का उत्पादन करते हैं उनको उनकी फसल का उचित मूल्य मिल पाये इसके लिए 05 नये फुड पार्क हेतु लगभग 50 करोड़ रूपये का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र और जिस जिले से आता हूं वहां किसानों के द्वारा काफी अधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ना के बोनस के लिए लगभग 50 करोड़ रूपये का प्रावधान इस बजट में रखा है। बजट में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए जो पूर्व में 15 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी उसे बढ़ाकर 25 हजार करने का प्रावधान भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में रखा है। मैं अगर अपने जिले और अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो बेमेतरा हमारा कृषि प्रधान जिला है। साजा में नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने का प्रावधान इस बजट में रखा गया है जिसका लाभ पूरे बेमेतरा जिला और आसपास के अंचलवासियों को मिल पायेगा। बेमेतरा में एक खुली जेल का प्रावधान किया गया है जिसमें अच्छा आचरण करने वाले लगभग 200 कैदी रहेंगे, उसका भी प्रावधान बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। इसके साथ ही साथ मैं पूरे बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि बाईपास की हमारी बहुत पुरानी और बहुप्रतीक्षित मांग थी, बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र का बेमेतरा मुख्यालय जो नेशनल हाईवे-12-ए से होकर गुजरता है और जहां भारी वाहनों का आवागमन रहता है, यदि हम वहां का पुराना रिकार्ड निकालकर देखें तो वहां एक्सीडेंट के माध्यम से कई जानें गई हैं। हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि बेमेतरा में बाईपास का निर्माण हो। पिछले 15 सालों में जो सरकार थी उससे हम लोगों ने लगातार मांग की, आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया लेकिन सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे बेमेतरा शहर की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी उस बाईपास के लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

साथ ही साथ विधायन निधि को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रूपये भी की गई है। साथ ही साथ हमारे 25 हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में किया शामिल है जिसमें मेरे बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम भिलौरी में भी जो काफी पुरानी मांग थी। हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने का कार्य इस बजट में उसके लिये भी प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के जो रिक्त पद थे। अच्छी शिक्षा की हम बात करते हैं लेकिन प्राध्यापकों की अच्छी शिक्षा की कल्पना कोरी है जिसके लिए लगभग 1300 से अधिक पदों को भरने के लिए हमारी सरकार ने विज्ञापन जारी किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि लोकहित को ध्यान में रखते हुए, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलेने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री विक्रमशाह मंण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज समय दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण में, अपनी बात रखने के लिए समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से पहले इस विधानसभा में बहुत सारे बजट आये होंगे, और उसमें चर्चाएं भी हुई होगी लेकिन आज पहली बार देखने में ये हआ रह है कि इस बजट को लेकर जो लोगों में जन चर्चाएं है, जो लोगों में विषय है कि आज हर जगह चर्चा हो रही है, बात हो रही है इस बजट को लेकर। इस बजट में अगर हम बात करें तो इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ने सभी वर्गो का, सभी लोगों का इसमें ध्यान रखा है और हर वर्ग को लेकर चलने की बात इस बजट में है। मैं बस्तर से आता हूं और सबसे दूर विधानसभा क्षेत्र से आता हूं तो मैं वहां के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। बस्तर एक आदिवासी बहुत क्षेत्र है और इस बजट में जिस तरीके से आदिवासियों के ऊपर ध्यान दिया गया है, बहुत बड़ी बात है। तेंदूपत्ता दर जो बस्तर के अंदर में, तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए वहां के आदिवासी पूरे एक वर्ष से इंतजार करते हैं कि कब हम तेंदूपत्ता तोड़े और कब हमको पैसा मिले। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह से तेंदूपत्ता का रेट दर 250 रूपये था आज 400 रूपये की दर से लोगों को लाभ मिलने वाला है, इसलिए लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर हम आदिवासियों की बात करें तो वन अधिकार का जो पट्टा इससे पूर्व में नहीं मिलता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो भी वहां पर 15 वर्ष से 5 वर्ष से काबिज है, वहां पर सर्वे हो रहा है, लोगों को वन अधिकार पट्टा मिलने का काम हो रहा है और लगातार आदिवासियों के लिए बस्तर में और पूरे प्रदेश के अंदर में काम हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, को धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट लाया है, उस पर पूरी तरह से अपने समर्थन रखते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एक बार धन्यवाद कि उन्होंने बस्तर के आदिवासियों का विशेष ध्यान रखा इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, आप मोला माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बजट सत्र मा बोले के मौका दे हो। मैं गांव के गरीब आदमी, गांव मा रहने वाला, मैं सब कई प्रकार के

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए। मैं समझता हूं सभा इससे सहमत है।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, बजट ला मैं देखत रहव, ता मैं वोमा देखव कि येमा ये गांव के गरीब आदमी कि जे आदमी सुबह उठ करके किसानी करथे वो किसान के लिए का प्रावधान किये गेहे । मैं देखेव वो मजदूर आदमी जे हा पहली जम्मू कश्मीर में जा करके अपन जीवन यापन करत रिहिस हे, अपन घर के लोग लईका के पेट पालत रिहिस हे ये गरीब किसान के लिए का प्रावधान करे गे हे मे देखेव। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद दे थो, अऊ मैं धनयवाद देहू ये छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ जनता के द्वारा आज इतिहास गवाह हो जही, माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पेश करिश हे, पहली बार लागिस की छत्तीसगढ़ भवन में, छत्तीसगढ़ के विधानसभा में, छत्तीसगढ़ के बजट पेश होवथे ये पहली बार लगिस हे। मैं धन्यवाद देहू, आज नाना प्रकार के, मैं कुछ तुलना करना चाहथो, पहली के सरकार रहिस हावे, पावर प्लांट लगावे मोर जांजगीर जिला में आर.के., नेथना. डी.बी. नाना प्रकार के पावर प्लांट, पावर प्लांट लगाय के पहली अधिकारी मन आवय, माया जाल फैलावय, अऊ गरीब किसान निर्धन व्यक्ति मन ला, प्रलोभन देवय, कि आप मन हमन ला जमीन देवव, पावन प्लांट लगावव। तुहरों गांव ह दिल्ली बंबई कलकत्ता, कस होही कस सपना दिखावय । वह गरीब किसान खुश हो जाए। वो कहाए कि मोला जम्मू काश्मीर नहीं जाए बर लागए, हमर गांव हा दिल्ली बम्बई बन जही। अइसे सपना करके, बड़े-बड़े पॉवर प्लांट लगिस। लेकिन मय सदन ला कहना चाहत हों, पक्ष अउ विपक्ष दोनों ला कहना चाहत हों, मोर बात अधिकारी मन भी सुनत हे, कि आज वो गरीब किसान के जमीन चले गिस अउ ओला मुआवजा कुछ नहीं मिलिस अउ आज ओ मन के ऊपर नाना प्रकार के धारा लगे हे, ये धारा लगाने वाला कोन हे? पहली के सरकार मन। मे मुख्यमंत्री जी ला कहना चाहत हों, धन्यवाद देना चाहते हों, आप भी हमर जिला के हो, मैं वो सौभाग्यशाली हों कि मैं जांजगीर जिला के हों, आप जांजगीर जिला के हों और अउ विधान सभा के अध्यक्ष हो। मय कहना चाहत हों कि नरवा, गरूआ, घुरूआ बाड़ी के बात करे हे, कतको झन कहात रिहिसे, वो गरीब किसान के मजाक उड़ात रिहिने, एक जमाना रिहिस हावय, जब हमर गांव में नरवा बहए रहेय, वो समय में कोई डेम पुलिया नहीं राहए, हमर पूरखा मन जाकर के नरवा ला बांध देवय, अउ बड़े-बड़े कनिहा भर के मुड़ई उपजे रहाए। अइसे प्रकार के आज हमर बारी से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उपजत रिहिसे। मैं धन्यवाद दूहूं, वही ला कहे आवए कि खग ही जाने खग की भाषा। आज हमर मुख्यमंत्री जी गरीब किसान घर के धरती के सिना ला चिरकर के अन्न उपजाए हावए। वो किसान के दर्द ला जानथे। ओकरे खातिर 2500 रूपये समर्थन मूल्य में धान लेकर काम करिस।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मय 5 मिनट अउ लूहूं। बस दो मिनट में अपन बात ला पूरा करहूं। आज मोर क्षेत्र में 5 ठोक बैराज बने हे। मोर क्षेत्र के विषय हे तेकर बर कहना चाहत हों। 5 ठोक बैराज बने हे। कलमा, साराडिह, मिरौनी, बसंतपुर, शिवरीनारायण, काबर बनिस, पॉवर प्लांट ला पानी देबर। कोई बात नहीं हे पॉवर प्लांट ला पानी देवव, पहली के सरकार मन बनाए रिहिसे तेकर बात ला कहत हों। लेकिन नदी पहली छोटे रहिसे, धीरे-धीरे वो बड़े होगे। ओमा ककड़ी, कलिंदर, तरबूज, आप कभी-कभी जावत रहे हो हू तो बड़े-बड़े तरबूज मिले, ये नदी के अंदर के रिहिसे। ओ नदी के अंदर रहने वाला किसान ला, ओ मन ला मुआवजा नहीं मिलिसे। माननीय राहुल गांधी जी ला दिल्ली ले आकर के ओकर लिए पद यात्रा करना पड़ गे। लेकिन मैं आप ला कहना चाहत हों, माननीय मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद दूहूं कि जैसे मुख्यमंत्री बनिस, आज पहिली प्रावधान करिसे कि ये किसान मन ला मुआवजा मिलना चाहिए। ये किसान ला भी पानी मिलना चाहिए। पॉवर प्लांट ला मिले तो मिलबे करए। किसान ला भी मिलए । अइसे प्रकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ला में धन्यवाद दूहूं। बस अंत में एक बात बोलहूं कि नरवा गरूआ, घुरूआ बाड़ी जब महात्मा गांधी जी बोल रिहिसे हावय कि जब तक के गांव विकास नहीं करही। हमन कभु-कभु आ जथन रायपुर शहर में देखन जाकर के नवा रायपुर ला, हमन सोचन की हमन कहां आगे हावन। चिकचिकाती रोड आज हमर लोग लईका घर ले निकले तो माड़ी भर के चिखला ले बुलके पढ़े बर जाए। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी हर नाना प्रकार के गांव के लिए योजना बना दे हावए। मैं धन्यवाद दूहूं कि अइसे मुख्यमंत्री अइसे वित्तमंत्री जी अउ धन्य हे ओकर कैबिनेट के मंत्री, जेमन आज अतके बड़े योजना बनाकर के आज छत्तीसगढ़ ला एक सौभाग्यशाली प्रदेश बनाथे। आज छत्तीसगढ़ ला पूरा देश देखत हावए कि अइसे बजट बनाने वाला धन्य हे मुख्यमंत्री, धन्य हे वहां के सदन। आप मोला बोले के मौका दे हो, पुन: सदन ला और कैबिनेट मंत्री जी ला सबे ला धन्यवाद देवत हुए अपन वाणी ला विराम देवत हों। (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 91 हजार, 542 करोड़ रूपये का ये प्रथम आम बजट प्रस्तुत किया गया है। वास्तविक में ये जो आम बजट प्रस्तुत हुआ है और इस बजट के माध्यम से हमारे पूरे साल भर के इस प्रदेश के हमारे विकास की क्या-क्या योजना बनेगी, हम कौन-कौन से कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेंगे, साथ ही हमारे विकास के कौन-कौन से बिन्दु हैं, उसके आधार पर हम इस विकास की रूपरेखा निर्धारित करेंगे। और पूरे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

साल भर की आर्थिक गतिविधियां हमारे इस पूरे प्रदेश के विकास से लेकर योजनानाओं तक, और उन योजनाओं से लेकर उनका क्रियान्वयन इस बजट के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को और इस प्रदेश के लोगों के लिए लाभ की योजना बनेगी, विकास की योजना बनेगी। आज बजट को जब छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे थे तो उनकी अपेक्षायें थीं और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चाहे अपनी घोषणाओं, जन घोषणाओं के माध्यम से प्रदेश के लोगों के बीच में एक जो उनकी भावनाओं को जागृत किये, जनभावनाओं को जगायें और मुझे लगता था कि इस बजट में शायद ये समाहित हो कि प्रदेश के लोगों की आकाक्षांयें पूरी हो सकें। किन्तु इस बजट को देखने के बाद में ऐसा लगा एक नहीं बल्कि सभी वर्गों को छला और ठगा गया है। अभी मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसकी चर्चा हो रही है। मैं देख रहा हूं कल से जो प्रारंभ हुए हैं और कल से प्रारंभ होने के बाद में आज तक जो उसकी चर्चा हो रही है। वह चर्चा क्या है, जब कोई भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनको सलाह देने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं और बहुत सारे लोग जो सलाह देते हैं वह सलाह देकर उनको बता देते हैं कि आप इस रास्ते पर चलो और उस रास्ते पर चलना मुख्यमंत्री शुरू कर देते हैं। ये पहले मुख्यमंत्री नहीं हैं इसके पहले भी लोग मुख्यमंत्री को सलाह दिये हैं।

श्री अमरजीत भगत :- पहले वाले वैसे करते थे?

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं उस बात को भी बता रहा हूं, उसमें दिक्कत क्या है। जो बातें आई हैं, मैं उसको बता रहा हूं। मुख्यमंत्री को नरूआ, घुरूआ, बारी के बारे में सलाह दिये। मैं कहना चाहता हूं कि कहां है नरूआ का घुरूआ, बारी, छल, कपट और बदला लबारी, ये सरकार के इही चिन्हारी। इसका नोडल विभाग कौन सा है? सरकार के द्वारा जब बजट का प्रावधान किया गया तो इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया है? उस अवधारणा को जमीन में उतारने के लिए उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उसके बाद में उसमें ला दिया कि उसको हम मनरेगा के माध्यम से रोजगार का सृजन करेंगे, हम मनरेगा के माध्यम से पूरा करेंगे। कोई भी योजना जब सरकार के द्वारा बनाई जाती है तो उसको सुनिश्चित किया जाता है कि हमारा ये कांसेप्ट है, इतना हम रखेंगे, इसके आधार पर इतना हमारा खर्च होगा और खर्च करने के आधार के लिये प्रावधान बजट में सुनिश्चित होगा। लेकिन ये केवल जो भाषा एक मुख्यमंत्री प्रयोग करते हैं बाकी प्रयोग करते हैं जुमला, मैं भी कह सकता हूं कि ये केवल आपका जुमला है और जुमला के रूप में उसको उपयोग किया गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय नेता जी, दिल्ली में जुमलेबाजी होती है, 15 लाख रुपये नहीं मिला, वह जुमलेबाजी है।

श्री धरमलाल कौशिक :- हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख कभी नहीं कहा कि हम 15 लाख आपके खाते में भिजवायेंगे। आपके पास कोई रिकार्ड हो तो अभी भी आप लाकर दे सकते हैं। मैं इस बात

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

को जवाबदारी के साथ बोल रहा हूं। यदि हमारे प्रधानमंत्री जी 15 लाख की बात किये हैं तो कोई रिकार्ड हो या उनके कोई भाषण का हो कि 15 लाख खाते में जमा कर रहे हैं तो आप लाकर दे सकते हैं, मैं उस विषय में बात करूंगा।

श्री कवासी लखमा :- देने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दिल्ली में हमारी सरकार आने वाली है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए पूर्व मुख्यमंत्रियों का उदाहरण दिया। जब एक मुख्यमंत्री प्रथम मुख्यंमत्री बने, प्रथम मुख्यमंत्री को लोगों ने बता दिया, उनको एक सलाह दी गई कि हमारे प्रदेश का वनांचल बहुत अच्छा है, औषधि का केन्द्र बहुत अच्छा है इसलिए आप यहां सफेद मुसली का प्रयोग करो। सफेद मुसली के लिए एक राजाराम त्रिपाठी आ गया। वह सफेद मुसली को 5 साल चलाये लेकिन जुमला ही चला, वह सफेद मुसली आज तक दिखाई नहीं दिया, वह भी कांग्रेस सरकार की है। आप भी विधायक थे। यह जो सफेद मुसली की बात आई, मुख्यमंत्री जी भी उस समय मंत्री थे।

श्री अमरजीत भगत :- एक मुख्यमंत्री आये थे जो रतनजोत लगाने की भी सलाह दिये थे। उन्होंने भी खूब डीजल निकाला।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं उसमें भी आ रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अमरजीत जी, 37 पृष्ठ का जो घोषणा पत्र है न, इसमें आधा जुमला में ही 5 साल चलेगा।

श्री कवासी लखमा :- लंदन से नहीं खाड़ी से, डीजल मिलेगा बाड़ी से।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं उसमें भी आ रहा हूं। यह जो सफेद मुसली की बात आई, यह सफेद मुसली की बात आने के बाद में 3 साल सफेद मुसली की बहुत चर्चा हुई, लेकिन 3 साल के बाद में न तो वह सफेद मुसली से किसी को कोई इनकम हुई और न वह सफेद मुसली का यहां पर प्रचलन शुरू हुआ, न किसी को रोजगार मिला और वह सफेद मुसली भी चली गयी उसके बाद में हमारे डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं बता रहा हूं न, आप क्यों चिंता कर रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- श्री सत्तू भैया को तो उससे फायदा हुआ है । (हंसी)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- देखिये, सफेद मुसली का पूरा-पूरा लाभ आपको भी मिला है तभी तो बाल सफेद होने के बाद भी जवान दिखते हैं । (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- मुझे तो नहीं मालूम था कि मिला कि नहीं मिला लेकिन आप बता रहे हैं तो दो दिन से जरूर सत्तू भैया में सफेद मुसली का असर दिखाई दे रहा है । (हंसी) माननीय अध्यक्ष

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

महोदय, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी बदले और उसके बाद सलाह दिये कि अब तेल नहीं खाड़ी से अब मिलेगा बाड़ी से । यह भी चला और चलने के बाद में हम लोगों ने देखा है कि उसमें कितना क्या हुआ है । मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सचेत करना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह केवल एक जुमला बनकर न रह जाये, केवल एक स्लोगन बनकर न रह जाये और ईमानदारी से यदि आपकी इच्छा है तो निश्चित रूप से आप इस बजट में विनियोग के समय, उसके पहले उसकी व्यवस्था करें ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह स्लोगन हिट हो गया है । सब लोग जानते हैं कि ऐसा ही है ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं और आज तो और भी अच्छा बोल रहे हैं । डॉ. रमन सिंह जी नहीं रहते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं । (हंसी)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- कहीं न कहीं से डॉ. रमन सिंह जी को खबर मिलेगी । आपके बाजू वाले तो इधर देख रहे हैं, वह आपकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप सामने देखते रहिए । तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस माध्यम से सचेत करना चाहता हूं कि यदि वास्तविक में धरातल में उतारना है तो उसकी कोई न कोई बजट की व्यवस्था होनी चाहिए । उसका क्लियर कांसेप्ट होना चाहिए कि आखिर यह नरवा, घुरवा की बात आयी तो अभी तक जो हश्र हुआ है लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूं कि इसका भी मुख्यमंत्री जी वही हश्र होने वाला है और यह जुमला बनकर रहने वाला है, यह बात आज मैं आपको बता देता हूं । किसी भी प्रदेश का बजट और यदि उसका आंकलन हमको करना है तो आंकलन करने के बाद में उसके जो आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि बहुत बातें इसके पहले वित्तीय प्रबंधन की आ रहीं थी कि हमारा वित्तीय प्रबंधन कैसा होना चाहिए कि हम उसको 3 परसेंट के नीचे कैसे रख सकें । हमारा जो ब्याज दर है उसको हम कैसे कर सकें ।

श्री कवासी लखमा :- हमारे नेता प्रतिपक्ष जी फोन में देख-देखकर बता रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- क्या देख-देखकर बता रहे हैं ।

श्री कवासी लखमा :- क्या श्री मोदी जी का फोन आ रहा है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय प्रबंधन की बात तो वर्षों से चली आ रही है कि इस प्रदेश को विकास की दिशा में चलाने के लिये हमारा वित्तीय प्रबंधन कैसे होना चाहिए । अच्छा वित्तीय प्रबंधन हम किसको मानते हैं और अच्छे वित्तीय प्रबंधन के साथ यदि हम प्रदेश को चलायेंगे तो निश्चित रूप से हम विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे और उस दृष्टिकोण से मैं यह कहना

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चाहता हूं । आप देखेंगे कि हमारा वर्ष 2017-18 का जो बजट है उसमें सकल वित्तीय घाटा 68 सौ करोड़ रूपये का है । उसके बाद में हमारा जो वर्ष 2018-19 का आया तो 9 हजार 990 करोड़ का लेकिन अभी जब पुनरीक्षित आया और पुनरीक्षित आने के बाद में हमारा जो बढ़ा तो 18768 करोड़ रूपये और यह 18768 करोड़ रूपये लगभग यदि प्रतिशत में हम आते हैं तो यह हमारे 6 परसेंट के आसपास लगभग आ रहा है और 6 परसेंट के आसपास तो 3 परसेंट तक लगातार उसको नियंत्रण करके रखा गया है । एक अच्छे वित्त मंत्री के रूप में और एक अच्छे वित्त प्रबंधन के रूप में लेकिन जो आंकड़ा आने के बाद में यह स्पष्ट हम सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि यह आने वाले समय में केवल हमारा प्रतिशत नहीं बढ़ा है बल्कि हमारी देनदारियां भी बढ़ेंगी । जो विकास है, हमारे विकास भी प्रभावित होंगे । हमारी जो ब्याज की राशि जायेगी वह ब्याज की राशि भी बढ़ेगी और यदि ब्याज की राशि बढ़ेगी तो कहीं न कहीं हमारे छत्तीसगढ़ का विकास प्रभावित होगा और इसलिये अभी इसमें जो प्रयास किया गया है कि 10 हजार 880 करोड़, 2.9 अब यह कैसे, एक कल्पना है कि हम उसको आगे आ करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं । कर्ज माफी के बाद में आर्थिक चिंतकों और विश्लेषकों के जो वक्तव्य आए । रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी इस पर चिंता जाहिर की। यदि इस प्रकार की नीतियां चलेंगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसके दुष्प्रभाव भी हमारे सामने आएंगे । इसको कैसे नियंत्रित किया जाना है इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर न सिर्फ हम लोगों ने चिंता जाहिर की बल्कि इस देश के आर्थिक विश्लेषकों और सब लोगों ने इस पर चिंता जाहिर की है ।

अध्यक्ष महोदय, हम जो टोटल खर्च करते हैं । हम आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में प्राप्तियां और व्यय, इसी पर हमारा सारा बजट आधारित है । मैं इस पर आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी राजस्व प्राप्तियां 2017-18 में 59,647 करोड़, 2018-19 में 72,867 करोड़ यानी लगभग 24 परसेंट की वृद्धि । अभी 79746 करोड़ यानी 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शा रहे हैं । ये हमारी राजस्व प्राप्तियां हैं लेकिन जब हम पूंजीगत प्राप्तियों की बात करेंगे तो 2017-18 में 7251 करोड़, 2018-19 में 10228 करोड़ और पुनरीक्षित में करके 12998 करोड़, यह जो वृद्धि हुई है । उसके बाद 11796 करोड़ यानी 9 प्रतिशत की कमी आई है । यदि पूंजीगत प्राप्तियों में कमी आएगी तो स्वाभाविक रूप से हम जो खर्चा यहां करना चाहते हैं । उस खर्च में भी कमी आएगी और इसके कारण विकास में कमी आएगी । प्राप्तियों के बाद मैं व्यय पर आना चाहूंगा । 2017-18 में राजस्व व्यय 56229 करोड़ रूपए, 68422 करोड़ और यदि हम उसको पुनरीक्षित मानें तो 80370 करोड़, अभी हमारे 78594 करोड़ । ये राजस्व के व्यय हैं । उसके बाद हम पूंजीगत व्यय देखेंगे कि 10370 करोड़ 2017-18 के बजट के हैं । 2018-19 में 12638 करोड़, अभी 12315 करोड़, यानी पूंजीगत व्यय में लगभग 17 प्रतिशत की कमी है । हमारे पूंजीगत व्यय में कमी आई है तो स्वाभाविक रूप से हमारे विकास के जो कार्य हैं, हमको सड़क बनवाना है, सिंचाई की व्यवस्था

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करनी है ताकि हम किसानों के खेत में पानी पहुंचा सकें । उसके साथ ही हमारे वन विभाग के बहुत सारे काम चल रहे हैं । शिक्षा के गुणात्मक विकास की जो बातें हैं कि जब तक हम शिक्षा के स्तर को ऊपर नहीं ले जाएंगे तब तक विकास संभव नहीं है । हम जब कल्पना करते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में विकास के मामले में प्रथम 3-4 की श्रेणी में प्रवेश करे । जब तक हम शिक्षा पर जोर नहीं देंगे, शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर नहीं देंगे, अधोसंरचना पर जोर नहीं देंगे, हायर एज्युकेशन पर जोर नहीं देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के विकास के क्षेत्र में आगे जा पाएगा । इसलिए यह निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है । अध्यक्ष महोदय, हमारा राजस्व घाटा 2017-18 में 3400 करोड़ रूपय आधिक्य है। इसके बाद भी हमारा 2018-19 का 4400 करोड़ रूपये और पुनरीक्षित होकर हमारे 6300 करोड़ रूपये घाटा और अभी जो 1,151 आधिक्य दिया गया है। यदि यह आधिक्य हमारे पास है तो मैं मुख्यमंत्री जी से इस विषय में आग्रह करना चाहूंगा, जानना भी चाहता हूं कि जब बजट में आपके पास पैसे हैं और यदि लाभ का हमारा बजट है तो हमारे जो पुलिसकर्मी आंदोलन की राह पर जा रहे हैं, आपने उनके लिए बजट में व्यवस्था क्यों नहीं किया? आपने 7वां वेतनमान लागू कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं किया? शिक्षाकर्मी जो आंदोलन की राह में जाने को तैयार हैं, उनकी बैठकें हो रही हैं, उनकी जो संलग्नीकरण की बात है, जो नियमितिकरण की बात है। इस विषय में आपने बजट में चिंता क्यों नहीं की और यदि आप यह चिंता करते तो हम आंकलन से यह मान सकते थे कि यदि हम सही दिशा में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जिनकी भावनाओं को हमने खुद जगाया, उनकी अपेक्षाओं को जगाया और आज जब करने की बारी आयी है और यदि आप बता रहे हैं कि 1,151 आधिक्य की दिशा में हम जा रहे हैं तो आखिर इनके लिए बजट में प्रावधान क्यों नहीं किया गया है? और नहीं किया है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पैसे का अभाव दिखाई दे रहा है और अभाव के कारण शायद यह संभव नहीं हो पा रहा है। जहां तक हमारी अदायगी की बात है आज की स्थिति में 4500 करोड़ रूपये केवल ब्याज की राशि हमें देनी पड़ेगी और यदि हम देखें तो 2017-18 में हमारा लगभग 19 प्रतिशत राशि है। हमारे 2018-19 में 22 प्रतिशत के आसपास और आज हमारा 23-24 प्रतिशत अदाएगी के लिए हमको यह राशि केवल ब्याज के लिए देनी पड़ेगी। यह जो स्थिति का निर्माण हुआ है निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए छत्तीसगढ़ के विकास के लिए..........।

श्री कवासी लखमा :- 15 साल में किये न साहब। अभी तो हम लोग नये-नये आये हैं। ये करने वाले उनको बताओ न जो तुम्हारे बाजू में बैठते हैं। ये मोबाइल बांटना, टिफिन बांटना यही तो काम गलत हुआ है।

श्री धरमलाल कौशिक :- तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकास की परिकल्पना और मुख्यमंत्री जी की जन घोषणाएं निश्चित रूप से इसका जो विरोधाभास यहां पर दिखाई दे रहा है, मुझे

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लगता है कि इसमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि जिससे लोगों की अपेक्षाएं पूरी हो सकें और कहीं न कहीं उस दिशा में हम पीछे हो रहे हैं। यहां पर जो मुख्य रूप से बजट में दो-तीन बातों के ऊपर एक किसानों के ऊपर 21000 करोड़ रूपये की जो बात आयी। ज्यादा से ज्यादा इस दो दिन में चर्चा हुई है कि किसान हमारे खुशहाल हुए और किसानों के लिए एक बड़ा काम हम लोगों ने किया है, मैं इस विषय पर कहना चाहता हूं कि हमारा जो पिछला बजट किसानों के लिए.......

श्री अमरजीत भगत :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, विधायक निधि बढ़ा है, उसके लिए भी एकाक बार तो धन्यवाद दे दीजिए। हम लोग इतने दिन से लड़ रहे थे, नहीं बढ़ रहा था।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधायक निधि इसलिए बढ़ा है कि आपके मुंह को बंद रखा जाये। बजट में एक रूपया नहीं मिलेगा। मुंह बंद करने के लिए.....

श्री कवासी लखमा :- वापस कर दोगे क्या उसको। इधर वापस करो। हम लोगों को देखो।

श्री धर्मजीत सिंह :- अमरजीत जी, अब कैसे धन्यवाद दें ? दे तो रहे हैं। आप चलो तो गांधी चौक पर चलकर भाषण दे देते हैं। 10 बार तो बोल डाले भैया, बहुत अच्छा किये हो करके। अब आप हर थोड़ी देर में विधायक निधि बोलते हो। जो अच्छी बात है उसको बोल तो रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- आपके तरफ नहीं है भैया। तुम्हारा तो ग्रुप अलग है। हम इस ग्रुप को बोल रहे हैं। दो ग्रुप है न उसमें। एक ग्रुप को बोल रहे हैं भाई। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- जो अच्छी बात हुई है, उसको कोई नहीं बोल रहा है क्या? हम तो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने एक करोड़ का दो करोड़ करके अच्छा किया। 3 करोड़ कर दीजिए हमारी तरफ से।

श्री शिवरतन शर्मा :- देखिए, जो दो करोड़ भी है न, वह भी स्पष्ट नहीं है। उसमें 50 लाख रूपये शायद प्रभारी मंत्री का है।

श्री कवासी लखमा :- वह पहले का है.....

श्री शिवरतन शर्मा :- लखमा जी, बाजू में अकबर भैया जी से कुछ सीखो।

श्री केशव चन्द्रा :- अमरजीत जी, अगर विधायक निधि 3 करोड़ कर देंगे तो पुन: धन्यवाद देंगे।

श्री अमरजीत भगत :- इसके लिए एक कार्यकाल और आयेगा।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय जी, ऐसे हे, चार आना के घाघर बारह आना के पुदगौनी, हमर छत्तीसगढ़ी में कहावत हे। मोबाइल ला बांटना हे तो तिहार मनावय अउ ज्यादा खर्च होवय। ओखरे बर कहत हे कि आसानी से मिल गय हे ओखर लिए धन्यवाद कहत हे।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसानो की बात कर रहा था। किसानों के सन्दर्भ में लगातार चर्चा हो रही है। बजट में आया है कि हमने 21 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किए है, ड्ढोहा बजट किये हैं। यह ठीक है कि पहले से डेढ़हा किए हैं। आप किसानों का पूरा बजट देखेंगे,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तो तुम्हारी फाईल में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आकड़ें झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। उसमें 10 हजार करोड़ रूपये तो केवल किसानों के लिए जो घोषणा किए थे, उसके अनुरूप 2500 रूपये में धान खरीदी और ...। इसमें मूल रूप से 13,500 करोड़ रूपये पिछले बजट में पारित किए थे।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, गुलाबी रंग से आप भी नहीं बच पाये।

श्री धर्मजीत सिंह :- गुलाबी के असर से तो आप भी बाकी नहीं हो, यहां अगर भाभी जी पहनी हैं तो उधर भी भाभी जी पहनकर बैठी हैं। थोड़ा पलटकर देखो।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 13,500 करोड़ रूपये पिछले बजट में पारित हुआ था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें हम किसानों के खेती के लिए और आने वाले समय के लिए 10 हजार करोड़ रूपये छोड़ देंगे तो शेष केवल 11 हजार करोड़ रूपये बचेगा। उससे अच्छा तो हमारा बजट था। जिसमें किसानों के उत्पादन, उनके यंत्र, उनकी योजनाओं के लिए, किसानों के सशक्तिकरण के लिए और खासकर कृषि की जो योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए जो-जो प्रावधान किया गया था, उसमें आज हम अभाव देख रहे हैं। आने वाले समय में हमारे किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके, मजबूत हो सके, उनको बैंक के दरवाजे तक नहीं जाना पड़े, ऐसा आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ ही साथ मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान एक तरफ और आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे यहां सीमान्त किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे सीमान्त किसान जिनका डेढ़ एकड़, दो एकड़ खेत है। बहुत कम सीमान्त किसान हैं जो बैंकों के दरवाजे तक पहुंच पाते हैं। ये कहीं न कहीं साहूकार के चक्कर में फंस जाते हैं, धनी व्यक्ति के चक्कर में फंस जाते हैं, उसके कारण ज्यादा ब्याज की उगाही होती हैं और इस अधिक ब्याज उगाही के कारण हमारे किसान परेशान होते हैं। इसमें कई घटनाएं घटी हैं। ये घटनाएं वास्तव में बैंकों के लोन के कारण नहीं है कि किसानों को कहीं गलत दिशा में जाना पड़े। वास्तव में जो साहूकार हैं, उनके चंगुल में फंसने के कारण है। मुझे इस दिशा में लगता है कि आने वाले समय में इस पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि हम साहूकार के चुंगल से किसानों को कैसे मुक्त करा सकें और हम किसानों के लिए ऐसी कौन सी योजना बने, जिससे वे साहूकार के चुंगल से मुक्त हो सके। वहां के धनी व्यक्ति से जो कर्ज लेते हैं, उनसे मुक्त हो सके। तो मुझे लगता है कि यदि आने वाले समय में इसकी चिंता करेंगे तो हम उसमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कर्ज माफी की बात आई तो गाड़ी अल्पकालीन ऋण में आकर अटक गई। चाहे वह हमारे ग्रामीण बैंक का विषय हो, चाहे हमारे सहकारी बैंक के हो या व्यवसायिक बैंक के हो। मैं आज आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो मध्यमकालीन ऋण लिए हैं, जो दीर्घकालीन ऋण लिए हैं, यह किसानों की यह अपेक्षाएं रहीं कि कर्जा माफ मतलब सारे लोगों के कर्जे माफ हो जायेंगे। यह जो कर्जा माफ होगा तो छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, उनको पूर्ण रूप से कर्जों से मुक्ति मिल

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

जायेगी और वे खुशहाली के साथ नया जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन आज मध्यमकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण के लिए इस बजट से उन किसानों को मुक्त कर सकें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं आज भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा वित्तीय प्रबंधन 3 से 6 प्रतिशत में चला गया है तो उसमें और ले लें, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के किसान यदि कर्जे से मुक्त हो जाएं तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में किसानों के जीवन में सबसे खुशहाली होगी । इस दिशा में कहीं न कहीं कदम उठाने की आवश्यकता है, लेकिन अल्पकालीन ऋण में रहकर हम कर्जे में भी फंस रहे हैं, हमारे बैंक के ब्याज की अदायगी भी बढ़ रही है और हमने किसानों को कहा कि हम कर्ज माफ करेंगे, उस कर्जे को भी हमने माफ नहीं किया, ये सरकार की हालत हमको दिखाई दे रही है । बिजली बिल हाफ...

अध्यक्ष महोदय :- धरमलाल जी, आप जितना समय चाहें, ले सकते हैं, लेकिन आपने तो कहा था कि आधे घंटे में पूरा कर लूंगा ।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, प्रथम आम बैठक है और उसमें आप बोलेंगे कि आधा घंटा में खतम करो, मैं आधा घंटा में बंद कर दूंगा, लेकिन आधा घंटा में कैसे होगा । बिजली बिल हाफ....

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी, 15 साल में तो 15 पैसा माफ नहीं किये ।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं आपके बिजली बिल में आ रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, बिजली बिल हाफ । आपने जो बिजली बिल हाफ किया है, वह वास्तव में पूरी गणना करेंगे तो बिजली बिल हाफ का हाफ है क्योंकि आपने पहले ही 400 यूनिट का बंदिश लगा दी, जबकि उस समय बिजली बिल हाफ में 400 यूनिट की बात नहीं थी । 400 यूनिट के हिसाब से आपने बजट में प्रावधान किया तो आपने हाफ तो पहले ही कर दिया और हाफ करने के बाद में 400 यूनिट का हाफ मिलेगा तो बिजली बिल कितना हुआ-हाफ का हाफ । ये बिजली बिल आधा नहीं है । ये हाफ का हाफ है और यदि 400 यूनिट से 1 यूनिट ज्यादा हो जायेगा, उस स्थिति में क्या स्थिति बनेगी, उनको पूरा पैसा पटाना पड़ेगा, उस 400 यूनिट का भी लाभ नहीं मिलेगा । इसको भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि 400 यूनिट से ज्यादा हुआ तो 400 यूनिट तक का तो लाभ मिले, लेकिन 400 यूनिट के ऊपर केवल अतिरिक्त बिल मिले तो मुझे लगता है कि उपभोक्ता को लाभ मिलेगा, नहीं तो 400 यूनिट के चक्कर में जो लाभ मिलना है, उन सारे लाभों से हमारे उपभोक्ता वंचित हो जाएंगे। इस दिशा में उसका स्पष्ट क्रियान्यन कैसे होगा, वह बात आनी चाहिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी, ईमानदारी से बोलिएगा कि आपका कर्ज माफ हुआ है या नहीं, आप धान बेचे हैं कि नहीं। दोनों का लाभ मिला है कि नहीं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- आप मुझे ये बताएं कि जब कोई सरकार घोषणा करती है तो केवल एक पार्टी के लिए घोषणा करती है । नहीं । जब डा. रमन सिंह ने धान खरीदी की बात की, बोनस की बात की तो केवल बीजेपी के लिए की, आपको कोई लाभ नहीं मिला । आप इस बात को क्यों पूछ रहे हैं, आप क्या जताना चाहते हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- पूछ तो रहे हैं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- आप कोई अहसान कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर कोई अहसान कर रहे हैं । आप सरकार में बैठे हो, सरकार में आपको जवाबदारी दी गई है, इस बात को भुनाने की आपको क्या आवश्यकता है । ऐसा लगता है कि आप कोई अहसान कर रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- इस योजना का लाभ मिला कि नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस का राजनीतिकरण । जब से ये सरकार आई है, तब से पुलिस का राजनीतिकरण कैसे किया जाता है, उसका उदाहरण हमारे सामने में प्रस्तुत है । कल हम लोगों ने इसलिए स्थगन दिया । रात को डेढ़ बजे एफआईआर किया गया, लेकिन आपके शहर में यह प्रदेश की राजधानी है, आज ही वह विषय आया कि प्रदेश की राजधानी में....

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग तो रात को जमीन नपवाते थे महाराज । (हंसी) भरी बरसात में रात को जमीन नपवाते थे । काहे भूल जाते हैं ।

श्री कवासी लखमा :- ये तो छत्तीसगढ़ की बात है साहब, दिल्ली में रात को पहुंच जाते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- लखमा जी, बाकी सब रात को होता है, आज सेवा आपको जल्दी प्राप्त हो गई क्या, आप ये बताओ । आज लखमा जी को जल्दी सेवा मिल गई क्या ।

डा. शिवकुमार डहरिया :- बरसात में रात को नापने का प्रावधान नहीं है, संडे को भी नहीं है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था और यहां के जो हालात हैं, आपने देखा है, ध्यानाकर्षण के माध्यम से आज वह बात आई है और उसमें हम पूरे प्रदेश की चर्चा न करें, केवल मैं रायपुर राजधानी की बात कर रहा हूं कि राजधानी के आसपास की जो घटनाएं हैं, 30 जनवरी, 2019 को दिन दहाड़े ट्रांसपोर्टर सूरजसिंह की हत्या, डी.डी. थानांतर्गत सराफी व्यापारी जसराज सोनी को दिनांक 1 फरवरी को खुले आम गोली मारी गई, 2 फरवरी को टिकरापारा थाना रायपुर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ज्वेलर्स के यहां चोरी करके ले गए और उसके बाद में हमारे गृहमंत्री जी के क्षेत्र के प्रश्न के जवाब में आया है कि 5 पद स्वीकृत हैं उसमें एक भरा हुआ है और उसमें चार रिक्त है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय नेता जी, ये तो अजय चन्द्राकर जी के समय का है। श्री अजय चन्द्राकर जी ने कोई काम ही नहीं किया।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं बोल रहा हूं ना कि पहले का है तो क्या आप उस दिशा में काम करना चाहते हैं? आप इस बात को कहकर टालना चाहते हैं कि यह पहले का है इसलिए हमें नहीं करना है।

श्री शिवरतन शर्मा - ऐसा है कि अजय चन्द्राकर जी ने नहीं किया तो आप लोगों को काम करने का अवसर दिया। पर आपने पहला काम क्या किया तो सिम्स में आग लगाने का किया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अभी तो पांच साल है, चिन्ता क्यों कर रहे हैं? बढ़िया-बढ़िया काम करेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा:- नहीं, जो काम करने का अवसर मिला उसमें सबसे पहला काम आप लोगों ने सिम्स में आग लगाने का किया।

श्री धरमलाल कौशिक :- जो डॉक्टर के पद रिक्त पड़े हुए हैं, वहां पर टेक्निशियन के जो पद रिक्त हैं और अन्य भी जो पद खाली पड़े हुए हैं, यदि इस बात को यहां सुनिश्चित करेंगे।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवरतन शर्मा जी ने कहा कि सरकार में आने के बाद पहला काम सिम्स में आग लगाने का किया। इसको विलोपित कराया जाए। कोई भी सरकार अस्पताल में आग लगाती है क्या?

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें क्या असंसदीय है जो विलोपित होगा।

श्री शिवरतन शर्मा:- आग लगी या नहीं लगी यह बता दो? आज इस संबंध में ध्यानाकर्षण था। स्वयं मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि आग लगी है। उसमें मैंने क्या गलत कह दिया?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर के पद रिक्त हैं, टेक्निशियन के पद रिक्त हैं, उसमें केवल इतना ही नहीं है, आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुए हैं लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं हैं। प्रदेश में अनेक ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जो बिना डॉक्टर के संचालित हैं। यदि हम इस व्यवस्था को इस बजट के माध्यम से ठीक नहीं करेंगे, हम डॉक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं करेंगे, यदि हम डॉक्टर की भर्ती सुनिश्चित नहीं करेंगे, और जहां पर पद रिक्त हैं यदि उनको फुलफिल नहीं करेंगे, उसकी भर्ती नहीं करेंगे तो क्या ये उदाहरण देकर चल जायेगा कि अजय चन्द्राकर जी ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन उसका अभाव यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपने स्वास्थ्य के बजट में कटौती कर दी। स्वास्थ्य के बजट को आपको बढ़ाने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य का बजट यदि आप बढ़ायेंगे तो प्रदेश की जनता की खुशहाली और लोगों के स्वास्थ्य की दिशा में उसका लाभ मिलेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय नेता जी, अभी जो मुख्य बजट आया है उसको छोड़कर इस पूरे प्रतिवेदन में हमारे पर ही चर्चा होगी। अगला प्रतिवेदन देखेंगे कि आप उसमें क्या-क्या किये हो। अभी जितनी टिप्पणी कर लो, वह हमारा है। अगली बार देखेंगे कि आप कितना काम किये हो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भईया, 15 साल बिगाड़े हो, तेला ठीक करे बर थोड़ा समय लगबे करिही।

श्री अमरजीत भगत :- हाथ जोड़े ले काम नई चलय, तोला बोले ला पड़िही।

श्री अजय चंद्राकर :- हाथ तो मैं माननीय, परमपूज्य डहरिया जी को ही जोड़ता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- दादी, एक बार ध्यान रख लो कि आप मंत्री बन गये हो। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह इस बात को स्वीकार किया, कम से कम उसका प्रदर्शन तो आज मत करो। बोलने के बाद, स्वीकार करने के बाद तो प्रदर्शन मत करो। बार-बार, बार-बार, बार-बार।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, वह दादी का दोष नहीं है। मंत्रि-मंडल में दो प्रकार का बेंच है- एक ताली वाला और एक गाली वाला। इधर माननीय मुख्यमंत्री जी के पीछे जो बैठे हैं सब ताली वाला बेंच है यानी सब चकाचक विभाग है। इधर टी.एस.बाबा साहब बेचारे सिम्स में आग लगे तो वह जवाब दें और गाली खायें, कहीं कोई मर गया तो गाली खायें, उनके किनारे वाले डकैती पड़ा तो गाली खायें या विरोध करें, तो यह गाली डिपार्टमेंट है और उधर ताली डिपार्टमेंट है। (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी, ये भाभी जी के पास बैठते हैं। पहले सत्तू भैय्या बैठते थे वह बिल्कुल ठीक हो गये हैं, अब ये अगली बार बिल्कुल ठीक हो जायेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हमारे जो वर्क्स डिपार्टमेंट हैं जहां पर हमारे काम को आगे विस्तार से बढ़ाने की आवश्यकता है, कहीं न कहीं ऐसे विभागों के बजट में जो कटौती की गई है उसके कारण कार्य प्रभावित होंगे और छत्तीसगढ़ का विकास प्रभावित होगा। हमको लग रहा था कि ये जो युवा हैं, उनके रोजगार के श्रृजन के लिए कोई न कोई कारगर पहल करेंगे इसमें उठायेंगे। 200 फूटपार्क की बात आई थी, लेकिन जब बजट में प्रावधान किये तो 5 फूटपार्क की बात उसमें आई है। मुझे लगा कि शायद 200 बनाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हमारे युवाओं को रोजगार की दिशा में कुछ लाभ मिलेगा, कुछ करने का उनको अवसर प्राप्त होगा, लेकिन उस दिशा में आपने उसे कंट्रोल कर दिया, सीमित करके वहीं पर ब्रेक लगा दिया। ये बहुत बड़ी अपेक्षाएं जो सरकार को ले करके थी और आज भी जो प्रश्न में जवाब आया। जवाब में ये आया कि मुख्यमंत्री जी तो स्वयं अपने ऊपर न ले करके कि बाकी के ऊपर उसको उढेलना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, बल्कि आपकी जनता की जवाबदारी है। जनता उसको सुनिश्चित करे, तो जब आपने घोषणा किया तो उस समय जनता से पूछा क्या? जब जनता सुनी न तो

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

आपको एक लाईन में पूर्ण शराबबंदी की बात करनी चाहिए और उसको बंद कद देना चाहिए। फिर इस बजट में प्रावधान रखने की आवश्यकता नहीं कि दारू से पैसा आए तो दारू के पैसा से हम सरकार चलायें, दारू के पैसे से हम विकास के काम करें, ये आप बंद कर दें तो मुझे लगता है कि शायद उनके जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरी करने में आप सफल होंगे। इसलिए इस विषय पर, ये गंभीर विषय है आज भी जो बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी जो बातें आ रही हैं, केवल ये दारू के कारण ये शराब के कारण है। यदि समाज को सही दिशा में और सबको सकारात्मक दिशा में ले जाएं आप बंद करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होगी और निश्चित रूप से उसमें लोगों को लाभ मिलेगा। उस दिशा में काम करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद थी कि इस बजट के माध्यम से कि जो हमारे किसान हैं और किसानों के बारे में जो पेंशन की बात आई थी, जो 60 साल के हो गये है, 75 साल के हो गये हैं, उसके बाद में जो अन्य लोग हैं, जिनको पेंशन देने की बात आई है । यदि उस दिशा में बजट बढ़ा करके उनको 1000, 1500 रूपये यदि उनको पेंशन देने की बात आई तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को, एक बड़े वर्ग को जो असहाय की स्थिति में और जो दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, ऐसे लोगों को उसका लाभ मिले उसकी चिंता करने की आवश्यकता है। उसमें बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, यदि उसमें बजट बढ़ा करके उनको पैसे दी जाये तो ऐसे लोगों को उसका लाभ मिले लेकिन उसका अभाव दिख रहा है। वहां पर कहीं ये प्रावधान और कहीं ये व्यवस्था नहीं की है हम उसकी चिंता करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत सारे विभाग है, खास करके लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग की मैंने बात बताई। लोक निर्माण विभाग हैं, लोक निर्माण विभाग में हमारे सड़कें की बात हो, पुल, पुलिया की बात हो। इस बजट में पिछला जो 25 सौ 22 करोड़ से 22 सौ 91 करोड़ कर दिये हैं। ये जो कटौती हमारे प्रदेश के विकास में की गई है, ये जो पुल पुलिया बना रहे थे और जो लोग मांग करते हैं, कि अमूल नहीं में अमूक गांव में हमारे पुल पुलिया जोड़ दिया जाये तो नजदीकी बढ़ जायेंगे, शहर से हम जुड़ जाएंगे। ये काम प्रभावित होंगे और इसका प्रदेश के ऊपर में असर होगा। उसी प्रकार से पंचायत और ग्रामीण विकास हमारे हैं ....।

अध्यक्ष महोदय :- 45 मिनट हो चुके हैं और कितना देर बोलेंगे।

माननीय नेता प्रतिपक्ष :- अध्यक्ष महोदय, मैं, जल्दी समाप्त कर देता हूं। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में जो दो प्रकार की बातें हैं, एक तो पंचायत ग्रामीण विकास में और दूसरा ....।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जितनी देर चले हम लोग तो बैठते रहे हैं शुरू से ।

श्री कवासी लखमा (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री) :- अध्यक्ष जी, लेकिन माननीय नेता जी भाषण दे रहे हैं, उधर से साफ होते जा रहे हैं, कुर्सी खाली होती जा रही है। हमारे वरिष्ठ विधायक इधर देख रहे हैं, चेहरा नहीं घूमा रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, इनके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जितना समय बोलेंगे हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं।

माननीय नेता प्रतिपक्ष :- अध्यक्ष जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की बात हमारे ग्राम की जो सारी विकास की योजनाएं हैं, और उनसे लोगों से जो जुड़ी हुई बातें हैं। उसमें जो कटौती की गई है, पहले हमारे 4300 करोड़ रूपये के लगभग और अभी 3500 करोड़ रूपये। इसी प्रकार से आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत में उसमें जो बजट में जो कमी की गई है और इस प्रकार से आप देखेंगे, अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र क्रमांक संख्या 41, 1900 करोड़ से 1700 करोड़, 11 प्रतिशत की कटौती हुई है और कौन से क्षेत्रों में हुई है, जहां पर हमारे वनवासी भाई रहते हैं। जहां पर हमारे जंगल में रहने वाले लोग हैं, जिनके लिए विकास के कार्य चलाये जा रहे हैं। ऐसे कार्यों को प्रभावित करने के लिए ये जा बजट में कटौती की गई है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके जीवन पर, उस क्षेत्र पर उसका असर आने वाले समय में दिखाई देने वाला है । इसमें मैं समाज कल्याण की जो बात कर रहा था कि इसमें कटौती की गई है, खेल एवं युवक कल्याण में एक बड़ी कटौती की गई है। खासकर के खेल युवक कल्याण में हमारे नवजवान साथियों की खेल के मैदान की बात हो, मिनी स्टेडियम की बात हो, स्टेडियम की बात हो, जिससे खेल के क्षेत्र हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा सकें और इसमें कटौती करने का जो कारण है कि हमारे युवाओं को जो प्रेरणा मिलनी चाहिए। कहीं न कहीं ये हमारा प्रदेश है खेल के क्षेत्र में जो अग्रणी जाना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं ये रूकावट है इसलिए ऐसी राशि की कमी की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में मांग संख्या 80 और 90 में 29 प्रतिशत की जो कमी की गई है मांग संख्या 80 और 81 में 3500 करोड़ से 3200 करोड़, मांग संख्या 81 में 2300 करोड़ से 1600 करोड़, ये बजट में जो कमी आई, पूरे छत्तीसगढ़ में हम सब के जीवन पर उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा और उसको जो विकास के कार्य में आगे जाना चाहिए। निश्चित रूप से हम केवल ये देख रहे है सारी जो विकास की बातें आयीं हैं उसमें कहीं न कहीं कटौती करके इस प्रदेश को विकास के रास्ते से पीछे ले जाने का काम, धकेलने का काम किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही मैं देख रहा था कि हमारा जो जंगल सफारी है नंदन वन है उसकी व्यवस्था करने के लिए वन विभाग को जो राशि दी जानी चाहिए। उस राशि पर भी रोक लगा दी है। अब उसको देखने के लिए प्रदेश भर के लोग आते हैं उसमें सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए। वहां के जो पशु हैं और बाकी चीजों में वहां के यदि उसको विस्तार करेंगे और राजधानी में लोग आ रहे हैं तो एक अलग देखने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन आपने उसमें कटौती कर दी है। आज के ही पेपर में उस विषय में छपा हुआ है और इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है उसमें कमी करके आप क्या दिखाना

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चाहते हैं ?उसमें कटौती करके आप क्या बताना चाहते हैं ? ये सरकार की नियत की बात है कि उनकी नियत किस दिशा में जा रही है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो ऐसी चीजों में सरकार को थोड़ा बड़ा मन बनाना चाहिए और बड़े मन बनाकर काम करने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अनुसूचित जाति उपयोजना मांग संख्या 15 में 22 प्रतिशत की जो कमी की गई है और इस प्रकार से आप बहुत सारे आप देखेंगे तो इन योजनाओं में कमी किये हैं और जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को भी उन्होंने दरकिनार किया है इसलिए मैं इस बजट में कि वास्तविक में बजट, इस प्रदेश के विकास की अवधारणा और इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए होनी चाहिए। न कि इसमें सारे कटौती करके, इस प्रदेश को पीछे धकेलने का काम करें। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वित्तीय प्रबंधन की जो बात आयी है कि हमारा वित्तीय प्रबंधन कैसे ठीक हो, उस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है और इन सारी योजनाओं में जो कटौती वर्ष डिपार्टमेंट में की गई है, उस कटौती को समाप्त करें और उसमें बड़े दिल के साथ काम करें तो जिससे प्रदेश के लोगों को लाभ मिले और इस बजट को कुल मिलाकर देखने के बाद में मैं अपनी असहमति व्यक्त करता हूँ और आपने मुझे बोलने का समय दिया है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी आईये। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल):- माननीय अध्यक्ष महोदय, ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं थोड़ा सा आपके पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं पहले दिन भी आपका पहला भाषण हुआ था तो बोला था। आपके दल के अंदर आपका नियंत्रण नहीं है कि लोग इंट्रस्टेड नहीं है आपके मंत्रिगण भी आपके भाषण के समय नहीं रहते। न आपके विधायकगण नहीं रहते और हम लोग चाहते हैं कि आपका भाषण हम बहुत ध्यान से सुनें, देखें, समझे, नये मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं लेकिन वैसा आपका दल ही नहीं चाहता।

नगरीय प्रशासन मंत्री(डॉ शिवकुमार डहरिया) :- सब हैं, आप चिंता मत करिये।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से सामान्य बजट पर चर्चा हो रही है उसमें माननीय मोहन मरकाम जी, माननीय अजय चन्द्राकर जी, माननीय श्री अमरजीत भगत जी, माननीय नारायण चंदेल जी, माननीय दीपक बैज जी, माननीय सौरभ सिंह जी, माननीय केशव चन्द्रा जी, माननीय बृहस्पत सिंह जी, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी जी, रजनीश कुमार सिंह जी, लालजीत सिंह राठिया जी, श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी, इंदु बंजारे जी, रेखचंद जैन जी, डमरूधर पुजारी जी, शैलेष पाण्डेय जी, प्रमोद कुमार शर्मा जी, कुंवर सिंह निषाद जी, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी, शिशुपाल शोरी जी,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विनय जायसवाल जी, डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जी, श्रीमती ममता चन्द्राकर जी, श्रीमती रश्मि आशिष सिंह जी, आशीष छाबड़ा जी, विक्रम मंडावी जी, रामकुमार यादव जी और अंतिम भाषण माननीय नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी का हुआ, मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों को, माननीय सदन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने बहुत अच्छी बातें रखी हैं। विशेष रूप से भाई केशव चन्द्रा जी को और उनकी सहयोगी बहन जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कल आप लोगों ने जो गर्भगृह में प्रदर्शन किया उसमें एक दल ने सहयोग किया है। लेकिन आप पहचान गये और साथ नहीं गये, इसके लिए भी विशेष रूप से बहुजन समाज पार्टी के साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से जो कभी ट्रेजरी बेंच में हुआ करते थे, बृजमोहन जी, अजय जी, बांधी जी ट्रेजरी बेंच में रहे हैं। शिवरतन जी को तो कभी मौका मिला ही नहीं। उन्होंने कभी हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, बृजमोहन जी आपने हमारे खिलाफ, हमारे सदस्यों के खिलाफ कभी कार्यवाही किया? माननीय अजय जी, अपने कभी हमारे किसी सदस्य के खिलाफ कोई कार्यवाही की? आपने नहीं किया। मैं समझता हूं कि इससे सहमत होंगे। क्यों बांधी जी? कभी नहीं किया। जब आपने हम लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की तो बदला कैसे? कोई गाली दे, दले में कोई थप्पड़ मार दे तो वह बदला होता है, आपने हमारे खिलाफ कभी कुछ किया ही नहीं तो फिर बदला किस बात का? यह बदलापुर नहीं, यह वक्त बदलाव का है। (मेजों की थपथ्पाहट) इसको आप देखिये। लेकिन केशव चन्द्रा जी बाद में थोड़ा समझें। सहयोग जिनसे लिये, वह 5 सीट और जो सहयोग दिये वह केवल 2 सीट, वह समझ गये। लेकिन जो हम लोग कहते थे कि ये बी टीम है, सहयोगी दल है, कल सदन में भी दिखाई दिया। दोनों का जो सहयोग है वह कल दिखाई दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धर्मजीत सिंह जी का हम लोग बहुत आदर करते हैं और अभी भी करते हैं, बहुत विद्वान हैं, उनकी विद्वता में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप इनकी संगत में मत आईये, इनके बहकावें में मत आईये। ये आपको बिगाड़ देंगे। गांधी जी की बात हो रही थी, हम लोग उसके रास्ते में चलने वाले हैं। आसंदी में जो बैठे हुए हैं, वह कबीरपंथ के मानने वाले हैं, जो सत्य के रास्ते में चलने वाले, प्रेम और अहिंसा की बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़े संत बाबा गुरू घासीदास जी हुए, उनके छठे वंशज हमारे मंत्रिमंडल में बैठे हैं। हम लोग सत्य और अहिंसा, प्रेम और न्याय के रास्ते में चलने वाले हैं, साहब बदला की राजनीति हमसे नहीं होगी, ये समझ लीजिए। (मेजों की थपथपाहट) लेकिन न्याय के लिए सत्याग्रह करेंगे, सत्य के लिए आग्रह करेंगे, उसमें दृढ़ता हमारी रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में बहुत सारी बातें हुईं। साथियों ने, आप सबसे बजट के कुल आकार 95 हजार करोड़ का है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बड़े अच्छे ढंग से बात रखी कि हम बदले की कार्यवाही नहीं करेंगे । मैं खाली आपका सार्वजनिक बयान याद दिलाता हूं कि आपने सार्वजनिक बयान दिया कि मैं सुपर सी.एम. अमन सिंह को नहीं छोडूंगा । आपका यह बयान क्या सिद्ध करता है ?

श्री भूपेश बघेल :- देखिये, पेपर के हिसाब से आप यहां बात न करें । मैंने तो केवल एक सुपर सी.एम. है कह दिया था उससे अधिक बात नहीं कही ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सारे सोशल मीडिया में आया था ।

श्री भूपेश बघेल :- सुन तो लीजिये । इसी सदन की बात है । उस समय आप भी वहीं थे, मैं भी आपके बगल में बैठता था । उनको नागवार गुजरा और उन्हीं का विभाग है जो मेरे घर को दिन में 3 बार नपवाया और आप कुछ नहीं कर सके थे । आपका कंट्रोल ही नहीं था और जैसे ही आपकी सरकार हटी, दूसरा दिन नहीं लगा वह आपको छोड़कर भाग गये, वे कहां हैं ? (मेजों की थपथपाहट) यदि छत्तीसगढ़ से बहुत प्रेम था, सरकारी नौकरी, भारत सरकार की नौकरी छोड़कर आये थे । अगर छत्तीसगढ़ से इतना प्रेम था तो उन्हें छत्तीसगढ़ में रहना था फिर नौकरी से इस्तीफा क्यों दिये ? क्या हमने उनसे इस्तीफा मांगा ? आप उनके ईशारे में चलते रहे और स्थिति यह रही कि 15 साल की सरकार रही और 15 सीट में सिमट गये । अगर आप अपने विवेक से चलते तो आपकी यह स्थिति नहीं आती । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट का कुल आकार 95 हजार 899 करोड़ । कुल प्राप्तियां 91 हजार 542 करोड़, कुल शुद्ध व्यय 90 हजार 910 करोड़, राजस्व व्यय 78 हजार 595 करोड़, कुल व्यय का 86.68 प्रतिशत । पूंजीगत व्यय 11 हजार 110 करोड़, कुल व्यय का 13.32 प्रतिशत, राजस्व आधिक्य 1 हजार 151 करोड़, राजकोषीय घाटा 10 हजार 880 करोड, जीएसडीपी का 9.99 प्रतिशत जो एफआरबीएम एक्ट द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत है । माननीय नेताप्रतिपक्ष जी ने इस बारे में बहुत विस्तार से बात की और मैं समझता हूं कि इन सब बातों को माननीय सभी सदस्य समझते हैं । जो आर्थिक स्थिति है वर्ष 2018-19 में स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी विकास दर 6.08 प्रतिशत भारत का जो जीडीपी है विकास दर 7.2 प्रतिशत अनुमानित है । अखिल भारतीय वृद्धि दर से राज्य की वृद्धि दर में 1.12 प्रतिशत कम होना अनुमानित है । कृषि के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 3.8 प्रतिशत है, वृद्धि के विरूद्ध में राज्य में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । औद्योगिक क्षेत्र में 7.8 प्रतिशत के विरूद्ध 5.4 प्रतिशत, सेवा के क्षेत्र में 7.3 प्रतिशत के विरूद्ध में 6.9 में राज्य की वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर से कम रहने का अनुमान है ।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय 96 हजार 887 रूपये संभावित है । जो गत् वर्ष की तुलना में 7.9 प्रतिशत अधिक है । इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 11.1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बहुत सारी कटौतियों की बात कही कि इतना पैसा कहां से आयेगा, कैसे आप किसानों के ऋण माफ करेंगे ? पिछली सरकार में आपने देखा होगा मोबाईल बांटने के लिये 14 सौ करोड़ का बजट आपने दे दिया । 3 उद्योगपतियों के स्टाम्प ड्यूटी में छूट 16 सौ करोड़ रूपया आपने दे दिया । 3 हजार करोड़ आपने ऐसे ही लूटा दिया और आज हमसे हिसाब मांगते हैं, किसानों को यदि दे रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है ? हम सभी किसानों को, आप कहते हैं ट्रेक्टर वालों को नहीं मिला, बारवेट वॉयर (Barbatewire) लिया उसको नहीं मिला, मध्य श्रेणी का जो ऋण लिये उसका नहीं मिला । जो बात हम लोगों ने किसानों से कही, किसानों ने वही सुना और वही समझा । हमारी बात को उन्होंने समझा, अन्नदाताओं ने समझा और हमको वोट दिया, तीन चौथाई बहुमत में आये हैं । (मेजों की थपथपाहट) और आज कोई किसान नहीं कह रहा है कि ट्रैक्टर का क्यों नहीं किया, मध्यकालीन ऋण का क्यों नहीं किया और माननीय अजय जी तो किसानों के जो 4 हजार करोड़ के बारे में बात कह रहे थे । ये बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया है । ये बड़े लोग कौन हैं ? ये किसान हैं और किसान कभी बड़ा नहीं होता, आप समझ लीजिए । फार्म हाऊस वाले बड़े किसान हो सकते हैं । जो दूसरा धंधा करते हैं और फार्म हाउस बनाकर रखे हैं । लेकिन जो किसान खेती कर रहा है और ये वह लोग हैं, आपने 30 नवम्बर की जो बात कही, ये वह क्षेत्र है जहां चना लेते हैं, गेहूं बोते हैं जो उन्हारी लेते हैं । चाहे रविन्द्र चौबे जी का क्षेत्र हो,चाहे अकबर जी का क्षेत्र हो, चाहे आपके नेता ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने उसमें बात कही थी कि आप उसमें खरीफ कर रहे हैं या पूरा ऋण कर रहे है । मैंने इसलिए भी कहा था कि व्यवसायिक बैंकों के ऋण देने की प्रवृत्ति दूसरी है और सहकारी बैंकों के ऋण देने की प्रवृत्ति दूसरी है । नियमों को आप देख लीजिए, आपके पास पूरी संस्थाएं हैं । आप अचानक यदि 4 हजार करोड़ का निर्णय लेते हैं तो जो बातें मैंने कही वह अभी भी मेरे जेहन में हैं । आप कहेंगे तो मैं सहमत हो जाउंगा, यदि आपकी बात आएगी तो ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चिंता न करें, जो माफ होगा, हम लोग उसके नियम बनाएंगे, बजट में 4 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। जो ऋण माफी को-ऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंक में की है उसके अनुपात में ही होगा, इस बात को समझ लीजिए (मेजो की थपथपाहट) । अध्यक्ष महोदय, हमारा कृषि बजट, वह पिछले बजट की तुलना में डेढ़ गुना से भी अधिक है । हमारी प्राथमिकता किसान रहे हैं और यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है । 75 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं और अधिकांश लोग कृषि से जुड़े हुए हैं । यदि किसान खुशहाल है तो पूरा छत्तीसगढ़ खुशहाल होगा । आपने उनसे वोट लेने के लिए वायदा कर लिया लेकिन उनके लिए कुछ किया नहीं । 2003 में भी आपने ऋण माफी की बात की थी और ढाई हजार रूपए की छूट दी । 106 करोड़ रूपया दिया था । आज छत्तीसगढ़

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

में कांग्रेस की सरकार ने 10 हजार करोड़ का ऋण माफ किया है (मेजो की थपथपाहट)। अब, आप किसानों की भाषा नहीं समझ पाए या आप नहीं समझा पाए, यह आप लोगों की कमजोरी है । हमने कहा कि हम क्रॉप लोन ही माफ करेंगे और वह बात हम कहते थे, वही बात वे कह रहे हैं, यह बात वे समझ गए । इसमें इतना विवाद करने की आवश्यकता नहीं है । आप ट्रैक्टर के पीछे मत पड़ें । ट्रैक्टर वाला भी शॉर्ट टर्म लोन लेता ही है । ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ट्रैक्टर लिया है वे शॉर्ट टर्म लोन नहीं लेते, वे खाद बीज के लिए लोन नहीं लेते । ऐसा तो है ही नहीं और उनका भी ऋण माफ हुआ है । बल्कि उनका ज्यादा माफ हुआ होगा, अगर आप गांव के हिसाब से देखेंगे तो । अध्यक्ष महोदय, ये कहते रहे धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपया और 300 रूपया बोनस देंगे लेकिन आपने कभी दिया नहीं । आप केवल चुनाव के लिए देते रहे । यह पहला राज्य है जो 2500 रूपए क्विंटल में धान खरीद रहा है और किसानों के खाते में पैसा जाना शुरू हो गया है (मेजो की थपथपाहट) । अध्यक्ष महोदय, हम यहीं तक नहीं रूके । हमने किसानों के जलकर की 207 करोड़ की राशि को भी माफ किया है (मेजो की थपथपाहट) । अध्यक्ष महोदय, सोयाबीन के उत्पादन की प्रोत्साहन राशि के लिए10 करोड़ का प्रावधान । केवल धान के लिए ही नहीं, हमने गन्ना बोनस के लिए भी 50करोड़ का प्रावधान किया है । दलहन-तिलहन के प्रोत्साहन के लिए भी हमने 7 करोड़ 21 लाख की राशि रखी है ।

अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो पहले मुख्यमंत्री थे उन्हें किसी ने मुसली उगाने की सलाह दी । बजट में कोई प्रावधान नहीं था । लेकिन आपने रतनजोत पर कितने करोड़ खर्च कर दिये और कहीं एक लीटर डीजल भी बना ? अभी हमारे कवासी लखमा जी बोल रहे थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वो डीजल बनाने की सलाह देने वाले भी आपकी जगह में आकर बैठ गए हैं, अब देखिएगा थोड़े ही दिनों में आपको भी सलाह देंगे । एक्सपोर्ट करके उनको लाए हैं, डीजल बनाने की सलाह के लिए ।

श्री अमरजीत भगत :- सरगुजा जिले में जितना रकबा नहीं है, उससे ज्यादा में रतनजोत लग गया पूरे-पूरे जिले में।

श्री भूपेश बघेल :- बड़े-बड़े होल्डिंग लगे रहते थे। डीजल नहीं अब खाड़ी से, डीजल मिलेगा अब बाड़ी से। और माननीय अकबर जी ने प्रश्न किया था कि एक लीटर डीजल आप नहीं कर पाये, 100 करोड़ से ऊपर खर्च कर डाले तो उन्होंने कहा डीजल नहीं अब बाड़ी से तो क्या वापस जाये क्या खाड़ी में। यह उन्होंने कहा था। तो आपने सैकड़ों करोड़ों रूपये बर्बाद करके बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया है । उसे खा-खाकर लोग हॉस्पिटल जाते रहे हैं। उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। न मवेशी के खाने के काम आया न डीजल बनाने का काम आया। जिसकी आप हंसी उड़ा रहे थे। अभी कह रहे थे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गोबर बनाने खण्डा गोबर खापे पर ते देबे ओकर से रोजगार मिलही। यह जो नारा है वह जनमानस से निकला है । मेरे क्षेत्र में एक व्यक्ति आया। उन्होंने कहा कि मैं अब गाय नहीं पाल सकता, उसे गौशाला में भेजने के लिए आप फोन लगा दीजिए। मेरे पास वह एप्रोच लगाने के लिए आया कि अब मैं गौ-पालन नहीं कर सकता क्योंकि मिसेज की तबियत खराब रहती है। वह बाथरूम में गिर गई है। उसकी हड्डी टूट गई है और सेवा वही करती थी। अब वह नहीं कर पायेगी इसलिए गाय को गौशाला में भेजने के लिए आप फोन लगा दीजिए। मैंने कहा क्यों? बेच नहीं सकते। वे बोले कि कोई खरीदार नहीं है। फिर मैंने उससे कहा कि किसी को दान दे दीजिए। वे बोले कि दान में भी लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। यह एक घटना। दूसरी घटना, मैं अपने कार्यकर्ता के पास साथियों के साथ बैठा था। बरसात के दिनों में गया था, मीटिंग लिया बोला कि क्या स्थिति है? हाल-चाल पूछा तो बोले फसल तो बहुत बढ़िया है लेकिन हम लोग चराई से परेशान हैं और एक गांव के मवेशी को हम दूसरे गांव में इकट्ठा किये। मेटाडोर में भरे और उसे दूसरे गांव में छोड़कर आये। वो तो भागकर आ गये, नहीं तो गांव वाले लाठी लेकर पीछे पड़ गये थे, जिस गांव में छोड़कर आये हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में कमोबेश स्थिति यही है। एक गांव के मवेशी को दूसरे गांव में छोड़ रहे हैं। दूसरे गांव के मवेशी को तीसरे गांव में छोड़ रहे हैं। लड़ाई झगड़ा का कारण बन गया है, जो हमारे आर्थिक स्थिति के लिए किसानों के लिए......

श्री अजय चन्द्राकर :- पाटन के हरहा गरवा कुरूद पहुंचथे नदी में आके। एकर से हमन परेशान हन। ऐला तो निजात दिलवा ते हा।

श्री भूपेश बघेल :- मैं आप ही की व्यवस्था कर रहा हूं चिंता मत करो।

श्री रविन्द्र चौबे :- क्या बात है। क्या बात है।

श्री भूपेश बघेल :- अब कोई मवेशी आपको सड़क पर दिखाई नहीं देगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- पाटन डहान के हरहा गरवा ऐती आथे काबर। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- ऐसा है.........

श्री रविन्द्र चौबे :- विरासत से कुरूद में आ रहे हैं.......

श्री भूपेश बघेल :- चौबे जी कुछ बोल रहे हैं (हंसी) एक गंभीर समस्या जो मवेशी किसानों की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार हुआ करता था, आज वही मवेशी किसानों की परेशानी का कारण बना हुआ है। ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात। शहर में आप क्या सुझाव दे रहे हैं? आप रेडियम पट्टा लगा दीजिए। एक्सीडेंट नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ कि तमाम दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, उसमें बड़ा कारण कारण है कि मवेशी सड़क में बैठे रहते हैं। ट्रक वाले, मोटरसाइकिल वालों का, कार वालों वहां एक्सीडेंट हो रहा है। उससे जान-माल की हानि हो रही है। यह चिंतन का विषय है कि आखिर यह क्यों ?यह स्थिति क्यों बन रही है? और इस सब चीज को आज पानी की समस्या, रामकुमार यादव जी ने अभी कहा कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महानदी के तमाम बैराज आप उद्योगपतियों को दे दिये। किसानों के लिए कुछ नहीं किये। आपकी पहली सरकार रही। आपने किसानों के लिए योजना न बनाकर उद्योगपतियों के लिए बनाई। तो पानी की समस्या। मवेशी एक समस्या और आज कंपोस्ट खाद, आज हमारे कृषि कार्य में कृषि लागत इतनी बढ़ गई है, उसके लिए क्या करना है? कृषि लागत कम हो, जिसके बारे में आपने कहा । ऋण माफी स्थाई हल नहीं है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा, मैंने अभी दो उदाहरण दिए, आप उद्योगपतियों के 1600 करोड़ रूपये की स्टाम्प ड्यूटी माफ कर सकते हैं, केन्द्र सरकार तीन लाख करोड़ रूपये माफ कर सकते हैं तो क्या हम लोग किसानों का ऋण माफ नहीं कर सकते ? इसलिए हमने किसानों का ऋण माफ किया है। लेकिन दूसरी समस्या निजात दिलाने के लिए, हमने कहा कि ऋण माफी से काम नहीं चलेगा, किसानों के उपज का मूल्य भी मिलना चाहिए। इसलिए पूरे देश में सर्वाधिक 2500 रूपये क्विंटल में धान खरीदी का फैसला किया है, ताकि हमारे किसान आर्थिक रूप से मजबूत हों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा नारा है-" छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी, येला बचाना हे संगवारी" यह हमारी छत्तीसगढ़ की परम्परा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की परम्परा है। लेकिन आज कोई गांव में रहना नहीं चाहता है। यदि आज किसानों को दाम मिलना शुरू हो जाए, हम मवेशी की व्यवस्था कर दें, वहां आवागन की सुविधा कर दें, उनके बच्चों के शिक्षा की उचित व्यवस्था कर दें, तो कौन आदमी गांव को छोड़कर शहर आना चाहेगा। लेकिन आज गांव में व्यवस्था बिगड़ चुकी है। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आज यह स्थिति है। उसमें हमको कहीं न कहीं शुरूआत तो करनी पड़ेगी। इसके लिए बजट नहीं है, बजट है, पैसे हैं। ग्रामीण विकास विभाग में है, पशुपालन विभाग में है, कृषि विभाग में है, इसको केवल समायोजित करने की आवश्यकता है। यह आपकी दृष्टि में नहीं आई तो यह आपका दोष है। लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि उस पैसे का क्या करना है। केवल बिल्डिंग बना देने से विकास नहीं होता है। जो लोग वहां रह रहे हैं, ढाई करोड़ जनता जो रह रही है, उनके जीवन में परिवर्तन आये, उनके जीवन में खुशहाली आये, यह विकास हमारा पैमाना है। आपके विकास का पैमाना कांक्रीट है। आपके विकास का पैमाना गिट्टी और सीमेन्ट है। हमारा विकास का पैमाना व्यक्ति है, किसान है, मजदूर है, आदिवासी है, अनुसूचित जाति है, नवजवान है, यह हमारा पैमाना है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत नहीं है। अजय जी, आप पकौड़ा और गोबर से तुलना कर रहे थे। मुझे बहुत दु:ख हुआ। ये जो ट्रेनिंग देंगे, वह गोबर गैस प्लाण्ट के लिए है। आज जो इंडीव्यूजवल गोबर गैस प्लाण्ट लगा रहे हैं, बहुत जगह सफल है और अधिकांश जगह असफल हो गया है। हम यदि गौठान को घेर दें, हम प्रत्येक गांव में 3 एकड़ को घेरने की व्यवस्था कर रहे हैं, ज्यादा मवेशी हैं तो 4 एकड़ घेर लें, 5 एकड़ कर लें, ग्राम पंचायत है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समय था, गवर्नमेंट ने गोबर गैस प्लाण्ट लगाने के लिए 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी थी। आज उसकी क्या स्थिति है, आप उसको देख लो। जो 90 प्रतिशत सब्सिडी में गोबर प्लाण्ट लगे उनकी स्थिति आप देख लो।

श्री भूपेश बघेल :- शिवरतन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने कहा न कि जो लोग प्रापर ध्यान दे रहे हैं उनके यहां गोबर गैस प्लाण्ट चल रहा है। लेकिन जहां ध्यान नहीं दे पाये, वह असफल है। मैं यही तो कह रहा हूँ। आप उसके लिए ट्रेनिंग दीजिये, उसको बराबर पेमेन्ट दीजिये, क्योंकि एक किसान जब अपने घर में लगाता है, तो उसकी अलग-अलग समय अलग-अलग प्राथमिकताएं होती हैं। यदि खेती-किसानी का समय है और यदि परिवार में गमी है तो वह खेत छोड़कर नहीं जाता, वह किसी और को भेज देता है, वह बाद में चला जाता है। उस समय वह गोबर गैस प्लाण्ट को सुधारेगा या वह खेत में जाकर काम करेगा। तो उस समय किसान की प्राथमिकताएं बदलती हैं। चाहे धान कटाई का समय हो, चाहे रोपाई का सीजन हो, चाहे चना बोना है, काटना है, उस समय उसकी प्राथमिकताएं अलग-अलग होती है। यदि हम उसमें परमानेंट आदमी लगा दें। हमारे जो नवजवान जो 10वीं, 12वीं पढ़े लड़के हैं, उनको ट्रेनिंग दे दें, तो उसमें वह लगातार काम करता रहेगा। आज आप उज्जवला योजना की बात कर रहे हैं, उसकी रिफिलिंग कौन करा रहा है, कितने लोग करा रहे हैं, आप एक हजार रूपये में गैस दे रहे हैं, उसमें रिफिलिंग कितने लोग करा रहे हैं ? कोई नहीं करा पा रहा है। अधिकांश लोग नहीं करा पा रहे हैं। यदि उसी गोबर प्लाण्ट से गैस निकलेगा, उसमें पाईप लगाकर घर-घर तक पहुंचा दीजिये या वहीं सिलेण्डर भरने की व्यवस्था कर दीजिये, यदि 3 हजार, 4 हजार ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उज्जवला की आलोचना की, लेकिन आपके घोषणा-पत्र में चार गैस सिलेण्डर देंगे, ये शामिल है । आप उसको दूसरे तौर पर स्वीकार कर रहे हैं । एक तरफ आप आलोचना कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसको घोषणा-पत्र में स्वीकार भी कर रहे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, बल्कि उससे अवगत करा रहा हूं । उसकी क्रय शक्ति है ही नहीं, लोगों की क्रय शक्ति नहीं है, इस कारण से वह नहीं ले पा रहा है । कौन चाहता है कि गैस में खाना न पके, लेकिन क्रय शक्ति है ही नहीं, वह किसान खरीद नहीं पा रहा है । हम क्रय शक्ति बढ़ाने का काम कर रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी गोबर गैस से आप घर-घर में जितनी उसकी केपेसिटी है, उतने घरों में आप कनेक्शन दे दीजिए, उससे सस्ते में भोजन पक जायेगा । जो पंचायत के द्वारा पैसा आयेगा, वह बेरोजगारों को भी मिलेगा और वहीं वर्मी खाद और कम्पोज खाद बनाने की यूनिट डाल दीजिए, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी । आप तो स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, स्मार्ट घुरवा ही बना लीजिए । गांव-गांव में स्मार्ट घुरवा बन जायेगा । (मेजों की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

थपथपाहट) जो यहां-वहां पड़ा रहता है, वह एक जगह रहे । आज प्रदूषण की कितनी समस्या है, हम सब उस पर चर्चा करते हैं । सुप्रीम कोर्ट तक कहते हैं कि दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है । क्योंकि आसपास के राज्यों से फसल कटाई के बाद जो पैरा बचता है, उसे जलाते हैं । हमारे छत्तीसगढ़ में भी हारवेस्टिंग हो रहा है और यहां भी जला रहे हैं । उसी पैरे को मनरेगा के तहत इकट्ठा कर लीजिए, कुट्टी काटने की व्यवस्था कर दीजिए, हरे चारे की भी व्यवस्था कर दीजिए । आज सभी जगहों में मक्का खूब हो रहा है । उससे जो निकल रहा है, उससे कुट्टी काट दीजिए, मवेशी को बिठाकर खिलाईए, नस्ल सुधार करने की व्यवस्था करिए। गांव में दूध की नदिया बहेगी । नस्ल सुधार करेंगे तो दूध का उत्पादन बढ़ेगा। ये जो ग्रामीण व्यवस्था है, उसको सुधारने की आवश्यकता है । यदि ये करेंगे तो तीन एकड़ को घेर देंगे तो यदि गांव में 1 हजार एकड़ का रकबा है तो हमको एक हजार एकड़ को घेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी । जो चरवाहा हैं, उसको आप बारह महीने वहां पर मजदूरी दीजिए । व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है, इतनी व्यवस्था तो आपको करनी ही है । ये सारे विभागों के बजट से हो जाना है । इसमें अतिरिक्त क्या बात है कि उसमें बजट नहीं रखे, बजट नहीं रखे, वही हश्र होगा, जो मुसली का हुआ, वही हश्र होगा, जो रतनजोत का हुआ। ये गांव से निकला हुआ चिंतन है और हमारे छत्तीसगढ़ में लागू होगा और ये सब पसंद कर रहे हैं । किसानों ने कहा, मैं अनेक गांवों में गया हूं, खुद ग्राम सभा में गया हूं, उन्होंने कहा कि ये बात हमारे समझ में पहले क्यों नहीं आई ? यदि ये सोच हमारे मन में आई है और इसको हाथों-हाथ सारे लोग ले रहे हैं तो इसको तो आपको बढ़कर करना है । ये छत्तीसगढ़ के लिए है और ये पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगा। आज खुले में जो मवेशी चर रहे हैं, उससे पूरा देश परेशान है । एक नया रास्ता निकलेगा । हम तो इस योजना को पूरे शहर में भी लागू करेंगे । वहां चारा भी हो जाए, गोबर गैस प्लांट भी बन जाए, खाद बनाने की यूनिट हो जाये, ये आर्थिक होगा, अनार्थिक नहीं । ऐसे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, गैस भी मिलेगा और चार लोगों को, नगर निगम, नगर पंचायत को चार पैसे भी मिलेंगे, फिर मवेशी कहां खुले में घूमता नजर आयेगा ? रेडियम बांधने की जरूरत नहीं है, हर शहर में इस प्रकार की व्यवस्था, आपने जितने आऊटर ग्रोथ आपने बनाया, नेता प्रतिपक्ष के शहर में भले ही आउटर ग्रोथ में एक गांव नहीं लिये हैं, लेकिन रायपुर में तो आऊटर ग्रोथ है। वहां जो गौठान की जमीन है, उसी में आप घेरा कर दीजिए, शेड बना दीजिए, ये क्यों नहीं हो सकता, हम मवेशी की सेवा क्यों न करें ? ये जो योजना है, उसमें आप सबकी भागीदारी की आवश्यकता है । जहां तक नालों की बात है, वह नाला शुरू से वाटर रिचार्जिंग कर लीजिए, आप पंचायत मंत्री थे, पूर्व राजस्व मंत्री भी बैठे हैं, लेकिन भुइयां कार्यक्रम में हमने सेटे लाईट से जो इमेज लिया था, उसका उपयोग आपने 15 साल नहीं किया । यदि उसको कर लेते तो वाटर रिचार्जिंग आजतक सभी छत्तीसगढ़ के जितने नदी-नाले में हो चुका होता, हम 15 साल पीछे रह गए और जहां-जहां आपके फ्रैक्चर्स हैं, उस

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मामले में मेरा 2004 का पुराना भाषण निकाल लीजिएगा, पीएचई विभाग से मैंने कराया था, मेरा भाषण विधान सभा के पुस्तकालय में होगा, उसे निकाल लीजिए और मेरे भाषण के बाद रमन सिंह जी मेरे क्षेत्र देखने गए भी थे कि वाटर रिचार्जिंग कैसे किया जाता है, लेकिन उसके बाद एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट पूरे छत्तीसगढ़ के किसी विधान सभा में नहीं आया था । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आज पानी के लिए सब लोग परेशान हैं, सिंचाई के लिए परेशान हैं, पेयजल के लिए परेशान हैं, लेकिन वाटर रिचार्जिंग का काम कोई नहीं कर रहा है । हम वाटर रिचार्जिंग की तरफ बढ़े । आपने नदियों में स्टॉप डेम तो बना दिया, लोग शिल्टिंग के कारण परेशान है, यदि हम नालों को ट्रीटमेंट करते आये तो नदी में शिल्ट नहीं होगा । उससे बचना होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आपको एक बात कही थी । बजट की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी । चूंकि अध्यक्ष महोदय ने उसमें एक चर्चा स्वीकार कर ली है, जिस दिन भी तय करे । आप बोलिये, आपके बोलने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है । एक कार्यक्रम की आप संस्मरण सुना रहे हैं, मेरे और आपके कांस्टिटयूऐंसी के बीच में खारून नदी बहती है । छत्तीसगढ़ की सबसे मरती हुई नदियों में खारून नदी है । जो आप नालों के लिए कर रहे हैं, नरूवा, घुरवा, गरूवा, बारी उसमें विस्तार से चर्चा होगी । नदी के संरक्षण के लिए भी और दूसरी चीजों के लिए भी, जब उसमें मजबूत कार्यक्रम आये, हमने उसमें कार्यक्रम शुरू किया था, वह रूक क्यों गया, शहरी क्षेत्र में नदियां यदि रायपुर में बह रही है, उसके लिए आर्थिक प्रबंध कैसे होगा । ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी हमने सफाई करवाई । शहरी क्षेत्रों में नहीं हो पाया । ऐसी स्थिति सब जगह बनेगी । इसलिए यदि आप काम करते हैं तो नरवा जो है, शहरी क्षेत्र में भी बहेगा । आप जो रेगुलर बजट की बात कर रहे थे ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ऐसा है कि माननीय अजय जी बोल रहे हैं कि खारून नदी, एक पार्ट में आप है, दूसरे पार्ट में मैं हूँ, धनेन्द्र भईया भी हैं, आप ही के यहां पिचिंग हुआ है । ना धनेन्द्र भईया के क्षेत्र में हुआ ना मेरे क्षेत्र में हुआ है । एक तरफ सुरक्षा करवाये हैं, मेरे तरफ तो नहीं हुआ है । मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ यदि आप नदियों को जीवित करना चाहते हैं तो नालों को सुरक्षित करना होगा । आप स्टॉप डेम तो बना दिये, पानी रूक नहीं रहा है । आप यदि वैज्ञानिक विधि से स्टॉप डेम करते हैं, उसके पास वह नक्शा था, यदि इमेजरी है उसका उपयोग आप करते, वहां जहां फ्रेक्चर्स हैं, नीचे आपके स्टॉप डेम, बोल्डर चेक डेम या डाईक वाल बनाते, निश्चित रूप से वाटर रिचार्जिंग होता । आपको सतही जल भी मिलता । आपने वैसा किया नहीं । जहां चाहे वहां आपने बना दिया । उसका नुकसान पूरे छत्तीसगढ़ को हो रहा है । पैसेका अपव्यय हुआ है । यदि आप वैज्ञानिक विधि से करते, एक-एक नाला का आप ट्रीटमेंट करते आईये, आपकी सारी नदियां पुनर्जीवित हो जायेगी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- देखिये, सैद्धांतिक रूप से जो आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी है । व्यावहारिक रूप से क्या यह कर पाना संभव है । आप नरवा की जो बात कर रहे है, आज छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी समस्या है, नरवा, गौठान, धरसा और मरघट । यह सब अतिक्रमण के भेंट हो गये । तीन एकड़ जमीन अपने को गौठान के लिए चाहिये । हमको नरवा की व्यवस्था करना है । आपको पहले इस कार्य की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा । यह अतिक्रमण हटकर जगह सुरक्षित करें । आप झगड़ा करवाने वाली बात क्यों करते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जो वास्तविकता है । यह पूरे गांव की स्थिति है ।

श्री भूपेश बघेल :- ग्राम सभा में हमने अधिकार दे दिया है । वह चिन्हांकित कर ले । ऐसा लगता है कि आप बैठक करवाने नहीं दे रहे हैं, अभी भी आपके प्रभाव में है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ग्राम सभा को अधिकार देने की बात कर रहे हैं । ग्राम सभा में सरपंच किसी भी पार्टी का हो, वह अतिक्रमण हटाने में सक्षम है क्या । बिना शासन के सहयोग के अतिक्रमण हट नहीं सकता । आप इसको क्रियान्वित करना चाहते हैं तो पहले आपको इस व्यवस्था को करना होगा। वह तो शुरू से अधिकार है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामसभा मतें तयकर लें, मैं भी ग्राम सभा में गया था, वहां मरते हुये डबरी है, उसको चिन्हांकित किया । सुप्रीम कोर्ट का गाईड लाईन है, आप इस तालाब का उपयोग नहीं कर सकते । उनको बताया गया, ग्राम पंचायत के सचिव ने भी कहा । आप दूसरे जगह देख लीजिए, उन्होंने बताया कि इस खसरे नंबर पर तीन एकड़ जमीन है, वहां दो-चार छायादार वृक्ष भी हैं,

वहीं आप चिन्हांकित कर लीजिए । वहां प्लेटफार्म भी बनाईये, घेरा भी करिये, पानी की व्यवस्था भी करिये, चारा की भी व्यवस्था करिये, आपके गोबर गैस प्लाण्ट भी डालिये, कंपोस्ड खाद बनाने का काम, एक साथ आप सभी काम करेंगे, निश्चित रूप से आर्थिक होगा, अनार्थिक नहीं होगा । यह मैं निवेदन कर रहा हूँ । जहां तक जगह की बात है, लड़ाई-झगडा करने की जरूरत नहीं है । यदि आपके पास गौठान सिकुड़ गया है, आप दूसरे जगह चिन्हांकित कर लीजिए । यदि आपको अतिक्रमण हटाना है, हटा लीजिए, नहीं हटाना है तो मत हटाईये । उसमें क्या है, इसमें लडाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसके लिए आपके यहां कुरूक्षेत्र नहीं बनाना चाहते। गांव के लोग मिलकर तय कर लेंगे। यह हमारा कान्सेप्ट है कि-

छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी
नरवा, गरवा, घुरूवा, बारी
येला बचाना हे संगवारी.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

और काम शुरू हो गया है। नोडल जो विभाग है वह रविन्द्र चौबे जी के पास रहेगा। आप कल जो प्रश्न कर रहे थे उसका उत्तर यही है कि सभी विभाग इसमें साथ देंगे लेकिन नोडल विभाग कृषि विभाग होगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है कि तीन विषय आ गया, अब बारी की बात आती है। छत्तीसगढ़ के गांवों में परंपरा रही है कि पहले गांव में 16-17 हाथ का कुआं हुआ करता था, उसमें टेड़े से लोग बारहों महीना निस्तार करते थे और निस्तार का जो वेस्ट पानी है वह बारी के काम आता था। आज की तारीख में गांव में कुआं समाप्त हो गये। बाद में 100 फीट की बोरिंग का कान्सेप्ट आया, आज गांव में छः महीना बोरिंग बंद हो जाता है तो बारी के लिए पानी की भी व्यवस्था चाहिए ना।

श्री भूपेश बघेल - बिल्कुल होगा। जब हमारे नाले का ट्रीटमेंट कर देंगे तो सब-स्वायल वॉटर भी होगा। आपका बोर में पानी चल रहा है और कुआं क्यों सूख गया क्योंकि आपका सब-स्वायल वॉटर है ही नहीं। तो आप नाले का ट्रीटमेंट करते आईये, आपके जमीन में नमी आयेगी और उससे आपका कुआं भी रिचार्ज होगा और ट्यूबवेल भी रिचार्ज होगा और आपको नये स्रोत भी मिलेंगे। मैं समझता हूं कि शिवरतन जी इतना पर्याप्त होगा, आप समझ गये होंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बाकी समझ गये हैं। आपने जब बजट प्रस्तुत किया तब हम समझ गये थे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि दूसरे विभागों के बजट में जो कटौती करनी पड़ी उसका कारण ही यही है कि हम कृषि के क्षेत्र में ज्यादा दिये हैं और इस कारण से कमी आई है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपसे बस यह निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि बिलासपुर में एक सीवरेज प्लांट लगाने के लिए 10 साल से इधर वालों की सरकार ने काम किया, उससे कई लोग मर गये। आपके लोगों ने वहां विरोध भी किया है, शायद आपके नेता लोग या आप भी बोले थे कि इसको बंद कर देंगे और उसमें पर्चे लगे थे। यह बजट सत्र है, मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि उस प्लांट या उस योजना को आप बंद करेंगे या चलायेंगे? इन लोगों को पता नहीं कौन महापुरूष सलाह दिया था कि रायपुर में स्काई वॉक बना दो। उस महापुरूष के कहने से स्काई वॉक बना और अभी-अभी कोई और महापुरूष पैदा हो गये, उन्होंने कहा कि वहां बाजार लगायेंगे, ऊपर में टमाटर बेचेंगे। तो उसको भी बता दीजिए?

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें जन सुनवाई चल रही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मुख्यमंत्री जी, उसको पूरी तरह से डिस्मेंटल कराईये और आप दिल्ली जाकर मेट्रो रेल के लिए उसको बनाईये। ये फालतू का स्काई वॉक। वहां सब सुई लगाकर, इंजेक्सन लगाकर,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नशा करने वाले लोग रहेंगे या फिर वह सुसाईडल पाईंट रहेगा। मैं चाहता हूं कि बजट में आप इन दोनों योजनाओं के बारे में सरकार की नीति, नीयत के बारे में बता दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, स्काई वॉक के बारे में मैंने बृजमोहन जी से भी पूछा कि इसका क्या करना चाहिए। उसको तोड़ने का भी पैसा लगेगा, साहब। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- वह थोड़ा ही लगेगा लेकिन वह तो जीवनभर के लिए नासूर बन जायेगा। रायपुर शहर की दुर्दशा करा देगा।

श्री भूपेश बघेल :- उसका सही सदुपयोग हो इसलिए मैंने सबसे सलाह मांगी है। सीवरेज में भी आपसे सलाह ले लेंगे, शैलेष पाण्डेय जी भी हैं, आप हैं, नेता प्रतिपक्ष जी भी हैं, सबसे सलाह लेंगे और जो उस शहर के लिए अच्छा हो वह सब काम करेंगे। ऐसे कामों में आपसे सहयोग लेने में हमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन नेता जी, सवाल इस बात का है कि उसमें पूर्व मंत्री जी नाराज न हों, ये देख लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- किसी की नाराजगी और किसी की संतुष्टि के लिए नहीं है। वास्तव में सीवरेज का जो प्रोजेक्ट है, जिस भावना से लाये होंगे वह अच्छी भावना से लाये होंगे, काम भी शुरू किए। यह छत्तीसगढ़ के लिए एक नया प्रोजेक्ट था। अब उसमें काफी पैसा लगा चुके हैं। शहर के लोग भी ये चाहते हैं कि आखिर उसका निराकरण हो। तो एक बार उसका पूरा परीक्षण कराना चाहिए। परीक्षण कराने के बाद में कितना सफल है,...

श्री रवीन्द्र चौबे (संसदीय कार्य मंत्री) :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा न, माननीय धर्मजीत भैया ने कहा कि वहां का सिवरेज वाला और यहां का स्काई लेब क्या बोले (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय वो एक प्रकार का स्काई लेब ही है। क्योंकि लोग उसमें कूदेंगे तो शास्त्री चौक पर मरेंगे।

श्री रवीन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, ये इनकी पार्टी का सोसाईडल एक्ट है दोनों समझ लीजिए। ता आपने पूछा ....।

माननीय नेता प्रतिपक्ष :- अध्यक्ष महोदय, मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूं।

श्री रवीन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, तो आपने पूछा ये 8 मार्च तक चलेगा विधानसभा, जो सुझाव देना है बहुत अच्छे से दे दीजिए। मुख्यमंत्री आपसे भी पूछ रहे हैं, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी से भी पूछ रहे हैं, माननीय धर्मजीत भैया जी से भी पूछ रहे हैं, कुछ तो सुझाव दो भैया।

माननीय नेता प्रतिपक्ष :- अध्यक्ष जी, मैं सुझाव दे रहा हूं न । मैं इसीलिए खड़ा हूं। मैं सुझाव दे रहा हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, सुझाव देना था, इसीलिए तो मैं पूछा।

श्री रवीन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, अब आप सुझाव दे दीजिए फिर कि क्या करना है ? (हंसी)

माननीय नेता प्रतिपक्ष :- नहीं, नहीं मैं उसमें सुझाव दे रहा हूं न।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, तोड़ दो तो बोल रहा हूं मैं और कैसा सुझाव दूं। इसको तोड़ दीजिए(हंसी) इसको बना दीजिए। यहां कोई आधे अधूरे हाप हार्टेड में बात नहीं करता। ये पागलों की सोच में निर्माण हुआ है इसको तोड़ दीजिए। अब वो चूंकि 80 प्रतिशत बन गया है इसलिए वे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय नेता प्रतिपक्ष :- अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि सिवरेज का जो अच्छे टेक्निकल जो जानकार हैं, मुख्यमंत्री जी वहीं एक बैठक ले लें बिलासपुर में, वहां के जनप्रतिनिधियों को भी बुला लें, अधिकारियों को भी बुलवा लें और बुलवा करके उसका एक बार परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण करने के बाद में लगता है कि अब ये सफल है और थोड़े बहुत पैसे से इसे पूरा कर सकते हैं। लोगों को इसमें लाभ मिलेगा तो आगे बढ़ना चाहिए। मेरा केवल इतना ही आग्रह है, इस सुझाव में।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, और ये रायपुर वाले तो तोड़ने की घोषणा कर ही दो साहब। ये बिल्कुल फालतू है, इसको तोड़वा दीजिए, जितना बजट और लगे जोड़ लीजिए अभी लगे हाथ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष जी, ये दोनों का परीक्षण करा लेते हैं और आप जो सुझाव दे रहे हैं, बिलासपुर में भी मीटिंग करा लेते हैं, और यहां रायपुर में भी जनप्रतिनिधि का मीटिंग करा लेते हैं, दोनों जगह मीटिंग करके जो उचित सुझाव आएगा वो कर लेंगे। मैं इस बात की यहां घोषणा करता हूं।(मेजों की थपथपाहट) आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि अब काफी समय जो चुका है, मैं जल्दी समेटने की कोशिश कर रहा हूं। स्थानीय उद्योग और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभाग में जो जेम के स्थान पर सी.एस.आई.डी.सी. से सामग्री क्रय करने का फैसला हमने किया है ताकि जो स्थानीय उद्योग है, उसको लाभ मिले। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीम कुंभ का नाम हमने राजीम पुन्नी मेला करने का फैसला इस प्रयुक्त सदन ने किया है। चिटफंड कंपनी जो पैसा गया है लोगों का और हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही घर के लोग हैं, जो जेल में हैं, उसे छुड़वाने का काम और साथ ही साथ पैसा कैसे आए। मुख्य उद्देश्य किसी को जेल भेज देना नहीं है, मुख्य उद्देश्य उन गरीबों का, जो मेहनतकश लोगों का जो नौकरी पेशा जो, रिटायरमेंट के बाद या जमीन बेचने के बाद जो पैसा जमा किये उन लोगों को पहुंचे और इसके लिए आप सबका सहयोग हम चाहते हैं, इस दिशा में हमने काम किया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदन सही समय पर निपटाया जाये इसके लिए हमने निर्देश दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 डिसमिल तक के कम भूखंडों की खरीबी बिक्री व पंजीयन पर रोक हमने हटा दी है और लगभग 10 हजार रजिस्ट्री हुई है जिससे आम जनता को इसका

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लाभ मिल रहा है। (मेजों की थपथपाहट) बस्तर और सरगुजा में जो प्राधिकरण बना है, उसकी अध्यक्षता हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, वे लोग करेंगे। उद्योग नहीं लगाने के कारण से जो टाटा, जहां से टाटा करके चला गया था, लोहण्डीगुड़ा में 774 हेक्टेयर जमीन हमने किसानों को वापस किया है। (मेजों की थपथपाहट) तेंदूपत्ता संग्रहण पर पारिश्रमिक 2500 से बढ़ाकर 4 हजार क हमने फैसला किया है। वनाधिकार नियम को प्रभावी बनाने के लिए हमने निर्देश दिये हैं और जितने भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग है, उनकी हमने संयुक्त रूप से बैठक की थी। मंत्री लोग भी उसमें उपस्थित थे, जो जहां काबिज है। 13 दिसंबर 2005 से पहले जो आवेदन निरस्त कर दिये गये थे, उसका पुन: परीक्षण किया जा रहा है और उन सब लोगों को पट्टा दिया जा रहा है। आपने तो वहां जो आदिवासी के अलावा गैर आदिवासी जो रहते हैं, उनको तो आपने दिया ही नहीं था। अभी हम लोग मैनपाट गये थे, श्री अमरजीत भगत जी के क्षेत्र में मैनपाट गये थे, वहां हम लोगों ने 1 हजार पट्टा बांटा, जिसमें हमारे 600 हमारे आदिवासी और 400 गैर आदिवासी थे। (मेजों की थपथपाहट)जो वहीं परम्परागत रूप से जीवन यापन कर रहे हैं उनको भी हमने पट्टा दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बात झीरम घाटी की है। झीरम घाटी में हमने एस.आई.टी. का गठन किया है। इसी पवित्र सदन में पिछले सत्र में आपने सीबीआई जांच की घोषणा की थी। लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। परंतु आप सब इस बात से सहमत हैं कि ये जो घटना है साधारण नक्सली घटना नहीं है। ये सुपारी किलिंग हैं और हमारे नेताओं को पूछ-पूछ कर, उनकी हत्या की गई और इसलिए ये राजनीतिक अपराधिक षड्यंत्र है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए हमने एस.आई.टी. का गठन किया था और इसके लिए हमने भारत सरकार को पत्र लिखा था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज ही वह पत्र आया है कि होम डिपार्टमेंट ने एनआईए से केस वापस देने के लिए मना कर दिया है और ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है कि आखिर भारत सरकार खुद भी एनआईए ने जो रिपोर्ट दी है उसमें पढ़ लीजिएगा। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों को जो गवाही है, उनसे पूछताछ करने की जरूरत है, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी करने की आवश्यकता है और यह कहते हुए भी उन्होंने फाईनल रिपोर्ट सबमिट कर दी और ये एनआईए के रिपोर्ट से ये परिलक्षित होता है कि इसमें और अधिक जांच करने की आवश्यकता है, गहराई से जांच करने की आवश्यकता है और इसके लिए हमने एस.आई.टी. का गठन किया था। लेकिन भारत सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के राशन में जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं। पिछले समय नान घोटाला बड़ा प्रचलित था, पूरे 5 साल उसकी चर्चा इस पवित्र सदन में होती रही। लेकिन आधी-अधूरी जांच हुई थी और ये भी मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने उसके लिए एस.आई.टी. का गठन किया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है और जो लोग उसमें मिले हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। आधी-अधूरी कार्यवाही नहीं, बल्कि उस कार्यवाही को आगे बढ़ाने की बात और उस डायरी में जिनका नाम है सबसे पहले पूछताछ की जाएगी और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और मैं समझता हूँ कि इसीलिए शायद ये बदलापुर की जो बात कह रहे हैं, ये उसी कारण से कह रहे हैं इसलिए तकलीफ हो रही है। यदि सही जांच करते तो जहां पैसा गया है उसकी भी जांच कर लेते, उससे भी पूछताछ कर लेते तो ये बात नहीं आती, आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- करिये साहब, अच्छी बात है। बदलापुर से नहीं अच्छी भावना से करें, लेकिन मैंने आज अपने भाषण में एक एस.आई.टी. की मांग की है 20 करोड़ में कांग्रेस की टिकट बिकी वालें में भी एक एस.आई.टी. बना दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- साहब, आप प्रमाण दे दीजिए। कहने भर से क्या होगा। आपकी सरकार में हुआ। आप ही ने जांच करवाई। हम तो वही कर रहे हैं, जो आपने किया उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने नान ऑफिस में छापा मारा। आपने जांच कराई। इसको तो हमने केवल आगे बढ़ाने का काम किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने भी आज एक विषय में एस.आई.टी. की मांग की है।

श्री भूपेश बघेल :- हॉं, आदरणीय आप प्रमाण तो दे दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिल्कुल मैं आपको दे दूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- उस प्रमाण को लाईये, उसका परीक्षण करवा लेंगे। उसमें क्या तकलीफ है? लेकिन आप हवा हवाई बात न करें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 10 दिनों में किसानों का कर्ज का पैसा खाते में पहुंचना चाहिए, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ऐसा बोले थे। वह तो कर ही नहीं रहे हो। पहले घोषणा किये थे उसको तो कर दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरे प्रदेश के मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक स्टींग ऑपरेशन को प्रसारित किया था और उसमें आपकी और अन्य किसी व्यक्ति के बातचीत का उल्लेख था और आपके माननीय प्रदेश प्रभारी जी का भी जिक्र था। अंतागढ़ टेपकाण्ड में एस.आई.टी.बन गई, जो व्यक्ति अंतागढ़ टेपकाण्ड का तथाकथित हीरो है, वही उस स्टींग ऑपरेशन का हीरो है उस पर आप एस.आई.टी. बनाईये, उसकी भी जांच कराईये।

श्री भूपेश बघेल :- हो गया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिवरतन शर्मा :- जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतागढ़ में किसने एफ.आई.आर. करवाई थी ? आपको पता है ? बिलासपुर में भी हुआ था, इस सदन के सदस्य हैं इसलिए मैं नाम नहीं लेता। कांकेर में हुआ था, रायपुर में भी हुआ था आपके शासन का वर्ष 2014 का मामला है 4-5 साल बीतने के बाद भी उसमें आपने कोई कार्यवाही नहीं की। 3 जिलों में 3 अलग-अलग जगहों में एक ही प्रकार के आवेदन थे, उसको आपने खारिज भी नहीं किया। वह आवेदन वहीं के वहीं पड़े हुए हैं उसको हमने एक जगह करके जांच करा दी तो तकलीफ किस बात की है ? आपके ही प्रकरण है जैसे आप कह रहे हैं कि जो हमने किया है वही बजट आप प्रस्तुत कर रहे है, हमारा ही किया है। कॉलेज में जो भर्तियां हो रही हैं हमने, हमने मेहनत की और आप श्रेय ले रहे हैं। ये काम भी आपका ही है। आपके शासनकाल में उसकी जांच करा लेते तो मुझे जांच कराने की आवश्कयता नहीं पड़ती, नंबर एक। नंबर दो नान घोटाले में भी यदि आप सही जांच करा लेते तो हमको उसको अतिरिक्त जांच कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते बहुत दुख हो रहा है कि नान में जो फाईल है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अधिकारियों के, नेताओं के, पता नहीं किसके-किसके फोन टेप हो रहे थे। इसी कारण से हमने निलंबित किया है। आप जब मंत्री थे, विधायक थे, फोन में बात नहीं करते थे, वाट्सअप लगाते थे, सिग्नल में बात करते थे। आप भी दहशत में थे। मंत्रियों को, अधिकारियों को इतनी दहशत थी। कोई अधिकारी सामान्य टेलीफोन से बात नहीं करते थे, ये स्थिति थी, मैं समझता हूं कि सारा सदन इससे सहमत होगा। (मेजों की थपथपाहट) आप सुन लीजिए, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, चिंता मत कीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- इसी से रिलेटेड मेरी एक बात थी।

श्री भूपेश बघेल :- आप सुन तो लीजिए। बिना अनुमति के आप किसी का फोन टेप कर रहे हैं, आपने इतनी खुली छूट दे रखी थी। आपको याद होगा जब उसी अधिकारी के खिलाफ मैंने 40 मिनट भाषण दिया था तो बहुत सारे मंत्री मुझे बोले कि भाषण 40 मिनट में क्यों समाप्त कर दिये ? आप और बोलते हम लोगों के दिल में ठंडक मिल रही है। बहुत सारे जो मंत्री हैं, अब वह नहीं हैं, कुछ तो अभी हैं, सामने भी हैं जिन्होंने मुझे बधाई दी थी। अभी कार्यवाही किया मैं समझता हूं कि उससे आप लोग ज्यादा खुश हैं, आप जो नहीं कर पाये, ननकीराम कंवर जी ने खुले-आम बधाई दी कि कोई तो है जो साहस किया। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बजट की बात कह रहे थे, मैं उसमें नहीं आया था, जनसंपर्क विभाग में कभी 130, 140 करोड़ का बजट हुआ करता था, लेकिन इलेक्शन ईयर था, आपने 260 करोड़ का बजट किया और नेता जी, खर्चा कितना किया? 400 करोड़ का खर्चा किया। और क्या करवाते रहे, यही सब करवाते रहे? आप उसका क्यों एफ.आई.आर. नहीं कराये? आपके समय का है, आप एफ.आई.आर. करा देते। हम जांच भी करा देते। हम उसके पीछे भागने वाले नहीं हैं। लेकिन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आपने एफ.आई.आर. नहीं कराया। ये जितने भी हैं वह सब आपके समय का है, उसको हमने जांच कराया है। इन सबको जनसंपर्क विभाग में जो गड़बड़ी हुई हैं, उसको भी हमने ई.ओ.डब्ल्यू. में दिया है। 400 करोड़ एक दिन में वह भी उस दिन जिस दिन आचार संहिता लगी, उस दिन जनसंपर्क विभाग के मंत्री दस्तखत कर रहे हैं। और तीन दिन बाद आचार संहिता लगने के बाद वह जो जनसंपर्क का अधिकारी है, वह रिलीज कर रहा है। आप बंदरबाट कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की संपत्ति है, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा है, किसी के घर का पैसा नहीं है जिसको लुटाने का आपको अधिकार दिया गया था। अब उसमें जांच करायें तो आपको तकलीफ होती है। ये बदलापुर है? ये न्याय की बात है। छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे की एक-एक पाई का हिसाब लेने का अधिकार है और हम लेकर रहेंगे। आपने 400 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। आपने बजट से बाहर जाकर खर्च कर दिया। उसमें जांच कर रहे हैं तो बदलापुर कहते हैं। कितनी सारी एजेन्सी जो छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं हैं, जो इस प्रदेश में हैं, बाहर हैं, आपने सबको पैसा दे दिया। काम हो गया, टेन्डर बाद में हो रहा है। कार्योत्तर स्वीकृति और उसके बाद 5 दिन में काम करके करोड़ों रुपये का भुगतान करने का ये काम हुआ है। यदि हम इसकी जांच करा रहे हैं ये बदलापुर की नहीं है, आर्थिक अनियमितता की है, छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटने का आपने प्रयास है, उसकी जांच करायेंगे। आप जितने बार बदलापुर बोलना है, बोलते रहिये, लेकिन हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, जनसंपर्क में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद आखिरी दिन 28 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे।

श्री अमरजीत भगत :- इनका तो काम ही था राम नाम जपना, पराया माल अपना।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला खनिज संस्थान न्यास के बारे में बड़ी चर्चा हुई। हम लोगों ने वहां बैठे थे, नेता प्रतिपक्ष जी बार-बार कहते रहे कि वहां जनप्रतिनिधियों को रखिये । कलेक्टर को अध्यक्ष मत बनाईये लेकिन आपने माना नहीं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं एक विषय बोल रहा था, आप उसका जवाब दे रहे थे आपने स्वयं ने बताया कि अंतागढ़ वाले मामले में 3 दरख्वास्त अलग-अलग जगह थी तो रात के डेढ़ बजे आपको थाने में नामजद रिपोर्ट लिखाने की आपको जरूरत क्यों पड़ गयी ?

श्री भूपेश बघेल :- आपको कहां से पता चल गया ? कोई और करा दिया हो तो क्या उसमें कोई रोक सकता है ? यदि आम जनता कोई आवेदन दे दे तो क्या उसमें कोई रोक है ? आप लोग किसी भी बात को घुमा रहे हैं । अभी माननीय अजय जी ने क्या कहा था कि एक अधिकारी न्यायालय के सामने खड़ा हो गया उसको ससपेंड कर दिया गया । बताईये कहां सस्पेंड हुआ है, कोई अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने सस्पेंड कर दिये नहीं कहा, आप रिकॉर्ड दिखवा लीजिये । मैंने यह कहा कि वह सुरक्षा के लिये त्राहि-त्राहि कर रहा है, मांग रहा है यह बोला, रिकॉर्ड देख लीजिये ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अजय चंद्राकर जी, हमें भी मालूम है । 3 साल हमारी सरकार थी लेकिन प्रथम कार्यकाल में आपकी नहीं चलती थी । पिछले वाले की चलती रही । अभी भी उसका दहशत इतना है । वे दबाव में काम कर रहे हैं वह भी हम प्रमाणित कर देंगे । किस प्रकार से अधिकारियों को कंट्रोल करके रखा गया था, मैं सभी अधिकारियों की बात नहीं करता, बहुत सारे ईमानदार अधिकारी हैं, बहुत सारे ईमानदार कर्मचारी हैं । मैं उनकी बात नहीं करता लेकिन चंद मुट्ठीभर लोगों को आपने जो उनका अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर छोड़ दिया था, सीमा से बाहर आपने अधिकार दे दिया था, स्वेच्छाचारिता की सीमा लांघ चुके थे । जो आपके पास भी अधिकार नहीं था उससे बाहर जाकर काम करते रहे, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे दण्डित करने की कोशिश कर रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिला खनिज संस्थान न्यास के बारे में चर्चा कर रहा था । ढ़ाई हजार करोड़ आपके पास पैसा है । 4 हजार करोड़ की स्वीकृति । सड़क बना रहे हैं उस गांव में अच्छी बात है, स्कूल-बिल्डिंग बना रहे हैं, वहां मार्शल नियुक्त कर दें तो अच्छी बात है, डॉक्टर नियुक्त कर दें तो और अच्छी बात है । वहां के लोगों को सुविधा मिलेगी लेकिन आपने क्या किया केवल बिल्डिंग बनाते रहे, यहां बिल्डिंग बनाओ, वहां बिल्डिंग बनाओ, हवाई पट्टी तक आप बना दिये हैं, वह गरीब आदिवासी हवाई पट्टी का क्या करेगा ? कलेक्ट्रेड में लिफ्ट बना रहे हैं तो आखिर यह जनता का पैसा है, आपने ही नियम बनाया है कि यह बीमा का पैसा उन लोगों के जो खदान हैं या उद्योग हैं उससे प्रभावित लोग हैं उस क्षेत्र के उसे कंपनसेट हो, उसके जीवन में सुधार आये । मैं पूछना चाहता हूं कि उन लोगों के जीवन में कितना सुधार आया है ? आप उसके पैसे से उज्जवला का गैस बांट दिये । आपकी योजना थी तो आप अपने मद से पैसा बांटते लेकिन गैस सिलेण्डर से लेकर बिल्डिंग बनाने का काम आप करते रहे और 4 हजार करोड़ का सेंक्शन तो उसको रोकेंगे नहीं तो क्या करेंगे ? पैसे का बंदरबांट, दुरूपयोग उसकी जांच हम करा रहे हैं, अब वह कलेक्टर नहीं रहेगा, वहां प्रभारी मंत्री उसके अध्यक्ष होंगे और कलेक्टर सचिव रहेगा और विधायक लोग भी सदस्य रहेंगे । यह आदेश बहुत जल्दी हम निकालने वाले हैं । (मेजों की थपथपाहट) और उसकी समीक्षा भी करेंगे और वहां जो उपयोगी है । जो वहां आदिवासी निवास कर रहे हैं, परंपरागत रूप से वहां जो लोग निवास कर रहे हैं उनके जीवन में सुधार हो इसके लिये धन का उपयोग होगा यह हम लोगों ने निर्णय लिया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए और सदन को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं आराम देता हूं । धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ । (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

<u>अध्यक्षीय व्यवस्था</u>

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद । आज ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने आसंदी की व्यवस्था के विरोध में बहिर्गमन किया । मेरा यह मानना है कि ऐसे अवसर आ सकते हैं जब माननीय सदस्य आसंदी की व्यवस्था से सहमत न हों लेकिन इसके बावजूद भी आसंदी की व्यवस्था के विरोध में बहिर्गमन करना संसदीय परम्पराओं के विपरीत है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है भविष्य में संसदीय परम्परा का ख्याल रखेंगे । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 13 फरवरी, 2019 को 11.00 बजे तक के लिये स्थगित ।

(सायं 7.15 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 13 फरवरी, 2019 (माघ 24, 1940) के पूर्वाह्न 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई)

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 12 फरवरी, 2019

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं